राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 276

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 14 मार्च 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

कोरोना को लेकर चीनी राष्ट्रपति के दावों पर उठ रहे सवाल

>> 13

आइपीएल, वनडे मैचों की सीरीज स्थगित

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

वैश्विक खेल जगत पर कहर बरपाने के बाद कोरोना वायरस ने भारतीय क्रिकेट को भी अपनी जद में ले लिया है। चैंपियंस लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरी-ए और एनबीए जैसी विश्व की शीर्ष खेल लीगों के बाद भारत की सबसे बड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) भी 15 अप्रैल तक टाल दी गई है। यही नहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज भी स्थगित कर दी है।

एक दिन में दो मैच कराने की योजना: आइपीएल 29 मार्च को शुरू होना था लेकिन अब यह 15 अप्रैल के बाद होगा। बीसीसीआइ को लग रहा था कि वह खाली स्टेडियम में आइपीएल करा लेगा लेकिन केंद्र सरकार के विदेश से आने वाले लोगों के वीजा निलंबन के कारण उसकी उम्मीदों को झटका लगा। सभी आइपीएल फ्रेंचाइजी और प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स विदेशी खिलाड़ियों के बिना खाली मैदान में लीग आयोजित कराने के पक्ष में नहीं थे। महाराष्ट्र सरकार ने आइपीएल की टिकट बिक्री पर पहले ही रोक लगा दी थी जबकि कर्नाटक सरकार ने सुरक्षा देने से मना कर दिया। वहीं दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दर्शकों की उपस्थिति में आइपीएल के आयोजन से साफ-साफ इन्कार कर दिया।

फिर से होगी तीन वनडे मैचों की सीरीज : आइपीएल के टलने के बाद बीसीसीआइ के सचिव जय शाह ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) और बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) के अधिकारियों से बातचीत की। भारत और दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाड़ियों से भी बात की गई। सभी मैच को बाद में करवाने के पक्ष में नजर आए। इसके बाद बोर्ड ने 15 मार्च को लखनऊ और 18 मार्च को कोलकाता में होने वाले बचे हुए दोनों मुकाबले स्थगित करने की घोषणा की। सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में बारिश के कारण रद हो गया था। अब दक्षिण अफ्रीका बाद में तीन वनडे मैचों की सीरीज के खेलने के लिए भारत का दौरा करेगी। बीसीसीआइ और क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका मिलकर बाद में नई तारीखों पर फैसला करेंगे। सरकारी दिशानिर्देशों के कारण पहले इन मैचों को खाली स्टेडियमों में करवाने का फैसला किया गया था।

> बीसीसीआइ साझेदारों और लोगों की सुरक्षा के प्रति सचेत है। इसके लिए हम सभी जरूरी कदम उठाने को तैयार हैं। बीसीसीआइ सरकार के साथ खास तौर से खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में है। हम सभी के साथ मिलकर काम करेंगे।
>
> **जय शाह,** सचिव, बीसीसीआइ

खेल पर गाज

- महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली की सरकारों के हाथ खड़े करने व विदेशी खिलाड़ियों के वीजा निलंबन के कारण आइपीएल को टाला गया
- 15 अप्रैल तक विदेशी खिलाड़ी नहीं आ सकते हैं भारत, उनके बिना लीग आयोजित कराना संभव नहीं
- फिलहाल आइपीएल के मैचों की संख्या में कमी नहीं की गई है और बोर्ड को लगता है कि आने वाले समय में पूरे मैच आयोजित होंगे
- दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो वनडे के लिए बीसीसीआइ ने दोनों टीमों के खिलाड़ियों की राय ली जिसमें सभी ने मैच स्थगित करने को कहा
- बाद में द. अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज दोबारा होगी

कोरोना कर्फ्यू

महामारी बन चुके कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। शिक्षण संस्थान, दुकान, बाजार, सिनेमा घर व शापिंग कांप्लेक्स आदि बंद किए जा रहे हैं। देश-विदेश के कई बड़े खेल आयोजन भी ठप होने लगे हैं। ओलंपिक पर भी संशय है। संसद सत्र पर तो फिलहाल असर नहीं पड़ा है, लेकिन कई राज्यों के विधानसभा सत्र को स्थगित करना पड़ा है। एयर इंडिया की फ्लाइट 30 अप्रैल तक इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन आदि के लिए उड़ान नहीं भरेंगी।

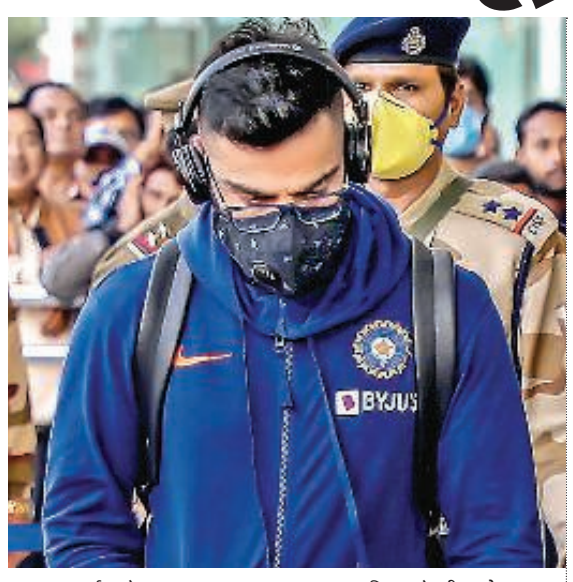

लखनऊ हवाईअड्डे पर मास्क लगाए नजर आए कप्तान विराट कोहली ● प्रेट्र

देश और दुनिया में तेज हुए बचाव और एहतियात के कदम

82 हुई देश में पीड़ितों की संख्या, दो की हो चुकी है मौत

- सेना ने महीने भर के दौरान होने वाली सभी भर्ती रैलियां रद कीं
- उत्तर प्रदेश में 22 मार्च तक सभी स्कूल व कॉलेज बंद किए गए
- हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश बिहार में शिक्षण संस्थान 31 तक बंद
- जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की कक्षाएं 31 तक निलंबित
- जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की सभी कक्षाएं 31 तक निलंबित की गईं
- ओडिशा में भी 31 तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया
- दिल्ली सरकार ने खेल संबंधी सभी गतिविधियों पर लगाई रोक
- बॉलीवुड को भी उठाना पड़ रहा 40-50 फीसद का नुकसान

अर्जेंट मामले ही सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: कोरोना ने सुप्रीम कोर्ट के कामकाज पर भी असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार से सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई करेगा। अदालत कक्ष के अंदर बहस करने वाले वकील और उसके साथ एक मुवक्किल को ही जाने की इजाजत होगी। (पेज-5)

5,043 हुए दुनियाभर में मरने वाले, 1,34,000 से ज्यादा पीड़ित

- नेपाल ने एवरेस्ट की चढ़ाई पर लगाई रोक
- ईरान में हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी
- पूर्वी अफ्रीका में घुसा वायरस, केन्या के एक व्यक्ति में हुई पुष्टि
- भारतीयों को लाने के लिए आज इटली जाएगा एयर इंडिया का विमान
- ईरान से वापस लाए गए 44 भारतीय

कोरोना का कहर >> पेज 5 और 6

वायरस से दिल्ली में पहली मौत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में भर्ती कोरोना वायरस से संक्रमित 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला की शुक्रवार को मौत हो गई। कोरोना के संक्रमण से यह देश में दूसरी और दिल्ली में पहली मौत है। इसके अलावा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती दिल्ली निवासी एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर सात हो गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जनकपुरी निवासी 46 वर्षीय शख्स जापान व इटली से लौटने के बाद कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद परिवार के नौ सदस्यों को आइसोलेट करा दिया गया। बाद में उनकी मां भी वायरस की चपेट में आ गई थीं। परिवार के लोगों के अनुसार, करीब एक सप्ताह से बुजुर्ग महिला आरएमएल अस्पताल में भर्ती थीं। अस्पताल में भर्ती होने पर जांच में पता चला कि उन्हें मधुमेह भी है और शुगर का स्तर (300-350 मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर) काफी बढ़ा हुआ था। उन्हें निमोनिया भी हो गया था। शुक्रवार रात उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य महानिदेशालय का कहना है कि शुक्रवार रात 8:30 बजे बुजुर्ग महिला की मौत की सूचना अस्पताल से प्राप्त हुई है। महिला को को-मॉर्बिडिटी भी थी। डेथ-समरी मंगाई गई है।

असमंजस में परिजन

परिजन इस बात को लेकर असमंजस में है कि दाह संस्कार के लिए उन्हें शव मिलेगा या नहीं। परिजनों ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क करने की भी कोशिश की है। बताया जा रहा है कि शव का पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा।

महामारी से मिलकर लड़ें सार्क देश : मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत और पड़ोसी देशों में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों को एकजुट करने का प्रयास शुरू कर दिया है। शुक्रवार को कोरोना वायरस के खिलाफ सामूहिक रणनीति बनाने के लिए उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के सदस्य देशों से एकजुट होने की अपील की, जिसका असर भी दिखा। शुक्रवार देर शाम तक नेपाल, मालदीव, भूटान व श्रीलंका की तरफ से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया जताई गई।

मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 'दुनिया में कोविड-19 कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई चल रही है। सरकार व जनता कई स्तरों पर इसके खिलाफ पूरी क्षमता से निपटने में लगे हैं। मैं सार्क देशों के नेताओं को प्रस्ताव करता हूं कि हम कोरोना वायरस के खिलाफ मजबूत रणनीति बनाएं। हम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपने नागरिकों को स्वस्थ्य रखने पर चर्चा कर सकते हैं।'कुछ ही देर बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने मोदी को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया और कहा, श्रीलंका इस अभियान में हिस्सा लेने को तैयार है। इस कठिन समय में क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए संगठित होने की जरूरत है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मुहम्मद सोलिह ने भी इस प्रयास में हर मदद का आश्वासन दिया।

नरेंद्र मोदी ● जागरण अर्काइव

नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा, जिस तरह से उन्होंने (मोदी) सार्क देशों की अगुआई में मजबूत रणनीति बनाने का आह्वान किया है, वह स्वागत योग्य है। हम हर मदद को तैयार हैं। भूटान के पीएम ने ट्वीट किया, यही नेतृत्व क्षमता होती है। एक क्षेत्र के तौर पर हमें आगे आना चाहिए। इसमें शक नहीं है कि आपके नेतृत्व में हम सफल रणनीति बना सकते हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी भारतीय प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर चर्चा में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हालांकि, पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

कूटनीतिक गलियारे में चर्चा, माहौल जांच रहा भारत

- प्रधानमंत्री के ट्वीट को लेकर कूटनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि भारत कोरोना वायरस के बहाने ठंडे बस्ते में पड़े सार्क सहयोग वार्ता को फिर से शुरू करने को 'स्थिति की पड़ताल' कर रहा है।
- वर्ष 2016 में सार्क देशों के प्रमुखों की बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होने वाली थी, लेकिन उसके पहले पाक समर्थित आतंकी संगठनों की तरफ से हमले के बाद भारत की अगुआई में सार्क देशों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया।
- उसके बाद भारत ने सार्क के चार देशों को मिलाकर बनाए गए संगठन बिम्सटेक को बढ़ावा देना शुरू किया। भारत कहता रहा है कि सार्क देशों के सहयोग को बढ़ाने में सबसे बड़ी अड़चन पाकिस्तान का रवैया है।

सरोकार

बंजर भूमि में जंगल बन लहलहा रहा 30 वर्ष का प्रयास

रुद्रप्रयाग : उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की बुजुर्ग महिला प्रभा सेमवाल के लगाए जंगल से आसपास के दर्जनभर गांवों को सुकून मिला है। जो जमीन बंजर थी, आज उस पर विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों वृक्ष सीना ताने खड़े हैं। यह उनकी तीस वर्षों की मेहनत का फल है। (पेज-10)

जागरण विशेष

सूर्य के रहस्यों को सुलझा रहा अंशु का आविष्कार

पूर्वी चंपारण : बिहार के रक्सौल जिले की बेटी अंशु कुमारी ने रेडियो स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर नामक जो यंत्र विकसित किया, वह सूर्य के रहस्यों को समझने में सहायक विवरण जुटा रहा है। यह शोध एस्ट्रोफिजिकल जर्नल अमेरिका और सोलर फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। (पेज-10)

यस बैंक में निजी क्षेत्र के चार बैंक लगाएंगे 31 अरब रुपये

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आरबीआइ के प्रस्तावित रिकंस्ट्रक्शन प्लान को कैबिनेट की मंजूरी
- केंद्रीय बैंक जल्द ही करेगा इस संबंध में फाइनल प्लान का एलान

नई दिल्ली में शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया को कैबिनेट के फैसले की जानकारी देतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, साथ में सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर। प्रेट्र

विवादों में घिरे निजी क्षेत्र के यस बैंक को उबारने की कोशिशें रफ्तार पकड़ चुकी हैं। बैंक को फिर से दुरुस्त करने की भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की प्रस्तावित योजना को कैबिनेट ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। वहीं, देश के चार निजी बैंकों ने यस बैंक में 3,100 करोड़ के नए निवेश की तैयारी दिखाई है। इसके तहत आइसीआइसीआइ और एचडीएफसी बैंक 1,000-1,000 करोड़ व एक्सिस बैंक 600 करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक भी 500 करोड़ रुपये निवेश करने को तैयार है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) पहले ही इस बैंक में 7,250 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव अपने बोर्ड से पारित करवा चुका है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैबिनेट ने आरबीआइ की तरफ से प्रस्तावित रिकंस्ट्रक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। अब आरबीआइ इसका अंतिम रूप तैयार कर रहा है जिसका एलान जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा, यस बैंक पर लगी कारोबार पाबंदियां जल्द ही हटा ली जाएंगी। पूरा ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि यस बैंक में स्थायित्व हो और उसके ग्राहकों व खाताधारकों के हितों की रक्षा हो सके। अभी इस बैंक में एसबीआइ 49 फीसद हिस्सेदारी खरीद रहा है। दूसरे वित्तीय संस्थानों को भी हिस्सेदारी बेची जाएगी। यस बैंक का पूंजी आधार 1,100 करोड़ से बढ़ा कर 6,200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ज्ञात हो, जब आरबीआइ ने यस बैंक को उबारने का प्रस्ताव जारी किया था, तब पूंजी आधार को 5,000 करोड़ रुपये करने की बात कही थी। वित्त मंत्री की तरफ से इस एलान के कुछ ही देर बाद आइसीआइसीआइ बैंक के बोर्ड ने 1,000 करोड़ की लागत से यस बैंक में पांच फीसद हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एचडीएफसी बैंक ने भी उतने ही निवेश से पांच फीसद हिस्सेदारी लेने का फैसला किया है। एक्सिस बैंक ने 60 करोड़ शेयर 600 करोड़ रुपये में खरीदने का प्रस्ताव बोर्ड से पारित करवाया है। कोटक महिंद्रा भी 50 करोड़ शेयर 10 रुपये मूल्य की दर से खरीद रहा है। इस तरह से यस बैंक के संचालन के लिए 10,350 करोड़ का इंतजाम हो गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसद की वृद्धि पेज>>3

780 किलोमीटर का होगा ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर पेज>>3

निर्यात बढ़ोतरी के लिए नई स्कीम को सरकार की हरी झंडी पेज>>12

दलाल स्ट्रीट में रोमांचक फ्राइडे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

गुरुवार को वैश्विक शेयर बाजारों की जो दशा हुई थी, उससे सभी को आशंका थी कि भारतीय शेयर बाजार के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन एक ही दिन में बाजार ऐसा रंग दिखाएगा इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार का माहौल पहले गम और बाद में खुशी जैसा रहा। कारोबार के शुरुआती दौर में बीएसई का सेंसेक्स 3,474 अंकों की रिकॉर्ड गिरावट के साथ 29,389 के स्तर पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी भी 1,034 अंकों की गिरावट के साथ 8,555 तक लुढ़क गया। दोनों प्रमुख सूचकांकों में 10 फीसद की गिरावट होते ही 12 वर्षों बाद लोअर सर्किट लगाना पड़ा। बाजार में कारोबार 45 मिनट के लिए रोक दिया गया। जब दोबारा कारोबार शुरू हुआ तो माहौल बदला हुआ था। बाजार में निवेशक लौटने लगे थे। उसके बाद अधिकतर शेयरों में वैल्यू बाइंग के चलते सेंसेक्स 1,325.34 अंक चढ़कर 34,103.48 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 365.05 तेजी के साथ 9,955.20 अंकों पर बंद हुआ।

शुक्रवार को दोबारा शेयर बाजार में आई तेजी के लिए सेबी का आश्वासन, वित्त मंत्रालय की तरफ से अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्वों के मजबूत होने का भरोसा और एसबीआइ और एलआइसी जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों की तरफ से जमकर की गई खरीददारी को कारण बताया जा रहा है। कम कीमत पर बड़ी कंपनियों के शेयर उठाने के चक्कर में नए निवेशक भी बाजार में आए जिससे माहौल में गर्माहट आई।

- कारोबार के शुरुआत में ही सेंसेक्स भरभराकर 3,474 अंक टूटा, निफ्टी में 1,034 अंकों की गिरावट
- 12 वर्षों बाद प्रमुख सूचकांकों में लोअर सर्किट लगा, कारोबार 45 मिनट के लिए स्थगित किया गया
- कारोबार दोबारा शुरु हुआ तो बदला माहौल, सेंसेक्स में निचले स्तर से 5,380 अंकों की रिकवरी
- कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 1,325 अंक व निफ्टी 365 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ

सेंसेक्स में एक दिन में 5380 अंकों की हुई रिकवरी पेज>>12

पीयूष गोयल ने की रेलवे में निजी निवेश की जोरदार वकालत

नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल बजट खत्म किए जाने को उचित ठहराते हुए रेलवे में निजी निवेश की जोरदार वकालत की है। गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि इससे सरकार को अगले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। हाल में उजागर दलाली रैकेट और गिरफ्तारियों के मद्देनजर रेलवे में निजी बुकिंग एजेंटों को खत्म किए जाने के संकेत देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि अब ज्यादातर लोग मोबाइल पर टिकट खरीद सकते हैं, लिहाजा निजी टिकट एजेंटों की जरूरत नहीं है। (पेज-3)

राजभवन की चौखट पर मध्य प्रदेश का सियासी संग्राम

नईदुनिया : मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जारी सियासी संग्राम अब राजभवन की चौखट पर पहुंच गया है। सभी की निगाहें अब राजभवन से लिए जाने वाले निर्णयों पर टिक गई हैं। सियासी उठापटक, सरकार के बहुमत पर संशय और राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण को लेकर शुक्रवार दिन भर सवाल उठते रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजभवन पहुंचकर अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट की बात रखी, जबकि भाजपा का तर्क है कि अल्पमत सरकार के बजट का क्या औचित्य? पहले बहुमत साबित हो। इन सब के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल कर दिया। (पेज-4)

बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश-2020 को मंजूरी, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई योगी सरकार ने किया अहम फैसला

उपद्रवियों से वसूली को उप्र सरकार ने बनाया कानून

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

विरोध प्रदर्शनों, आंदोलनों, जुलूसों और धरने के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है। शुक्रवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रापर्टी अध्यादेश, 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई।

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका (क्रिमिनल) संख्या-77/2007 व इसके साथ संलग्न याचिका (क्रिमिनल) संख्या-73/2007 की सुनवाई करते हुए विशेष रूप से राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों व आंदोलनों के दौरान संपत्तियों को क्षति पहुंचाने की गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराकर दोषियों से नुकसान की भरपाई कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने यह अध्यादेश लाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अध्यादेश को अमली जामा पहनाने के लिए जल्द ही नियमावली बनायी जाएगी।

सुरेश कुमार खन्ना फाइल फोटो

सरकार के प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि उप्र में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली के लिए अब तक कोई कानून नहीं था। अभी जो व्यवस्था है, वह शासनादेश के माध्यम से चल रही है। कोर्ट ने कहा, इसके लिए कानून होना चाहिए। आदेश का सम्मान करते हुए सरकार ने अध्यादेश के जरिये अब इसके लिए एक्ट बनाने का फैसला किया है।

उपद्रव के 27 आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई पेज>>7

हाई कोर्ट ने लिया था संज्ञान

लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शनों के दौरान संपत्तियों को क्षति पहुंचाने वाले लोगों से नुकसान की भरपाई के लिए लगाये गए उनके फोटो और पतायुक्त होर्डिंग व पोस्टर लगाये जाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने नौ मार्च को राज्य सरकार को ऐसे होर्डिंग व पोस्टर को हटाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी है कि संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के फोटो व पतायुक्त होर्डिंग व पोस्टर लगाना उनके निजता के अधिकार का हनन नहीं है। प्रवक्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। उसने मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे तीन जजों की बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया है।

पहलू खान की मौत के मामले में दो नाबालिगों को तीन-तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, जयपुर : पहलू खान की मॉब लिंचिंग (उन्मादी हिंसा) में मौत के मामले में शुक्रवार को किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ ने दो नाबालिगों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों को बाल सुधार गृह भेजने का आदेश दिया गया है।

हरियाणा के नूंह जिला निवासी पहलू खान परिजनों के साथ एक अप्रैल 2017 को जयपुर के पशु हटवाड़ा से 36 गायें खरीदकर गांव जा रहे थे। अलवर के बहरोड थाना क्षेत्र में कथित गोरक्षकों ने उनसे मारपीट की थी। गंभीर रूप से घायल पहलू की अस्पताल में इलाज के दौरान 4 अप्रैल को मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने नौ आरोपित बनाए थे। अगस्त 2019 में छह आरोपितों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। एक मामला कोर्ट में है। वहीं, नाबालिगों के स्वजनों ने कहा है कि फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।

पीएसए हटा, साढ़े सात महीने बाद रिहा हुए पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- गृह विभाग ने रिहाई पर लगाई मुहर, चार अगस्त 2019 को नजरबंद हुए थे फारूक
- डॉ. अब्दुल्ला बोले, जब तक उनके साथी हिरासत में हैं यह रिहाई अधूरी

जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला पर लगाए जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को समाप्त कर दिया। करीब साढ़े सात माह बाद रिहा होते ही डॉ. फारूक ने दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के अलावा सभी नेताओं की रिहाई की मांग की है।

शुक्रवार दोपहर को राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर डॉ. फारूक की रिहाई पर मुहर लगाई। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी ने डॉ. फारूक के घर जाकर रिहाई के दस्तावेज सौंपे। डॉ. फारूक की अचानक हुई रिहाई ने जितना चौकाया, उससे ज्यादा हैरानगी मौजूदा हालात पर उनकी चुप्पी को लेकर हुई। पत्नी मौली, बेटी साफिया व नाती समेत परिवार के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में पत्रकारों से रूबरू होते हुए डॉ. फारूक ने कहा, मैं संसद में जम्मू-कश्मीर के लोगों की बात उठाऊंगा। उन्होंने कहा, जल्दबाजी में सियासी कदम नहीं उठाऊंगा। हालात का जायजा लेने के बाद नए एजेंडे को सार्वजनिक करूंगा। मैं जम्मू-कश्मीर के अवाम और देश के सभी नेताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने हमारी रिहाई की आवाज उठाई है। बेशक मैं रिहा होने के बाद आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन जब तक सभी राजनीतिक नेताओं की रिहाई नहीं होती यह आजादी अधूरी है।

उमर-महबूबा जैसे नेताओं की रिहाई तक नहीं होगी कोई सियासी बातचीत पेज>>7

400 से अधिक दंगाइयों की पहचान कर चुकी है पुलिस उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 24 व 25 फरवरी को हुए दंगों के मामलों में। इनकी तलाश में 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 मार्च 2020

न्यूज गैलरी

आज कुछ जगह हो सकती है हल्की बारिश

नई दिल्ली : मौसम के उतार-चढ़ाव के बीच शनिवार को दिल्ली में फिर से हल्की बारिश होने की संभावना है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। इससे शनिवार को भी मौसम में ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम 28.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 38 से 91 फीसद रहा। रविवार से मौसम बदलने लगेगा। अनुमान है कि 18-19 मार्च तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। दिन में धूप खिलने से गर्म हवा चलने के कारण न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम के रुख में आए बदलाव के बाद स्थानीय कारणों से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एयर बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 173 दर्ज किया गया। (जासं)

एक लाख 28 हजार छात्र गेट परीक्षा में उत्तीर्ण

नई दिल्ली : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) दिल्ली की ओर से फरवरी में ग्रेजुएट एप्टिट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) 2020 परीक्षा करवाई गई थी। सभी आइआइटी के पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस परीक्षा में कुल 8 लाख 58 हजार छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से सिर्फ 6 लाख 85 हजार छात्र ही परीक्षा में बैठे थे। इनमें से कुल 18.8 फीसद यानी 1 लाख 28 हजार छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। आइआइटी दिल्ली ने शुक्रवार को नतीजों की घोषणा की। संस्थान की तरफ से अपने नतीजों से जुड़ी जानकारी के लिए छात्रों से आइआइटी दिल्ली की गेट 2020 परीक्षा की वेबसाइट को देखने के लिए कहा गया है। (जासं)

युवक के अंगदान से चार लोगों को मिला जीवनदान

नई दिल्ली : होली के दिन छत से गिरने के कारण उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले राजमणि गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें आरएमएल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वह खुद तो नहीं बच पाए लेकिन उनके अंगदान से चार लोगों को जीवनदान मिला। आरएमएल अस्पताल में पहली बार लिवर, दोनों किडनी व दिल भी दान किया गया। एम्स में दिल व एक किडनी, यकृत व पित्त विज्ञान संस्थान में लिवर और आरएमएल में एक मरीज को किडनी का प्रत्यारोपण हुआ। आरएमएल अस्पताल के अनुसार होली के दिन रंग खेलते समय राजमणि छत से नीचे गिर गए थे। इस कारण उसके सिर में गंभीर चोट लगी थी। 12 मार्च को डॉक्टरों ने मरीज को ब्रेन डेड घोषित किया। इस बीच उनके अंगदान के लिए परिजनों की काउंसलिंग की गई। (जासं)

मेरे पास नहीं है जन्म प्रमाण पत्र : केजरीवाल

विशेष सत्र ▶ मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार से मेरी अपील एनपीआर और एनआरसी को रोक दिया जाए

एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को राजधानी में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (एनआरसी) नहीं लागू करने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने यह प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा। इस पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष व विपक्ष के सदस्यों ने अपने विचार रखे और उनके बीच जमकर बहस हुई। इस दौरान एक बार सदन की कार्यवाही को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एनपीआर और एनआरसी के तहत जनता से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। 90 फीसद लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। मेरे, मेरी पत्नी और मेरे माता-पिता के साथ मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित विधानसभा के 61 सदस्यों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? ये डर सबको सता रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि एनपीआर और एनआरसी को लागू न किया जाए। ज्यादातर सदस्यों ने राय के प्रस्ताव के समर्थन में अपना पक्ष रखा।

विधानसभा में बोलते अरविंद केजरीवाल। साथ में मंत्री मनीष सिसोदिया। सौ. दिल्ली सरकार

एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में पेश प्रस्ताव के पक्ष में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। कई लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे देश में अभी उतना नहीं फैला है। लेकिन हमारे देश के अंदर भी जनता के मन में इसे लेकर बहुत बड़ी चिंता है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि इस समय देश के सामने, सभी सरकारों व सभी पार्टियों के सामने यह सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए।

हमारे देश में इस समय बेरोजगारी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी हुई है। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं और बेरोजगारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। मुझे लगता है कि सभी सरकारों को मिल कर इस वक्त बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि 20 जून 2019 को राष्ट्रपति ने कहा था कि एनआरसी को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जाए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गत 10 दिसंबर को इसे लागू करने का संसद में वक्तव्य दिया था तो अब बचा क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ये कह रहे हैं कि सीएए अलग है और एनपीआर अलग है। एनआरसी अलग है, जबकि ऐसा नहीं है। इन सभी कानूनों का एक-दूसरे से रिश्ता है। एनपीआर तो 2010 में भी हुआ था। तब अफरातफरी नहीं मची। एनपीआर 2015 में भी भाजपा की सरकार ने किया था। तब तो अफरातफरी नहीं बची। अब अफरातफरी क्यों मच रही है। उन्होंने कहा कि अब अफरातफरी इसलिए मच रही है, क्योंकि गृहमंत्री जी ने खुद समझाया है कि पहले सीएए आएगा, फिर एनपीआर आएगा और फिर एनआरसी आएगा। उन्होंने बताया कि गृहमंत्री ने कहा था कि तीनों चीजें एक-दूसरे से संबंधित हैं। केजरीवाल ने कहा कि लोगों में इस बात की चिंता है कि पांच साल के दौरान असम में डिटेंशन सेंटर के अंदर क्या हुआ। असम में एनआरसी हुआ। एनआरसी होने के बाद 19 लाख लोग भारत के नागरिक नहीं है। यह घोषित कर दिया गया और उन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। उन लोगों का क्या हाल हुआ, यह सारा देश देख चुका है। इसलिए देश में इस बात को लेकर चिंता है कि कहीं मेरा भी नाम एनआरसी से गायब तो नहीं हो जाएगा। कहीं मैं भी डिटेंशन सेंटर में भेज तो नहीं दिया जाऊंगा।

मुख्यमंत्री ने कहा आप चाहे हिंदू हो पंचायत का चलेगा।

केंद्रीय कैबिनेट में भी कई के पास नहीं होगा जन्म प्रमाण पत्र : केजरीवाल ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि केंद्रीय कैबिनेट में पता कर लें कि कितनों के पास जन्म प्रमाण पत्र के कागज हैं। देश के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।

दिल्ली दंगे पर हुआ हंगामा, निष्कासित किए गए विजेंद्र गुप्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता की विवादित टिप्पणी पर विस में जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ गई। इसके बाद भी सत्ता पक्ष के विधायक भाजपा विधायक से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग पर अड़े रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनसे अपने शब्द वापस लेने के लिए कहा, लेकिन जब वह नहीं माने तो उन्हें सदन की कार्यवाही से निष्कासित कर दिया गया। दरअसल, विधानसभा में दिल्ली हिंसा पर बोलते हुए विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगे में आप शामिल रही है। इस पर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। वे हंगामा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की कुर्सी तक पहुंचने लगे। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही करीब आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ गई। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायक फिर से हंगामा करने लगे। पार्टी के चीफ व्हिप दिलीप पांडे सहित सभी विधायक विजेंद्र गुप्ता से अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कई बार भाजपा विधायक से अपने विवादित शब्द वापस लेने का अनुरोध किया। गुप्ता जब इसके लिए नहीं माने तो अध्यक्ष ने उन्हें दिन भर के लिए सदन की कार्यवाही से निष्कासित कर दिया।

प्रस्ताव को नेता प्रतिपक्ष ने किया खारिज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को एनपीआर और एनआरसी पर सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि इस प्रस्ताव को सदन में लाए जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह अपनी और भाजपा के सभी सदस्यों की ओर से इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी (आप) इस पर जानबूझकर भ्रम फैला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बार-बार आश्वासन दे चुके हैं कि एनपीआर में दी गई जानकारी का प्रयोग किसी भी नागरिक के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने संसद में स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य केवल गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए किया जाएगा।

बिधूड़ी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ही संसद में कहा था कि एनपीआर के तहत किसी से भी कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। किसी भी नागरिक को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनपीआर मामले में कहीं किसी बात का कोई संदेह नहीं बचता। यदि आम आदमी पार्टी इस पर राजनीति करना चाहती है तो ये और बात है। नेता विपक्ष ने कहा कि भाजपा पर इंसानियत के दुश्मन होने का आरोप लगाया गया। उन्होंने सत्तापक्ष से पूछा कि पड़ोसी देशों में हिंदू-सिख बेटियों को मंडप से उठा लिया जाता था। क्या प्रधानमंत्री उनके लिए फरिश्ता बनकर आए हैं या नहीं? 1984 के दंगों और हाल ही में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। क्या 36 घंटे में हिंसा पर काबू पाना इंसानियत नहीं है? उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं।

ताहिर को तीन और सलमान को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ दोनों पर आइबी सिपाही अंकित शर्मा की हत्या का है आरोप

उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को पार्षद ताहिर हुसैन और सलमान को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया। यहां से ताहिर को तीन दिन की, जबकि सलमान को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। दोनों पर आइबी कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है।

ताहिर की सात दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने पर शुक्रवार को क्राइम ब्रांच ने उसे कड़कड़डूमा कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट विनोद कुमार गौतम की अदालत में पेश किया। यहां क्राइम ब्रांच ने कहा कि अभी आरोपित से अंकित शर्मा और दिल्ली हिंसा से संबंधित मामलों में और पूछताछ करनी है। इस पर मजिस्ट्रेट ने ताहिर हुसैन को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

इसी मामले में एक अन्य हत्यारोपित सलमान कड़ी सुरक्षा में नकाब पहनाकर पवन सिंह राजावत की अदालत में पेश किया गया। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से कहा कि उन्हें आरोपित से इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने के लिए पूछताछ करनी है।

इसके अलावा ताहिर हुसैन के जांच अधिकारी अमलेश्वर राव ने कहा कि पूछताछ के दौरान सलमान का ताहिर से भी सामना कराया जाएगा। इस पर उत्तर-पूर्वी जिले के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह राजावत ने सलमान को 17 मार्च तक चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को ही आरोपित सलमान को गिरफ्तार किया था।

ताहिर के भाई सहित चार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा : ताहिर हुसैन के घर से हिंसा फैलाने के मामले में शाह आलम, आबिद, राशिद और शादाब को क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को कड़कड़डूमा स्थित उत्तर-पूर्वी जिले के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह राजावत की कोर्ट में पेश किया। इसके बाद चारों आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शाह आलम ताहिर हुसैन का भाई है। इन चारों आरोपितों को क्राइम ब्रांच ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था।

रतन लाल की हत्या के तीन आरोपितों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा : हिंसा में मारे गए हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के तीन आरोपितों जलालुद्दीन उर्फ गुड्डू, सलीम और मुन्ना को भी शुक्रवार को मुख्य महानगर दंडाधिकारी पवन सिंह राजावत की कोर्ट में पेश किया गया। तीनों को कोर्ट ने 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, इनकी न्यायिक हिरासत 25 मार्च को खत्म होगी। इससे पहले रतन लाल के चार अन्य हत्यारोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। उस समय इन तीनों आरोपितों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था, जो शुक्रवार को पूरी हो गई।

इंटेलीजेंस ब्यूरो के सिपाही अंकित पर सलमान ने चाकू से किए थे तीन वार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ स्पेशल सेल ने सलमान को चार दिन की रिमांड पर लिया

▶ स्पेशल सेल को अंकित हत्याकांड में बदमाश मूसा का भी हाथ होने का शक

आइबी (इंटेलीजेंस ब्यूरो) के सिपाही अंकित शर्मा की हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित हसीन उर्फ सलमान उर्फ मुल्ला उर्फ नन्हें को शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया। यहां से स्पेशल सेल ने पूछताछ के लिए उसे चार दिन की रिमांड पर लिया है। क्राइम ब्रांच की अब तक की जांच में पता चला है कि सलमान ने अंकित पर चाकू से तीन वार किए थे। इससे पहले ही ताहिर के यहां मौजूद भीड़ अंकित की बुरी तरह से पिटाई कर चुकी थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि ताहिर ने अंकित पर हमला किया या नहीं किया। लेकिन उसके भीड़ को उकसाने, दंगे करवाने, आगजनी व तोड़फोड़ में साथ देने की बात साफ हो चुकी है।

सलमान के बारे में जानकारी स्पेशल सेल को मूसा नाम के बदमाश का मोबाइल फोन इंटरसेप्ट करने के दौरान मिली थी। दरअसल, दंगे के दौरान चांद बाग निवासी बदमाश मूसा का मोबाइल फोन स्पेशल सेल ने सर्विलांस पर लगा रखा था। उसकी बातचीत सुनी जा रही थी, जिसमें सलमान का नाम सामने आया। इस पर सलमान का फोन भी सर्विलांस पर लगा दिया गया। इसमें वह फोन पर किसी को बता रहा था कि उसने एक को गोद दिया है। इस बातचीत के आधार पर ही स्पेशल सेल ने शिकंजा कसा और गुरुवार को चांद बाग इलाके से सलमान को दबोच लिया। सलमान मूलरूप से अलीगढ़ का रहने वाला है। यमुनापार में वह नंदनगरी स्थित सुंदरनगरी में रह रहा था।

पूछताछ में उसने बताया कि दंगे के दौरान चांद बाग इलाके में 25 फरवरी की दोपहर अफवाह फैली कि मुस्लिम परिवार के चार साल के बच्चे की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। इससे चांद बाग में समुदाय विशेष के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे उपद्रव करने लगे। इस बीच करावल नगर रोड पर चांद बाग पुलिया के पास पत्थरबाजी हो रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सैकड़ों लोग ताहिर हुसैन के घर के बाहर जमा होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। वहीं कुछ युवक एक शख्स को पीटने के साथ ही घसीट रहे थे। वह अंकित थे, जिनके कपड़े फट चुके थे। इसके बाद आवेश में आकर उसने भी चाकू से अंकित पर तीन वार करने के बाद लात-घूसों से भी पीटा। अंकित की मौत के बाद चार-पांच लोगों ने शव को डंडे पर उठाकर नाले में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद भीड़ ने शव को उठाकर तार के ऊपर से नाले में फेंक दिया। स्पेशल सेल को शक है कि अंकित हत्याकांड में बदमाश मूसा का भी हाथ है इसलिए उसकी भी तलाश की जा रही है।

प्रदीप ने तैयारी के साथ घटना को दिया था अंजाम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा

▶ मीटिंग में फायरिंग मामला

ग्रेटर नोएडा स्थित यूपी टेलीलिंक्स फैक्ट्री में गुरुवार को निदेशक और उनके भाई को गोली मारने के बाद आत्महत्या करने के मामले में संकेत मिल रहे हैं कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि 15 दिन से बन रही थी। फैक्ट्री में लेन-देन को लेकर लगातार बैठकें हो रही थीं। इनमें दोनों पक्षों में गर्मागर्म बहस होती थी। गुरुवार को निदेशक प्रदीप अग्रवाल रिवॉल्वर लेकर फैक्ट्री आए थे। उन्होंने उसे बाथरूम में रखा था। बैठक के दौरान जब लेन-देन पर तीखी बहस शुरू हुई तो वह उठकर बाथरूम गए और बाहर निकलते ही पहले निदेशक के भाई नरेश गुप्ता और फिर प्रबंध निदेशक राकेश जैन के सिर को निशाना बनाकर गोली चलाई। इसके बाद खुद को गोली मार ली। मामले में पुलिस ने प्रदीप के खिलाफ हत्या व जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है।

इस बीच शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि प्रदीप और नरेश को सिर में एक-एक गोली लगी है। एक गोली नरेश के मोबाइल पर भी लगी मिली है। तीसरे पार्टनर राकेश जैन के सिर को रगड़ती हुई एक गोली निकली है। इस वजह से उनकी जान बच गई। अब तक की जांच में पता चला है कि गुरुवार दोपहर ढाई बजे के करीब प्रदीप के रूम में मीटिंग हो रही थी। प्रदीप और नरेश के बीच दस करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद पुराने हिसाब को लेकर था।

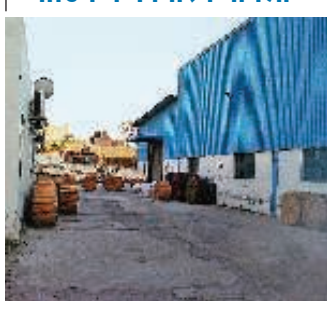

दो निदेशकों की मौत के बाद शुक्रवार को फैक्ट्री परिसर में सन्नाटा। जागरण

पूर्व में भी इसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है। बतौर गवाह राकेश जैन को मीटिंग में बैठाया गया था। पुलिस में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर से प्रदीप ने नरेश को दो गोली मारी। उसके बाद राकेश को एक गोली मारी। नरेश को गोली मारते देख राकेश भागने लगे, लेकिन सिर में गोली रगड़ाने से एकबारगी वह गिर गए। यह देख प्रदीप को लगा कि राकेश की भी मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने खुद को गोली मार ली। राकेश ने दावा किया है कि उन्होंने प्रदीप को खुद को गोली मारते देखा। घटना के समय राकेश के पुत्र मयंक भी फैक्ट्री परिसर में मौजूद थे। वह अन्य कर्मचारियों की मदद से राकेश को अस्पताल लेकर गए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि नरेश और राकेश को तीन से चार मीटर की दूरी से एक ही तरह के रिवॉल्वर से गोली मारी गई, जबकि प्रदीप को कनपटी से सटाकर गोली मारी गई।

धर्म परिवर्तन व्यक्तिगत पसंद, नहीं लगा सकते रोक : कोर्ट

जासं, नई दिल्ली : आर्थिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने या विनियमित करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास है और अन्य धर्म में परिवर्तन करना व्यक्ति की पसंद है। पीठ ने सवाल किया कि अदालत धर्म परिवर्तन को कैसे विनियमित कर सकती है। यदि कोई किसी को धमकी दे रहा है या किसी को डरा रहा है तो यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है। धर्म परिवर्तन के लिए ऐसी धमकियों के सामने डरने का कोई कारण नहीं है।

भाजपा नेता व अधिवक्ता अश्विनी कुमार की याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को डराने, धमकाने, मौद्रिक लाभ से लालच देकर और चमत्कारिक उपचार, काला जादू से धर्म परिवर्तित करा रही हैं।

बिजली की नई दरें निर्धारित करने के लिए जनसुनवाई 18 को

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने वर्ष 2020-21 में बिजली की दरें निर्धारित करने के लिए आपत्ति और सुझाव मांगें हैं। इसकी अंतिम तिथि 18 मार्च निर्धारित की गई है और उसी दिन जनसुनवाई होगी। दिल्ली में बिजली की दरों का निर्धारण डीईआरसी करता है। दूसरी ओर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के प्रतिनिधि इसका विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि सुझाव की तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। इसे लेकर दिल्ली सरकार और डीईआरसी को पत्र भी लिखा गया है।

हर वर्ष यह प्रक्रिया अमूमन फरवरी या मार्च में शुरू हो जाती है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई थी। इस बार समय पर बिजली की दरें घोषित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम), बिजली उत्पादन इकाइयां और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2018-19 के व्यय और वित्त वर्ष 2020-21 के कुल राजस्व आवश्यकताओं से संबंधित टैरिफ याचिकाएं दायर की हैं। डीईआरसी ने इनकी टैरिफ याचिकाओं को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इनकी मांगों पर उपभोक्ता डाक या ईमेल से या फिर डीईआरसी के कार्यालय में जाकर 18 मार्च तक आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं।

प्राप्त सुझावों की समीक्षा करने के बाद 18 मार्च को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में जनसुनवाई होगी। उसके बाद बिजली की नई दरें घोषित की जाएंगी। यूनाइटेड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली के महासचिव सौरभ गांधी का कहना है कि बिजली कानून का पालन नहीं किया जा रहा है।

दंगे के आरोपित 10वीं के छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगे के आरोप में गिरफ्तार 10वीं कक्षा के एक छात्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के साथ ही बोर्ड परीक्षा में भी बैठने की अनुमति दी है। इस दौरान आरोपित छात्र 27 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर उसके लिए विशेष प्रबंध करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, उत्तर-पूर्वी जिले के मुख्य 18 मार्च को होने वाली सामाजिक विषय की परीक्षा में का अधिकार है, इसलिए छात्र को मौजूद रहेंगे।

बढ़ेगी सुविधा

विकासपुरी से वजीराबाद के बीच दोनों तरफ हैं कई रिहायशी कॉलोनियां, फुट ओवरब्रिज बनने से सड़क दुर्घटनाओं में आएगी कमी

बाहरी रिंग रोड पर आठ में से पांच फुट ओवरब्रिज तैयार

स्टेशन की सुरक्षा पर रोडमैप पेश करे रेलवे : हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने भारतीय रेलवे को स्टेशनों पर सुरक्षा और सुरक्षा के उपायों को लेकर भविष्य का रोडमैप पेश करने का निर्देश दिया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने भारतीय रेलवे को 15 दिन में सुरक्षा के संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इसमें बताए कि भविष्य में रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को लेकर उनका रोडमैप क्या है।

हालांकि सुनवाई के दौरान रेलवे ने बताया कि स्टेशनों की सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए गए हैं। स्टेशनों की सुरक्षा के लिए बैगेज स्कैनर, हैंड मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिवक्ता कुश कालरा ने याचिका दायर कर देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर सामान के स्कैनर, मेटल डिटेक्टर और सीसीटीवी कैमरे जैसे सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश के अधिकांश स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों की कमी है। उन्होंने विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों की कमी को दूर करने व इसमें सुधार करने की मांग की है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि रेलवे ने सूचना के अधिकार के तहत दिए जवाब में स्वीकार किया है कि उसे अपने सभी स्टेशनों पर सुरक्षा और सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए भारी बजट प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके बावजूद रेलवे वांछित सुरक्षा और सुरक्षा तंत्र की स्थापना के माध्यम से रेलवे स्टेशनों को सुरक्षित बनाने की दिशा में विफल रहा है।

प्रति वर्ष करीब 50 लोग जान गंवा देते हैं। लोक निर्माण विभाग के इन फुट ओवर ब्रिज से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। सभी इनका इस्तेमाल करें इसके लिए इनमें लिफ्ट लगाई जा रही हैं।

पांच तैयार फुट ओवर ब्रिज में विकासपुरी, मुकरबा चौक, जहांगीरपुरी, गोपालपुर लाल बत्ती व आइआइटी धीरपुर शामिल हैं। एक फुट ओवर ब्रिज सरस्वती विहार का भी तैयार हो चुका है। शिव मार्केट के एफओबी का स्ट्रक्चर बन चुका है। अगले एक से डेढ़ माह में इसे शुरू कर दिया जाएगा। वहीं प्रशांत विहार के एफओबी का काम जल्द शुरू होगा। इसे बनाने के लिए बीच में आ रहे पेड़ काटने की विभाग को अनुमति मिल गई है। एक माह के अंदर इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। जिसे अगले चार से पांच माह में पूरा कर लिया जाएगा।

दुर्घटनाओं के लिए बदनाम बाहरी रिंग रोड पर आठ फुट ओवरब्रिज (एफओबी) पैदल चलने वालों को सड़क पार करने का सहारा बनेंगे। विकासपुरी से वजीराबाद के बीच पांच फुट ओवरब्रिज बनकर तैयार हो गए हैं। इनमें लिफ्ट लगाए जाने का काम अंतिम चरण में है। दो पर काम शुरू होने जा रहा है। मधुबन चौक के पास स्थित शिवा मार्केट और प्रशांत विहार स्थित पावर हाउस लाल बत्ती के पास बनने वाले फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य भी अगले कुछ माह में पूरा होने जा रहा है। जबकि एक पूरी तरह से तैयार हो चुका है।

बाहरी रिंग रोड पर विकासपुरी से वजीराबाद के बीच दोनों तरफ कई रिहायशी कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों के लोगों के लिए रोजाना इस हाई स्पीड कॉरिडोर को पार करना जोखिम भरा होता है। अक्सर यहां सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस हाईवे पर

फरीदाबाद में चारों वकीलों को छह साल की जेल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

साल 2006 में जिला अदालत परिसर में हुए गोलीकांड में दोषी करार दिए गए चारों वकीलों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश गर्ग की अदालत ने शुक्रवार को छह साल जेल की सजा सुनाई। चारों पर पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना भी किया है। दोषियों में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान ओपी शर्मा, एलएन पाराशर, गौरव शर्मा (ओपी शर्मा के पुत्र) और कैलाश वशिष्ठ शामिल हैं। अदालत ने 7 मार्च को चारों को जानलेवा हमले व जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार दिया था। यह मुकदमा 31 मार्च 2006 को वकील राकेश भडाना की शिकायत पर सेंट्रल थाने में दर्ज हुआ था। राकेश भडाना अदालत में प्रैक्टिस करने के अलावा इस वक्त नगर निगम पार्षद भी हैं।

दर्ज मुकदमे के अनुसार 31 मार्च 2006 को कैंटीन और पार्किंग को लेकर वकीलों के दो गुटों में झगड़ा हो गया था। एक गुट के वकीलों ने फायरिंग कर दी। वकील राकेश भडाना को जांघ में गोली लगी थी। उनकी शिकायत पर 25 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमले, आर्म्स एक्ट, साजिश रचने सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तभी से अदालत में विचाराधीन था। 25 आरोपितों में से एक की मृत्यु हो चुकी है। बाकी 20 आरोपितों को अदालत ने बरी कर दिया।

हाईकोर्ट जाने का है विकल्प : इस फैसले पर एडवोकेट पीएल गोयल ने कहा अब दोषी वकीलों के पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प है। वकील हाईकोर्ट में मामले की दोबारा सुनवाई के साथ ही जमानत की भी अपील कर सकते हैं।

2450 पद खाली हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में पिछले पांच वर्षों से। यह जानकारी परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित संसद की स्थायी समिति को संस्कृति मंत्रालय ने दी है।

गोयल ने की रेलवे में निजी निवेश की वकालत

अनुदान मांगों पर चर्चा ▶ कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो बढ़ाने पड़ेंगे कर और किराये

दलाली रैकेट के मद्देनजर निजी टिकट एजेंट खत्म करने के संकेत, बोले– स्वतंत्र रेल बजट झूठ का गुब्बारा था

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल बजट खत्म किए जाने को उचित ठहराते हुए रेलवे में निजी निवेश की जोरदार वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को अगले 12 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। हाल में उजागर दलाली रैकेट और गिरफ्तारियों के मद्देनजर रेलवे में निजी बुकिंग एजेंटों को खत्म किए जाने के संकेत देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि अब ज्यादातर लोग मोबाइल पर टिकट खरीद सकते हैं, लिहाजा निजी टिकट एजेंटों की जरूरत नहीं है।

लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि धन जुटाने की पूरी जिम्मेदारी अगर सरकार पर होगी तो उसका असर कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ेगा।

लोकसभा में बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल। उन्होंने सदन में रेल बजट खत्म करने के फैसले को सही ठहराया। प्रेट्र

लिहाजा सरकार को राजस्व बढ़ाने के लिए करों और किरायों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। उन्होंने निजी क्षेत्र के कौशल और उनकी संभावित कम मूल्य की सुविधाओं की वकालत करते हुए कहा कि इससे रेलवे को मजबूती मिलेगी और इसके विस्तार में मदद मिलेगी। गोयल के जवाब के साथ ही सदन ने ध्वनिमत से अनुदान मांगों को पास कर दिया।

इससे पहले चर्चा के दौरान कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामदलों के सदस्यों ने रेलवे के निजीकरण और रेलवे बोर्ड के काडर विलय का विरोध करते हुए रेल बजट बहाल करने की मांग की। जबकि शिवसेना ने छोटी खानपान इकाइयों पर संकट का मुद्दा उठाया। जवाब में गोयल ने कहा कि रेल बजट एक गुब्बारा था जिसमें चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता था। रेल बजट के खात्मे के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए गोयल ने कहा कि पिछली सरकारों ने रेल बजट का इस्तेमाल राजनीतिक हित साधने, झूठे वादे करने और जनता को गुमराह करने में किया था। उन्होंने कहा, 'पृथक रेल बजट से सिर्फ सदन में तालियां बजती थीं। उन्हीं रेल बजटों का नतीजा है कि कुछ रेल परियोजनाएं 1974 से अब तक पूरी नहीं हुई हैं। पृथक रेल बजट के तहत 2013-14 में मात्र 54,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था। जबकि रेल बजट समाप्त होने के बाद इस वर्ष आवंटन बढ़कर 1.61 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इस बढ़े आवंटन का उपयोग 58 अति महत्वपूर्ण और 68 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किया जा रहा है। तब सालाना 600-650 किमी विद्युतीकरण होता था, जबकि अब 5000-6000 किमी का हो रहा है।' गोयल ने रेलवे में पेंशन कोष की स्थापना पर ध्यान नहीं देने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की। जबकि किराये बढ़ाए बगैर राजस्व बढ़ाने के लिए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। गोयल ने आठ सेवाओं को एक सेवा इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में विलय करने के निर्णय को उचित ठहराया। उन्होंने दावा किया कि विलय के खिलाफ शिकायतों को समय के साथ दूर कर लिया जाएगा।

रेल मंत्री ने कहा कि पहले शिकायत दर्ज करने के लिए रेलवे में 60 हेल्पलाइन नंबर होते थे। अब सामान्य शिकायतों के लिए 139 और सुरक्षा संबंधी शिकायतों के लिए 182 नंबर पर्याप्त है। पूर्वोत्तर और जम्मू एवं कश्मीर की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। जबकि जम्मू-कश्मीर में बनिहाल-बारामूला लाइन दो-ढाई वर्ष में चालू हो जाएगी। करीब 99 फीसद ट्रेनों में बायो टायलेट लग गए हैं। साथ ही हाईस्पीड वंदे भारत ट्रेन के 44 नए रैक के टेंडर दिए जा चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रेलवे की खाली जमीन पर सोलर पैनल लगाकर 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य दिया है। रेल मंत्री ने बताया कि तीन वर्षों में 1.37 लाख लोगों की नियुक्तियां की गई है।

'सशस्त्र बलों को हथियारों के लिए और धन की जरूरत'

▶ राज्यसभा के पटल पर रखी गई स्थायी समिति की रिपोर्ट

नई दिल्ली, आइएएनएस : एक संसदीय स्थायी समिति ने कहा है कि सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियारों की खरीद के लिए और ज्यादा धनराशि की जरूरत है। लेकिन 2020-21 के बजट में मांग के मुकाबले 35 फीसद कम धनराशि आवंटित की गई है।

समिति की यह रिपोर्ट शुक्रवार को राज्यसभा के पटल पर रखी गई। समिति का कहना है कि धन की काफी कमी है और ऐसे हालात आधुनिक समय के युद्ध में हतोत्साहित करने वाले हैं। पूंजी की कमी से नए हथियारों, विमानों, युद्धपोतों और टैंकों की खरीद पर असर पड़ने के साथ ही भू, इमारत और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी पूंजीगत परियोजनाओं पर भी असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, समिति को लगता है और वह चाहती है कि सबसे अत्याधुनिक युद्धक प्रणालियां विकसित और खरीदी जाएं जो उत्तरी और पश्चिमी पड़ोसियों के मुताबिक हों। इसके लिए समुचित आवंटन बेहद जरूरी है। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब पाकिस्तान और चीन अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ा रहे हैं।

समिति ने कहा कि 2015-16 से सेना के किसी भी अंग को उसकी मांग के अनुसार धन आवंटन नहीं किया गया। समिति का मानना है कि आधुनिक युद्ध में अत्याधुनिक हथियारों का होना न सिर्फ युद्ध को अपने पक्ष में करने के लिए जरूरी है बल्कि ये विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करते हैं। समिति के मुताबिक, अगले वित्त वर्ष के लिए एक फरवरी को पेश किए गए बजट में कुल पूंजी आवंटन 1,13,734 करोड़ रुपये है। लेकिन सशस्त्र बलों ने 1,75,702.06 करोड़ की मांग की थी जो 61,968.06 करोड़ कम है। रक्षा बजट के आवंटन को मंजूरी देने से पहले रक्षा मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए और उन्हें पूंजीगत कार्यों की अहमियत बतानी चाहिए जो राजस्व और पूंजी के मद में 60:40 के अनुपात को बरकरार रखने के लिए किए जाते हैं।

प्रतीकात्मक फोटो

राणा कपूर और उसकी पत्नी के खिलाफ नया मामला दर्ज

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ भ्रष्टाचार का नया मामला दर्ज किया है। दोनों पर दिल्ली के एक प्रमुख इलाके में बंगला खरीदने के माध्यम से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। 1900 करोड़ रुपये का कर्ज मुहैया कराने के लिए एक रियल एस्टेट फर्म से बाजार मूल्य से आधी कीमत पर यह बंगला खरीदा गया था। सीबीआइ के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

यस बैंक मामला

- बंगला खरीदने के माध्यम से 307 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप
- बदले में बैंक से 1900 करोड़ का कर्ज मुहैया कराया गया

जांच एजेंसी को संदेह है कि अमृता शेरगिल मार्ग पर 1.2 एकड़ वाले बंगले के लिए कम कीमत पर हुआ सौदा ब्लिस एबॉड प्राइवेट लिमिटेड के मध्यम से कपूर को दी गई रिश्वत थी। यह रिश्वत यस बैंक से गौतम थापर के अवंता रियल्टी एंड ग्रुप कंपनीज को 1900 करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज के लिए दी गई थी। कपूर की पत्नी बिंदू ब्लिस एबॉड प्राइवेट लिमिटेड की दो निदेशकों में से एक है।

अधिकारी ने कहा कि सीबीआइ ने थापर, राणा कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ आपराधिक सांठगांठ के लिए आइपीसी के तहत और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत नया मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने कपूर और उनकी पत्नी के मुंबई में आवास और कार्यालय पर छापेमारी की और साथ ही ब्लिस एबॉड, अवंता रियल्टी और इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के दिल्ली एवं एनसीआर में स्थित कार्यालयों की भी तलाशी ली।

आरोप है कि राणा कपूर ने ब्लिस एबॉड के माध्यम से भुगतान कर 378 करोड़ रुपये में बंगला खरीदा। 685 करोड़ रुपये कर्ज के लिए इस संपत्ति को तुरंत ही इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास गिरवी रख दी गई। यह राशि बाजार मूल्य से 307 करोड़ रुपये कम थी। जांच एजेंसी का आरोप है कि संपत्ति आइसीआइसीआइ बैंक के साथ गिरवी थी जो अवंता रियल्टी को दिए गए 400 करोड़ रुपये के कर्ज के माध्यम से यस बैंक के पक्ष में रिलीज कर दी गई।

केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसद की बढ़ोतरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) में चार फीसद की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी एक जनवरी, 2020 से मान्य होगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी में यह फैसला किया गया। सरकार के इस फैसले से 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनभोगी को फायदा होगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17 फीसद महंगाई भत्ता मिलता है जो अब 21 फीसद हो जाएगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार पर 14,595 करोड़ रुपये का भार आएगा।

780 किलोमीटर का होगा ग्रीन एनएच कॉरिडोर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट कमेटी की बैठक में ग्रीन नेशनल हाईवे (एनएच) कॉरिडोर बनाने का भी फैसला किया गया। फैसले के मुताबिक ग्रीन एनएच की लागत 7662.46 करोड़ रुपये होगी। यह देश के चार राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को जोड़ेगा। इस एनएच को ग्रीन कॉरिडोर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसके निर्माण में गिट्टी-पत्थर का कम और सीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल होगा।

2017 से 2020 के बीच मनरेगा पर 1.83 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए

▶ कृषि मंत्री ने कहा, 2011-14 के दौरान 92,483 करोड़ हुए थे व्यय

नई दिल्ली, प्रेट्र : मनरेगा के तहत 2017-18 से 2019-20 के दौरान 2011-12 से 2913-14 के बीच की तुलना में करीब दुगना 1.83 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि सरकार ने 2017-18, 2018-19 और 2019-20 वित्त वर्षों के दौरान 1,83,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह राशि 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान खर्च हुए 92,483 करोड़ रुपये से दोगुनी है। उन्होंने कहा कि काम सौंपने में देरी या लाभार्थियों को भुगतान में देरी की दशा में मजदूरी भुगतान का प्रावधान है।

चार वर्षों में सीपीसीबी ने 700 उद्योगों का निरीक्षण किया : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पिछले चार वर्षों के दौरान 700 उद्योगों का निरीक्षण किया जिनमें 300 से ज्यादा को पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करता पाया। ये उद्योग प्रदूषण पैदा करते पाए गए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीपीसीबी ने अप्रैल 2016 और मार्च 2020 के बीच पर्यावरणीय मानकों के पालन की पुष्टि के लिए 700 उद्योगों का निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'सीपीसीबी ने रिपोर्ट दी है कि निरीक्षण किए गए 700 उद्योगों में 342 उद्योग नियमों का पालन नहीं करते पाए गए।' उन्होंने कहा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत 159 यूनिटों को कारण बताओ नोटिस-तकनीकी दिशानिर्देश और 181 यूनिटों को बंद करने का दिशानिर्देश जारी किया गया है।

पुरुषोत्तम रुपाला फाइल फोटो

एनसीएपी परिकल्पना शहर केंद्रित योजना

लोकसभा में एक अन्य सवाल के जवाब में जावडेकर ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनसीएपी) का लक्ष्य स्थानीय स्तर पर प्रदूषण की समस्या का समाधान सुनिश्चित करना है। शहरों से इस मुद्दे से निपटने के लिए योजना तैयार करने को कहा गया है। हर शहर में भिन्न प्रदूषण कारक हैं और स्रोत भी अलग-अलग हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में जल निकाय प्रदूषित हैं क्योंकि 70 फीसद सीवेज शोधन के बगैर जा रहे हैं।

वर्तमान पोषित योजना के तहत वन क्षेत्र की तारबंदी की अनुमति

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकर ने लोकसभा में शुक्रवार को एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि सरकार ने वन क्षेत्र के आसपास तारबंदी की अनुमति दी गई है। यह काम समीप के गावों में रहने वाले लोगों को वन्यजीवों के हमले से सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

कई देशों में डेस्कटॉप पर ट्विटर चलाने वालों को हुई परेशानी

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारत समेत कई देशों में शुक्रवार को ट्विटर यूजरों को डेस्कटॉप पर इस सोशल साइट के इस्तेमाल में परेशानियों का सामना करना पड़ा। वेबसाइट में आने वाली तकनीकी दिक्कतों की निगरानी करने वाली डाउनडिटेक्टर के अनुसार, डेस्कटॉप पर ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले 85 फीसद व एंड्रॉयड डिवाइस पर इस्तेमाल करने वाले आठ फीसद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस तकनीकी दिक्कत से जापान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, लेकिन भारत, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी लोगों को परेशानी हुई। भारत में सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और चेन्नई के ट्विटर यूजरों को हुई।

डेस्कटॉप पर ट्विटर का इस्तेमाल करने वालों को एक संदेश मिल रहा था, जिसमें कहा गया था, 'परेशान न हों।' हालांकि, इस संबंध में ट्विटर ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। बता दें कि फरवरी में भी भारतीय यूजरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बीच, ट्विटर ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अपने 5,000 कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कह दिया है।

आइआइएम और आइआइटी में छात्रों के फेल होने की संख्या में आई कमी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- ऐसे छात्रों की संख्या सिर्फ नाम मात्र की, फेल होने पर भी मिलेंगे बेहतर विकल्प
- 2015-16 में आइआइटी में 2.25 फीसद और आइआइएम में 1.04 फीसद बच्चे होते थे फेल

प्रतीकात्मक फोटो

आइआइटी, आइआइएम जैसे देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के फेल होने या पढ़ाई बीच में छोड़ने जैसे मामलों में भारी कमी आई है। पिछले पांच वर्षों में यह कमी पचास फीसद से ज्यादा की है। इसके पीछे सरकार की वह पहल सफल हुई है, जिसमें खराब शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने के लिए उठाए गए सुधारात्मक कदम शामिल हैं। ऐसे पहल में संस्थानों में छात्रों की देखरेख के लिए सलाहकार की नियुक्ति भी शामिल है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, इन संस्थानों में फेल होने वाले या पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा संख्या ऐसे छात्रों की होती है, जो पहले सेमेस्टर में होते हैं। इसके पीछे छात्रों के परिवेश को बड़ी वजह माना गया था। कड़ी प्रतिस्पर्द्धा वाली प्रवेश परीक्षा देकर आने के बाद भी वह पढ़ाई में पिछड़ जाते थे। भाषाई समस्या भी एक वजह थी। इसके चलते जहां इन छात्रों और परिजनों को जहां गहरी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता था। वहीं इससे देश के इन प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों की छवि भी बिगड़ रही थी। मंत्रालय के मुताबिक, इसे लेकर कई अहम कदम उठाए गए थे जिसका परिणाम दिखने लगा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2015-16 में जहां आइआइटी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 2.25 फीसद थी, वहीं 2019-20 में 0.68 फीसद है। इसी तरह आइआइएम में 2015-16 में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 1.04 फीसद थी, जो 2019-20 में सिर्फ 0.78 फीसद है। इसी तरह देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में भी फेल होने वाले या पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या 2015-16 में जहां औसत 7.49 फीसद थी, वहीं 2019-20 में यह सिर्फ 2.82 फीसद है। इसके साथ ही मंत्रालय ने आइआइटी में फेल होने वाले छात्रों को बेहतर विकल्प भी देना शुरू कर दिया है। इसके तहत उन्हें बीएससी (बैचलर आफ साइंस) जैसे कोर्सों में दाखिला दिया जा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, इन छात्रों को संस्थान सम्मानजनक ढंग से विदा करना चाहते हैं ताकि वह संस्थान से निकलकर भी अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकें।

ओवैसी, वारिस पठान और कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआइआर दर्ज

हैदराबाद, एएनआइ : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआइएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान और कपिल मिश्रा के खिलाफ विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्यता पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है। मुगलपुरा पुलिस के मुताबिक, इंकलाब-ए-मिल्लत के सदस्य बालकृष्ण राव नामधारी ने शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में आरोप लगाया है कि एमआइएम नेता वारिस पठान ने कर्नाटक के कलबुर्गी में सीएए विरोधी सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। उस समय पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी वहां मौजूद थे। भड़काऊ भाषण से सांप्रदायिक टकराव पैदा हो सकता था और दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क सकती थी। पुलिस ने कहा है कि नामधारी ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में सीएए के समर्थन में भीड़ जुटने के बाद सीएए-समर्थक और विरोधी गुटों के बीच हिंसा शुरू हो गई। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने आइपीसी की धारा 153, 153-ए, 117, 295-ए और 120 बी के तहत शिकायत दर्ज कर ली है।

स्कूलों और केयर होम्स के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने बच्चों के यौन शोषण के मामलों में सजा को और कड़ा करने वाले नए पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज रूल्स, 2020) नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इनके तहत स्कूलों और केयर होम्स के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

नए पॉक्सो नियम नौ मार्च से प्रभावी हो गए हैं। नए पॉक्सो संशोधन कानून में कुछ नए नियम शामिल किए गए हैं। पोर्नोग्राफी या यौन उत्पीड़न संबंधी सामग्री की शिकायत करने की प्रक्रिया, बाल अधिकारों की शिक्षा और अन्य प्रावधानों को सख्त किया गया है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नए नियम के तहत जिस किसी को भी किसी बच्चे से जुड़ी पोर्न सामग्री मिलती है या ऐसी किसी सामग्री के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे स्टोर किया गया है, तैयार किया गया है या फिर

- केंद्र सरकार ने नए पॉक्सो अधिनियम की अधिसूचना जारी की
- बच्चों के यौन शोषण मामलों में सजा और कड़ी करने के हैं प्रावधान

बांटा, दिखाया या प्रसारित-प्रचारित किया जा रहा है, उसकी जानकारी तत्काल विशेष जुवेनाइल पुलिस यूनिट (एसजेपीयू) या पुलिस या साइबर क्राइम पोर्टल को दी जाए।

नए नियमों के तहत राज्य सरकारों को कहा गया है कि वह बच्चों की रक्षा की नीति 'जीरो टॉलरेंस' के आधार पर बनाएं ताकि बच्चों को हिंसा का शिकार होने से बचाया जा सके। यह व्यवस्था सभी संगठनों और संस्थानों को लागू करनी होगी। इतना ही नहीं, जो भी संस्था बच्चों के लिए काम करती है, या बच्चों के संपर्क में आती है, उन सब पर पॉक्सो के नए नियम लागू होंगे।

नए नियमों के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को समय-समय पर कार्यशालाएं और ओरियंटेशन प्रोग्राम चलाने होंगे जिससे नियमित रूप से या कभी-कभार बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी लोग बच्चों की सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशीलता दिखाएं। ऐसे लोगों को इस एक्ट के तहत उनकी जिम्मेदारियों के प्रति शिक्षित किया जाएगा।

1098 पर चाइल्डलाइन हेल्पलाइन सेवा : केंद्र और राज्य सरकारों को कहा गया है कि वह आयु आधारित शैक्षणिक सामग्री और पाठ्यक्रम बच्चों के लिए तैयार करें जिसमें उनकी निजी सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को उन्हें समझाया जाए। साथ ही उन्हें यह सिखाया जाए कि वह अपनी शारीरिक पहचान और ऑनलाइन पहचान को कैसे सुरक्षित रखें। साथ ही उन्हें यौन अपराधों से बचाने के साथ ही उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाए। इसके लिए टोल फ्री चाइल्डलाइन हेल्पलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। यह नंबर 1098 है। इस पर शिकायत करने पर तत्काल कार्रवाई होगी।

पहल

अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने कहा, 30 वर्ष से ऊपर के ये सभी स्वयंसेवक हैं व्यवसायी, 15 से 17 मार्च तक चलने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक में सीएए पर हो सकती है चर्चा

समाज में परिवर्तन के लिए संघ के 15 लाख स्वयंसेवक करेंगे कार्य

जागरण संवाददाता, रांची

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 15 लाख स्वयंसेवक पूरे देश में समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए कार्य करेंगे। ये सभी 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यवसायी स्वयंसेवक हैं। पूरे देश में इन सभी स्वयंसेवकों के साथ बैठक कर संघ ने यह निर्णय लिया है। वे क्या कार्य करेंगे, इसकी चर्चा 15 मार्च से प्रस्तावित आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक में होगी। बैठक में सीएए सहित अन्य समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने यह जानकारी दी। वह शुक्रवार को बेंगलुरु के चेन्नहल्ली स्थित जनसेवा विद्या केंद्र में प्रतिनिधि सभा से संबंधित विषयों को लेकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।

अरुण कुमार ने कहा कि आरएसएस ने स्वयंसेवकों का सर्वेक्षण (समय की उपलब्धता व रुचि-क्षमता आदि) किया था। इसमें 15 लाख स्वयंसेवकों से चर्चा हुई थी। संघ इन स्वयंसेवकों को समाज की आवश्यकता के अनुसार कार्य में लगाएगा। 17 मार्च तक चलने वाली प्रतिनिधि सभा की बैठक में पूरे देश से 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। रविवार को बैठक का उद्घाटन सरसंघचालक मोहन भागवत एवं सरकार्यवाह भय्याजी जोशी करेंगे। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 35 अनुषांगिक संगठनों से प्रतिनिधि भाग लेंगे। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर व दक्षिण मध्य क्षेत्र कार्यवाह तिप्पेस्वामी भी उपस्थित थे।

बेंगलुरु में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक के बारे में प्रेसवार्ता में जानकारी देते संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार (बीच में)। साथ हैं सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार (दाएं) व दक्षिण मध्य क्षेत्र के कार्यवाह तिप्पेस्वामी (बाएं)। सौजन्य : आरएसएस प्रचार विभाग

आज अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक : प्रचार प्रमुख ने कहा कि शनिवार को अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होगी, जिसमें प्रतिनिधि सभा की बैठक का एजेंडा (चर्चा के विषय, प्रस्तावित प्रस्ताव) तय होगा। कार्यकारी मंडल में प्रांत व क्षेत्र स्तर के संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक एवं अखिल भारतीय कार्यकारिणी के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे।

प्रतिनिधि सभा की बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों की हो रही जांच : कोरोना वायरस को लेकर आरएसएस भी चिंतित हैं। बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचने वाले सभी प्रतिनिधियों की कार्यक्रम स्थल पर कोरोना वायरस से संबंधित जांच की जा रही है। साथ ही वहां व्यवस्था में लगे लोग, सुरक्षाकर्मी एवं मीडिया से जुड़े लोगों को भी जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जांच करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा एहतियातन किया जा रहा है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

329 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है मप्र में भाजपा से राज्यसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। सिंधिया ने शुक्रवार को राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में दाखिल नामांकन के साथ लगाए गए शपथ पत्र में इस संपत्ति का उल्लेख किया है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 मार्च 2020

राजभवन की चौखट पर मप्र का सियासी संग्राम

भाजपा का तर्क ▶ सरकार अल्पमत में इसलिए अभिभाषण के पहले बहुमत साबित हो

कमलनाथ बोले-फ्लोर टेस्ट को तैयार, लेकिन पहले अभिभाषण हो

नईदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जारी सियासी संग्राम अब राजभवन की चौखट पर पहुंच गया है। सभी की निगाहें राजभवन से लिए जाने वाले निर्णयों पर टिक गई है। सियासी उठापटक, सरकार के बहुमत पर संशय और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर शुक्रवार दिन भर सवाल उठते रहे। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजभवन पहुंचकर अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट की बात रखी, जबकि भाजपा का तर्क है कि अल्पमत की सरकार के बजट का क्या औचित्य? पहले बहुमत साबित हो।

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल लालजी टंडन को तीन पेज की चिट्ठी सौंपी और कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री से आग्रह कर बेंगलुरु में बंधक बनाए गए कांग्रेस के 19 विधायकों को मुक्त कराएं। राजभवन से बाहर निकलकर कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा में दावा किया कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। वह विधानसभा में बहुमत साबित कर देंगे। कुछ देर बाद ही भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने राजभवन पहुंचकर सरकार के बहुमत पर सवाल उठाए। तर्क था कि राज्यपाल अल्पमत की सरकार का अभिभाषण क्यों पढ़ें? ऐसी सरकार के बजट का क्या औचित्य? इसलिए सरकार को पहले बहुमत साबित करने को कहा जाएगा।

उधर, संसदीय कार्यमंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों को फर्जी बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को पत्र सौंपकर मामले की गहन छानबीन की मांग की है।

अभिभाषण पर सबकी नजरें: विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च को आहूत किया गया है। उसी दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है। अब गेंद राजभवन के पाले में है। बताया जाता है कि सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद राज्यपाल विधिवेत्ताओं से परामर्श में जुट गए हैं।

मध्यप्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को राज्यपाल लालजी टंडन से भोपाल में मुलाकात की। एएनआइ

हमारे 22 विधायकों ने समर्थन वापस लिया : सिंधिया

राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचे सिंधिया ने भी उन्हें मौखिक रूप से कहा है कि उनके समर्थन में कांग्रेस के 22 विधायकों ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है इसलिए सरकार अल्पमत में आ चुकी है।

बेंगलुरु से लौटे मंत्री बोले- बंधक हैं विधायक

सिंधिया समर्थक 19 विधायकों से बात करने के लिए बेंगलुरु गए कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी और लाखन सिंह यादव शुक्रवार को लौट आए। दोनों ने कहा कि विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है।

संभवतः रविवार शाम तक राजभवन की ओर से अभिभाषण और फ्लोर टेस्ट को लेकर फैसला सामने आ जाएगा। भाजपा की ओर से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा सहित अन्य सभी नेता सरकार को अल्पमत में बताकर कमलनाथ के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं।

सिंधिया समर्थक छह मंत्री बर्खास्त: राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सिफारिश पर मंत्रिमंडल के छह सदस्यों को बर्खास्त कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक इन सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा दूसरे मंत्रियों के बीच कर दिया गया है। बर्खास्त मंत्री इमरती देवी, तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉ. प्रभुराम चौधरी हैं। उधर, सिंधिया समर्थक छह कांग्रेस विधायक शुक्रवार को विधानसभा नहीं पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के सामने इन्हें इस्तीफे की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने के नोटिस जारी किए थे।

दिनभर बनी रही गहमागहमी : वहीं, बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते से मौजूद सिंधिया समर्थक 19 विधायकों के भोपाल पहुंचने को लेकर दिन भर गहमागहमी बनी रही। बड़ी संख्या में दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता भी विमानतल पहुंच गए। शाम पांच बजे उनके भोपाल आने का कार्यक्रम रद हो गया। वजह बताई गई कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा वहां पहुंच गए इसलिए विधायक नहीं आए, लेकिन सूत्रों के अनुसार सुरक्षा कारणों के चलते विधायकों का भोपाल आना टाल दिया गया। इन विधायकों ने राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर कहा है कि राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमें सीआरपीएफ की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

इस्तीफे की मंजूरी के लिए हाई कोर्ट गए सोलंकी

नईदुनिया, इंदौर

- कोर्ट ने कहा, तत्काल निर्णय ले राज्य सरकार
- भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया नामांकन

कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया, लेकिन पार्टी के दूसरे प्रत्याशी प्रो. डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी पर संशय बना हुआ है। सरकार ने उनके इस्तीफे पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। इसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि उनके इस्तीफे पर तत्काल निर्णय ले।

सोलंकी ने अपनी याचिका में राज्य सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने 12 मार्च को सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। संबंधित अधिकारी ने इसे शासन को भेज दिया था, लेकिन वहां से कोई निर्णय नहीं हो रहा। वह राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन जमा कर चुके हैं। 16 मार्च को नामांकन पत्र की जांच होनी है। इसके पहले इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ जाएगी। मालूम हो कि सोलंकी बड़वानी स्थित शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रोफेसर थे। रास उम्मीदवार घोषित होने के तुरंत बाद 12 मार्च को उन्होंने कॉलेज के प्राचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। प्राचार्य ने उसी दिन इस्तीफा शासन को भेज दिया, लेकिन राज्य शासन कोई निर्णय नहीं लिया है। शुक्रवार को जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की बेंच ने शासन को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया कि शासन प्रो. सोलंकी के इस्तीफे पर 13 मार्च को ही निर्णय ले और कोर्ट को 16 मार्च को इससे अवगत करवाए।

सोलंकी का नामांकन रद हुआ तो रंजना बघेल हो जाएंगी प्रत्याशी: राज्यसभा चुनाव में भाजपा ने दूसरी सीट के लिए दो प्रत्याशियों से नामांकन पत्र दाखिल कराया है। पर्चा भरने की आखिरी तारीख 13 मार्च से ठीक एक दिन पहले भाजपा ने डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी को प्रत्याशी तो बनाया लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार न होने के कारण पूर्व मंत्री रंजना बघेल से भी नामांकन जमा करवाया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली रंजना बघेल भी राज्यसभा की टिकट की प्रबल दावेदार रही हैं।

उप्र में संगठन की राय की अनदेखी कर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारती रही है कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की भूल को आगे बढ़ा रही हैं प्रियंका
- पांच विधायक और एक सांसद तक सिमटी, 10 सीएम देने वाली कांग्रेस

मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत से कांग्रेस सरकार का संकट में आना वहां के लिए अप्रत्याशित घटना हो सकती है। मगर, उत्तर प्रदेश में तीन दशक से कांग्रेस आत्मघाती फैसलों की शिकार रही है। स्थानीय संगठन की राय और विचारधारा की अनदेखी कर कांग्रेस अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारती चली आई है। आज स्थिति यह है कि उसके दोबारा सूबे में उठ खड़े होने पर बड़ा सवाल है।

कांग्रेस ने प्रदेश में भी सबसे अधिक 35 वर्ष तक शासन किया है। जीबी पंत से सिलसिला शुरू हुआ और एनडी तिवारी 10वें और आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद गलतियों का जो क्रम आरंभ हुआ, वह आज तक जारी है। पार्टी के उजियारे और अंधेरे दिनों के हमसाया रहे बुजुर्ग नेता चुटकियों में खामियां गिनाते हैं। पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी दो फैसलों को ऐतिहासिक भूल मानते हैं।

वह कहते हैं कि 1990 में दिल्ली में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार गिरी। जनता दल टूटा और तब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार पर संकट आया। कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया कि मुलायम सिंह को समर्थन नहीं दिया जाएगा। मगर, राजीव गांधी ने प्रदेश संगठन की अनदेखी कर मुलायम का साथ दिया। उसी का परिणाम था कि 1991 के चुनाव में वोट फीसद सिमट गया और विधायक भी 48 रह गए।

प्रतीकात्मक

त्रिपाठी कहते हैं कि दूसरी गलती बसपा के उद्भव के समय की। दलित कांग्रेस का वोटर था। बसपा भी उसी वोट के भरोसे मैदान में आई। यह जानते हुए 1996 में तत्कालीन प्रदेश प्रभारी गुलाम नबी आजाद के कहने पर बसपा से गठबंधन कर लिया। बसपा 300 सीट पर लड़ी, जबकि कांग्रेस मात्र 125 सीटों पर। तब कांग्रेस के सिर्फ 33 विधायक जीते। इन गलतियों से कांग्रेस का समर्थक सवर्ण वोटर भाजपा में, जबकि दलित बसपा और मुस्लिम सपा में खिसक कर चला गया।

सटीक समीकरण को किया नजरअंदाज: पूर्व विधायक भूधर नारायण मिश्र कहते हैं कि गलतियों से सबक लेने का प्रयास नहीं किया। 1998 के लोकसभा चुनाव में बेहद निराशाजनक परिणाम के बाद 2009 में थोड़ा अच्छा वक्त आया। सवर्ण को उपेक्षा दूर होती दिखी। उसका असर हुआ कि कांग्रेस के 22 सांसद जीते और वोट फीसद भी बढ़ा। मगर, उस फार्मूले को आगे नहीं बढ़ाया। 2014 में गुलाम नबी ने पार्टी पर प्रो-मुस्लिम का टैग लगवाया, जो मोदी की आंधी में खास नुकसानदेह रहा। इसी तरह 2017 में जब खाट सभाओं से माहौल बन रहा था तो सपा से गठबंधन कर लिया।

अपने धक्के देकर निकाले, गैर गले लगाए: इतनी बदहाली के बावजूद कांग्रेस उसी दिशा में कदम बढ़ा रही है। सिर्फ अपनी बात कहने पर 30-40 वर्ष पुराने कांग्रेस के 10 पूर्व सांसद और पूर्व विधायक पार्टी से निकाल दिए। वहीं, वामपंथी विचारधारा रखने वाले रिहाई मंच और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं को अहम पद दिए जा रहे हैं। इन्हीं में से संदीप सिंह को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निजी सचिव बना रखा है। पार्टी के तमाम फैसलों में उनका दखल रहता है।

मध्य प्रदेश के भाजपा विधायकों से मिले अनिल जैन व राकेश

जासं, तावडू (नूंह) : गुरुग्राम-नूंह सीमा पर स्थित होटल आइटीसी ग्रैंड भारत में ठहरे मध्य प्रदेश के भाजपा विधायकों से शुक्रवार को भी पार्टी महासचिव डॉ. अनिल जैन ने मुलाकात की। उनके साथ सांसद राकेश सिंह भी रहे। दोनों नेताओं ने तीन दिन से ठहरे विधायकों को मौजूदा राजनीतिक हालात की जानकारी दी। दिल्ली लौटने के दौरान सांसद राकेश सिंह ने कहा कि सियासी मौसम पार्टी के अनुकूल है। मंगलवार देर रात यहां आए 106 विधायकों से भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल व पार्टी महासचिव अनिल जैन मुलाकात कर चुके हैं। अनिल जैन शुक्रवार को दोबारा आए थे। संभावना जताई जा रही है कि फ्लोर टेस्ट होने तक विधायक होटल में ही रहेंगे। इधर, होटल में विधायकों के पहुंचने के साथ ही देशभर की मीडिया का होटल के बाहर जमावड़ा लगा है। विधायकों से लेकर होटल में मौजूद भाजपा के तमाम बड़े नेताओं व यहां तक की होटल प्रबंधन भी कुछ भी बताने से बच रहा है।

विधायक बोले-सिंधिया को उम्मीद से कम विधायकों का समर्थन मिलेगा

जागरण संवाददाता, जयपुर

मध्य प्रदेश की सियासत का केंद्र बने जयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस के रणनीतिकारों ने फ्लोर टेस्ट की रणनीति पर मंथन किया। पिछले दो दिन से जयपुर में ठहरे मध्य प्रदेश के विधायकों से कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, महासचिव मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लंबी बातचीत की। इन नेताओं ने विधायकों से फ्लोर टेस्ट तक एकजुट रहने और बेंगलुरु में ठहरे अपने साथी विधायकों से संपर्क कर कांग्रेस सरकार के पक्ष में बने रहने को लेकर तैयार करने की भी बात कही। विधायकों से कहा गया कि यदि संभव हो तो वे भाजपा के विधायकों से भी संपर्क साधें।

वासनिक और रावत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद मध्य प्रदेश में पार्टी पर होने पर असर को लेकर बातचीत की तो कई विधायकों ने कहा कि उनके भाजपा में जाने से कम नुकसान होगा, लेकिन यदि वे नई पार्टी बनाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। कांग्रेस के कई विधायक ऐसे हैं जो सिंधिया के साथ तो हैं, लेकिन भाजपा में नहीं जाना चाहते। नई पार्टी बनाने पर ये विधायक सिंधिया के साथ हो सकते थे। इन विधायकों ने कहा कि सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी नई पार्टी बनाने पर सिंधिया के साथ हो सकते थे, लेकिन अब इनकी संख्या कम रहेगी। विधायकों से बातचीत के बाद गहलोत ने कहा कि यदि बेंगलुरु गए विधायकों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो अधिकांश कमलनाथ सरकार के समर्थन में आ जाएंगे। उधर राजनीतिक पर्यटन के तीसरे दिन विधायक खाटूश्याम मंदिर और सालासर हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। तीन बसों में पहुंचे इन विधायकों ने दोनों मंदिरों में पूजा-अर्चना कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बरकरार रखने को लेकर मन्नत मांगी। इससे पहले सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान वरिष्ठ नेताओं ने इन्हें कांग्रेस के त्याग, बलिदान, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, स्व. इंदिरा गांधी और स्व. राजीव गांधी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कुछ विधायकों से अलग-अलग बात की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कई विधायकों से मोबाइल पर बात भी की ।

ईश्वर ज्योतिरादित्य को सद्बुद्धि दें : बाला बच्चन

सालासर हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद मध्य प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि ईश्वर ज्योतिरादित्य सिंधिया को सद्बुद्धि दें। उनहोंने कहा कि फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस सफल होगी। विपक्ष को इस बात का भय है कि कहीं कमलनाथ पूरे प्रदेश को छिंदवाड़ा जैसा मॉडल क्षेत्र न बना दें। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि मध्य प्रदेश के विधायक अभी तीन दिन और जयपुर में रहेंगे। उसके बाद इन्हें भोपाल या किसी अन्य शहर में ले जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली रोड स्थित ब्यूना बिस्टा रिसोर्ट और ट्री हाउस रिसोर्ट में ठहरे विधायकों ने यहां टीवी पर समाचार देखने के साथ ही क्रिकेट और टेनिस भी खेला। लगातार दो दिन से राजस्थानी भोजन के साथ कल्चरल कार्यक्रम का भी आनंद लिया। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक अमिन कागजी सहित एक दर्जन नेता मध्य प्रदेश के विधायकों के साथ जुटे हुए हैं।

मोदी से आज मिलेंगे जेके अपनी पार्टी के नेता

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: जेके अपनी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सईद अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य बनाने की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए ज्ञापन भी सौंपेगा।

जेके अपनी पार्टी का गठन गत रविवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से निष्कासित पूर्व वित्त मंत्री सईद अल्ताफ बुखारी ने किया है। जेके अपनी पार्टी में पीडीपी के लगभग दो दर्जन बागी नेता शामिल हैं। इनमें एक दर्जन पूर्व विधायक व एमएलसी हैं। कांग्रेस के भी छह वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायकों के अलावा नेशनल कांफ्रेंस के एक विधायक और एक एमएलसी भी अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी को अपना चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के चेयरमैन गुलाम हसन मीर भी अपने संगठन संग अपनी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं।

जयपुर शिफ्ट होंगे गुजरात के कांग्रेस विधायक

शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद

- कांग्रेस को विधायकों के टूट का डर, भाजपा ने पूर्व डिप्टी सीएम अमीन को बनाया प्रत्याशी

भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात योजना आयोग के उपाध्यक्ष व पूर्व उपमुख्यमंत्री नरहरी अमीन को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना तीसरा उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने के लिए 17 मार्च को जयपुर शिफ्ट करेगी। राकांपा व बीटीपी विधायकों का समर्थन भाजपा को मिल सकता है।

गुजरात से राज्यसभा की चार सीट के लिए प्रत्याशियों ने शुक्रवार दोपहर अपना पर्चा भरा। इससे पहले भाजपा ने वडोदरा के अधिवक्ता व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अभय भारद्वाज व पूर्व विधायक व पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रमीला बारा के नाम की घोषणा के बाद वरिष्ठ नेता नरहरी अमीन को मैदान में लाकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। भाजपा के पास 103 विधायक हैं जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 73 है। दो उम्मीदवारों को मत

नरहरी अमीन। फाइल

देने के बाद भाजपा के पास अपने तीसरे प्रत्याशी के लिए अतिरिक्त 29 मत होंगे, उन्हें जिताने के लिए भाजपा को 7 से 8 मत की दरकार होगी। राकांपा के एक व भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) के दो विधायकों का समर्थन भाजपा को मिल सकता है। भाजपा अध्यक्ष जीतूभाई का मानना है कि भाजपा के पास पर्याप्त मत हैं, सीएम विजय रूपाणी व उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी तीनों उम्मीदवारों के जीत का भरोसा जताया साथ ही कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी के चलते उनके विधायकों का समर्थन भी उनके प्रत्याशी को मिल सकता है।

कांग्रेस विधायकों को टूट से बचाने के लिए 17 मार्च को जयपुर लेकर जाएगी, अगस्त 2017 में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस अपने विधायकों को बेंगलुरु लेकर गई थी। उधर कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी तथा बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्तिसिंह गोहिल को अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन भाजपा की ओर से अमीन को मैदान में लाने से कांग्रेस में सेंध लगने की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अमीन 2012 तक कांग्रेस में थे और विधानसभा का टिकट नहीं मिलने के चलते भाजपा में शामिल हुए थे। कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावडा का दावा है कि कांग्रेस के पास दो सीट के लिए पर्याप्त मत हैं और कांग्रेस का एक भी विधायक इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आएगा।

बिहार में विस की सीटों पर कांग्रेस बढ़ाएगी दावेदारी

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार में भले ही राजद ने वादा करके भी कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट नहीं दी लेकिन, कांग्रेस इससे हतोत्साहित नहीं है। कांग्रेस की नजर उन एक सौ एक सीटों पर है जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इतना ही नहीं विधान परिषद में भी एक अतिरिक्त सीट के लिए भी वह राजद पर दबाव बनाने की तैयारी में है। सूत्रों की मानें तो हाल ही में बिहार के दोनों प्रभारी अजय कपूर और बीरेंद्र सिंह राठौर के बिहार दौरे के क्रम में पार्टी की बैठक में आगामी चुनाव में विधानसभा सीटों के बंटवारे और उनकी पहचान का मसला उठा। पार्टी के नेता मानते हैं कि पिछले चुनाव में राजद-जदयू के बाद कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी। ऐसे में उसे कम सीटों पर संतोष करना पड़ा था। परंतु बदले राजनीतिक हालात में अब कांग्रेस महागठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में उसकी अधिक सीटों पर स्वाभाविक दावेदारी बनती है।

फारूक अब्दुल्ला की रिहाई ने चौंकाया, चुप्पी पर सब हैरान

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- हर किसी को उम्मीद थी कि रिहा होने के बाद वह जरूर गरजेंगे
- पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेकां सांसद के सियासी कदम पर सबकी नजर

नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री व श्रीनगर के वर्तमान सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला से पीएसए हटाकर उनको अचानक रिहा करना हर किसी को चौंका रहा है। वहीं, रिहाई के बाद फारूक की चुप्पी ने भी सभी को हैरान कर दिया है। सभी को उम्मीद थी कि वह रिहा होने के बाद जरूर गरजेंगे। ऐसे में उनके सियासी कदम पर सियासी दलों समेत राजनीतिक विशेषज्ञों की पैनी नजर है। फारूक ऐसे नेता हैं जो कभी भी कोई भी बयान दे सकते हैं। फारूक को पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की घोषणा के मद्देनजर एहतियातन हिरासत में लिया गया था। इसके बाद सितंबर 2019 में उन पर पीएसए लगाया गया था।

कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ रशीद राही ने कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला की रिहाई अचानक हुई है। किसी ने नहीं सोचा था कि उन्हें रिहा किया जाएगा। इससे भी ज्यादा हैरानी अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और ऑटोनामी जैसे मुद्दों पर उनकी तथाकथित चुप्पी से हुई है। सभी यहां उम्मीद कर रहे थे कि वह आज गरजेंगे। ऑटोनामी, अनुच्छेद-370 जैसे मुद्दों को हवा देते हुए उन पर सियासत शुरू करने का एलान करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि पहले वह हालात का जायजा लेंगे और उसके बाद ही अपने अगले कदम का एलान करेंगे।

कश्मीर मामलों के एक अन्य विशेषज्ञ अहमद अली फैयाज ने कहा कि डॉ. फारूक अब्दुल्ला एक मंझे हुए सियासतदान हैं। वह कश्मीर और कश्मीरी भावनाओं को ही नहीं, बल्कि दिल्ली को भी अच्छी तरह समझते हैं। उनकी रिहाई को आप जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य बनाने व राजनीतिक गतिविधियों को बहाल करने की केंद्र सरकार की कोशिशों का हिस्सा बता सकते हैं। फारूक पहले अपने लोगों और नेकां के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ही वह तय करेंगे कि ऑटोनामी जैसे सियासी एजेंडे को आगे लेकर चलना है या इससे बचना है।

फैयाज कहते हैं कि जहां तक मैं समझता हूं कि वह 370, आटोनामी जैसे मुद्दों को उठाएंगे जरूर, लेकिन उन पर जोर नहीं देंगे। वह कोशिश करेंगे कि उन्हीं मुद्दों को उठाया जाए जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इनमें जम्मू-कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और डोमिसाइल जैसे मुद्दे होंगे। इसके अलावा वह जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम बहुल इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

कश्मीर की उपेक्षा का उठा सकते हैं मुद्दा

फैयाज का मानना है कि फारूक अब्दुल्ला उपराज्यपाल के सलाहकारों में कश्मीर की उपेक्षा, जम्मू-कश्मीर के बैंक के निदेशक मंडल में कश्मीर के प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी जैसे मुद्दों को उछालेंगे और अपना खोया जनाधार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल, हमें अगले कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। वैसे भी फारूक किसी भी समय कोई भी बयान दे सकते हैं, कोई भी सियासी कदम उठा सकते हैं। वह कोशिश करेंगे कि अलगाववाद और आतंकवाद को शह देने वाले किसी मुद्दे को न छेड़ा जाए।

नहीं मिला मौका

ममता बनर्जी ने आखिरी क्षणों में पूर्व लोस अध्यक्ष को प्रत्याशी बनाने का दिया प्रस्ताव, तब तक माकपा को वादा कर बैठी थी कांग्रेस, चाहकर भी दीदी का प्रस्ताव कुबूल नहीं कर पाई कांग्रेस

हाथ आकर भी मीरा कुमार से दूर रह गई उम्मीदवारी

संजय मिश्र, नई दिल्ली

राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रहे सियासी ड्रामे, सस्पेंस और रोमांच के दौर में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके हाथ सीट आते-आते दूर रह गई। इनमें सबसे प्रमुख चेहरा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का है जिन्हें राज्यसभा में भेजने के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को अंतिम क्षणों में प्रस्ताव दिया, मगर कांग्रेस तब तक माकपा उम्मीदवार के समर्थन का वादा कर बैठी। कांग्रेस ऐसे में चाहते हुए भी मीरा कुमार को राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बना पाई। पार्टी सूत्रों ने ममता की ओर से दिए गए इस प्रस्ताव की पुष्टि की। गुरुवार की रात दीदी ने कांग्रेस के रणनीतिकार अहमद पटेल को फोन किया और कहा कि कांग्रेस मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाती है तो तृणमूल कांग्रेस पांचवीं सीट के लिए उनका समर्थन करेगी। राज्यसभा की एक सीट अपने खाते में आने के इस आकर्षक प्रस्ताव ने कांग्रेस को लुभाया, मगर माकपा उम्मीदवार के नामांकन के पक्ष में तब तक कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव जारी हो चुका था।

मीरा कुमार। फाइल

सूत्र ने कहा कि यह प्रस्ताव दो-तीन दिन पहले आया होता तो मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। दरअसल दीदी ने माकपा उम्मीदवार बिकास रंजन भट्टाचार्य का राज्यसभा का रास्ता रोकने के लिए मीरा के समर्थन का दांव चला। कोलकाता के पूर्व मेयर बिकास ममता के मुखर विरोधियों में गिने जाते हैं।

प्रस्ताव पहले आता तो मीरा के नाम पर कांग्रेस को माकपा को दावेदारी छोड़ने के लिए मनाने का मौका मिल जाता। मीरा को उम्मीदवार बनवा दीदी जहां एक ओर बिकास की राह रोकना चाहती थीं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और माकपा के गठबंधन में दरार भी पैदा करना चाहती थीं।

वैसे दिलचस्प बात यह है कि ममता ने मीरा कुमार को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव कांग्रेस को दूसरी बार दिया। इससे पहले जुलाई 2017 में राज्यसभा के चुनाव के दौरान भी दीदी ने कांग्रेस को मीरा कुमार को उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन तब कांग्रेस ने पेशकश इसलिए स्वीकार नहीं की थी कि उसके स्थानीय नेता की उम्मीदवारी का माकपा समर्थन कर रही थी।

राज्यसभा चुनाव के सस्पेंस-रोमांच में कांग्रेस की एक अन्य प्रमुख महिला नेता कुमारी सैलजा के लिए भी सियासी क्लाइमेक्स निराशाजनक रहा। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष सैलजा दस जनपथ की पहली पसंद थीं और उनका नाम लगभग तय था। मगर सूबे की सियासत में मजबूत पकड़ रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाजी पलटते हुए अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बनवा लिया। कांग्रेस नेतृत्व को हुड्डा और उनके समर्थक नेता यह समझाने में कामयाब रहे कि भाजपा दूसरा उम्मीदवार देगी तो हरियाणा में भी मध्य प्रदेश की तरह विधायक टूट सकते हैं। खतरे की आशंका के चलते हाईकमान ने अंततः टिकट की जगह सैलजा से सहानुभूति जताई और दीपेंद्र को उम्मीदवार बना दिया। दिलचस्प यह भी रहा कि हरियाणा में भाजपा ने दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारा है और दीपेंद्र की जीत तय है। वहीं मध्य प्रदेश की तरह गुजरात में कांग्रेस से दूसरी सीट छीनने के लिए भाजपा ने नरहरि अमीन को उम्मीदवार बना चुनौती बढ़ा दी है।

कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज, संक्रमितों की संख्या हुई 82

प्रकोप ▶ पिछले चौबीस घंटे में आठ नए मामले दर्ज, कर्नाटक में वायरस से मरे व्यक्ति के संपर्क में रहे 46 लोग कोरंटाइन

देशभर में 42 हजार से ज्यादा लोग सामुदायिक निगरानी में

नई दिल्ली, एजेंसियां : घातक कोरोना वायरस से देश में पहली मौत के बाद कई राज्य इसके प्रसार को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हाल बंद कर दिए गए हैं। सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है या उन्हें स्थगित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में कोरोना वायरस के 81 मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में आठ नए मामले दर्ज किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यहां मीडिया से कहा, 'अभी तक भारत में कोरोना वायरस के 81 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें 64 भारतीय, 16 इटली के और एक कनाडा का नागरिक शामिल है। इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की तेजी से पहचान की जा रही है। अब तक चार हजार लोगों की पहचान हुई है, जिनको निगरानी में रखा गया है।' हालांकि, उनकी प्रेस कांफ्रेंस के बाद जम्मू में भी एक व्यक्ति के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसको मिलाकर कुल संख्या 82 हो गई है।

संयुक्त सचिव अग्रवाल ने बताया कि पूरे देश में 42 हजार से ज्यादा लोगों को सामुदायिक निगरानी में रखा गया है। इनमें से ढाई हजार से ज्यादा लोगों में कुछ लक्षण पाए गए हैं और 522 लोगों को अस्पताल में रखा गया है, जिनमें 17 विदेशी भी शामिल हैं।

वहीं, मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कम से कम 11 राज्यों में कोरोना के मामले पाए गए हैं। हालांकि, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसे स्वास्थ्य इमरजेंसी नहीं करार दिया है और लोगों से भयभीत नहीं होने की अपील की है।

केंद्र सरकार 37 में से सिर्फ 19 अंतरराष्ट्रीय चेकपोस्ट के जरिए ही देश में प्रवेश की अनुमति दी है। शेष नाकों को बंद कर दिया गया है। भारत-बांग्लादेश ट्रेन सेवा को भी 15 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।

कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि के बाद राज्य सरकार ने सभी माल, सिनेमा हाल, पब्स और नाइट क्लब को हफ्ते तक बंद रखने का आदेश दिया है। व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के साथ ही उसके संपर्क में आए 46 लोगों को कोरंटाइन किया गया है। इनमें से 36 लोगों को उच्च जोखिम और 13 लोगों को कम जोखिम की श्रेणी में रखा गया है। व्यक्ति के परिवार के चार सदस्यों में फ्लू के लक्षण मिलने पर उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कर्नाटक में संक्रमित लोगों की संख्या छह हो गई है।

केरल में और दो मामले मिले : केरल के त्रिशूर और कन्नूर में कोरोना वायरस के दो पॉजिटिव मामले मिले हैं। ये दोनों हाल ही में पश्चिम एशिया से लौटे थे। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने गुरुवार को यह जानकारी दी थी। वहीं, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि तिरुअनंतपुरम में भी एक पॉजिटिव केस मिला है। हालांकि, कोरोना की पुष्टि के लिए उसके सैंपल को जांच के लिए पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया है।

अब तक 1031 लोग विदेश से निकाले गए : लव अग्रवाल के मुताबिक सरकार ने अब तक 48 विदेशी नागरिकों समेत 1,031 लोगों को चीन, इटली, जापान और ईरान से निकाला है। निकाले गए विदेशियों में मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, अमेरिका, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और पेरु के नागरिक शामिल हैं।

दर्शन से पहले थर्मल स्क्रीनिंग : कोरोना वायरस को लेकर हर जगह सतर्कता देखने को मिल रही है। शुक्रवार को राजस्थान के बीकानेर स्थित कर्णी माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे नवविवाहित जोड़े की थर्मल स्क्रीनिंग डिवाइस से जांच की गई। प्रेट्र

बढ़ती दहशत

- दुनियाभर में कोरोना वायरस से 5,043 लोगों की मौत हुई है और एक लाख 34 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं
- सेना के मानेसर कैंप में रखे गए इटली से लौटे एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव। व्यक्ति को सफदरजंग अस्पताल भेजा गया
- एयर इंडिया ने इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इजरायल, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका के लिए 30 अप्रैल तक के लिए अपनी उड़ानें रद की
- केरल के पतनमतिट्टा जिले में नौ सौ लोगों को निगरानी में रखा गया है। ये लोग इटली से लौटे कोरोना से संक्रमित तीन लोगों के संपर्क में आए थे
- छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के एक जवान को तेज बुखार और खांसी होने के बाद जांच के लिए उसका सैंपल लिया गया है। वह 10 मार्च को केरल के अपने गृह जिले कोट्टयम से लौटा था
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों को संयुक्त रणनीति अपनाने का प्रस्ताव दिया।
- प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव का श्रीलंका, मालदीव, नेपाल और भूटान के राष्ट्राध्यक्षों ने स्वागत किया है
- यूरोपीय यूनियन के सभी 27 सदस्य देशों में वायरस पहुंच गया है। इन देशों में संक्रमितों की संख्या 22 हजार के पार पहुंच गई है
- ईरान में कोरोना से 85 और लोगों की जान चली गई। एक दिन में यह सर्वाधिक मौत है। इसे मिलाकर मरने वालों की संख्या 514 हो गई है

संसद के कामकाज पर वायरस बेअसर, पूरा चलेगा सत्र

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने संसद के मौजूदा सत्र को घटाने का सुझाव दिया

हरसिमरत कौर। फाइल

संसदीय कार्य मंत्री जोशी बोले-अवधि को घटाने का कोई सवाल नहीं

प्रह्लाद जोशी। फाइल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस को लेकर जब स्कूल और दूसरे संस्थान बंद होने लगे हैं तो सांसदों की ओर से भी सत्र का कार्यकाल कम करने की मांग उठने लगी है। संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 3 अप्रैल तक चलने वाले संसद के मौजूदा सत्र को घटाने का सुझाव दिया है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि अवधि को कम करने का कोई सवाल ही नहीं है। अभी औपचारिक रूप से सदन के अंदर इसकी मांग नहीं उठी है।

केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने शुक्रवार को कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों से बचने की हिदायत दी जा रही है। जबकि संसद में तो हर दिन बंद कमरे में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। किसी से यह कहा नहीं जा सकता है कि वह दो फीट की दूरी पर बैठे। जैसा कि इससे बचने के लिए निर्देश हैं। इनमें किसी को खांसी आ रही है तो किसी को छींकें आ रही हैं। किसी को कैसे दूर जाने के लिए कह सकते हैं। ऐसे में सरकार से सुझाव है कि इस महामारी से बचाव के संसद सत्र की अवधि कम करनी पड़े तो विचार करना चाहिए। वहीं संसद भवन परिसर के बाहर पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉ. महेश शर्मा ने भी लोगों से कोरोना को लेकर सावधान किया। साथ ही दावा किया कि जैसी ही तापमान 30 से 35 डिग्री तक पहुंचेगा, यह खुद ही नष्ट हो जाएगा। वैसे भी इसका वायरस सिर्फ डेढ़ फीट तक के दायरे में प्रभाव छोड़ सकता है। बचाव के एहतियात के रूप में परिसर के अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखे गए हैं जो अंदर जाने वाले हर व्यक्ति के लिए है।

छत्तीसगढ़ विस सत्र 25 तक टला : रायपुर में नईदुनिया के राज्य ब्यूरो के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार ने एहतियातन विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक स्थगित कर दिया है। सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के बाद अब तकनीकी समेत सभी शिक्षण व ट्रेनिंग संस्थान 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, लेकिन रेडी-टू-ईट का वितरण जारी रहेगा। इस बीच रायपुर नगर निगम ने कोरोना से निपटने के लिए 98 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है।

ओडिशा विस सत्र 29 तक स्थगित : वहीं भुवनेश्वर के जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के चलते विधानसभा अध्यक्ष सूर्यनारायण पात्र ने शुक्रवार को 29 मार्च तक बजट सत्र को स्थगित कर दिया। हालांकि, इस पर विरोधी दल के सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है। 31 मार्च तक मुख्यमंत्री शिकायत प्रकोष्ठ को भी बंद कर दिया गया है। इधर, कोरोना वायरस के संक्रमण को ओडिशा सरकार ने राज्य आपदा घोषित किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में बताया कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज भी मंजूर किया है।

केरल विधानसभा सत्र समय से पहले समाप्त

केरल विधानसभा का 19वां सत्र समय से पूर्व ही खत्म कर दिया गया है। कोरोना की दहशत का असर है कि शुक्रवार को कामकाज के बाद सत्र समाप्ति की घोषणा कर दी गई। हालांकि बाद में विपक्षी दल कांग्रेस ने इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री पिन्नरई विजयन ने कहा कि विधानसभा की सलाहकार समिति ने सत्र समाप्त करने की सिफारिश की है।

केरल में तीन चिकित्सा सहायकों से खाली कराए गए मकान

कोट्टयम (केरल), प्रेट्र : कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की देखरेख करने वाले तीन पुरुष चिकित्सा सहायकों से उनके मकान मालिक ने घर खाली करा लिया।

जानकारी के मुताबिक, तीनों अलग-अलग पालियों में काम करते हैं। उनमें से एक अपनी पाली खत्म होने के बाद शुक्रवार सुबह जब आराम करने के लिए घर पहुंचा तो मकान मालिक ने उसे घर खाली करने को कहा। टीवी चैनलों पर इस खबर का प्रसारण होते ही कोट्टयम के कलेक्टर सुधीर बाबू ने कॉलेज क्वार्टर में उनके ठहरने की व्यवस्था कराई। गौरतलब है कि कॉलेज में कोरोना से संक्रमित तीन रोगियों का इलाज चल रहा है।

'चीन में पल-पल डरा रहा था जानलेवा वायरस'

मुकेश कुमार 'अमन', सीतामढ़ी

- **चीन से सीतामढ़ी लौटी मेडिकल छात्रा कोमल ने सुनाई अपनी दास्तां**
- **पढ़ाई बाधित न हो, यूनिवर्सिटी ने शुरू कराई ऑनलाइन व्यवस्था**

चीन के सियान शहर से लौटी मेडिकल की छात्रा कोमल भारती। जागरण

जांच रिपोर्ट में स्वस्थ होने की सूचना पर राहत

कोमल भारती ने कहा, भारतीय दूतावास ने जल्द ही वतन लौटने की व्यवस्था कर दी। फिर भी डर सता रहा था, क्योंकि फ्लाइट को वुहान होकर ही जाना था। खैर, चीन से सुरक्षित निकलकर हम दो फरवरी को दिल्ली एयरपोर्ट उतरे। यहां स्वास्थ्य अधिकारियों ने हमारी स्क्रीनिंग की। उसके बाद हमें आइटीबीपी सेंटर में रखा गया। वहां 14 दिनों की गहन जांच हुई। उन्होंने कहा कि चीन से आए लोगों को एक सीमित क्षेत्र में रखा जाता है, ताकि ये आमलोगों से दूर रहें। सावधानी भी बरती जाती है। रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सभी स्वस्थ हैं। 14 दिन बाद वहां से डॉक्टरों ने हमें डिस्चार्ज कर दिया।

'कोरोना वायरस की वजह से चारों ओर भय का माहौल। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंखों से नींद गायब थी। खाने की भी इच्छा नहीं होती थी। बार-बार असुरक्षित होने का भाव। एक प्रश्न मन में बार-बार उठ रहा था कि क्या वतन लौट पाऊंगी? मगर, मोदी सरकार पर पूरा भरोसा था कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते किसी भारतीय को कोई परेशानी नहीं हो सकती।' ये बातें चीन से लौटी सीतामढ़ी की कोमल ने शुक्रवार को दैनिक जागरण से विशेष बातचीत में कही। कोमल चीन के सियान शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी।

कोमल ने कहा, विदेश में पहली बार डर का एहसास हुआ क्योंकि चीन की सरकारी मीडिया के माध्यम से विचलित करने वालीं सूचनाएं मिल रही थीं। घबराहट बढ़ रही थी। वुहान की तरह सियान में भी सभी सार्वजनिक सेवाएं बंद थीं। हॉस्टल से बाहर नहीं जाने का आदेश था। खाने-पीने की दिक्कत तो नहीं हुई। मगर बाद में पानी की किल्लत जरूर होने लगी। ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, लेकिन सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थीं। कोई किसी के पास नहीं जाता था, अगर कोई सामने आ भी जाता तो झट से हट जाता था। कहा, घर आकर खुश हूं, लेकिन पढ़ाई की चिंता सता रही। हालांकि यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवा दी गई है।

महामारी का असर, सिर्फ अर्जेंट मामलों को ही सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस ने सर्वोच्च अदालत के कामकाज पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 16 मार्च से सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई करेगा। इतना ही नहीं अदालत कक्ष के अंदर सिर्फ बहस करने वाले वकील और उसके साथ एक मुवक्किल को ही जाने की इजाजत होगी।

सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल एक सप्ताह से होली का अवकाश चल रहा है। इस दौरान अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए अवकाश कालीन पीठ ही बैठती थी। सोमवार से विधिवत कोर्ट खुलना है, लेकिन देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने बैठक बुलाई थी, जिसमें स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय के अधिकारियों व अन्य लोगों के साथ हालात पर मंथन हुआ था।

शुक्रवार को कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर कोरोना के खतरे को देखते हुए कामकाज सीमित करने की जानकारी दी। नोटिफिकेशन में कहा कि कोर्ट आने वाले सभी लोगों, मुवक्किलों, वकीलों, कोर्ट स्टाफ व सभी अन्य की सुरक्षा को देखते हुए सक्षम अथारिटी ने सोमवार 16 मार्च से कोर्ट का कामकाज सीमित करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अर्जेंट मामलों की सुनवाई करेगा।

मुकदमों की सुनवाई के लिए सिर्फ उतनी ही अदालतें बैठेंगी जितनी की अर्जेंट सुनवाई के लिए जरूरी होंगी। सिर्फ बहस करने वाले वकीलों और उनके साथ एक मुवक्किल को ही जाने की इजाजत होगी और किसी व्यक्ति को अदालत के अंदर घुसने की इजाजत नहीं होगी। अर्जेंट सुनवाई की मेंशनिंग सिर्फ मेंशनिंग अफसर के पास की जाएगी।

कोरोना रोकने को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : कोरोना वायरस को अदालतों में फैलने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ के समक्ष पेश हुई याचिका को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता रश्मि बंसल ने पीठ से कहा कि कोरोनो से अदालतों को बचाने के लिए हाई कोर्ट का दखल चाहते हैं। बंसल ने याचिका में कहा है कि वकील, वादियों और कर्मचारियों सहित हजारों लोग हर रोज अदालत आते है और वायरस को देखते हुए लोगों की भीड़ को अदालत में आने से रोकना जरूरी है।

सिद्धिविनायक मंदिर के पुजारी भी सतर्क...

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए शुक्रवार को मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पुजारी मास्क पहने नजर आए। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए मंदिर ट्रस्ट नियमित तौर पर दवाओं का छिड़काव भी कर रहा है। प्रेट्र

संकट को देखते हुए सेना ने सभी भर्ती रैलियां एक माह के लिए टालीं

नई दिल्ली, प्रेट्र: कोरोना वायरस संकट को देखते हुए सेना ने अपनी सभी भर्ती रैलियां एक माह के लिए टाल दी हैं। साथ ही अपने कार्मिकों से बहुत ही जरूरी होने पर यात्रा करने की सलाह दी है। यह जानकारी शुक्रवार को सेना के सूत्रों ने दी। सूत्रों ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए सभी संबंधित लोगों को निर्देश जारी कर स्वास्थ्य संबंधी उपायों का पालन करने को कहा गया है।

इस दौरान सभी भर्ती रैलियों को एक माह के लिए टालने के साथ कार्मिकों की यात्रा सीमित करने के उपाय किये जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठकों के लिए वीडियो कांफ्रेंस जैसी सुविधाओं के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। सेना के कमांड मुख्यालय को जरूरत पड़ने पर संक्रमित लोगों की रखने की व्यवस्था करने को कहा गया है। अभी फिलहाल मानेसर में 300, जोधपुर में 1000, जैसलमेर में 1000, झांसी में 1000, बिन्नागुरी में 300 और गया में 300 बेड का बंदोबस्त किया गया है।

आयोजन

नेताजी इंडोर स्टेडियम में खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में उमड़ा हुजूम, ममता बोलीं, रोज-रोज नहीं आता ऐसा दिन इसलिए इकट्ठा हुए, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं

मनाही के बावजूद ममता सरकार ने जुटाई 10 हजार की भीड़

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार की मनाही के बावजूद ममता सरकार ने शुक्रवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में 10,000 लोगों की भीड़ जुटा ली। मौका था विभिन्न खेलों से जुड़े बंगाल के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का। हालांकि, ममता ने इसे लेकर सफाई भी दी। वे अपने साथ केंद्र की तरफ से गुरुवार को जारी की गई एडवाइजरी की प्रति लेकर आईं और उसे पढ़ते हुए कहा, 'केंद्र ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि खेल आयोजन समेत अन्य कार्यक्रमों में भीड़ न होने पाए। विभिन्न आयोजनों पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद हम यहां इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ऐसा दिन रोज-रोज नहीं आता।' ममता ने आगे कहा, 'कोरोना को लेकर लोगों में डर का माहौल है। इससे डरने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है।

ममता ने कहा कि जिस तरह किसी भी मच्छर के काटने से डेंगू नहीं होता, उसी तरह किसी को सर्दी-खांसी होने का मतलब यह नहीं कि वह कोरोना से संक्रमित है। कोरोना एक वायरस है और यह मानव से मानव में फैल रहा है। चूंकि इस बीमारी के लिए अभी तक किसी दवा का आविष्कार नहीं हुआ है इसलिए लोगों को खुद ही सावधानी बरतनी होगी और सफाई का ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने लोगों को फिलहाल किसी से हाथ नहीं मिलाने की सलाह दी। भीड़-भाड़ वाली जगहों या बाजारों में जाने से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक-दूसरे से बात करने पर पांच मीटर की दूरी रखें। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और एडवाइजरी के मुताबिक हर संभव कदम उठा रही है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में मोहनबगान एसी खिलाड़ियों के साथ। यहां शुक्रवार को खेलश्री सम्मान वितरण समारोह आयोजित किया गया था। प्रेट्र

विपक्ष ने समारोह के आयोजन पर उठाया सवाल : विपक्षी दलों ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुए समारोह के आयोजन पर सवाल उठाया। बंगाल भाजपा के महासचिव सायंतन बसु ने कहा-'ये बेहद गैरजिम्मेदाराना रवैया है। समारोह को रद कर दिया जाना चाहिए था जबकि मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल हुईं।' वहीं, कांग्रेस विधायक मनोज चक्रवर्ती ने कहा, 'ऐसा लगता है कि ममता सारे नियमों से आगे हैं।'

केंद्रीय कर्मचारियों का सालाना हेल्थ चेकअप 30 जून तक टला

- **सरकार नहीं चाहती अस्पतालों के वार्डों में अनावश्यक भीड़**
- **अस्पतालों में कोरोना फैलने के अंदेशे के चलते उठाया कदम**

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के अनिवार्य रूप से कराए जाने वाले सालाना हेल्थ चेकअप को 30 जून तक के लिए टाल दिया है। हालांकि, इससे अप्रेजल प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अधिकारियों का कहना है कि सरकार नहीं चाहती कि कोरोना वायरस के चलते अस्पतालों और विभिन्न वार्डों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोई अनावश्यक बोझ पड़े।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों के लिए अप्रेजल से पहले सालाना चिकित्सकीय जांच अनिवार्य होती है, जो 40 साल से अधिक आयु के हैं या इस साल 31 मार्च तक 40 साल के हो गए हैं, लेकिन देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए इस प्रक्रिया को 30 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि उनके यहां ऐसे 50-60 लाख अधिकारी हैं और इसमें से बड़ी तादाद में लोगों की आयु 40 साल से ज्यादा की है। ऐसी आपात स्थिति में यह चेकअप अभी कराना चिकित्सा सेवाओं के लिए बड़ा व्यवधान साबित हो सकता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे समय में चिकित्सा जांच कराना अतिरिक्त बोझ तो हो ही सकता है, बल्कि इन अधिकारियों को अस्पताल जाने की कवायद के दौरान उन्हें कोरोना से संक्रमित भी कर सकता है। इसलिए सालाना हेल्थ चेकअप को 30 जून तक के लिए टाल दिया गया है।

1000 से ज्यादा लोगों की जान इटली में जा चुकी है कोरोना वायरस के कारण। इस वायरस से सबसे ज्यादा मौतें चीन के बाद इटली में हुई हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 मार्च 2020

हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड व बिहार में 31 तक सभी शिक्षण संस्थान बंद

एहतियात ▶ बिहार में रोटेशन के आधार पर कार्यालय बुलाए जाएंगे सरकारी कर्मचारी

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सभी एंट्री गेट पर होगी स्क्रीनिंग

जेएनएन, नई दिल्ली

कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई राज्यों ने पहले ही शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी इस बाबत आदेश पास हो गया। उप्र में 22 मार्च तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे तो हरियाणा में 31 मार्च तक। बिहार में भी सभी सरकारी, निजी स्कूल तथा कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। पंजाब में भी सरकारी स्कूलों को 31 तक बंद करने के आदेश राज्य सरकार ने दिया है। उत्तराखंड में भी 31 तक सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश में भी एतिहातन स्कूल और कॉलेज 31 तक बंद हैं। सिनेमाघर भी 31 तक बंद रहेंगे।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सभी एंट्री गेट पर आने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिए जल्द ही स्क्रीनिंग मशीन सभी गेट पर लगाई जाएगी। बिहार में सरकारी दफ्तरों में रोटेशन के आधार पर कर्मियों को बुलाया जाएगा। अगर दस कर्मी किसी दिन आते हैं तो उन्हें अगले दिन नहीं बुलाया जाएगा। सरकारी दफ्तरों में कंजेशन (भीड़) न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। राजस्थान में कोरोना वायरस को सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। स्कूल और कॉलेज भी बंद किए जाने का फैसला जल्द लिया जा सकता है। झारखंड में भी विपक्ष सरकार पर सभी शिक्षण संस्थान बंद करने का दबाव बना रहा है। इस बाबत जल्द निर्णय लिया जा सकता है।

श्रीनगर में शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले जामिया मस्जिद के आसपास नगर निगम कर्मियों ने दवा का छिड़काव किया। जागरण

उत्तर प्रदेश
- जिन शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, वहां यथावत चलेंगी
- सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक, सरकार भी नहीं मनाएगी तीन साल पूरा होने का जश्न
- आगरा में दो महीने में ताज के 2.2 लाख पर्यटकों में कमी आई है।

दिल्ली
- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सभी कक्षाएं, व्याख्यान, प्रेजेंटेशन व परीक्षाएं 31 मार्च तक रद।
- जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 31 तक सभी कक्षाएं बंद।

हरियाणा
- राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध।
- धार्मिक समागम और खेल आयोजनों पर भी लगाई गई रोक
- हर तीन दिन में समीक्षा करेंगे गृह व स्वास्थ्य मंत्री विज
- आइआइएम रोहतक का दीक्षांत समारोह स्थगित।
- फतेहाबाद जिले के सभी डाक्टरों की छुट्टी रद।

पंजाब
- पटियाला में विदेश से आए दो लोगों को गांव छोड़ने का फरमान।
- लुधियाना में आयात व निर्यात बाधित। चीन से आयात लगभग बंद।
- यूरोप व एशिया के देशों में ऑर्डरों की डिलीवरी रोकी।
- चीन, अमेरिका, थाईलैंड जैसे देशों से आने वाले फलों का आयात भी बंद।

जम्मू
- कोरोना वायरस से निपटने में कोताही बरतने पर नोडल अधिकारी समेत दो डॉक्टर निलंबित।
- जम्मू में सभी शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम और क्लबों को बंद करने के निर्देश।
- सार्वजनिक गाड़ियों के इस्तेमाल कम करने को कहा गया।

बिहार
- सूबे के सभी सिनेमा हॉल, पार्क, चिड़ियाघर व संग्रहालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे।
- 22 मार्च तक होने वाले बिहार दिवस के तीन दिवसीय आयोजन भी रद।
- राजद का 14 मार्च से राजगीर में होने वाला प्रशिक्षण शिविर स्थगित।

बंगाल
- अप्रैल तक नहीं होगा कोई खेल आयोजन।
- रविवार को ईस्टबंगाल-मोहनबगान में होने वाला डर्बी मैच भी स्थगित।

ओडिशा
- 31 मार्च तक शिक्षा संस्थान, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल सब बंद
- कोरोना से निपटने को 200 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मंजूर

छत्तीसगढ़
- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, राजनांदगांव में विदेशी छात्रों पर रोक।

हिमाचल
- अगले आदेश तक मेलों व खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर रोक।
- कोई भी सरकारी अधिकारी अगले आदेश तक विदेश दौरे पर नहीं जाएगा।
- धार्मिक आयोजनों में जनसाधारण को एकत्र न होने के दिशानिर्देश। लोगों को धार्मिक यात्राएं स्थगित करने के लिए कहा गया।

उत्तराखंड
- नेपाल सीमा से सटी आठ चौकियों पर 22968 लोगों की स्क्रीनिंग
- राज्य-जिला स्तर पर रेपिड रिस्पांस टीम गठित

उप्र में इलाज से भागने पर दर्ज होगी एफआइआर

जागरण संवाददाता, लखनऊ

▶ लखनऊ में आउटब्रेक रिस्पांस टीम 24 घंटे निगरानी करेगी

कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन एक्शन प्लान तैयार किया गया है। लखनऊ में आउटब्रेक रिस्पांस टीम बना दी गई है, जो चौबीस घंटे निगरानी करेगी। शहर के प्रत्येक बड़े अस्पतालों में जांच की सुविधा होगी। यह भी तय किया गया है कि संक्रमित व्यक्ति अगर इलाज से भागेगा या फिर जो इलाज में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ एफआइआर होगी। प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज और जांच की व्यवस्था होगी। लखनऊ में मरीज के सामने आने के बाद से ही प्रशासन कोरोना से बचाव को लेकर सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। लगातार बढ़ रहे संदिग्ध मरीजों की संख्या को देखते हुए डीएम ने निर्देश दिए हैं कि लखनऊ के समस्त अस्पतालों व सीएचसी और पीएचसी में थर्मल स्कैनर व इंफ्रारेड थरमोमीटर की तत्काल व्यवस्था कराई जाएगी।

चीन, इटली, ईरान, साउथ कोरिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी से यात्रा कर गाजियाबाद जिले में लौटने वाले लोग अब सीधे अपने घर नहीं जा सकेंगे। इन लोगों को 14 दिन तक कवारंटाइन एरिया वार्ड में रखा जाएगा। इस वार्ड की स्थापना ईएसआइ साहिबाबाद में की जा रही है। मंडलीय सर्विलांस अधिकारी डॉ. अशोक तालियान ने बताया कि इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन मिली है। उसके अनुपालन में तत्काल प्रभाव से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोरोना को फैलने से रोकने को यह कदम उठाया गया है। उपरोक्त देशों से आने वाले लोगों पर ही यह सख्ती लागू होगी।

बैठक के अहम फैसले
- रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन। इसमें प्रशासन, पुलिस, नगर निगम व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अफसर। मुख्य विकास अधिकारी नोडल अफसर। टीमें स्वयं जाकर लोगों की जांच करेंगी
- वायरस से प्रभावित सात देशों (चीन, इटली, ईरान, साउथ कोरिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी) से आने वाले शत प्रतिशत भारतीय व विदेशी नागरिकों, जिन्होंने विगत 12 फरवरी से इन देशों की यात्रा की है या वहां होते हुए आए है उनको मॉनीटर व ट्रैक करने की व्यवस्था है
- चिकित्सालयों में ओपीडी में लाइन नहीं लगेगी। डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से मेडिकल स्टाफ मरीजों को बुलाएगा
- शॉपिंग मॉल, व्यापारिक व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पर्सनल हाईजीन के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।

ईरान में फंसे 44 भारतीय वापस लाए गए

नई दिल्ली, एजेंसियां : विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया है कि 44 भारतीय श्रद्धालुओं का दूसरा बैच शुक्रवार की दोपहर भारत वापस लाया गया है। कोरोना संकट से जूझ रहे ईरान से इनको एक ईरानी विमान से मुंबई एयरपोर्ट लाया गया। उसके बाद इन सभी लोगों को मुंबई के घाटकोपर स्थित नौसेना के एक ठिकाने पर चिकित्सकीय निगरानी के लिए रखा गया है। इससे पहले, इन लोगों को राजस्थान के जैसलमेर जिले में सेना के एक ठिकाने पर अलग-थलग रखने की तैयारी थी।

विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि 44 भारतीय श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था शुक्रवार को ईरान से यहां आ गया है। औरों को भी वापस लाने का हमारा अभियान जारी है। ईरान में भारत की चिकित्सा टीम ने अच्छा काम किया है। हम ईरानी प्रशासन के सहयोग और उनकी एयरलाइंस के आभारी हैं। उन्होंने बताया कि ईरानी एयरलाइंस के विशेष विमान आइआर810 से तेहरान से भारतीयों को लेकर आया विमान यहां शुक्रवार को दोपहर 12.07 बजे पहुंचा। सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की स्क्रीनिंग एपीएचओ ने आइसोलेशन बे में की। इन लोगों को घाटकोपर के नौसैनिक अड्डे पर अलग-अलग अकेले रखा जाएगा। जयशंकर ने विगत गुरुवार को कहा था कि छह हजार से अधिक भारतीय ईरान के विभिन्न प्रांतों में अभी भी फंसे हुए हैं। ईरान से 58 भारतीयों का पहला जत्था इसी मंगलवार को वापस लाया गया था।

भारतीय वैज्ञानिकों को प्रयोगशाला बनाने की अनुमति नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : ईरान में फंसे भारतीयों में कोरोना वायरस की जांच के लिए गए भारतीय वैज्ञानिकों को वहां के अधिकारी अस्थायी प्रयोगशाला बनाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। लगभग 1,200 भारतीयों की लार का नमूना भारत लाया गया है, ताकि उनमें कोरोना के संक्रमण की जांच की जा सके। भारत के चार वैज्ञानिक कोरोना के संक्रमण की जांच के लिए इस समय तेहरान में हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वहां के अधिकारी भारतीय वैज्ञानिकों को अस्थायी प्रयोगशाला बनाने की इजाजत नहीं दे रहे। उनका कहना है कि वे सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं। भारतीय वैज्ञानिक अब भी तेहरान में रुके हुए हैं और भारतीयों की लार का नमूना जुटाने में लगे हैं। उल्लेखनीय है कि ईरान कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल है। भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों को स्वदेश लाना चाहती है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ईरान में फंसे भारतीयों की जांच के लिए वहीं पर अस्थायी प्रयोगशाला बनाना चाहती है, ताकि वहां से लाने से पहले यह पता चल सके कि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। जो लोग ईरान में फंसे हुए हैं, उनमें ज्यादातर छात्र और तीर्थयात्री हैं। इसके अलावा एक हजार मछुआरे भी वहां फंसे हुए हैं। भारतीय वायु सेना के विमान से 58 लोगों के पहले जत्थे को भारत लाया गया था।

जम्मू में मिला एक और मरीज

राज्य ब्यूरो, जम्मू : जम्मू में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। सरवाल क्षेत्र के बुजुर्ग व्यक्ति में वायरस की पुष्टि हुई है। यह व्यक्ति पीड़ित महिला के संपर्क में आया था। वहीं, जम्मू जिले में प्रशासन ने शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम व क्लब बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अभी तक जम्मू-कश्मीर में विदेशों से लौटने वाले व उनके संपर्क में रहे 1754 संदिग्ध लोगों को निगरानी में रखा है। इनमें 159 लोगों को जरूरी 28 दिन तक अलग से रखने का समय पूरा हो गया है। 1485 लोगों को घरों में अलग से व 18 लोगों को अस्पतालों में रखा है। 85 संदिग्धों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इनमें दो में कोरोना की पुष्टि हुई है। छह के सैंपलों की रिपोर्ट आना शेष है। जिन दो मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है, उनमें एक कुछ दिन पहले ही ईरान से लौटी थी। उसे जीएमसी में भर्ती करवाया था, लेकिन कुछ घंटों के बाद वह वापस घर चली गई थी।

भारतीय सेनाएं बना रहीं अलग निगरानी केंद्र

नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय रक्षा बलों ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर देश भर में पांच हजार लोगों की देखभाल के कई अलग निगरानी केंद्र बनाए हैं। जो लोग इस वायरस से संक्रमित होने के संदिग्ध हैं, उन्हें यहां 14 दिनों तक रखा जाएगा। यह सभी लोग कोरोना प्रभावित देशों से भारत लौट रहे हैं। भारतीय थलसेना ने अब तक चार हजार लोगों के लिए केंद्र बनाए हैं। जबकि नौसेना और वायुसेना ने कुल एक हजार लोगों के लिए निगरानी केंद्र स्थापित किए हैं।

ट्रेनों में घटी यात्रियों की संख्या

जेएनएन, नई दिल्ली : कोरोना के खौफ से ट्रेन यात्रियों की संख्या कम हो रही है। पहले जहां बुकिंग काउंटर पर टिकट लेने के लिए यात्रियों को लंबी कतार लगानी पड़ रही थी, अब आसानी से टिकट मिल रहा है। संक्रमण के डर से यात्री बुकिंग काउंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। वहीं कई अपनी यात्राएं टाल भी रहे हैं। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में सबसे अधिक कमी आई है। शुक्रवार को भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या बेहद कम रही। ट्रेनों में यात्री कोरोना संक्रमण की ही चर्चा में मशगूल दिखे। फिरोजपुर डीआरएम आफिस से मिले आंकड़ों के मुताबिक 3 से लेकर 12 मार्च तक ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में एकाएक गिरावट आई। इस दौरान कुल ढाई लाख के करीब मुसाफिरों की संख्या में कमी आई है। 3 मार्च के दिन आरक्षण और जनरल टिकट पर ट्रेनों में सफर करने वाले मुसाफिरों की संख्या जहां 70 हजार के लगभग थी, वहीं 12 मार्च तक कम होकर यह 58 हजार तक रह गई है।

बॉलीवुड में भी दहशत, तीन अप्रैल तक कोई फिल्म नहीं होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई

दिल्ली, जम्मू, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल के बाद शुक्रवार को मुंबई में भी 31 मार्च तक सिनेमाहॉल बंद करने का निर्णय लिया गया है। मुंबई में सिनेमा हॉल बंद होने का सबसे बुरा असर शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म अंग्रेजी मीडियम पर पड़ा। जबकि फिल्म सूर्यवंशी और सर की रिलीज टाल दी गई है। अब तीन अप्रैल तक कोई भी नई फिल्म रिलीज नहीं होगी।

फिल्म के निर्देशक होमी अदजानिया ने इंस्टाग्राम पर कहा कि मध्यरात्रि से सभी सिनेमाघर बंद हो जाएंगे। हम सही समय आने पर फिल्म अंग्रेजी मीडियम को दोबारा रिलीज करेंगे। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन के मुताबिक एक अनुमान के अनुसार कोरोना के चलते देश की फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सिनेमा के अलावा मुंबई स्थित नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) को भी 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। एनसीपीए की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन्होंने शोज की टिकट खरीदी है, उन्हें पूरा रीफंड मिल जाएगा। टीवी इंडस्ट्री भी लगातार सतर्कता बरत रही है। 'द कपिल शर्मा' शो पर पूरा क्रू मास्क लगाकर काम कर रहा है। इस शो में दर्शक भी आते हैं, ऐसे में सेट पर डॉक्टर की संख्या बढ़ाई गई है। पहले दो डॉक्टर थे, अब तीन हो गए हैं। मशीन के जरिए सबकी जांच की जा रही है।

हॉलीवुड फिल्मों की रिलीज भी टली : कोरोना की वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने लॉस एंजिलिस का अपना ऑफिस बंद कर दिया है। वहीं कई हॉलीवुड फिल्मों की रिलीज डेट बदल दी गई। जेम्स बांड सीरीज की फिल्म नो टाईम टू डाई कोरोना से प्रभावित होने वाली पहली फिल्म बनी। पहले यह फिल्म अप्रैल माह में रिलीज होनी थी अब नवंबर में रिलीज होगी। फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की नौवीं फिल्म एफ 9 की रिलीज 22 मई से करीब 11 महीने आगे बढ़ाकर अगले साल दो अप्रैल कर दी गई है। एमिली ब्लंट अभिनीत फिल्म अ क्वाइट प्लेस की रिलीज स्थगित कर दी गई है। डिजनी स्टूडियो ने भी 27 मार्च और 3 अप्रैल को रिलीज होने जा रही अपनी दोनों फिल्में मूलन और द न्यू म्यूटेंट्स की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। कंपनी इनकी नई रिलीज तारीख बाद में घोषणा करेगी। फिल्म ब्लैक विडो, वंडर वुमन और टॉप गन मैवरिक की रिलीज डेट भी टलने की संभावना है।

वर्ष 1986 में हड़ताल के चलते बंद हुए थे सिनेमाघर : कोरोना के चलते देशभर में सिनेमाघरों को बंद किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1986 में पूरी बांबे फिल्म इंडस्ट्री ने हड़ताल कर दी थी। तब भी सिनेमाघर बंद हुए थे। महाराष्ट्र सरकार से उनकी तीन मांगे थी। पहली, कैमरे और साउंड रिकॉर्डिंग मशीन को छोड़कर सभी वस्तुओं से नए बिक्री कर समाप्त करना, दूसरी, बांग्लादेश युद्ध के दौरान शुरू किए गए सिनेमाघरों के टिकटों पर विशेष अधिभार को समाप्त करना और तीसरी, मनोरंजन कर में कटौती। उस समय फिल्म इंडस्ट्री ने एक दिन का राष्ट्रव्यापी बंद भी आयोजित किया था। इस बंद के कारण डेढ़ लाख लोग बेरोजगार हो गए थे।

यह विश्व में फिल्म इंडस्ट्री की सबसे लंबे समय तक चली हड़ताल थी। उस समय इंडस्ट्री में 700 फिल्में सालाना बनाती थी। जबकि हॉलीवुड में तीन सौ।

ट्रेड एनालिस्ट विनोद मीरानी के मुताबिक उस समय थिएटर मालिकों की हालात खराब थी ऊपर से सरकार ने चार प्रतिशत अतिरिक्त कर लगा दिया था। यह टैक्स फिल्म को शूट करने से लेकर शूटिंग में काम आने वाले उपकरणों, डिस्ट्रीब्यूशन तक पर था। इस तरह से हर चरण में चार प्रतिशत होते-होते यह टैक्स कई गुना बढ़ जाता था। उसकी वजह से सिनेमा मालिकों ने हड़ताल की थी, जो 32 दिन चली थी।

वर्ष 1975 में इमरजेंसी के समय भी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई थी। लेकिन इस समय थिएटरों को कोरोना की वजह से बंद किया गया है। इसमें इंडस्ट्री का कोई हाथ नहीं है। यह लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2009 में मल्टीप्लेक्स मालिकों और निर्माताओं के बीच कमाई के हिस्से को लेकर विवाद हुआ था। जिसकी वजह से निर्माता हड़ताल पर चले गए थे। तब दो महीने तक कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी।

दहशत न फैलाएं : करीना कपूर खान

सोशल मीडिया पर सितारे भी लोगों से संयम बरतने का आग्रह कर रहे हैं। करीना कपूर खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हमें सूचनाओं को फिल्टर करने के बाद सही स्रोत का पता लगाने की जरूरत है। दहशत में न आएं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि दहशत का कारण आप न बनें। आपकी गतिविधियां आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करती हैं। पूरी दुनिया में प्रयास किए जा रहे हैं। हम सब को भी अपने हिस्से का काम करना होगा। भले ही वह काम छोटा सा क्यों न हो। सुरक्षित रहें।' वहीं प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए लिखा, 'यह नमस्ते के बारे में है। दुनियाभर में चल रहे बदलाव के दौर में लोगों के अभिवादन का एक प्राचीन, साथ ही बिल्कुल नया तरीका। कृपया आप सभी सुरक्षित रहें।'

करीना कपूर खान फाइल

इतने कार्यक्रम रद हुए
- तीन अप्रैल से 12 अप्रैल तक सलमान खान का अमेरिका और कनाडा दौरा टला
- रितिक रोशन का 10 अप्रैल से शुरू होने वाला अमेरिका का टूर भी रद
- कोरोना का प्रकोप खत्म होने तक कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे गायक केके
- सरोद वादक अमजद अली खान का पांच अप्रैल को होने वाला शिकागो समारोह टला

कोरोना वायरस अभी भारत में महामारी नहीं : आइसीएमआर

नीलू रंजन, नई दिल्ली

कोरोना के कारण भले ही पूरे देश में शिक्षण संस्थानों, सिनेमाघरों को बंद और सार्वजनिक कार्यक्रमों को स्थगित किया जा रहा हो, लेकिन इससे निपटने में जुटे वैज्ञानिकों की मानें तो भारत में अभी महामारी जैसे हालात नहीं हैं। विदेश से आने वालों की अनिवार्य जांच और अलग-थलग रखने से लेकर तमाम प्रतिबंधों को जरूरी बताते हुए चिकित्सा अनुसंधान से जुड़ी देश की शीर्ष वैज्ञानिक संस्था आइसीएमआर के महानिदेशक डॉ. बलराम भार्गव ने कहा है कि इस वायरस से बच्चे से लेकर युवा तक कोई भी ग्रसित हो सकता है और उनसे दूसरे में फैल भी सकता है, लेकिन बुजुर्ग या पहले से बीमार व्यक्ति के ग्रसित होने की स्थिति में यह घातक साबित हो सकता है।

कोरोना को लेकर ज्यों-ज्यों एहतियाती कदम सख्त किए जा रहे हैं, वैसे-वैसे थोड़ा भय का माहौल भी बनता जा रहा है। मुंबई के एक बड़े स्कूल ने तो बच्चों के शहर से बाहर नहीं जाने और मुंबई से बाहर के किसी व्यक्ति को घर नहीं आने देने की हिदायत जारी कर दी है। ऐसा होने की स्थिति में स्कूल ने बच्चे को 14 दिन अलग-थलग रखने का निर्देश दिया है। दैनिक जागरण के एक सवाल के जवाब में बलराम भार्गव ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को 14 दिन तक अलग-थलग रखना तभी जरूरी है जब वह किसी कोरोना वायरस से ग्रसित इलाके से आया हो या फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति में देश के भीतर आने-जाने वालों को अलग-थलग रखने की जरूरत नहीं है। एक सवाल के जवाब में डॉ. भार्गव ने कहा कि यह वायरस युवा और बुजुर्ग किसी में भी जा सकता है और उनसे संपर्क में आने वालों में फैल सकता है।

देश में यह महामारी का रूप नहीं ले पाया है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में अभी तक कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसफर का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कोरोना से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने के दो मामलों में कुछ लोगों को इससे ग्रसित पाया गया है। यह किसी वायरस के फैलने का दूसरा चरण है। डॉ. भार्गव के अनुसार भारत में उठाए जा रहे सभी कदम कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसफर के स्टेज तीन तक पहुंचने से रोकने के हैं। एक बार कम्युनिटी ट्रांसफर की स्थिति में पहुंचने के बाद वायरस महामारी का रूप धारण कर लेता है। जैसा कि चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ईरान और इटली के साथ-साथ कई यूरोपीय देशों में देखा जा रहा है।

जनमत
मुद्दा

क्या कोरोना का टीका अगर मौजूद होता तो इस बीमारी के प्रति हम सब इतने भयाक्रांत होते?

mudda@jagran.com पर आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं।

वैक्सीन बनाने में लगेगा एक साल : डॉ. भार्गव ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन आने में कम-से-कम एक साल का समय लग सकता है। ऐसे में इस वायरस को जितना फैलने से रोका जाए उतना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा चुके हैं। देश में 67 लेबोरेटरी में हर दिन कोरोना के छह हजार से अधिक मामलों की जांच की क्षमता स्थापित की गई है, लेकिन अभी केवल 60-70 मामलों की ही जांच हो रही है। इसके अलावा देश के मेडिकल कॉलेजों, बायोटेक्नोलॉजी विभाग और राज्यों के अंतर्गत आने वाले हजारों लेबोरेटरी को जांच के लिए तत्काल तैयार किया जा सकता है। पुणे स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की निदेशक डॉ. प्रिया अब्राहम ने कहा कि दो कंपनियों ने अपनी किट को सत्यापित कराने के लिए भेजा है। कोरोना वायरस की सटीक पहचान कर पाने की इसकी क्षमता की जांच की जा रही है।

वायरस की कुंडली बनाने वाला भारत पांचवां देश : भारत अभी तक न सिर्फ कोरोना वायरस के महामारी का रूप धारण करने से रोकने में सफल रहा है, बल्कि इस वायरस की कुंडली तैयार करने वाला पांचवां देश भी बन गया है। भारत के अलावा अमेरिका, चीन, जापान और थाइलैंड ने इसकी कुंडली बनाई है। वायरस की कुंडली बनाने के साथ ही भारत इसके लिए वैक्सीन बनाने की स्थिति में भी पहुंच गया है। लेकिन वैक्सीन के लिए पहले जानवरों पर तीन-चार महीने और फिर छह से आठ महीने का क्लीनिकल ट्रायल अनिवार्य प्रक्रिया है। जाहिर है वैक्सीन बनने में कम-से-कम एक साल का समय लग सकता है। भार्गव ने कहा कि वैक्सीन बनाने के लिए आइसीएमआर के पास पर्याप्त धन है। इसके साथ ही नीपा वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने का अनुभव भी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने आइसीएमआर को 20 करोड़ रुपये और दिए हैं।

आइटीबीपी के कैंप में मिला घर जैसा माहौल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

छावला स्थित आइटीबीपी (भारत तिब्बत सीमा पुलिस) के कैंप में बने क्वारेंटाइन सेंटर में रखे 112 व्यक्तियों में से अधिकांश को शुक्रवार को घर रवाना कर दिया गया। शेष लोग अपनी सुविधा से शनिवार को रवाना होंगे। सभी को गुलाब का फूल और सर्टिफिकेट दिया गया। इन लोगों को 27 फरवरी को चीन से लाया गया था। इससे पूर्व भी 406 लोगों को यहां 14 दिनों तक रखने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर घर रवाना किया गया था।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आइटीबीपी के जवानों के हौसले को सराहना की। कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने व लोगों को क्वारेंटाइन सेंटर में पारिवारिक माहौल देने के लिए प्रत्येक भारतीय उनका आभार प्रकट करता है। उन्होंने कहा कि अभी क्वारेंटाइन सेंटर में मौजूद 112 लोगों में 36 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें चीन से छह, बांग्लादेश से 23, म्यांमार से दो, मालदीव से दो, संयुक्त राज्य अमेरिका से एक, दक्षिण अफ्रीका से एक व मेडागास्कर द्वीप से एक नागरिक शामिल हैं। चिकित्सकों ने बताया कि यहां से जाने वाले लोगों के घर पर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करती रहेगी। लखनऊ निवासी अभिषेक ने बताया कि चीन में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई थी। यहां आइटीबीपी के कैंप में कभी महसूस नहीं हुआ कि हमें क्वारेंटाइन किया गया है। जवानों के व्यवहार इतना अच्छा था कि कभी अकेलापन नहीं लगा। बेटी के मन से वायरस का डर भी निकल गया है। उन्होंने बताया कि चीन में उनके आसपास 24 लोग इस वायरस से संक्रमित थे। शुरुआत में डिपार्टमेंटल स्टोर सप्ताह में एक-दो बार खुलते थे। लोग वहां से जरूरत की चीजें खरीद लेते थे, लेकिन बाद में सब बंद कर दिया गया। आलम यह था कि एक व्यक्ति के एक समय के भोजन को पूरा परिवार दिनभर में खाता था। अभिषेक ने बताया कि वे 38 दिनों तक घर में बंद रहे थे। खिड़की से देखते थे तो सड़क पर सन्नाटा पसरा रहता था। सड़कों पर सिर्फ मरीजों को ले जाती एंबुलेंस दौड़ती दिखती थीं। आठ साल की बेटी तान्या पूछती रहती थी कि हम घर में बंद क्यों है। वह तरह-तरह की चीजें खाने की मांग करती थी। मजबूरन तरह-तरह की कहानियों से उसका मन बहलाना पड़ता था।

चीन के वुहान शहर से एयरलिफ्ट करके पिछले महीने दिल्ली के छावला स्थित आइटीबीपी के निगरानी केंद्र में रखे गए लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण नही पाए जाने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। प्रेट्र

उधर, गुरुग्राम के मानेसर स्थित सेना के आइसोलेशन सेंटर में इटली से लाए गए सभी 83 लोगों के शुक्रवार को सैंपल लिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉ. जसवंत सिंह पूनिया ने बताया कि सभी मरीज स्वस्थ हैं लेकिन एहतियातन सैंपल लेकर जांच की जा रही है।

भारतीयों को लाने आज इटली जाएगा विमान

नई दिल्ली, एजेंसियां : चीन के बाहर कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित यूरोपीय देश इटली में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया का विमान शनिवार को दोपहर बाद रवाना होगा। वहीं, भारतीयों में कोरोना वायरस की जांच करने के लिए डॉक्टरों का एक दल शुक्रवार को रोम पहुंच गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव रूबीना अली ने कहा, 'इटली में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया एक विमान मिलान भेजेगा। विमान कल दोपहर बाद उड़ान भरेगा और रविवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा।' वहीं, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव दम्मू रवि ने कहा कि इटली के मिलान और उसके आस-पास के क्षेत्रों में लगभग 220 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता उन्हें वापस लाने की है। अगर और कोई भी छात्र वहां रह गए हों तो वो दूतावास से संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद देखा जाएगा कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। वहीं, इटली की राजधानी रोम में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर बताया कि भारतीय मेडिकल टीम यहां पहुंच गई है।

बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

मौसम की मार ▶ गेहूं की बालियां झड़ जाने से प्रभावित होगी पैदावार, केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम बंद

उत्तर प्रदेश में रबी की फसल चौपट, आम के बौर भी गिरे

जेएनएन, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के स्वागत में लाल कालीन बिछी थी। ओलों की बारिश से पूरा कालीन ढक गया। अरुण कुमार दीक्षित

बेमौसम बारिश और ओले गिरने से उप्र में किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। यह तस्वीर श्रावस्ती जिले के अहिरनपुरवा बेलकर की है। गेहूं की गिरी फसल को किसान मालिकराम मायूसी से निहार रहे हैं। जागरण

उत्तर भारत में बारिश और ओलावृष्टि का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके चलते फसलों को नुकसान होने का सिलसिला भी जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही नहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी फसलों को नुकसान के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते गेहूं और रबी की फसल को नुकसान पहुंचा है।

बारिश-ओलावृष्टि से फसलें खराब : पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से शुक्रवार बरसात के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। किसानों के मुताबिक ओलावृष्टि के कारण गेहूं की बालियां झड़ जाने से पैदावार प्रभावित होगी। वहीं, टमाटर व शिमला मिर्च की फसल को भी नुकसान हुआ है। करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के मुताबिक आने वाले 24 घंटे बरसात हो सकती है। किसान बरसात का पानी खेतों में जमा ना होने दें। उत्तर प्रदेश में भी बारिश से रबी की फसल चौपट हो गईं और आम के बौर गिर गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे में लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगले दो तीन दिन बदली, बूंदाबांदी और बारिश के आसार बने रहेंगे।

पहाड़ों पर जारी बारिश से बढ़ी परेशानी : उत्तराखंड में मौसम मार्च में सावन का एहसास करा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है। हरिद्वार और देहरादून में जबरदस्त ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं, बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी का सिलसिला बना हुआ है। मौसम के मिजाज को देखते हुए केदारनाथ में पैदल मार्ग से बर्फ हटा रहे श्रमिकों को फिलहाल गौरीकुंड बुला लिया गया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार तक मौसम के मिजाज में कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है। हिमाचल में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बारिश जारी रही। लाहुल-स्पीति, सिरमौर व किन्नौर जिलों समेत प्रदेश के अन्य ऊंचे क्षेत्रों में दो से तीन फीट बर्फबारी हुई।

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग तीसरे दिन भी बंद, सैकड़ों वाहन फंसे : कश्मीर घाटी में श्रीनगर समेत अधिकतर हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश हुई। जवाहर टनल के अलावा पीरपंजाल की पहाड़ियों और गुलमर्ग व टंगमर्ग में बर्फबारी हुई। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार तीसरे दिन भी बंद रहा। बता दें कि 11 मार्च से जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश से हाईवे बंद है। रविवार को मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे सुचारु हो पाएगा।

वहीं, उत्तरकाशी जिले में भारी बर्फबारी के कारण हर्षिल के पास 30 लोग फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि इनमें से कुछ पर्यटक हैं।

राजाजी नेशनल पार्क के गेट दो दिन से बंद : दो दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण राजाजी नेशनल पार्क के गेट गुरुवार और शुक्रवार को बंद रहे। सैलानियों के पार्क में प्रवेश पर फिलहाल रोक लगी हुई है। चीला के रेंजर अनिल पैन्यूली ने बताया कि बारिश से ट्रैक प्रभावित हो सकते हैं।

अयोध्या, विंध्यवासिनी धाम व नैमिष के लिए भी तीर्थ विकास परिषद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▶ मथुरा-वृंदावन की तर्ज पर गठित होंगी परिषद

▶ अध्यादेश लाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार

मथुरा-वृंदावन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार अब अयोध्या, विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य के लिए भी तीर्थ विकास परिषद का गठन करने जा रही है। इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है। योगी सरकार मथुरा-वृंदावन के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कर चुकी है। मीरजापुर के विंध्यवासिनी धाम, सीतापुर के नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए भी मथुरा-वृंदावन की तर्ज पर तीर्थ विकास परिषद गठित किया जाएगा। इन तीनों तीर्थस्थलों के विकास के लिए तीर्थ विकास परिषदों के गठन की खातिर विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान ही विधेयक लाने का इरादा था। विधानमंडल सत्र में विधेयक न ला पाने के कारण सरकार अब इन तीर्थस्थलों में तीर्थ विकास परिषद के गठन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में जुटी है।

परिषद के गठन के बाद इन क्षेत्रों के विकास के लिए गठित विकास प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकारी का विलय तीर्थ विकास परिषद में हो जाएगा। तीर्थ विकास परिषद ही तीनों क्षेत्रों के विकास के लिए महायोजना तैयार करेगा। यह महायोजना एक तरह से संबंधित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए दीर्घकालिन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट होगी, जिसमें पर्यटन और तीर्थ विकास पर खास फोकस होगा। क्षेत्र के विकास की योजनाएं संचालित करने के लिए, शासन संबंधित क्षेत्र विकास परिषद को धनराशि मुहैया कराएगा।

विंध्यवासिनी मंदिर के चारों ओर बनेगा कॉरिडोर

वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर मीरजापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर के चारों ओर भी कॉरिडोर बनाने की योजना है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर की सीढ़ी संकरी है, जिस पर चढ़ने में बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुरानी सीढ़ी के बगल में एस्केलेटर स्थापित किया जाएगा। विंध्यवासिनी देवी मंदिर में चढ़ाये जाने वाले फूलों की रिसाइकिलिंग कर उससे इत्र और अगरबत्ती बनाई जाएगी।

विनय शर्मा ने अब दया याचिका खारिज करने में गिनाईं खामियां

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ निर्भया के गुनहगार ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका

निर्भया के दोषियों में शामिल विनय शर्मा ने नई पैंतरेबाजी करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने में प्रक्रियात्मक खामियां और संवैधानिक अनियमितताएं गिनाईं हैं। दलील दी गई है कि दया याचिका को खारिज करने के लिए राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिश में दिल्ली के गृह मंत्री सतेंद्र जैन के हस्ताक्षर नहीं थे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक फरवरी को विनय की दया याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में कहा गया है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया था, लेकिन तब केंद्र ने तर्क दिया था कि वाट्सएप पर जैन के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए थे। याचिका के मुताबिक दया याचिका दायर किए जाने के समय आचार संहिता लागू थी। चुनाव की घोषणा होने के साथ सतेंद्र जैन प्रत्याशी थे और वह बतौर गृहमंत्री अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे। लिहाजा दया याचिका को खारिज करने के लिए इस्तेमाल की गई शक्तियां गैरकानूनी, असंवैधानिक व चुनाव आयोग के संवैधानिक मूल्यों का हनन है। याचिकाकर्ता ने मांग की कि याचिका पर उचित कानूनी संज्ञान लें।

20 मार्च के लिए जारी है डेथ वारंट

गत पांच मार्च को निचली अदालत ने निर्भया के चारों दोषियों विनय, अक्षय कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह और पवन कुमार गुप्ता के खिलाफ 20 मार्च के लिए डेथ वारंट जारी किया है।

उमर-महबूबा जैसे नेताओं की रिहाई तक नहीं होगी कोई सियासी बातचीत

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

शुक्रवार को नजरबंदी से रिहा होने के बाद श्रीनगर स्थित आवास पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. फारूक अब्दुल्ला पत्नी मौली अब्दुल्ला (बाएं) और बेटी साफिया अब्दुल्ला के साथ। फारूक अब्दुल्ला के ऊपर से पीएसए हटा लिया गया है। एएनआइ

डॉ. फारूक ने जम्मू-कश्मीर की बदली प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्था के बीच आगे की राजनीति व ऑटोनामी जैसे मुद्दों से जुड़े सवाल टालते हुए कहा कि उमर और महबूबा जैसे नेताओं की रिहाई तक कोई सियासी बातचीत नहीं होगी। इस बारे में फैसला सभी नेताओं की रिहाई के बाद होगा। मैं सोमवार को संसद सत्र में हिस्सा लेने दिल्ली जाऊंगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज उठाऊंगा और हक की बात करुंगा।

मेरे पिता आजाद हैं : डॉ. फारूक अब्दुल्ला के रिहा होने पर उनकी बेटी साफिया अब्दुल्ला खान ने ट्विटर पर अपनी खुशी जताते हुए लिखा मेरे पिता एक बार फिर आजाद हैं।

इन नेताओं ने मोदी-शाह से किया था आग्रह : पांच दिन पूर्व राकंपा अध्यक्ष शरद पवार, तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी, माकपा प्रमुख सीता राम येचुरी समेत विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री को एक संयुक्त पत्र लिखकर जम्मू-कश्मीर के तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत प्रमुख राजनीतिक नेताओं की रिहाई का आग्रह किया था।

उमर-महबूबा की रिहाई की उम्मीद : डॉ. फारूक के पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अलावा पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत नौ नेता पीएसए के तहत बंदी हैं। डॉ. अब्दुल्ला की रिहाई के बाद इन नेताओं को पीएसए से मुक्त किए जाने की संभावना प्रबल हो गई है।

पांच अगस्त को लिया था एहतियातन हिरासत में : नेकां के अध्यक्ष, तीन बार के पूर्व मुख्यमंत्री और श्रीनगर के सांसद डॉ. फारूक अब्दुल्ला को पांच अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को लागू करने की घोषणा के मद्देनजर प्रशासन ने एहतियातन हिरासत में लिया था। सितंबर में उन्हें जन सुरक्षा अधिनियम के तहत बंदी बनाकर घर में ही कैद कर दिया था।

स्मार्ट सिटी रैंकिंग में आगरा अव्वल, अहमदाबाद को पछाड़ा

जासं, आगरा

स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में आगरा ने लंबी छलांग लगाई है। शुक्रवार को जारी मार्च की रैंकिंग में आगरा ने अहमदाबाद को पछाड़ दिया है। 13वें स्थान से नंबर एक पर पहुंच गया है। आगरा को 100 में 73.17 अंक मिले हैं। शहरी एवं आवास मंत्रालय हर महीने स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी करता है। पहली बार रिवाइज मानकों पर रैंकिंग जारी की गई। पूर्णांक 100 अंक है, जिसमें प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन पर 60 अंक, फंड ट्रांसफर में 14, फंड के उपयोग में 14, उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने में 12 अंक शामिल किए गए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट सिटी के अलावा अन्य किसी कार्य को शामिल नहीं किया जाएगा।

आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ अरुण प्रकाश ने बताया कि 19 में पांच प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं जिसमें माइक्रोस्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्वचलित शौचालय, स्मार्ट क्लासेस, नगर निगम इंटर कॉलेज का सुंदरीकरण व विस्तारीकरण, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को चालू करना शामिल है। इनमें आगरा को 100 में 73.17 अंक मिले हैं जबकि, अहमदाबाद के कुल 67.62 अंक हैं। बताया कि फरवरी में आगरा 13वें नंबर पर रहा और इससे पहले पांच माह तक लगातार 12वें नंबर पर रहा था। स्मार्ट सिटी पर कुल दो हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

देश के टॉप फाइव शहर

आगरा	73 .17 अंक
अहमदाबाद	67 .62 अंक
कानपुर	65 .98 अंक
इंदौर	60 .63 अंक
सूरत	58 .95 अंक

फिर लटका लोकायुक्त बिल, जस्टिस विनोद शर्मा की नियुक्ति पर संशय

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़ : भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए पंजाब में लाया जाने वाला लोकायुक्त का बिल एक बार फिर लटक गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार तीन साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन मजबूत लोकपाल बनाने का वादा पूरा करने की बजाय इसे लटकाया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस बिल को बजट सेशन में पेश किए जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन कानून बनाने के लिए जब इसे अंतिम समय में विधानसभा में पेश किया जाना था तो उसे पेश करने से रोक लिया गया। लोकायुक्त बिल के तहत नए लोकायुक्त की नियुक्ति पर सहमति न बन पाने के चलते सरकार ने इस बिल को विस में लाने को स्थगित कर दिया था।

सरकार में इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई है कि लोकायुक्त के पद पर वर्तमान लोकपाल जस्टिस विनोद कुमार शर्मा को ही नियुक्त किया जाए या इस पद के लिए किसी नए नाम की तलाश की जाए। गौरतलब है कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने लोकायुक्त बिल के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री सरकार के मंत्रियों और सार्वजनिक पदों पर बैठे सभी अधिकारियों को लोकायुक्त के तहत लाया गया है। मंत्रिमंडल की ओर से पारित पास किया गया पंजाब लोकायुक्त बिल 2020 राज्य में वर्तमान पंजाब लोकपाल बिल 1996 का स्थान लेगा।

कुलदीप सेंगर सहित सभी दोषियों को 10 साल की कैद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ पीड़िता के पिता की गैरइरादतन हत्या के मामले में हुई सजा

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की गैरइरादतन हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सात दोषियों को 10 साल कारावास की सजा दी गई। तीस हजारी अदालत के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर और उसके भाई अतुल पर 10-10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, जो उन्हें पीड़ित परिवार को तीन माह में देना होगा। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि मृतक के इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

शुक्रवार को सजा सुनाते वक्त जज ने कहा कि किसी परिवार के इकलौते रोजी-रोटी कमाने वाले की हत्या करने वालों पर कोई दया नहीं दिखा सकते। पिता को खोने वाले नाबालिग बच्चों और पीड़ित परिवार के बेघर होने को ध्यान में रखते हुए दोषियों को अधितकम सजा दी गई है। जज ने कहा कि एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया और सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद का काम कानून की रक्षा करना था, लेकिन इन्होंने खुद ही कानून को तोड़ा।

अदालत ने 4 मार्च को कुलदीप सेंगर, माखी थाने के तत्कालीन एसएचओ अशोक सिंह भदौरिया, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा, बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह और जयदीप सिंह उर्फ अतुल सेंगर को दोषी करार दिया था। आरोपपत्र में सीबीआइ ने कहा था कि 3 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता अपने एक सहयोगी के साथ काम से वापस घर लौट रहे थे। इस दौरान उन्होंने शशि प्रताप सिंह से लिफ्ट मांगी, लेकिन उसने इन्कार कर दिया। इस बीच बहस हो गई और शशि प्रताप ने कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सेंगर को फोन कर बुला लिया। अतुल अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर आया और पीड़िता के पिता, उनके सहयोगी के साथ बुरी तरह मारपीट की। इसके बाद उन्हें थाने में लेकर गए और फर्जी केस दर्ज करा दिया। वह सहयोगी इस मामले में चश्मदीद गवाह रहे।

गुरुवार को सेंगर ने कहा था कि अगर कुछ गलत किया है तो फांसी पर लटका दो और आंखों में तेजाब डाल दो। लेकिन शुक्रवार को जज के सजा सुनाए जाने पर कुलदीप सेंगर सहित अन्य दोषी रोने लगे। सेंगर निराश होकर कुर्सी पर बैठ गया। कोर्ट रूम के बाहर मौजूद दोषियों के परिजनों में से कुछ अंदर आ गए और रोने लगे।

पीठ दर्द के बाद अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में सुधार

मुंबई, प्रेट्र : मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की हालत पहले से काफी बेहतर है। अभिनेता गंभीर रूप से पीठ दर्द से पीड़ित थे। उनकी पत्नी और अभिनेत्री सायरा बानू ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

दिलीप कुमार के अधिकृत ट्विटर पेज पर एक आडियो नोट शेयर किया गया है। इसमें सायरा बानू ने कहा है कि हम लोगों ने लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों से संपर्क किया था। अब सबकुछ बेहतर है। सायरा ने कहा, 'मैं आप सभी को यह बताते हुए खुश हूं कि दिलीप साहब काफी बेहतर हैं। उन्हें पीठ दर्द था और हम लीलावती अस्पताल में जांच कराने गए थे। जांच की गई और हम घर वापस आ गए। भगवान की दया और आप सभी की शुभकामनाओं से अब सबकुछ बेहतर है।'

दिलीप कुमार के पारिवारिक मित्र फैसल फारूकी ने भी ट्विटर पर उनके प्रशंसकों को स्वास्थ्य की स्थिति बताई है। उन्होंने ट्वीट किया, 'दिलीप साहब की हालत में सुधार है। कृपया अफवाह नहीं फैलाएं।'

बॉलीवुड के ट्रेजडी किंग कहे जाने वाले 97 अभिनेता वर्षीय दिलीप कुमार ने अंदाज, आन, देवदास और मुगल-ए-आजम जैसी अनेक फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी है। उनके शानदार अभिनय को भारतीय सिनेमा में मिसाल के तौर पर देखा जाता है।

कश्मीर में मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ आठ दिन पहले ही बना था आतंकी, सात मिनट में किया ढेर

▶ साथी फरार, गांदरबल में भी चलाया गया तलाशी अभियान

▶ 10 दिनों में लापता हुए पांच लड़कों में से एक है मारा गया आतंकी

उत्तरी कश्मीर के शुटलु रफियाबाद में सुरक्षाबलों ने शुक्रवार को सात मिनट की मुठभेड़ में आठ दिन पुराने आतंकी को ढेर कर दिया गया। फिलहाल, उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। मारा गया आतंकी बारामुला जिले से बीते 10 दिनों में लापता हुए पांच लड़कों में से एक है। उसके परिजनों ने कुछ दिन पहले ही पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बीच, सुरक्षाबलों ने गांदरबल के परिबल और चुनदना इलाके में आतंकियों के छिपे होने पर तलाशी अभियान चलाया भी चलाया।

पुलिस को पता चला था कि सोपोर से सटे रफियाबाद में तीन से चार आतंकी हैं। यह आतंकी शुटलू में किसी से मिलने वाले हैं। इसके बाद पुलिस के विशेष अभियान और सेना की 32 आरआर ने शुटलू की तरफ आने जाने वाले विभिन्न रास्तों पर नाके लगाए। एक नाके पर तैनात जवानों ने तीन संदिग्धों को देख उन्हें रुकने का संकेत किया। इन युवकों ने नाका तोड़ भागने का प्रयास करते हुए जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब सात मिनट बाद आतंकियों की तरफ से गोलियों की आवाज पूरी तरह बंद हो गई। जवानों ने तलाशी ली तो उन्हें वहां गोलियों से छलनी आतंकी का शव मिला। अन्य आतंकी वहां से बच निकले।

मारा गया आतंकी मुदस्सर अहमद बट है। वह शुटलु गांव का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार, वह जिला बारामुला के विभिन्न हिस्सों में गत 10 दिनों के दौरान लापता हुए पांच युवकों में शामिल था। वह लापता होने के बाद ही आतंकियों से जा मिला था। उसके साथ लापता हुए अन्य चार युवकों फैयाज अहमद वार, गुलाम मोहिउद्दीन पर्रे, वलीद अहमद मीर और अनायतुल्ला मीर के भी आतंकियों से जा मिलने की आशंका है। इस बीच, शुक्रवार की सुबह गांदरबल के चुनदना-परिबल में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान चलाया। हालांकि आतंकियों का सुराग नहीं मिलने पर तीन घंटे बाद घेराबंदी हटा ली गई। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए सुरक्षाबल विशेष सतर्कता बरत रहे हैं।

लखनऊ में उपद्रव के 27 आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई

जासं, लखनऊ : सीएए और एनआरसी के विरोध की आड़ में लखनऊ में हिंसा फैलाने के मामले में पुलिस ने आरोपितों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एडीसीपी पश्चिम विकास चंद्र त्रिपाठी के मुताबिक, उपद्रव के 27 आरोपितों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। इनमें कई आरोपित नामजद हैं, जबकि कुछ के नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आए थे।

19 दिसंबर को गैंग लीडर मोहम्मद ताहिर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस चौकी सतखंडा, फारुखी मस्जिद कासिम अली पुलिया और हुसैनाबाद समेत अन्य सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ की थी। इस दौरान लूटपाट और आगजनी कर पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए चौकी में आग लगा दी थी। मामले में पुलिस ने ठाकुरगंज थाने में एफआइआर दर्ज की थी।

ये लोग हैं शामिल : आरोपितों में मोहम्मद ताहिर, गुड्डू, युसूफ, नदीम, हसन, तारिक, अनस, खलीक, मोहसिन, इमरान, असलम, इकलाख, मोहम्मद आलम, साहिल, अली तारिक, मोहम्मद बिलाल, इरशाद, इमरान, नयाब, अयाज अली, मोहम्मद सलमान, अल्लू, मुख्तार, अब्दुल बसर, इरशाद, रेहान और मोहम्मद अनस शामिल हैं। सभी आरोपितों के खिलाफ कुल तीन मुकदमे दर्ज हैं।

बागपत की धरती से फिर मिले पुरावशेष

बर्तन को आकार देने वाला मिट्टी का ठप्पा। जागरण

मृण प्रतिमा। जागरण

जासं, बागपत : पुरातात्विक दृष्टि से समृद्ध बागपत की माटी ने एक बार फिर हजारों साल पुराना इतिहास उगला है। बड़का गांव में खेत से मृण मूर्ति (मिट्टी की मूर्ति) का एक चेहरा, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और ठप्पा प्राप्त हुआ है। इतिहासविदों का दावा है कि ये वस्तुएं 1500 साल पूर्व के गुप्तकाल से संबंधित हैं। बड़का गांव में एक किसान के खेत की ऊपरी सतह पर शुक्रवार दोपहर बर्तनों को आकृति देने वाला मिट्टी का ठप्पा, मृणमूर्ति का करीब दो इंच लंबा-चौड़ा कलात्मक चेहरा व अन्य पुरावशेष मिले। शहजाद राय शोध संस्थान के निदेशक डॉ. अमित राय जैन ने मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया और इनके गुप्तकाल से संबंधित होने की पुष्टि की।

मृणमूर्ति के संबंध में डॉ. अमित कहते हैं कि गुप्त काल के लोग खेलने या घरों को सजाने के लिए मृण मूर्तियों का निर्माण करते थे। उस समय यह कला अत्यंत विकसित हो चुकी थी। उस काल के लोगों ने मृण मूर्तियों में पगड़ी के साथ-साथ मांसल चेहरा व आंखों की कलात्मकता पर विशेष जोर दिया। इससे पहले भी इस गांव से महाभारतकालीन चित्रित धूसर मृदभांड, कुषाण और गुप्त काल के अवशेष प्राप्त हो चुके हैं। डॉ. जैन ने बताया कि प्राप्त हुए अवशेषों की सूची भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेजकर यहां पुरातात्विक उत्खनन कराने की मांग की जाएगी।

पाक सेना की पुंछ के मनकोट सेक्टर में की भारी गोलाबारी

जासं, पुंछ : नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार पाक सेना के साथ आतंकियों का भी जमावड़ा है। जिन्हें भारतीय क्षेत्र में धकेलने की साजिशें हो रही हैं। जम्मू संभाग के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में पाक सेना ने शुक्रवार दोपहर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। गोलाबारी की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराने के प्रयास को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना के करारे जवाब के बाद भी पाक की ओर से गोलाबारी जारी थी।

दोपहर करीब तीन बजे पाक सेना ने मनकोट सेक्टर में सेना की अग्रिम चौकियों के अलावा रिहायशी क्षेत्रों में मोर्टार शेल और दूसरे हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी। पाक सेना की गोलाबारी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद भी पाक सेना रुक-रुक कर भारतीय क्षेत्र में गोलाबारी को जारी रखे हुए है। सूत्रों के अनुसार, गोलाबारी की आड़ में पाक सेना आतंकवादियों के दल को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने का प्रयास कर रही थी। आतंकी कई गुट में बंटे थे। भारतीय सेना के आला अधिकारी पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 समाप्ति के करीब साढ़े सात माह से पाक सेना लगातार राजौरी से लेकर पुंछ तक भारी गोलाबारी कर रही है।

15 लाख के इनामी तीन नक्सलियों ने किया समर्पण

नईदुनिया, सुकमा : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 15 लाख के इनामी नक्सलियों ने एसपी शलभ सिन्हा और सीआरपीएफ 226वीं बटालियन के अधिकारियों समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें एक दंपती है, जिनमें पुरुष करटामी बादल आठ लाख का इनामी और महिला कमली पांच लाख रुपये की इनामी है। इनके अलावा दो लाख रुपये के इनामी नक्सली मड़कम बीजू ने भी नक्सलियों का साथ छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि सभी नक्सलियों के खिलाफ इलाके के कई थानों में संगीन अपराध दर्ज हैं।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
बीओ: कौशाम्बी, गाजियाबाद
कब्जा सूचना [नियम 8 (1)]
जबकि, पंजाब नेशनल बैंक, बीओ : कौशाम्बी, गाजियाबाद के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद "उक्त एक्ट के रूप में ज्ञात") के अंतर्गत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 की नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में निम्नलिखित कर्जदारों श्री रमन नागपाल एवं श्रीमती ललिता नागपाल (खाता सं. 300000NC00005720 & 3000009900000847) को दिनांक 24.12.2019 को मांग सूचना जारी किया जिसमें कहा गया कि उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (12) के अंतर्गत उक्त सूचना मिलने की तिथि से 60 दिन के भीतर जब तक पूर्ण भुगतान नहीं होता है आगे ब्याज के साथ सूचना में वर्णित राशि रु. 27,50,954.18/-(रु. सत्ताइस लाख पचास हजार नौ सौ चौवन एवं अट्ठारह पैसे मात्र) (दिनांक 28.11.2019 को) का भुगतान करने के लिए कहा गया।
कर्जदार राशि का भुगतान करने में विफल रहे। एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटीकर्ता/पार्टियों एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि 12 मार्च 2020 को उक्त नियमावली की नियम 8 के साथ पठित उपरोक्त एक्ट की धारा 13(4) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से, कर्जदार/गारंटीकर्ता/पार्टियों एवं जनसाधारण को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि इस प्रापर्टी का कोई डीलिंग (लेनदेन) नहीं करें एवं उक्त संपत्ति का डीलिंग पूर्ण भुगतान होने तक उस पर आगे ब्याज के साथ रु. 27,50,954.18/-(रु. सत्ताइस लाख पचास हजार नौ सौ चौवन एवं अट्ठारह पैसे मात्र) (दिनांक 28.11.2019 को) सूचना में वर्णित राशि के लिए पंजाब नेशनल बैंक के प्रभार में होगा।
अचल सम्पत्तियों के विवरण
ईएम : आवासीय फ्लैट नं. एफ/डी 28, भूतल, निकट लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, कवि नगर, गाजियाबाद, यू.पी. 201002 में स्थित आईपी की ईएम
दिनांक : 12.03.2020, स्थान : गाजियाबाद
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

दैनिक जागरण

कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है

अफरा-तफरी न फैलने पाए

कोरोना वायरस से उपजी खतरनाक बीमारी कोविड-19 के महामारी का रूप ले लेने के बाद दुनिया भर में अफरा-तफरी का जो माहौल बन रहा है उसे रोकने की उतनी ही जरूरत है जितनी इस रोग के प्रसार को। यह विचित्र है कि एक ओर बार-बार यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं और दूसरी ओर ऐसे काम भी किए जा रहे हैं जिससे दहशत का माहौल बन रहा है। निःसंदेह लोगों को भीड़-भाड़ से बचने और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों से दूर रहने के लिए अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन इसके नाम पर ऐसा भी माहौल नहीं बनाया जाना चाहिए कि हर कोई खुद को घर में कैद कर ले। इससे न केवल जनजीवन ठप हो जाएगा, बल्कि अन्य दूसरी समस्याएं भी पैदा हो जाएंगी। बेहतर होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन उन तौर-तरीकों को रोकने के लिए सक्रिय हो जो जाने-अनजाने अफरा-तफरी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसे इसका संज्ञान लेना ही चाहिए कि आखिर अमेरिकी प्रशासन ने विदेशी छात्रों को अपने-अपने देश लौट जाने का निर्देश क्यों दिया? यदि अमेरिका सरीखा विकसित और हर मायने में सक्षम देश इस तरह के कदम उठाएगा तो इससे दुनिया में घबराहट ही फैलेगी। उसने अपने यहां पढ़ाई कर रहे लाखों विदेशी छात्रों में न केवल घबराहट पैदा करने, बल्कि उन्हें मुसीबत में डालने का ही काम किया है।

अपने देश में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ जाने से सतर्कता बढ़ाने की जरूरत बढ़ गई है। यह अच्छी बात है कि इस सतर्कता का परिचय भी दिया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य सरकारों को सावधानी बरतने के नाम पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं? यह नहीं होना चाहिए कि हर राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसले ले। उनके फैसलों में एकरूपता दिखनी चाहिए। ये फैसले ऐसे होने चाहिए जो हालात को नियंत्रित करने का तो काम करें, लेकिन आम लोगों में खौफ न पैदा करें। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उन राज्यों को भी स्कूल-कॉलेज बंद करने चाहिए जहां कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है? उचित यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस वायरस के संक्रमण को रोकने की रणनीति को लेकर एकजुटता का परिचय दें। चूंकि कोविड-19 का सीधा उपचार उपलब्ध नहीं इसलिए पूरी दुनिया की सेहत के लिए उपजा संकट गंभीर रूप ले रहा है, लेकिन इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि उसकी चपेट में आए लोग ठीक भी हो जा रहे हैं। इनमें भारतीय भी हैं।

रोशनी घोटाला

रोशनी एक्ट के तहत हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा कोर्ट में जवाब न दिए जाने पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कितनी बड़ी विडंबना है कि कोर्ट ने अधिकारियों को 20 फरवरी को निर्देश दिए थे कि वह बताएं कि रोशनी एक्ट की आड़ में शहरी, ग्रामीण और वन विभाग की कितनी भूमि पर कब्जा हुआ है, लेकिन विगत दिवस मामले की सुनवाई के दौरान यह अधिकारी कोर्ट के निर्देश पर ब्योरा नहीं दे पाए। रोशनी एक्ट की आड़ में कई पूर्व मंत्रियों, नौकरशाहों और बाहुबलियों ने कोड़ियों के भाव जमीन अपने नाम करा ली। इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस और पीडीपी सरकार ने सरकारी जमीन नेताओं और बाहुबलियों को आवंटित कर दी थी। हाईकोर्ट के लगातार दवाब में राजस्व विभाग ने रोशनी एक्ट के लाभार्थियों की जो सूची अभी तक डिवीजन बेंच के सामने पेश की है उसमें जम्मू संभाग के 25 हजार एवं कश्मीर के 45 हजार लोग शामिल हैं। जिन्होंने पहले सरकारी जमीन पर कब्जा किया और बाद में चंद रुपये देकर मालिक बन बैठे। पच्चीस हजार करोड़ रुपये के रोशनी अधिनियम घोटाले में कई पूर्व मंत्रियों, राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों पर सरकारी जमीन को हथियाने के लिए नियमों को ताक पर रखने के आरोप हैं। वर्ष 2001 में तत्कालीन सरकार ने जम्मू-कश्मीर स्टेट लैंड (रहने वालों को मालिक बनाने) अधिनियम को मंजूरी दी थी। इसे रोशनी अधिनियम का नाम दिया गया। विडंबना है कि सरकारी (नजूल) जमीनों पर रहने वाले लोगों से बाजार के भाव वसूल कर उन्हें जमीन का मालिकाना अधिकार मिल गया। सरकार ने इससे 25 हजार करोड़ रुपये का भारी भरकम राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा और यह तय किया गया कि इस राशि से राज्य में बिजली ढांचे को विकसित किया जाएगा। जिससे लोगों को बिजली मिलने में आसानी होगी। लेकिन सरकार तय लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। दुखद है कि कई राजनेताओं और नौकरशाहों ने सरकारी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कई हजार कनाल भूमि पर कब्जे की शिकायतें सरकार के समक्ष आने लगीं। यह सही है कि मामले की जांच पहले से हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि जांच वर्षों बाद भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। अधिकारियों को चाहिए कि वे कोर्ट के निर्देश का पालन और कोर्ट को सही जानकारी उपलब्ध कराएं।

संकुचित होता सार्वजनिक विमर्श

बैजयंत जय पांडा

अफसोस की बात है कि विभाजन की खाई ने 'परिपक्व' नेताओं, पत्रकारों और अन्य शख्सियतों को भी शिकंजे में ले लिया है

अवधेश राजपूत

फरवरी का अंतिम सप्ताह राजधानी दिल्ली में दो परस्पर विरोधी तस्वीरों का गवाह बना। एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुले दिल से स्वागत हो रहा था तो दूसरी ओर दिल्ली के कुछ इलाकों से हिंसा की हृदयविदारक तस्वीरें सामने आ रही थीं। शहर अभी तक इन दंगों के दाग नहीं धो पाया है। इनमें करीब 50 लोगों की जान चली गई। तमाम घायल अभी भी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। इस पर शायद ही किसी को हैरानी हो कि दिल्ली में ये दंगे 24 फरवरी को ही भड़के जिस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति का यहां आगमन हुआ। वैसे तो पिछले दो महीनों से टकराव के छिटपुट मामले देखने को मिले थे, लेकिन इन दंगों की टाइमिंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो, परिपक्वता का तकाजा यही कहता है कि ऐसे तल्ख समय में शांति एवं सद्भाव का ही परिचय दिया जाता, पर हमारा राजनीतिक वर्ग खास तौर से विपक्षी दल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों की मजबूरियों को समझे बिना ही उनकी कड़ी आलोचना करने लगे। इन आलोचकों ने उन मुश्किल परिस्थितियों को अनदेखा किया जिनके तहत पुलिस लगातार शांति कायम करने के प्रयासों में जुटी थी। वास्तव में सुरक्षा बल और पुलिस हमेशा निशाने पर होते हैं। वे प्रदर्शनकारियों के पत्थर खाते हैं। तेजाबी हमले झेलते हैं। गोलियों का निशाना बनते हैं। इसके बावजूद उनकी प्रतिष्ठा तार-तार की जाती है।

पूरे देश ने देखा कि जामिया मिल्लिया में पत्थरबाजों से निपटने में सुरक्षा बलों को कितनी आलोचना सहनी पड़ी। जेएनयू मामले में अराजक तत्वों से निपटने में भी उनके लिए कमोबेश यही स्थितियां रहीं। सुरक्षा बल भले ही सक्रियता दिखाएं या फिर टकराव टालने के मकसद से संयत रहें, लेकिन उन्हें हर हाल में निशाना बनाया जाता है। उन पर जो हमले होते हैं उससे शारीरिक एवं मानसिक आघात उनके लिए स्थितियां और खराब करता है। कभी-कभार बिगड़े हालात से जान पर भी बन आती है जैसा कि हेड कांस्टेबल रतन लाल के साथ हुआ जो ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए।

इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं की सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई गंभीर कदम उठाने को लेकर एहतियात बरती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली प्राथमिकता कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने की होनी चाहिए। दूसरी ओर शाहीन बाग के मसले पर शीर्ष अदालत ने अस्पष्ट रवैया ही अपनाया। वह भी तब जब सीएए के विरोध में वहां तीन महीनों से जारी विरोध-प्रदर्शन के चलते सड़क जाम से लाखों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना जरूर कहा कि प्रदर्शनकारियों को धरना देने का अधिकार है, लेकिन वे शहर की मुख्य सड़कों को अवरुद्ध कर लोगों की तकलीफ नहीं बढ़ा सकते। उसने इस गतिरोध को दूर करने के लिए वार्ताकार भी नियुक्त किए जो प्रदर्शनकारियों के साथ वार्ता में लगे हैं। एक मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्टिविस्ट को लताड़ भी लगाई कि अव्वल तो उनका शीर्ष न्यायपालिका में भरोसा नहीं और ऊपर से वह अपने भड़काऊ बयानों से लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाते हैं और फिर अदालत में गुहार लगाते हैं कि वह अन्य नेताओं के बयानों के लिए उन पर एफआइआर कराने का आदेश दे।

सार्वजनिक विमर्श की धारा बहुत ध्रुवीकृत हो गई है। लोग 'हम बनाम वे' की बहस में उलझे हैं। विभाजनकारी विमर्श ने दुनिया भर में वाम, दक्षिण और मध्यमार्गी विचारधाराओं को अपनी चपेट में ले चुका है। यहां तक कि जिस मीडिया पर तार्किक रूप से बिना किसी पक्षपात के तथ्यों को सामने रखने का जिम्मा है वह भी इससे अछूता नहीं। शाहीन बाग में रिपोर्टिंग के दौरान कुछ मीडियाकर्मियों के साथ हाथापाई हुई तो मीडिया के सभी वर्गों ने इसकी एक स्वर में आलोचना नहीं की। पूर्वाग्रह स्पष्ट दिखा। मीडिया को इस तरह प्रताड़ित करने का यह सिलसिला आम हो गया है। इसमें सुविधाजनक विरोध का रवैया भी दिखता है कि जब 'अपनों' पर हमला हो तब उसका विरोध करते हैं, लेकिन 'दूसरों' के साथ दुर्व्यवहार से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

अफसोस की बात है कि इस विभाजन की खाई ने 'परिपक्व' नेताओं, पत्रकारों और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी शख्सियतों को भी शिकंजे में ले लिया है। वे राष्ट्रपति ट्रंप के ऐतिहासिक दौरे की पूरी कटुता के साथ आलोचना में जुटे रहे जबकि इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों एवं साझेदारी में अप्रत्याशित रूप से सुधार हुआ। यह बहुत ही विचित्र है कि कोई व्यक्ति मोदी और ट्रंप के बीच शानदार तालमेल पर बेवजह नाक-भौं सिकोड़े जबकि हकीकत यह है कि ऐसे रिश्तों से देश और व्यापक भू-राजनीतिक हितों को बहुत लाभ होता है।

कुल मिलाकर यह स्पष्ट दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद, लगातार चुनावी सफलता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती उनकी लोकप्रियता से कुपित कुछ लोग किसी भी कीमत पर उनका विरोध करना चाहते हैं। उन्हें न तो सिद्धांतों का लिहाज है और न ही इसके नतीजों की परवाह। सीएए जैसे मानवीय कानून के बेजा विरोध में भी यही झलकता है। सीएए के तमाम विरोधियों ने निजी बातचीत में कई अवसरों पर खुद स्वीकार किया कि यह किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव नहीं करता और इससे किसी भारतीय की नागरिकता के लिए कोई खतरा भी नहीं। कुछ लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस यानी एनआरसी पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं कि खुद प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि अभी तक एनआरसी की कोई योजना नहीं। आलोचकों को इसके विरोध और इसे मुद्दा बनाने का अधिकार है, पर तभी जब इसका कोई आधिकारिक स्वरूप सामने आए।

तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों ने जानबूझकर मुस्लिमों को बरगलाने का काम किया कि इससे उनकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा डर एकदम निराधार है। हर किसी को असहमति का अधिकार है, लेकिन इसकी आड़ में कोई सार्वजनिक-निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, रास्ते रोककर या आम लोगों को प्रताड़ित कर कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। एक ऐसे दौर में जब हम महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं तब यह दर्शाने की जरूरत है कि हम सिद्धांतों के लिए कितने समर्पित हैं न कि यह जताने के लिए कि विरोध के नाम पर कैसा भी विरोध कर सकते हैं।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

चीन की लापरवाही से संकट में दुनिया

रमेश कुमार दुबे

चीन का असंगठित-अवैध वन्य जीव कारोबार ही कोरोना वायरस के जरिये दुनिया पर कहर बरपा रहा है

तमाम कोशिशों के बावजूद चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो इससे पीड़ित लोगों की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर गई है। तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं वाले यूरोप-अमेरिका में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर के वन्य जीवों के मांस बेचने वाले एक बाजार से हुई। चीन में पहले भी इस तरह के खतरनाक वायरस उपज चुके हैं। इनमें सार्स प्रमुख है। पिछले 50 वर्षों में संक्रमण से होने वाली बीमारियां तेजी से फैली हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि आम तौर पर पशु-पक्षियों को होने वाली बीमारियां मनुष्यों को अपनी चपेट में लेती जा रही हैं। पशु-पक्षियों से मनुष्यों में संक्रमण कोई नई बात नहीं, लेकिन जलवायु परिवर्तन और खान-पान संबंधी आदतों में बदलाव, शहरीकरण, अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के बढ़ते प्रचलन के कारण संक्रमण तेजी से फैलने लगा है। पूरी दुनिया में शहरी आबादी तेजी से फैल रही है। पचास साल पहले जहां 35 फीसद आबादी शहरों में रह रही थी वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 55 फीसद तक पहुंच चुका है। अधिकांश शहरों का विकास अनियोजित ढंग से हो रहा है। इन शहरों में गंदी बस्तियों की भरमार है जो बीमारियां के लिए उर्वर जमीन मुहैया कराती हैं। शहर आसपास की कृषि भूमि, जंगल आदि की कीमत पर फल-फूल रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लोमड़ी, बंदर, भालू जैसे वन्य जीवों का शहरों में अतिक्रमण बढ़ा है। इससे पशुओं से मनुष्यों में होने वाला संक्रमण बढ़ रहा है और नई-नवेली बीमारियां पैदा होने लगी हैं। सार्स, स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां इसी संक्रमण की देन हैं।

शहरीकरण, मध्य वर्ग का विस्तार, बढ़ती समृद्धि, आधुनिक संचार माध्यम जैसे कारणों से खान-पान की आदतें तेजी से बदल रही हैं। यहां चीन का उदाहरण प्रासंगिक है। कभी सुअर का मांस चीन के संभ्रांत वर्ग को ही नसीब होता था, लेकिन आज चीन का गरीब आदमी भी सुअर का मांस खाने लगा है। चीन ही नहीं पूरी दुनिया में मांसाहार और विदेशी खाद्य पदार्थों को स्टेटस सिंबल से जोड़ देने के कारण उनकी खपत तेजी से बढ़ रही है। मांसाहार के बढ़ते प्रचलन का कारण मशीन आधारित पशुपालन है जिसमें बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन होता है और वह सस्ता पड़ता है, लेकिन इस सस्ते मांस ने प्रकृति और मनुष्य से भारी कीमत वसूल की है। इसमें छोटी सी जगह में हजारों पशुओं को एक साथ पाला जाता है और पशुओं को परंपरागत चारे के बजाय अनाज, तिलहन, मांस खिलाया जाता है, ताकि जल्द से जल्द उनसे अधिकाधिक मांस प्राप्त किया जा सके। पशु आहार के लिए दुनिया भर में जंगलों को काटकर मक्का एवं सोयाबीन की खेती की जा रही है जिससे जैव विविधता संकट में पड़ती जा रही है। स्पष्ट है शहरीकरण, मांसाहार, वनों का विनाश, आधुनिक जीवन शैली ये सभी मिलकर जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे समूचा पारिस्थितिकीय तंत्र संकट में पड़ता जा रहा है।

उदारीकरण के दौर में सस्ता बेचो नीति के कारण चीन में समृद्धि आई और मध्य वर्ग का तेजी से विस्तार हुआ। इस विशालकाय मध्य वर्ग की खान-पान की आदतें भी अलग ढंग की रहीं, लेकिन चीन का मांस-मछली बाजार आधुनिक नहीं बना। चीन की संकरी गलियों में जिंदा मुर्गी से लेकर सांप, चूहे, चमगादड़ तक बिकने लगे। चीन के नव धनाढ्य वर्ग ने वन्य जीवों को अपने आहार का अहम अंग बना लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया भर में प्रतिबंधित वन्य जीव चीन के इन असंगठित बाजारों में बिकने लगे। चूंकि वन्य जीवों के कारोबार में भारी मुनाफा था इसलिए चीन से वन्य जीवों का वैध-अवैध कारोबार पूरी दुनिया में तेजी से फैला। चीन ने भारी मुनाफे को देखते हुए प्रतिबंधों की अनदेखी कर वन्य जीवों के गैर-कानूनी कारोबार को बढ़ावा दिया। इसका दुष्परिणाम वर्ष 2003 में आया जब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सार्स नामक बीमारी तेजी से फैली। इस महामारी ने मात्र छह महीने में ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को 40 अरब डॉलर की चपत लगाई। उसी समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी थी कि यदि वन्य जीवों की खरीद-बिक्री पर रोक और खान-पान संबंधी आदतों में बदलाव नहीं लाया गया तब इस तरह के वायरस दोबारा पैदा हो सकते हैं। इसे देखते हुए चीन की सरकार ने गली-कूचों में चल रहे मांस-मछली और वन्य जीवों के अवैध कारोबार को कुछ समय के लिए नियंत्रित तो किया, लेकिन जैसे ही सार्स का प्रकोप खत्म हुआ सब कुछ पहले की तरह चलने लगा। दुनिया को इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि चीन का यही असंगठित-अवैध वन्य जीव कारोबार अब कोरोना वायरस के जरिये पूरी दुनिया पर कहर बरपा रहा है। चीन ने दुनिया को जिस तरह संकट में डाला उसका विश्व समुदाय और खासकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से संज्ञान लिया जाना चाहिए। कोविड 19 को केवल महामारी घोषित करने से बात बनने वाली नहीं है।

निःसंदेह आज नहीं तो कल दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पा लेगी, लेकिन ऐसी महामारी फिर से न उभरे, इसके लिए ठोस जमीनी उपाय करने होंगे। इसमें सबसे जरूरी है शहरीकरण, मांसाहार और आधुनिक जीवन शैली में सामंजस्य बैठाना। इसी के साथ यह भी जरूरी है कि स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने पर जोर दिया जाए और उसे संचारी रोगों से बचाव के लिए समर्थ बनाया जाए। भारत और इस जैसे देशों को अपने स्वास्थ्य ढांचे को सक्षम बनाने का काम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए।

(लेखक केंद्रीय सचिवालय सेवा में अधिकारी हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रयास

यदि आप किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने प्रयासों में स्थायित्व अथवा दृढ़ता लानी होगी। यदि आप अपने ध्येय पर, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, निरंतर लगे रहते हैं तो अंततः आप सफल होते हैं। पानी के एक-एक बूंद में कितनी ताकत रही होगी जो उसने उस भारी पत्थर में भी गड्ढा कर दिया, बेशक इसमें समय लगा।

दरअसल किसी काम को लंबे समय तक करते रहने से मनुष्य उसमें निपुण हो जाता है और उसी निपुणता में छिपे हैं निर्माण, नवाचार और आविष्कार के बीज। अब यदि आप में किसी नई चीज के निर्माण की क्षमता आ जाए तो सफलता मिलनी ही है। थॉमस अल्वा एडिसन के नाम 1093 पेटेंट हैं, लेकिन उनकी ये उपलब्धियां कभी आसान नहीं रहीं। एडिसन बल्ब बनाने में दस हजार से अधिक बार असफल रहे, लेकिन रुके नहीं। अपनी असफलताओं पर उनका कहना था कि वह कभी नाकाम नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दस हजार उन रास्तों के बारे में जाना जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि सफलता पाने के मार्ग में आपको आरंभिक असफलताओं अथवा गलतियों से घबराना नहीं चाहिए। आपको बस इतना करना है कि अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना है, अपने संघर्षों को विराम नहीं देना है। एक बात और, जब हम संघर्षों और प्रयासों की बात कर रहे हैं तो यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसे आप कभी भी, जीवन के किसी भी पड़ाव पर शुरू कर सकते हैं।

श्री प्रभुपाद स्वामी का जीवन इसका शानदार उदाहरण है, जिन्होंने 69 वर्ष की अवस्था में अमेरिका जाकर कृष्ण भक्ति के प्रचार-प्रसार का निश्चय किया। वहां उन्होंने इस्कॉन नामक संस्था की स्थापना की, जो अगले एक दशक में ही विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था बन गई। तो कोई भी कार्य तभी तक कठिन है, जब तक आप उसे अपनी लगन और मेहनत से आसान नहीं बना लेते।

चंदन कर्ण

लक्जमबर्ग की अनोखी पहल

सुधीर कुमार

देश में एक समय कुल वाहनों में सार्वजनिक बसों की हिस्सेदारी 15 फीसद थी, जो अब घटकर एक फीसद पर आ गई है

सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के प्रति अपने नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक छोटे से यूरोपीय देश लक्जमबर्ग द्वारा की गई एक अनोखी पहल ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दरअसल सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क करने वाला लक्जमबर्ग दुनिया का पहला देश बन गया है। वहां के नागरिक अब टिकट लिए बिना ट्रेन, ट्राम और बस के जरिये देश के भीतर आवाजाही कर सकेंगे। इस तरह वहां का प्रत्येक नागरिक सालभर में 400 यूरो यानी तकरीबन 33 हजार रुपये तक की बचत कर सकता है!

हाल ही में प्रधानमंत्री जेवियर बेटल ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए इसकी घोषणा की। सार्वजनिक परिवहन को किराया रहित बनाने का उद्देश्य सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ को कम करना, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या को 20 फीसद तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। जब लोग अपने निजी वाहनों से इतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता देंगे तो इससे वायुमंडल में जहरीली गैसों के फैलने की प्रकिया भी धीमी होगी। लक्जमबर्ग में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन का आधा हिस्सा केवल गाड़ियों के धुएं से आता है। 2018 के एक सर्वे के मुताबिक वहां सार्वजनिक बसों और ट्रेनों का इस्तेमाल क्रमशः 32 और 19 फीसद ही होता है। शेष 49 फीसद लोग दफ्तर या अन्य जगह आने-जाने के लिए अपनी निजी वाहन का ही इस्तेमाल करते हैं। यूरोपीय यूनियन के सदस्य देशों में प्रति हजार व्यक्तियों में कारों की संख्या लक्जमबर्ग में ही सर्वाधिक है। वहां हर दूसरे व्यक्ति के पास अपनी कार है। दरअसल जीडीपी का सवा तीन फीसद अंश सार्वजनिक परिवहन में खर्च करने के बावजूद वहां की सड़कें निजी गाड़ियों से ही आच्छादित रहती हैं। जिससे वहां ट्रैफिक और वायु-ध्वनि प्रदूषण की समस्या आम हो चुकी है। यह निर्णय सड़कों पर निजी वाहनों की भीड़ कम करने, सुव्यवस्थित परिवहन को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कारगर कदम साबित हो सकता है!

भारत में उदारीकरण के बाद निजी साधनों की संख्या में तीव्रतर वृद्धि हुई है, जिससे यहां ट्रैफिक और वायु प्रदूषण की समस्या विद्यमान रहती है। यहां हर व्यक्ति यथाशक्ति निजी वाहन रखने को आमदा है। देश में एक समय कुल वाहनों में सार्वजनिक बसों की हिस्सेदारी 15 फीसद थी, जो अब घटकर एक फीसद पर आ गई है! यह चिंता की बात है। राजस्थान का यातायात विभाग महीने के पहले कार्य दिवस को नो व्हीकल डे के रूप में मनाता है। इस दिन सभी स्तर के कर्मचारी पैदल, साइकिल या सार्वजनिक वाहनों के जरिये कार्यालय पहुंचते हैं। यह पहल अन्य संस्थाओं के लिए भी अनुकरणीय है।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

सीएए विरोध की ओट में गहराती साजिश

अवधेश कुमार ने अपने आलेख सिर उठातीं देश विरोधी शक्तियां में जिस राष्ट्रघाती साजिश का उल्लेख किया है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। इतने पर भी यदि विपक्षी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए दिल्ली दंगों के आरोपियों को निर्दोष बता कर उनका बचाव कर रहे हैं तो यह माना जा सकता है कि इस देश में अब राजनीतिक स्वार्थ देशहित से ऊपर हो गया है। दिल्ली दंगों की जांच में जिस तरह से पीएफआइ और आइएस की साजिश का खुलासा हो रहा है और इस साजिश से जुड़े आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं वह देश के लिए चिंताजनक है। अब इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि सीएए विरोध की ओट में दिल्ली के मुख्य मार्ग को बाधित करके प्रायोजित किया जाने वाला शाहीन बाग का धरना एक गहरी साजिश का हिस्सा है। हैरत की बात है कि उप्र में अराजकता फैलाने वाले दंगाइयों के चेहरे सार्वजनिक करने पर न्यायपालिका ने जिस तरह से संज्ञान लेकर इन अपराधियों की निजता के अधिकार पर सवालिया निशान लगाया है, वैसा ही कुछ दिल्लीवासियों की परेशानी को देखते हुए आम सड़क को बाधित करके नाजायज रूप से धरना प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध नहीं किया गया। जिसके दुष्परिणाम स्वरूप महीनों तक शाहीन बाग में एक वर्ग विशेष की महिलाओं और बच्चों के द्वारा देश विरोधी नारे लगाकर देश के वातावरण को विषाक्त बनाया जाता रहा। यह जानते हुए भी कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय की नागरिकता पर कोई संकट नहीं आएगा, इसके बाद भी इस संवैधानिक कानून के विरोध में सुनियोजित रूप से धरना, प्रदर्शन, आगजनी और हत्या जैसी अराजकता को अंजाम देना किसी गहरी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। इसके लिए देश की वोटखोर विकृत राजनीति जितनी जिम्मेदार है उससे कहीं अधिक वे देशविरोधी शक्तियां जिम्मेदार हैं जो भारत के एक और विभाजन का दिवास्वप्न देख रही हैं।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

बरतें सावधानी

कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस खतरनाक वायरस के दुनिया में बढ़ते प्रभाव को देखकर महामारी मान लिया है। इस वायरस के प्रति हम और आप कितने सजग और संवेदनशील हैं यह अपने आप में एक सोचने और समझने का विषय है। इससे बचने के लिए की गई ताकीदों जैसे हाथ मिलाने के स्थान पर दूर से ही नमस्ते करना, खांसी जुखाम ठीक ना होने पर चिकित्सक की सलाह लेना, बार-बार हाथ धोना, स्वस्थ भोजन व नियमित व्यायाम करना, विदेश से लौटे लोगों की जानकारी देना अथवा उसे ना छुपाना आदि आवश्यक बातों का हम और आप अनुसरण कर रहे हैं या नहीं? यदि कर रहे हैं तो बेहतर है और यदि अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो हम एक तरह से कोरोना वायरस के इस खतरे से अपनी जिंदगी खतरे में डालने के साथ ही इस महामारी को बढ़ावा देने का भी कार्य कर रहे हैं।

पवन कुमार मुरली, कादीपुर, गुरुग्राम

सोशल मीडिया का दुरुपयोग

आज के दौर में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से फेक न्यूज और भड़काने वाली सामग्री परोसी जा रही है, यह सामाजिक समरसता वाले रसरंग को बदरंग करने का ही कुप्रयास है। दिल्ली के दंगों में भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर परोसी गई सामग्री ने आग में घी का काम किया, इस कारण जनहानि के साथ-साथ करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी सोशल मीडिया किस काम की जो आग लगाए? सबसे पहले चाहे कोई भी दल हो उनके आइटी सेल द्वारा संगठित होकर अगर इस प्रकार की सामग्री परोसी जाती है तो उस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ये दल राजनीतिक लाभ उठाने के चक्कर में भड़काने वाली सामग्री परोस कर वातावरण को बिगाड़ते हैं। जब स्वयं राजनीतिक दल ही संगठित होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करेंगे तो दूसरों को कैसे दोष दे सकते है! सोचने और समझने वाली बात है। हमें सोशल मीडिया के जरिये अफवाह फैलाने से बचना चाहिए।

hemahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

2.4 लीटर थी प्रति व्यक्ति शराब की खपत भारत में वर्ष 2005 में जो वर्ष 2016 में बढ़ कर 5.7 लीटर तक पहुंच गई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार।

डॉ. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु व वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

आजकल

आर्थिक विकास की कुंजी है स्वस्थ भारत

देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयासरत रहती हैं। इसके लिए नीतिगत स्तर पर अक्सर बदलाव किए जाते रहे हैं। हालांकि नए नए तरीकों से नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकारों द्वारा की जाती रही है, लेकिन उससे लोगों को किस तरह से और कितना लाभ मिल पाता है तथा खर्च की जाने वाली रकम का अल्पकालिक व दीर्घकालिक असर किस तरह से सामने आता है, इनका भी मूल्यांकन समय समय पर होना चाहिए

प्रतीकात्मक।

अगर हम 'स्वास्थ्य ही धन है' कहावत को मानते हैं तो भारत दुनिया का सबसे गरीब देश है। हमारे नीति निर्माताओं ने 'संचालन और तकनीक' के संकीर्ण नजरिये से देखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र की गलत व्याख्या की है जबकि समाधान सामाजिक और आर्थिक है। स्वास्थ्य, शिक्षा और समावेश ही एक बेहतर समाज का आधार है।

दरअसल अपर्याप्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, कम सुविधाएं एवं विफल सेवाओं ने देश में अमीरों को फायदा पहुंचाया है और गरीबों को निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कदमों में डाल दिया है। अपर्याप्त बीमा कवरेज और कम समझ से यह समस्या और बढ़ती है। निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, वे अपनी क्षमता के अनुपात से कई गुना अधिक खर्च करते हैं। इस कारण देश भर में सालाना करीब सात करोड़ लोग गरीबी की चपेट में आ जाते हैं।

नीतियों को तैयार करने, उन नीतियों के अनुरूप सेवाओं का प्रारूप तैयार करने और उनका उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के बजाय सरकार अक्सर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए उत्साही होती है। अस्पताल मरीजों को स्वास्थ्य सेवा नहीं बेचते हैं, यह काम बिचौलिया करता है और कई बार सरकार स्वयं बिचौलिये का काम करती है। निजी क्षेत्र को 'स्वास्थ्यवर्धक' बनाने के क्रम में अपनी जिम्मेदारी से बचने का यह तरीका गरीबों को 'उचित खर्च' पर स्वास्थ्य सेवा पाने से दूर रखता है। बढ़ती असमानता के चश्मे से देखने पर पता चलता है कि स्वास्थ्य अनिश्चितताएं जीवन भर के लिए असमानता को बनाए रखती है।

हमारी खराब स्वास्थ्य बीमा कवरेज, चाहे वह सीमित ही हो, बीमारी को बढ़ाने का काम करती है। जो लोग निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के शिकार हैं, वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इस मद में खर्च कर देते हैं और इससे गरीबी के दलदल में फंस जाते हैं। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य को बीमारी के नहीं होने से जोड़ कर देखा जाता है, जबकि वास्तविकता इससे बढ़कर है। अच्छा स्वास्थ्य आजीवन सामर्थ्य बढ़ाता है और क्षमता विकसित करता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आज तमाम विसंगतियों को देखते हुए सरकार को एक विकासपरक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की आवश्यकता है जिसमें रोकथाम और अनुमान का आधार हो। इस पर भी जोर दिया जाना चाहिए कि इलाज सस्ता कैसे हो और प्रभावी वितरण की तकनीक पर आधारित हो।

दृढ़ इच्छाशक्ति और कार्यान्वयन : अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि तकनीक आधारित चिकित्सा सेवा लागत में कमी लाती है और उच्च जीवन प्रत्याशा में योगदान देती है। सरकार को एक विकासवादी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए जो पूर्वानुमान और रोकथाम, सस्ते निदान और प्रभावी वितरण की तकनीक से लैस हो। हमें स्वास्थ्य सेवा में लागत को नियंत्रित करने के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए। कुशल, प्रभावी और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग शक्तिशाली उपकरण है। सुदृढ़ तरीके से इलाज को अंजाम देने पर उसका खर्च आधा किया जा सकता है। स्वास्थ्य व समाज पर इसका सकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्ष और स्पष्ट है।

आर्थिक बोझ : स्वास्थ्य सेवा केवल व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। देश के 14 राज्यों में किया गया एक अध्ययन स्वास्थ्य और जीडीपी के बीच व्यापक संबंध को उजागर करता है। साधारण स्वास्थ्य सेवा लोगों को कई तरह से प्रभावित करती है और यही वास्तविकता है। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की गैर-मौद्रिक लागत जीवन प्रत्याशा को कम करता है और जीवन भर के लिए असमानता सृजित करता है।

स्वास्थ्य का अर्थव्यवस्था पर असर : एक अध्ययन में उपभोग और स्वास्थ्य के बीच एक सकारात्मक संबंध पर प्रकाश डाला गया है जो यह दर्शाता है कि एक बेहतर अर्थव्यवस्था स्थापित करने में कुशल और विश्वसनीय स्वास्थ्य प्रणाली एक महत्वपूर्ण कारक है। शारीरिक और मानसिक सेहत में सुधार कई संदर्भों में उत्पादकता बढ़ाती है। इसके अन्य संकेत भी सामने आते हैं, विशेष रूप से सामाजिक सामंजस्य और कल्याण आदि पर सकारात्मक प्रभाव जो मानव संसाधनों का अनुकूलन करते हैं और जिससे मानव पूंजी कई आर्थिक गुणकों की ओर अग्रसर होती है। यह अध्ययन खराब स्वास्थ्य की प्रकृति और दृढ़ता से जुड़ी लागत और आर्थिक स्वास्थ्य की कीमत, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के बीच सहसंबंध को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रत्याशा में 10 प्रतिशत की वृद्धि से लगभग 1.1 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि होती है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो स्वास्थ्य आर्थिक विकास का कारण बनता है, क्योंकि यह श्रमिकों में बीमारी के कारण उत्पादन में कमी को कम करता है। साथ ही बेहतर पोषण के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाता है। उन संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करता है जो बीमारी के कारण उपलब्ध नहीं थे।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य अनिश्चितता जीवन भर असमानता को बनाए रखती है, जबकि कुशल और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा एक अच्छी अर्थव्यवस्था और बेहतर समाज की स्थापना का एक प्रभावशाली कारक है। हम ऐसी कई चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जो सरकार को खर्च में कटौती करने और राजस्व को बढ़ाने के साथ-साथ इस प्रक्रिया में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा के लिए रास्ता बनाने में मदद करेंगे। सार्वभौमिक स्वास्थ्य, समग्रता के सामाजिक लक्ष्य का समर्थन करेगा और गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य सेवा में होने वाला खर्च जीडीपी का करीब दो प्रतिशत है जो बहुत कम है। समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश तीन साल में लागत वापस कर देता है और कई गुना लाभकारी है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवा को लोगों का अधिकार बनाना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।

भूमंडलीकरण का डरावना चेहरा है कोरोना

लोकमित्र
वरिष्ठ पत्रकार

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सालाना करीब 46 लाख लोग वायु प्रदूषण के चलते मर जाते हैं। इसी तरह सीडीसी यानी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हर साल सड़क दुर्घटनाओं के कारण पूरी दुनिया में साढ़े तेरह लाख लोग मारे जाते हैं। इन दो आंकड़ों का उल्लेख यहां इसलिए किया गया है ताकि यह जाना जा सके कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में जो बदहवासी का आलम है, वह कितना हास्यास्पद है। अगर अब तक के वैश्विक आंकड़ों को देखें तो पिछले डेढ़ महीने में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में 4,300 लोगों की जान ली है और अब तक यह दुनिया के 126 देशों में फैल चुका है। साथ ही दुनिया में करीब एक लाख चालीस हजार लोग कोरोना से संक्रमित थे। भारत में अब इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 80 के करीब हो गई है और हमारे यहां इससे एक इंसान की मौत भी हो चुकी है।

सवाल यह है कि क्या इन आंकड़ों को देखते हुए जिस तरह से कोरोना को लेकर दुनिया में बदहवासी का माहौल बनाया गया है, वह कितना जायज है? अगर हर साल तमाम वजहों से असमय मरने वाले लोगों की संख्या देखें तो वह करीब पांच करोड़ से ज्यादा है। इसके बाद भी न तो प्रदूषण के नाम पर दुनिया में एक दिन को भी बदहवासी देखी गई है, न बाढ़, न सूखा, न सड़क दुर्घटनाएं, न बेरोजगारी और न ही मंदी के चलते। जबकि ऐसा नहीं है कि कोरोना के जरिये दुनिया पहली बार किसी महामारी से परिचित हुई है। इतिहास में ऐसी 100 से ज्यादा महामारियां दर्ज हैं, जिनमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं।

अगर भूमंडलीकरण इतने ही कमजोर आधार पर टिका है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? वर्ष 1918 में स्पेनिस फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था और करीब एक साल के भीतर पांच करोड़ लोग मौत की नींद सो गए थे। यह भी दुनिया के 90 फीसद देशों में फैला था। लेकिन तब इतनी भगदड़ नहीं मची थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बदहवासी को फैलाने में उस देश की सबसे बड़ी भूमिका है, जो अपने को हथियारों के मामले में ही नहीं, दवाओं और मेडिकल सुविधाओं के मामले में भी दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानता है। उस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति ने इस बदहवासी को फैलाने में आग में डाले जाने वाले घी की भूमिका निभाई है।

आज इस बीमारी से बचाव के लिए मेल-जोल की प्रक्रिया में हाथ नहीं जोड़ने से लेकर नमस्ते करने के संदर्भ से जोड़ा जा रहा है। बहरहाल यह महज हाथ जोड़कर व्यक्तिगत रूप से बरती गई सजगता भर नहीं है, बल्कि दुनिया को डराने का एक सबसे संवेदनशील तरीका भी है। कोरोना वायरस सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मौत के भय का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा, बल्कि इसने अपनी गैरजरूरी संवेदनशीलता के चलते न केवल दुनिया की अर्थव्यवस्था को महज 72 घंटों में चौपट कर दिया है, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी को खत्म कर दिया है।

सवाल यह है कि आखिर स्थानीय स्तर से लेकर भूमंडलीय स्तर तक इतनी बदहवासी क्यों? क्या इन्हीं दिनों के लिए भूमंडलीय एकता, साझेदारी और मेलमिलाप की कल्पना की गई थी? यह तो बर्बर युग से भी खराब आचरण है कि जरा से संकट आने पर हर देश अपने दड़बे में घुस जाए। अगर संकट के समय सबको अकेले-अकेले ही रहना है, तमाम परेशानियों को अकेले ही सहना है तो फिर शांति के समय के लिए भूमंडलीय एकजुटता मिल-जुलकर रहने की बड़ी बड़ी दुहाइयों का क्या मतलब है? क्या सिर्फ लाभ और कारोबार के लिए ही दुनियावी एकजुटता होनी चाहिए? क्या किसी संकट से निपटने के लिए इस तरह की एकजुटता की जरूरत नहीं है? इन सभी सवालों पर आज गौर करने की आवश्यकता है। - ईआरसी।

खरी-खरी

बुरी आदत है ये, आदत बदल डालो!

शशांक दुबे

जब से कोरोना वाइरस से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाथ मिलाने के बदले 'नमस्कार' करने की सलाह दी है, तब से वे लोग बहुत दुखी हो गए हैं जो दोपहर को कैंटीन में खाना खाकर हाथ धोने के बाद दो-चार लोगों से 'हैंड शेक' करके 'हाथ साफ' कर लिया करते थे।

भले ही सोशल मीडिया पर हम नेताओं की आलोचना कर नई नई चीजें गढ़ रहे हों, किंतु अभिवादन के मामले में नेता ही हमारे आदर्श हैं। कितना आसान है उनका अंदाज! दूर से जनता को देखा, तुरंत गले में डले हार में से दोनों हाथ ऊपर उठाकर नमस्ते का असली इमोजी बना दिया।

काश! हर आदमी का काम ऐसा हो कि उसे किसी को छूने की जरूरत न पड़े। जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला। यूं दिन भर पब्लिक के बीच होता है, लेकिन चालान काटते वक्त ही उसे 'स्पर्श थैरेपी' देनी पड़ती है, वरना दूर से ही काम चल जाता है। ऐसा ही हाल कॉल सेंटर वालों, ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों, रेलवे व बैंक की 'मे आय हेल्प यू' वालों का भी है।

बिल्डिंग के दरबान का तो कहना ही क्या! इधर साहब दिखे, उधर हाथ में रखा अखबार परे किया और सेल्यूट ठोंक दिया। चिंता तो हो रही है उन बुकिंग क्लर्कों की, जिनका सारा काम ग्राहक से नकद लेन-देन में होता है। वे क्या करें?

अब फिल्मी सितारों को भी अपने अंदाज बदलने होंगे। अब नायिका से प्रेम का इजहार रणवीर कपूर या इमरान हाशमी की तरह न करके मनोज कुमार की तरह नायिका से डेढ़ फुट दूरी बनाते हुए करना होगा। वैसे मनोज कुमार का अनुकरण सिर्फ रोमांटिक दृश्यों में ही किया जाए, नाटकीय में नहीं। क्योंकि ऐसे दृश्यों में वे पूरे समय हथेली से आधा मुंह ढके रहते हैं और कोरोना में यह वर्जित है। अक्षय कुमार की तरह बत्तीसी खुली रखना या नाना पाटेकर की तरह बार-बार सिर खुजाना भी सही न होगा। वायरस कहीं से भी घुस सकते हैं।

वैसे लोग हाथ हिलाकर अभिवादन तो कर लेंगे, लेकिन हाथ हिलाते वक्त बोलेंगे क्या? 'जय रामजी की' बोलेंगे तो सांप्रदायिक, 'नमस्ते' कहेंगे तो पिछड़े बता दिए जाएंगे। हालांकि झक और मन, दोनों को मारकर बोलना तो कुछ ऐसा ही पड़ेगा।

ट्वीट-ट्वीट

सात महीने तक नजरबंद रखने के बाद सरकार ने अपने आदेश को पलटते हुए फारूख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया है। उम्मीद है कि उसे अपनी गलतियों का अहसास होगा और उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती व दूसरे नेताओं को जल्द छोड़ेगी।
सुहासिनी हैदर@suhasinih

भाजपा ने सिंधिया में प्रतिभा देखी। कांग्रेस ने उन्हें खतरे के रूप में देखा। दोनों दलों में यही अंतर है।
चेतन भगत@chetan_bhagat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सार्क देशों को एकजुट करने के लिए 'सार्क लीडरशिप वीडियो कांफ्रेंसिंग' का सुझाव दिया है। देखना है कि क्या अब एक वायरस मोदी और इमरान के बीच वार्ता करा पाता है?
संजय बारू@Barugaru1

कोरोना वायरस को लेकर मचे हड़कंप से पता चलता है कि हमारी दुनिया कितनी क्षणभंगुर है। जैसे पूरी पृथ्वी बारूद के ढेर पर बैठी हो। चाहे इसे तबाह करने के लिए विशालकाय एटमी हथियारों का खौफ दिखाया जाता रहा हो, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म वायरस ही ऐसा करने में सक्षम हैं।
अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

सार्क कोमा में है। मोदी जी, भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। इसे सार्क को फिर से खड़ा करने के लिए आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए। मतलब कि भारत-पाक संबंधों की वजह से सार्क को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।
सुधींद्र कुलकर्णी@SudheenKulkarni

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए भारी क्षति है?

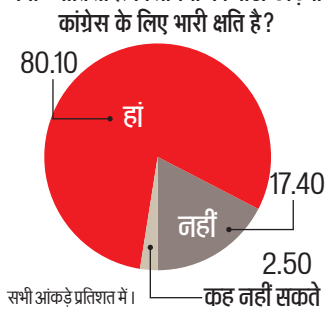

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कोरोना के संकट को देखते हुए ओलंपिक को एक साल के लिए स्थगित कर देना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दंगाई पर इस तरह पड़े सजा की मार,
दस पीढ़ी उसकी करें दंगे से इंकार।
दंगे से इंकार जलाई जिसने दिल्ली,
भेजो उसको जेल बनाकर भीगी बिल्ली।
उपद्रवी से जाय वसूली पाई-पाई,
दंगा करना भूल जायंगे सब दंगाई।
- ओमप्रकाश तिवारी

आलोक मिश्रा
स्थानीय संपादक, बिहार

बिहार डायरी

सेंधमारी की तैयारी या पोटली थी भारी

बिहार में अब पार्टियां अपना हर कदम विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही उठा रही हैं। नफा-नुकसान का आकलन कर पत्ते फेटे जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव इसकी बानगी है। प्रत्याशियों के चयन में खासकर राजद के रुख ने साफ कर दिया है कि वह अब अपना चोला बदल रहा है। तमाम समीकरणों को धता बताकर अचानक समृद्ध थैली वाले एक अनजाने नाम अमरेंद्र धारी सिंह (एडी सिंह) को सामने लाकर उसने ऐसी चाल चल दी, जो दल और बाहर दोनों के लिए विचारणीय है। कारण एडी सिंह का भूमिहार होना, जो लालू के परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम-यादव में फिट नहीं होता। ऐसे में लालू का यह कदम एनडीए के वोटों मे सेंधमारी जैसा दिख रहा है।

बिहार के चुनाव में जाति का खासा महत्व होता है। सभी दल अपने-अपने हिसाब से गोटियां सेट करते हैं। लालू को हमेशा अपने माय (मुस्लिम-यादव) समीकरण पर भरोसा रहा है, लेकिन लंबे समय से सत्ता से दूर रहने के कारण यह मिथक टूटा है। पार्टी भी मानकर चल रही है कि पिछड़ों और मुस्लिमों की राजनीति के सहारे सत्ता मिलना मुश्किल है। इसलिए सवर्णों को साधने की कोशिश शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष सहित संगठन में कई ओहदेदार सवर्ण जाति से बनाए हैं और अब राज्यसभा चुनाव में यह माना जा रहा था कि लालू अपने परंपरागत वोट बैंक को ध्यान में रखकर किसी को चुनेंगे, लेकिन यह कयास टूटा। सुबह राजनीति में अनजान साढ़े पांच सौ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाले अमरेंद्र धारी सिंह का जब नाम सामने आया तो वह अधिकांश के लिए अनजान था। वैसे उनके पिता तेजप्रताप धारी सिंह का संबंध समृद्ध घराने से रहा है और नाना सीपीएन सिंह कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। अमरेंद्र धारी सिंह व्यवसायी हैं। राजद ने उनका परिचय समाजसेवी के रूप में भी दिया। चर्चा की गई कि पटना में आइआइटी की तैयारी के लिए चलने वाला संस्थान अभयानंद सुपर-30 की वित्तीय सहायता करते रहे हैं। हालांकि इसका जिक्र करने पर इसे चलाने वाले पूर्व डीजीपी अभयानंद ने सुपर-30 से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि वे एक शिक्षक हैं और अब इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है, इसलिए वे इसे छोड़ रहे हैं।

अमरेंद्र धारी सिंह (बाएं), प्रेमचंद गुप्ता (बाएं से दूसरे), जगदानंद सिंह (दाएं) और तेजस्वी यादव।

राज्यसभा की पांच सीटें बिहार से खाली हुई थीं। पहले ये पांचों एनडीए के पास थीं, लेकिन इस बार दो राजद के कोटे में गईं और एनडीए में तीन, जिसमें दो जदयू व एक भाजपा के खाते में। जदयू ने कोई दांव न खेलते हुए पिछली बार के तीन सदस्यों में से कहकशां परवीन को छोड़कर रामनाथ ठाकुर व हरिवंश को, जबकि भाजपा ने पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर का नाम तय किया। विवेक ठाकुर भी भूमिहार ही हैं। राजद ने एडी सिंह के अलावा प्रेमचंद गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रेमचंद गुप्ता लंबे समय से लालू से जुड़े रहे हैं और वह भी अरबपति हैं। जातिगत समीकरण के अलावा सियासी हलके में राजद कोटे से तय नामों के पीछे उनका धनकुबेर होना ज्यादा चर्चा का विषय है।

राजद ने भूमिहार को टिकट क्यों दिया, पैसे के लिए या उस जाति के वोटबैंक में सेंध लगाने के लिए, इसी चर्चा के बीच बिहार की एक और घटना उत्सुकता जगा रही है। एक ऐसी युवती चर्चा में है, जो खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हुए नए तरह का राजनीतिक अभियान चला रही हैं। वह पहले विज्ञापन के माध्यम से अखबारों के पहले पन्ने पर और फिर सोशल मीडिया पर प्रकट हुईं। इनका नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है, जिन्होंने यूरोपियन शैली में बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पुष्पम बिहार के दरभंगा जिले के एक नेता की बेटी हैं, जो जदयू के टिकट पर विधान पार्षद (एमएलसी) रहे हैं। पुष्पम ने सीधे घोषणा कर दी कि वह बिहार की सीएम कैंडिडेट हैं। वह अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन संदेशों के जरिये बिहार के 'असंवेदनशील' और 'अयोग्य' नेताओं से बहस की चुनौती दे रही हैं। दावा, बिहार को 200 परसेंट ग्रोथ रेट देने की कार्ययोजना का ब्लू प्रिंट उनके पास होने का है। वह लंदन में पढ़ी हैं और उनके दावे लोगों को चौका रहे हैं। इस तरह के दावे पहले भी होते रहे हैं। सन ऑफ मल्लाह कहलाने वाले मुकेश सहनी और वरिष्ठ नौकरशाह अमिताभ वर्मा के पुत्र ऑक्सफोर्ड के छात्र रहे अक्षय वर्मा ने भी पहले ऐसे ही दावे किए थे।

चर्चा यह है कि इस बार चुनाव में इस तरह के और भी दावेदार मैदान में आएंगे। देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति इससे करवट लेगी या जाति-धर्म के गुणा-भाग पर ही चलेगी।

मंथन

बदलता यूरोप बहकता भारत

शराब से होने वाले अन्य नुकसान को छोड़ भी दें तो देश भर में सालाना लगभग एक लाख लोग इसका सेवन करके सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं

डॉ. अजय खेमरिया
स्वतंत्र टिप्पणीकार

मध्य प्रदेश और हरियाणा में अब आप घर बैठे ऑनलाइन शराब मंगा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार शराब से सालाना बारह हजार करोड़ रुपये और हरियाणा सरकार साढ़े सात हजार करोड़ रुपये राजस्व का इंतजाम करेंगे। दोनों ही राज्यों में इस प्रावधान को लेकर विरोध हो रहा है। असल में शराब की नई दुकानें खोलने की बदनामी से बचने के लिए सरकारें इस तरह के उपाय अमल में ला रही हैं। इधर केंद्रीय बजट में इस वर्ष नशामुक्ति कार्यक्रम के लिए 260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय 16 करोड़ नागरिक नियमित रूप से नशे का सेवन कर रहे हैं। एम्स और नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा तैयार इस शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि देश भर में 16 करोड़ शराब पीने वालों में से 6.7 करोड़ तो आदतन यानी एडिक्ट हैं। लगभग 5.7 करोड़ भारतीय इस वक्त शराब जनित रोगों से ग्रस्त हैं। समझा जा सकता है कि हमारे देश में शराब की खपत और इससे उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्यगत चुनौती कितनी भयानक होती जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री 'फिट इंडिया अभियान' पर काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश में शराब का बाजार सबसे तेज 8.8 फीसद की दर से बढ़ रहा है। अनुमान है कि वर्ष 2022 में 16.8 बिलियन लीटर शराब की खपत भारत में होगी।

सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें चुनावी वादों की पूर्ति के लिए अपने ही नागरिकों के जीवन को दांव पर नहीं लगा रही हैं? नजीर के तौर पर मध्य प्रदेश में 2003 में शराब का राजस्व 750 करोड़ रुपये था जो 12 हजार करोड़ तक पहुंच गया है। इसी वर्ष महाराष्ट्र सरकार द्वारा 17,477 करोड़, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 4,700 करोड़, उत्तर प्रदेश द्वारा 23,918 करोड़ और तमिलनाडु सरकार द्वारा 31,157 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जन अपने ही नागरिकों को शराब परोसकर किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारी सरकारें लोगों को शराब पिलाने में कितनी दिलचस्पी रखती हैं।

बीमारियों और मौत का कारण : बुनियादी रूप से भारत में शराब का सेवन नागरिकों को बीमारियों और अंततः मौत की ओर धकेलने का काम करता है, क्योंकि शराब में हार्ड अल्कोहल की मात्रा भारत में 90 फीसद है जो वैश्विक मानक और प्रचलन के 44 फीसद की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट कहती है कि एक दशक में भारत में शराब की खपत दोगुनी हो गई है। वर्ष 2005 में प्रति व्यक्ति यह 2.4 लीटर थी जो वर्ष 2016 तक 5.7 लीटर हो गई। उल्लेखनीय है कि सरकारी सर्वे के इतर करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो परंपरागत तरीकों से बनी शराब का सेवन कर रहे हैं, खासकर वनीय इलाकों में ताड़ी, खजूर, गुड़ आदि से बनने वाली शराब इसमें शामिल है। शराब केवल सरकारी राजस्व तक का मामला नहीं है, असल में यह नेताओं, अफसरों और माफिया के गठजोड़ की संपन्नता का माध्यम भी है। जितना राजस्व सरकारी खजानों में दिखता है कमोबेश उतना ही इसके खेल में अवैध रूप से भी बनता है। सीएजी की एक हालिया रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश सरकार के कार्यकाल में करीब 25 हजार करोड़ रुपये की चपत लगने की जानकारी सामने आई है। यह रकम बड़े सिंडिकेट ने शराब के दाम अवैध रूप से बढ़ाकर जनता से वसूल की, लेकिन खजाने में जमा नहीं हुई। यही खेल देश के कई अन्य राज्यों में सुनियोजित तरीके से चल रहा है। सरकार बदल जाती है, लेकिन माफिया नहीं।

प्रश्न यह है कि आखिर हम अपनी ही नीतियों से मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? वर्ष 1929 में महात्मा गांधी ने 'हरिजन' में लिखा था, 'अगर कोई मुझे स्वराज और शराबबंदी में से एक चुनने का विकल्प दे तो पहले शराबबंदी को चुनूंगा।' आज हमें इस बात पर विचार करना होगा कि गांधी के प्रति हमारी कितनी वैचारिक प्रतिबद्धता है। आज भारत को हमने वैश्विक शराब बाजार में तब्दील कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 47 में जो नैतिक आदेश सरकार को मिले हैं, क्या उनके प्रति कोई नैतिक जवाबदेही नहीं है संविधान की शपथ उठाने वालों की?

प्रतीकात्मक।

बेहतर होगा कि हम एक राष्ट्रीय शराब नीति का निर्माण करें। चरणबद्ध तरीके से शराब के प्रचलन और कारोबार को घटाने का प्रयास करें। लाखों करोड़ के राजस्व में से स्थानीय खनिज निधि की तरह हर जिले में राजस्व का एक-चौथाई हिस्सा नशामुक्ति केंद्रों या वेलनेस सेंटर के लिए आरक्षित कर दें। आदिवासियों पर केंद्रित एक शोध रिपोर्ट में बताया गया है कि 50 फीसद मजदूरी की रकम इस तबके की शराब पर खर्च हो जाती है। अगर महिलाएं अर्थ उपार्जन नहीं करें तो बड़ी आबादी भूखे मरने के कगार पर होगी। शराब की बिक्री को हतोत्साहित करने के लिए सामाजिक माहौल भी बनाना होगा, क्योंकि पिछले दो दशकों में युवाओं में इसका चलन तेजी से बढ़ा है। भारत में विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या इस समय है और शराब की आदी हमारी युवा पूंजी फिट इंडिया या स्किल इंडिया के लिए कैसे परिणामोन्मुखी हो सकती है? पूरी दुनिया जब योग की ओर उन्मुख हो रही है और यूरोप में 2010 के बाद शराब की खपत 10 फीसद कम हो गई है, तब भारत में यह खपत दोगुनी हो जाना हमारी सामूहिक चेतना हमारे मर्यादित जीवन को कटघरे में खड़ा करता है।

मध्य प्रदेश के सूचना मंत्री पीसी शर्मा ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर आबकारी राजस्व केंद्र से समायोजित करने का जो सुझाव दिया है उस पर भी बिहार, गुजरात मॉडल के आलोक में नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है।

32,605 किसानों ने 2001 से 2019 के बीच महाराष्ट्र में आत्महत्या की। ऐसा राज्य के राजस्व विभाग के हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में कहा गया है। 2015 में सबसे ज्यादा 3,273 किसानों ने खुदकशी की।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 14 मार्च 2020

उत्तराखंड

चारधाम यात्रा की चुनौतियां

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की उलटी गिनती शुरू हो गई हैं, लेकिन तैयारियों को लेकर शासन-प्रशासन की चिंता कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम का करवट बदलता मिजाज चिंता बढ़ा रहा है। आधा मार्च बीत गया, पर मौसम के तेवर ढीले नहीं पड़ रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में आए दिन बारिश और बर्फबारी हो रही है। ऐसे में सरकार की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। चूंकि इस बार शीतकाल में उत्तराखंड में रिकॉर्ड बर्फबारी और बारिश हुई। ऐसे में यात्रा मार्गों की स्थिति वैसे ही खराब हो रखी है। इसको देखते हुए शासन-प्रशासन ने इस बार चारधाम यात्रा की तैयारियां समय से पहले शुरू कर दी थीं, पर मरम्मत कार्य गति नहीं पकड़ पाए। मौसम इसमें बड़ी बाधा बन रहा है। बारिश और बर्फबारी नित नई चुनौती पेश कर रही हैं।

चारों धामों के हाईवे पर इनदिनों ऑलवेदर प्रोजेक्ट के तहत चौड़ीकरण का काम चल रहा है। सरकार की योजना यात्रा शुरू होने से पहले इन्हें दुरुस्त करने की थी, इसके लिए अतिरिक्त संसाधन भी जुटाए गए, परंतु इसमें अभी तक अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। सूरतेहाल दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बद्रीनाथ मार्ग पर अभी कई स्थानों पर रोड कटिंग का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। निर्माण एजेंसियों ने इस रूट को 15 दिन के लिए पूरी तरह बंद करने का प्रस्ताव तैयार किया है, मगर सरकार इस पर फैसला नहीं कर पा रही है। इसके विकल्प के रूप में जो मार्ग सुझाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार उलझन से बाहर नहीं निकल पा रही है। धामों के कपाट खुलने से पहले सभी हाईवे दुरुस्त हो जाएं, इसकी संभावना भी कम नजर आती है।

चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रशासन को रणनीति बदलनी होगी। पारंपरिक अंदाज से हटकर योजना बनाई जानी चाहिए

जाहिर है श्रद्धालुओं को यात्राकाल में हिचकोले खाकर सफर पूरा करना होगा। चारों धामों के कपाट खुलने की तारीखें तय हो चुकी हैं, इनमें किसी प्रकार के फेरबदल की गुंजाइश नहीं है। इसलिए तैयारियों को लेकर सक्रिय होना होगा। यह सही है कि प्रकृति पर किसी का वश नहीं चलता, इसलिए सरकार को अब उन विकल्पों पर मंथन करना चाहिए, जिसमें श्रद्धालुओं की दिक्कतें कम हों। बहरहाल यात्रा मार्गों पर यात्रा शुरू होने से पहले दिक्कतें पूरी तरह खत्म हो पाएं, इसकी संभावना कम ही नजर आती है। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं कि मौसम की आड़ हाथ पर हाथ रखकर बैठा जाए।

उम्मीद है सरकार हालात को देखते हुए यात्रा की तैयारियों को समय से पूरा करने के लिए नई रणनीति पर मंथन कर रही होगी। अगर सरकार ने इस दिशा में सोचना शुरू नहीं किया है तो समय गंवाए बगैर इसमें जुट जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश

बच्चों के हित में सही फैसला

शिक्षण संस्थानों में बच्चा सिर्फ शिक्षा ही ग्रहण नहीं करता, अपितु संस्कार भी सीखता है। कहा भी जाता है कि भोजन और भजन एकांत में और साफ सुथरी जगह पर किया जाना चाहिए, लेकिन कई शिक्षण संस्थानों में ऐसा नहीं होता था। दरअसल मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को भोजन परोसने की व्यवस्था में अनेक प्रकार की बदइंतजामी सामने आई हैं। बच्चों को खुले में और जमीन पर बैठाकर मिड डे मील परोसा जाता रहा है। इस पर शिक्षा विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया और सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी कर दिया कि बच्चों को अब खुले आसमान तले खाना नहीं परोसा जाएगा। स्कूलों के कमरों, हॉल या बरामदे में दरी बिछाकर ही बच्चों को खाना परोसा जाएगा। इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि खाना बनाने में साफ पानी का प्रयोग किया जाए। खाद्य सामग्री को पकाने से पहले दो बार साफ पानी से धोने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा ताजी सब्जियों का प्रयोग करें ताकि भोजन की गुणवत्ता कायम रह सके। खाना बनाने से पहले और बाद में बर्तन को अच्छी तरह साफ करें। साथ ही मिड डे मील कर्मी के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि वह अपनी सफाई का भी ध्यान रखे। खाना बनाने वालों के लिए निर्देश दिया गया है कि खाना बनाते समय सिर ढक कर रखना होगा और उसके नाखून भी सही प्रकार से कटे होने चाहिए।

प्रतीकात्मक फोटो

इसके अलावा शिक्षण संस्थानों की पानी की टंकियां हर माह कम से कम दो बार सफाई की जाए। इसका ब्योरा सूचना पट्ट पर भी दर्ज करना होगा। बच्चों को पेयजल स्रोत को साफ रखने व खुले में शौच न जाने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही स्कूल प्रबंधकों को कहा गया है कि खाना बनाने के बाद रसोईघर को ताला लगाया जाए। इसी के साथ यह निर्देश भी जारी किए गए हैं कि मिड डे मील परोसे जाने के दौरान बच्चों के साथ किसी तरह का भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को रोल नंबर के अनुसार ही बिठाया जाए।

मिड डे मील योजना पर सरकार के निर्देश बच्चों को तंदुरुस्त बनाने की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे

निःसंदेह ये निर्देश सराहनीय हैं। समझना होगा कि अधिकतर बीमारियां दूषित पानी के प्रयोग से ही फैलती हैं। बच्चों को हाथ धोने व साफ सफाई का महत्व भी बताना बहुत जरूरी है। बच्चे देश का भविष्य हैं। इनका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे बीमार होंगे तो सशक्त भविष्य की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। उधर अभिभावकों को भी चाहिए कि वे बच्चों को घर पर भी साफ सफाई के बारे में जागरूक करें। उम्मीद की जाने चाहिए कि शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन होगा और बच्चे स्वस्थ रहेंगे।

झारखंड

खतरनाक संकेत

हजारीबाग में आइस फैक्ट्री में सिलिंडर ब्लास्ट के बाद हुई गैस रिसाव की घटना खतरनाक संकेत है। अमोनियम नाइट्रेट गैस के रिसाव के बाद महिला की जान गई। दर्जनों की संख्या में लोग प्रभावित हुए। बड़ी संख्या में पक्षी भी काल कवलित हुए। दरअसल यह घटना तो एक उदाहरण मात्र है। राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में ऐसी फैक्ट्रियां घनी आबादी एवं बस्ती के बीच वैध-अवैध तरीके से संचालित हो रही हैं। जो कभी भी इस तरह हादसे की पुनरावृत्ति का कारण बन सकती हैं। अगले हादसे का दायरा और विकराल हो सकता है।

बहरहाल हजारीबाग में हुए हादसे के बाद अब राज्य भर में प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई है। हजारीबाग में तो प्रशासनिक तंत्र अब इस मामले में लाइसेंस देने की प्रक्रिया और फैक्ट्री का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच कराने और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कह रहा है, लेकिन सवाल यह है कि यह कदम पहले ही क्यों नहीं उठाया गया। लाइसेंस

प्रतीकात्मक फोटो

देने की प्रक्रिया और निरीक्षण के दौरान ही निर्धारित नियमावली के पालन और निर्दिष्ट मानकों की जांच राज्य में शत-प्रतिशत रूप से क्यों नहीं हो पा रही है। ताकि ऐसे हादसों के होने की किसी भी प्रकार की संभावना ही न बचे।

इतना ही नहीं, इस मामले में प्रदूषण विभाग की ओर से भी बड़ी लापरवाही बरते जाने की बात कही जा रही है। गैस का रिसाव पूरी तरह से बंद हुए बगैर ही फैक्ट्री को सील कर दिए जाने की बात सामने आ रही है। यदि ऐसा है तो यह राज्य में सरकारी तंत्र की लचर और गैर जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली का एक और ज्वलंत उदाहरण है। गौरतलब है कि विगत वर्ष जनवरी माह में मुरी में हिंडाल्को का रेड मड पौंड ढह गया था।

सौभाग्य से इसमें जानमाल की कोई हानि तो नहीं हुई, लेकिन वहां की जमीन की उर्वरा शक्ति का ह्रास हो गया। इस मामले में भी पहले तो कड़ी कार्रवाई किए जाने के तमाम दावे किए गए, लेकिन अंत में मामला सामान्य तरीके से निबट गया। ऐसे में अब सरकार और उसके शीर्ष प्रशासनिक अमले को इसे वाकई बेहद गंभीरता से लेना चाहिए।

नियमों का अनुपालन कराए जाने की दिशा में सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि झारखंड में कहीं पर भी ऐसे किसी हादसे के होने की संभावना ही न रहे।

बंगाल

ममता का समारोह और कोरोना की चिंता

कोरोना वायरस से विश्वभर में कोहराम मचा है। भारत में भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के लिए एडवायजरी से लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। यहां तक कि क्रिकेट और फुटबाल मैच तक खाली स्टेडियम में कराने का निर्देश है। आइपीएल शुरू होने की तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है, परंतु शुक्रवार को देखा गया कि केंद्र की एडवायजरी की अनदेखी कर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने करीब 10 हजार लोगों के समारोह को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में संबोधित किया।

इस समारोह से ममता ने लोगों को कोरोना वायरस से नहीं डरने और सतर्क रहने की अपील की, जबकि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एडवायजरी जारी कर राज्य सरकारों को कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए लोगों का जमावड़ा न हो यह सुनिश्चित करने को कहा था। केंद्र ने खेल से लेकर अन्य सभी तरह के भीड़ जुटने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाने को कहा है। ऐसे में इस समारोह को लेकर विपक्षी दलों ने ममता पर जमकर निशाना साधा है।

केंद्र के दिशा निर्देश की अनदेखी कर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने करीब 10 हजार लोगों के समारोह को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में संबोधित किया

हालांकि ममता ने केंद्र सरकार की एडवायजरी की बातें भी इस कार्यक्रम में की और लोगों को हाथ नहीं मिलाने तथा पांच मीटर की दूरी से बात करने की भी सलाह दी। ममता ने तर्क दिया है कि यह दिन रोज नहीं आता है। दरअसल नेताजी इनडोर स्टेडियम में ममता सरकार की ओर से खेलश्री योजना के तहत राज्य की खेल हस्तियों को सम्मानित करने के लिए यह समारोह आयोजित किया गया था। उन्हें पता था कि इस कार्यक्रम को लेकर विपक्षी दल निशाना साधेंगे। इसीलिए ममता ने समारोह को लेकर अपना तर्क भी रखा, परंतु सवाल यह उठ रहा है कि जब वह खुद ही लोगों को सतर्कता बरतने को कह रही हैं और समझा रही हैं कि इस महामारी से कैसे बच सकते हैं तो फिर 10 हजार लोगों की भीड़ जुटाकर समारोह आयोजित करना कितना उचित था।

विपक्षी दल भाजपा से लेकर माकपा तथा कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि असल में निकाय चुनाव होने वाले हैं और ममता बनर्जी ऐसे में इस मौके को वह भुनाना भला क्यों भूलेंगी? यदि मुहल्ला के क्लबों को अनुदान ही देना था तो भीड़ जुटाकर क्यों यह तो सीधे-सीधे उन क्लबों तक भी चेक पहुंचाया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो वोट दिखाई दे रहा है। यही नहीं समारोह से लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दे रही हैं और खुद भीड़ भी जुटवा रही हैं और खुद ही भीड़-भाड़ वाले जगहों तथा बाजार जाने से बचने की भी बात कह रही हैं।

सूर्य के रहस्यों को सुलझा रहा अंशु का आविष्कार

जागरण विशेष

- सूर्य से आने वाली चुंबकीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है रेडियो स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर
- एस्ट्रोफिजिकल जर्नल अमेरिका और सोलर फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध
- चार साल में सूर्य पर 50 से अधिक विस्फोट हुए दर्ज

विजय कुमार गिरि, पूर्वी चंपारण

रक्सौल, बिहार की बेटी अंशु कुमारी ने रेडियो स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर नामक जो यंत्र विकसित किया, वह सूर्य के रहस्यों को समझने में सहायक विवरण जुटा रहा है। सूर्य पर होने वाले विस्फोटों की जानकारी भी इसके माध्यम से दर्ज की जा रही है, समझी जा रही है। सूर्य से आने वाली चुंबकीय तरंगों के अध्ययन पर आधारित यह शोध एस्ट्रोफिजिकल जर्नल अमेरिका और सोलर फिजिक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

अंशु ने दैनिक जागरण को बताया, सूर्य के रहस्य को समझना कठिन है। दुनियाभर के वैज्ञानिक इसके बारे में जानने का यत्न कर रहे हैं। सूर्य की गतिविधियों और धरती पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए यह यंत्र- रेडियो स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर मैंने विकसित किया, जो अब बेहतर परिणाम दे रहा है। शोधार्थी वैज्ञानिकों और छात्रों को इससे मदद मिल रही। यंत्र से ही पता चला कि चार साल में सूर्य पर 50 से अधिक विस्फोट हुए हैं।

उन्होंने बताया कि इस यंत्र को जून 2015 में रेडियो एस्ट्रोनॉमी फील्ड स्टेशन गौरीबिदानूर, कर्नाटक में स्थापित किया गया। इससे मिलने वाले परिणामों पर आधारित शोध 2019 में अंतरराष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुआ है। यह यंत्र सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को रिकॉर्ड कर इनका आकलन करने में सहायता प्रदान करता है। इससे धरती के तापमान, मौसम, जनजीवन और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

अंशु ने सूर्य के रेडियो वेवलेंथ, कोरोनल मास इजेक्शन और उससे जुड़े पांच बड़े विस्फोटों का अध्ययन किया। इन विस्फोटों के कारण हुए रेडियो एक्टिव उत्सर्जन और चुंबकीय तरंगों पर इसके प्रभाव के अलावा सूर्य के कोरोना (सतह) पर मैग्नेटिक फील्ड में आए परिवर्तन को समझने पर उनका शोध केंद्रित रहा। अब अंशु सूर्य पर होने वाले इन स्थलीय परिवर्तनों का अध्ययन कर रही हैं। उन्होंने पता लगाया है कि जब सूर्य की मैग्नेटिक फील्डलाइन टूटती या जुड़ती है तो उसकी सतह पर विस्फोट होते हैं। कोरोनल मॉडलिंग से डाटा संग्रहण के जरिये वह उन संभावनाओं को जानने की कोशिश में हैं, जिनसे सूर्य की सतह पर होने वाली इन घटनाओं के कारण और समय की सही जानकारी मिल सके।

जंतु विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर चंद्रमा सिंह की बेटी अंशु बताती हैं कि उन्हें बचपन से ही सूर्य में रुचि थी। मां सविता शिक्षा पदाधिकारी थीं, जिन्होंने अपनी लाडली को हमेशा प्रोत्साहन दिया। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल अनुमंडल निवासी अंशु ने 2012 में जयपुर से इंजीनियरिंग के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु से प्रो. आर. रमेश और डॉ. सी. कार्थीरावन के निर्देशन में सोलर रेडियो विकिरण और उसके प्रभाव पर शोध किया। पीएचडी 2019 में पूरी हुई। नीदरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी में वह सूर्य अध्ययन से प्रोजेक्ट पर काम चुकी हैं। वर्ष 2019 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, इटली और इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस अर्थ इन्वायरमेंटल रिसर्च, नागोया यूनिवर्सिटी, जापान में आयोजित वर्कशॉप में इस अध्ययन को उन्होंने आगे बढ़ाया। फिलहाल, अंशु यूरोपियन शोध परिषद से मिले अनुदान से फरवरी 2020 से हेलसिंकी विश्वविद्यालय, फिनलैंड में शोधरत हैं। वहां वह कोरोनल मास एजेक्शन के नाम से ज्ञात सूर्य पर सबसे बड़े विस्फोट की मॉडलिंग पर कार्य कर रही हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

रेडियो स्पेक्ट्रो पोलरीमीटर से सूर्य की आंतरिक गतिविधियों और तापमान को आसानी से मापा जा सकता है। यह उपकरण सूर्य की सतह पर होने वाली रेडियो एक्टिविटी हलचल और चुंबकीय तरंगों को रिकॉर्ड करता है।
-अंशु कुमारी, रिसर्चर, हेलसिंकी विश्वविद्यालय, फिनलैंड

एंटीना से मिली जानकारी के अध्ययन के लिए लगे कंप्यूटर और अन्य उपकरण।

कर्नाटक के गौरीबिदानूर स्थित रेडियो एस्ट्रोनॉमी फील्ड स्टेशन पर लगा सूर्य की हलचल की जानकारी देने वाला एंटीना।

अंशु कुमारी की फाइल फोटो। सभी फोटो अंशु कुमारी के सौजन्य से

जंगल की आग में कीट-पतंगों की क्षति का भी होगा आकलन

राज्य ब्यूरो, देहरादून

- फायर सीजन में पारिस्थितिकी के संरक्षण में योगदान देने वाले इन जीवों को पहुंचती है भारी क्षति

71.05 फीसद वन भूभाग वाले उत्तराखंड में जंगलों में पारिस्थितिकी के संरक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले कीट-पतंगों समेत छोटे जीवों को फायर सीजन में पहुंचने वाली क्षति का भी आकलन किया जाएगा। पहली बार इस बिंदु को जंगल की आग से होने वाले नुकसान में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

प्रदेश के जंगलों में हर बार फायर सीजन (15 फरवरी से मानसून आने तक की अवधि) में बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। बीते एक दशक के आंकड़ों पर गौर करें तो सालाना औसतन दो हजार हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचता है। आग से पेड़ों, झाड़ियों, वनस्पतियों की क्षति का आकलन तो होता है। कीट-पतंगे, सांप-बिच्छू समेत अन्य छोटे जीवों को भी बड़े पैमाने पर हानि पहुंचती है और इनका आकलन नहीं हो पाता। अब इन छोटे जीवों की क्षति को भी जंगल की आग के नुकसान में शामिल करने की तैयारी है। इससे पता चल सकेगा कि इन्हें कितना नुकसान पहुंचा है।

प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराज बताते हैं कि जंगल की आग से क्षति के मानकों में इस अहम पहलू को शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसका क्या मैकेनिज्म होगा और किस तरह से छोटे जीवों की क्षति का आकलन होगा, इस पर मंथन चल रहा है। उन्होंने बताया कि मानक तैयार होते ही इस बिंदु को शामिल कर छोटे जीवों को पहुंचने वाले नुकसान का भी आकलन किया जाएगा।

इस बार अब तक सुकून में विभाग : फायर सीजन में जंगलों के धधकने से परेशान रहने वाला वन महकमा इस मर्तबा अभी तक सुकून में है। असल में 15 फरवरी को फायर सीजन शुरू होने के साथ ही जंगलों के धधकने का क्रम शुरू हो जाता है, जो मानसून के आने तक बना रहता है। ऐसे में बेबस वन महकमा जंगलों की आग पर नियंत्रण को आसमान की ओर ताकता रहता है। इस बार अभी तक नियमित अंतराल में हो रही वर्षा-बर्फबारी से जंगलों में अच्छी-खासी नमी बनी है।

यही वजह है कि अभी तक जंगल की आग की कोई घटना नहीं हुई है। जंगलों में जिस तरह से नमी बनी है, उससे अप्रैल तक सुकून बना रहने की उम्मीद जताई जा रही है।

मलमल को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आगे आई बंगाल सरकार

इंद्रजीत सिंह, कोलकाता

दुनिया भर में मशहूर बंगाल के मलमल यानी मसलिन को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। इसके जियोग्राफिकल इंडीकेशन टैग (जीआइ) यानी भौगोलिक संकेतक के लिए आवेदन किया गया है। यह टैग किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है, जिस पर राज्य का अधिकार होता है। बंगाल का दावा है कि देश में मलमल के निर्माण व विकास में उसका सबसे बड़ा योगदान है। बताते चलें कि करीब एक हजार साल पहले ब्रह्मपुत्र के किनारे आबादी बहुल क्षेत्र में जिस मलमल उद्योग को प्रसिद्धि मिली, उसका साम्राज्य गंगा के दोनों किनारों के विशाल क्षेत्र में भी था। अब राज्य सरकार उसी मलमल को दुनिया के दरबार में फिर से पेश करने का प्रयास कर रही है।

बंगाल सरकार का दावा : राज्य सरकार का दावा है कि बंगाल में ही सही मायने में मलमल का निर्माण व विकास हुआ था। पश्चिम बंगाल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने जीआई टैग के लिए चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय में आवेदन किया है।

अधिकार

- जियोग्राफिकल इंडीकेशन टैग यानी भौगोलिक संकेतक के लिए किया आवेदन
- बंगाल का दावा, देश में मलमल के निर्माण व विकास में उसका ही सबसे बड़ा योगदान
- 17वीं व 18वीं शताब्दी में बंगाल से ही पूरे यूरोप में मलमल का किया जाता था निर्यात

63 क्लस्टरों में हो रहा मलमल का उत्पादन

पश्चिम बंगाल खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड के मुताबिक राज्य में बांकुड़ा, बीरभूम, हावड़ा, मालदह, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, नदिया, पूर्व और पश्चिम बर्धमान, झाड़ग्राम, पुरुलिया, कलिम्पोंग, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में कुल 63 क्लस्टरों में मलमल का कपड़ा बनाया जाता है। इसके उत्पादन में 40 हजार बुनकर शामिल हैं।

आवेदन में मलमल के सुनहरे इतिहास का जिक्र

सूत्रों के मुताबिक आवेदन में बंगाल के मलमल के सुनहरे इतिहास का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मलमल पहनने के कारण पुत्री को फटकार लगाई थी। बताया गया है कि कैसे अंग्रेजी सरकार ने अपने देश के वस्त्रों के विपणन के उद्देश्य से बंगाल के मलमल कलाकारों के अंगुठे काट दिए थे। 17वीं व 18वीं शताब्दी में बंगाल से ही पूरे यूरोप में मलमल निर्यात किया जाता था। वर्ष 1717 में 1000 हजार मीटर मलमल का वजन एक ग्राम होता था, जिसकी कीमत तब चार सौ रुपये थी। उस समय एक परिवार का महीने का खर्च एक रुपये होता था। इन दस्तावेजों में बंगाल के मलमल का बखान है।

300 से ज्यादा उत्पादों को मिला है जीआइ टैग

देश में दार्जिलिंग की चाय, मलिहाबाद का आम, चंदेरी की साड़ी जैसे करीब 300 से ज्यादा उत्पादों को अपने क्षेत्र की विशिष्ट पहचान के लिए जीआइ टैग मिल चुका है।

बंजर भूमि में जंगल बन लहलहा रहा 30 वर्षों का प्रयास

बृजेश भट्ट, रुद्रप्रयाग

- 76 साल की प्रभा सेमवाल की सोच और प्रयास से बदल गई बंजर की तकदीर
- भूस्खलन तो रुका ही, लोगों की जंगल से जुड़ी जरूरतें भी हो रहीं पूरी
- दर्जनभर गांवों को मिल रही राहत, पशुओं के लिए चारा व पत्ती, बढ़ा इलाके का भूजलस्तर

प्रभा सेमवाल ने भले ही उम्र के 76 वसंत पूरे कर लिए हों, लेकिन कठिन परिश्रम से मुंह मोड़ना उन्हें आज भी गवारा नहीं। प्रभा के इसी परिश्रम का नतीजा है बंजर भूमि पर लहलहाता जंगल। इस जंगल में विभिन्न प्रजाति के 500 से अधिक पेड़ न केवल प्रकृति और समाज के प्रति उनके संघर्ष की गवाही दे रहे हैं, नई पीढ़ी को भी पर्यावरण रक्षा के लिए आगे आने को प्रेरित कर रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण

लगभग 30 साल पहले अवैध कटान और भूस्खलन से रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के ऊखीमठ ब्लॉक स्थित फली फसालत गांव से लगे जंगल का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था। इससे फली फसालत समेत आसपास के एक दर्जन से अधिक गांवों में जलावन लकड़ी और मवेशियों के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में प्रभा ने गांव के नीचे दरमई में अपने बंजर खेतों के किनारे विभिन्न प्रजाति के चारा-पत्ती वाले पौधों का रोपण किया। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के साथ करीब 30 वर्ष तक वह यहां तुन, बांज, बुरांश, काफल, रीठा, दाली चीनी, हैड़ा, भीमल, गुरियाल आदि प्रजातियों के पौधों को रोपण करती रहीं। नतीजा, गांव का भूस्खलन तो रुका ही, लोगों की जंगल से जुड़ी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करतीं प्रभा सेमवाल। जागरण

हरितिमा का उपहार...

प्रभा के अपने घर के आसपास खूबसूरत बागीचा खड़ा किया है, जहां माल्टा, संतरा, अनार अमरूद, आंवला आदि के 40 से अधिक पेड़ सालभर फल दे रहे हैं। आज फली फसालत ही नहीं, अन्य गांवों की महिलाएं भी उनसे प्रेरित होकर पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आ रही हैं। इस जंगल के कारण गांव में प्राकृतिक स्रोत भी पानी से लबालब हो गए हैं। जिससे ग्रामीणों की दिनचर्या काफी आसान हुई है।

जंगल में पारंपरिक वेशभूषा में प्रभा सेमवाल। जागरण

प्रभा बताती हैं कि पर्यावरण संरक्षण के इस कार्य में उनके पति शिव प्रसाद सेमवाल भी पूरा सहयोग करते हैं। शिव प्रसाद कहते हैं घर-परिवार और सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति पत्नी के समर्पण से उन्हें गर्व की अनुभूति होती है।

वर्ष 2019 तक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग में प्रभागीय वनाधिकारी रहे राजीव धीमान भी प्रभा के पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों को समाज के लिए नजीर मानते हैं। वहीं, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विष्णुकांत शुक्ला कहते हैं कि प्रभा ने गांव ही नहीं, क्षेत्र को भी नई पहचान दी है। उनसे प्रेरित हो आसपास के गांवों की महिलाएं भी अपने घरों के पास पौधारोपण कर रही हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए महिलाओं का आगे आने से पता चलता है कि वह पर्यावरण को लेकर कितनी गंभीर हैं। अच्छी बात यह है कि नई पीढ़ी भी इसमें सहयोग कर रही है।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

दैनिक जागरण
सबरंग
शहर को जानने के...
नई दिल्ली, शनिवार, 14 मार्च, 2020
सुझाव व प्रतिक्रिया के लिए लिखें : sabrang@nda.jagran.com
https://www.facebook.com/jagransabrang/

आइटीओ नहीं राम चरण अग्रवाल चौक है ये

नाम से पहचान है

दिल्ली पुलिस का पुराना मुख्यालय, लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय, इन्कम टैक्स विभाग जैसे तमाम बड़े दफ्तर यहां आसपास हैं। लाखों लोग हर दिन इस मार्ग से गुजरते हैं, सुबह-शाम तो इस जगह वाहनों का रेला रहता है। हम बात कर रहे हैं राम चरण अग्रवाल चौक की, जिसे बहुधा लोग आइटीओ ही बताते हैं। विरले ही किसी से सुना हो कि हां, वह राम चरण अग्रवाल चौक पर खड़ा है। या वहां से गुजर रहा है। यह महज चौक नहीं है बल्कि दिल्ली का इतिहास इसमें समाया है। यह दिल्ली के प्रथम उप महापौर लाला रामचरण अग्रवाल के नाम पर है। जिन्हें प्यार से लोग लाला जी ही बुलाते थे। जन्म 2 दिसंबर 1917 को नजीबाबाद, उप्र में हुआ था। लाला जी, महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रभावित थे। 19 साल की उम्र में ही वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष बन गए। स्वाधीनता आंदोन के दौरान उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें पहली बार 1939 में गिरफ्तार किया गया और 1942 एवं 1945 में उन्हें पुनः जेल जाना पड़ा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए दिल्ली से जिन 11 व्यक्तियों को चुना था उनमें एक लाला रामचरण अग्रवाल भी शामिल थे। समाज में इनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उन्हें दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी चुनाव 1951 में एवं पुनः 1954 में मालीवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिया गया। वे दोनों ही चुनावों में विजयी रहे। उन्होंने 1958 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीता और दिल्ली के प्रथम डिप्टी मेयर चुने गए। लालाजी

रामचरण अग्रवाल चौक ● जागरण

को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 'लिटिल बिग मैन' के नाम से जाना जाता था।

यमुना की सफाई की पहल : लालाजी महान दूरदृष्टा थे। उन्होंने यमुना नदी की सफाई करने की जरूरत पर बल दिया और नदी में गंदा पानी न गिरे, इसके लिए प्रस्ताव रखा। वे निर्धन, बेघरों की भी फिक्र करते थे। बेघरों के लिए उनके द्वारा शुरू की गई रैनबसेरा स्कीम सका प्रमाण है। 1966 में वे नवगठित मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के लिए चुने गए। स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान के लिए भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ फखरुद्दीन अली अहमद ने लाला जी को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया। इनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साल 2000 में आइटीओ क्रासिंग का नाम रामचरण अग्रवाल चौक रखा गया था। इनकी मृत्यु 25 जुलाई 1977 को हुई थी। भारतीय डाक ने भी इनके उपर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

संजीव कुमार मिश्र

दिल्ली की दास्तां

...जलाया यार ने ऐसा कि हम वतन से चले, बतौर शमा के रोते इस अंजुमन से चले, न बागबां ने इजाजत दी सैर करने की, खुशी से आए थे रोते हुए चमन से चले...आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की शायरी की ये पंक्तियां... उनके दिल्ली सल्तनत से रुख्सत होने की तकलीफ की बानगी हैं...इसके बाद उनके शहजादों की क्या कहानी रही, किस तरह सत्ता के लिए जीनत महल ने अपने शहजादे जवां बख्त को तैयार किया...फिर भी नाकाम रहीं, और पांचवे बेटा मिर्जा मुगल बगैर रजामंदी के कमांडर इन चीफ बने, भाइयों से बगावत का जिक्र भी इतिहास करता है। सबरंग के इस अंक में जफर के शहजादों की दास्तां जिसका दिल्ली के दरवाजों में ही अंत हुआ, रूबरू करा रहे हैं संजीव कुमार मिश्र :

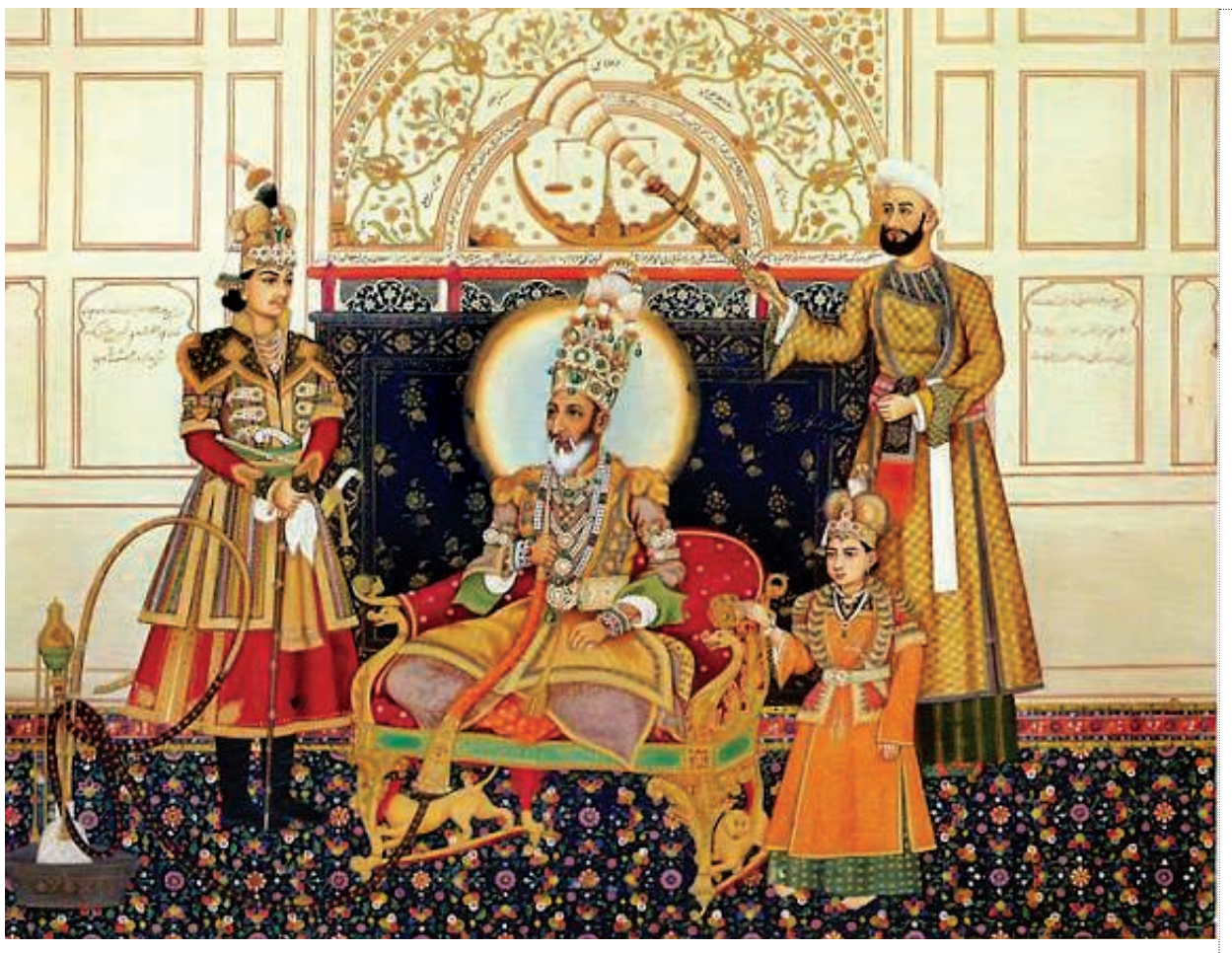
बदुर शाह जफर बीच में व छोटे मिर्जा मुगल दाईं तरफ तब उनकी उम्र यही कोई 10 वर्ष रही होगी। सौजन्य : द लास्ट मुगल किताब

सफर जफर के शहजादों का

नौ मार्च की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही वह दिन है जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के खिलाफ राजद्रोह और हत्या के आरोपों में 40 दिन तक चले मुकदमे का पटाक्षेप हुआ और ब्रितानिया हुकूमत ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान दिए गए वचन के मुताबिक जफर को बर्मा निवार्सित किया जाएगा। जफर के खिलाफ 27 जनवरी से 09 मार्च, 1858 तक मुकदमा चला था। पहले स्वतंत्रता संग्राम का यह मुकदमा जितना एकतरफा था, संग्राम की कहानी उतनी ही जुझारू। क्रांति के संदर्भ में आखिरी मुगल बादशाह जफर का जिक्र तो गाहे-बगाहे होता ही रहता है लेकिन शहजादों की भागीदारी पर बहुत बात नहीं होती। जबकि संग्राम में इनकी सक्रिय भागीदारी थी। इक्का-दुक्का अवसरों को छोड़ दें तो इनके बारे में लिखा भी बहुत कम ही गया है। शहजादों को आराम पसंद और कामचोर तक लिखा गया। जबकि दरबार के रिकार्ड बताते हैं कि बहुत से शहजादों ने 1857 में ना केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था बल्कि नेतृत्व किया था। शहजादे किले के अंदर व बाहर भी शासन में काफी सक्रिय थे। ये अलग बात है कि जफर की बेगम जीनत महल ने खुद के अलावा बेटे मिर्जा जवां बख्त और बादशाह जफर को इस बगावत से दूर दिखाने की कोशिश की थी।

जवां बख्त की आलीशान शादी के बावजूद रह गया ख्वाब अधूरा : सन् 1852 में मार्च का महीना लाल किले के लिए बहुत व्यस्तताओं भरा था। जफर की प्रिय बेगम जीनत महल शहजादे जवां बख्त की शादी की तैयारियों में लगी थीं। ये और बात है कि उस समय शहजादे की उम्र महज 11 साल थी। लेकिन जफर के बाद जवां बख्त के सिर पर दिल्ली का ताज सजाने के चलते जीनत इस शादी को यादगार बनाना चाहती थीं।

2 अप्रैल को जब जवां बख्त की बरात रात के दो बजे लाल किला के लाहौरी दरवाजे से निकली। किले की दीवार पर रखे तोप, गोलों से सलामी दी गई। इसी वक्त आतिशबाजी से पूरा आसमान रोशन हो उठा। साथ ही चांदनी चौक के सामने वाले दोनों दरवाजे खुल गए। सबसे पहले चोबेदार सामने आए। जुलूस के सारे रास्तों पर दोनों तरफ बांस की बल्लियां लगी थीं ताकि आम लोग जुलूस के रास्ते में ना आ जाएं। जुलूस को रास्ता दिखाने के लिए बल्लियों पर लॉलटेन लगाए गए थे। शुरुआत में दो शाही अफसर घुड़सवार निकले। जिनके घोड़ों की गर्दन के बालों में सीपियों के जेवर पिरोये गए थे। उनके गले और टखनों में चांदी की घंटियां थीं। इनके दाएं-बाएं किले के खिदमतगार हाथ में पंखा लिए चल रहे थे। और पीछे मुगलिया फौज एवं फिर हाथियों का दस्ता चल रहा था। हाथियों की गर्दन पर सुनहरी वर्क था। जाफरानी रंग का कपड़ा झूल रहा था। जिस पर बादशाह का अलामती निशान, सोने के तारों से कढ़ा था। हर हाथी के हौदे पर एक शाही अफसर हाथ में बादशाह के शाही खानदान का झंडा लिए था। किले के सेवक भी लाल वर्दी में थे। जिनके हाथों में ख्वानपोश से ढकी थालियां थीं। जिसमें दुल्हन के खानदान के लिए मिठाइयां और फल, मेवे थे। और अंग्रेजी दस्ता चल रहा था। जिसकी अगुवाई कमांडिंग कैप्टन डगलस कर रहा था। लंबे जुलूस के पीछे घोड़ों पर बैठकर शहजादे निकले। उनके बीच दुल्हे की बग्घी थी और उसके ठीक पीछे बादशाह का हाथी झूमते हुए चल रहा था। जीनत महल यह सब देखकर खुश थीं। इसकी तैयारी वो महीनों से कर रही थीं। पैसे के इंतजाम के लिए जीनत महल ने क्रूरता के लिए विख्यात ख्वाजासरा महबूब अली खान की मदद से साहूकारों से पैसा लिया था। हालांकि यह सारी कवायद विफल साबित हुई थीं और मिर्जा जवां बख्त के सिर पर ताज नहीं सज सका था।

शहजादा बनने के लिए होती रही जोर आजमाइश: विलियम डेलरिम्पल अपनी किताब 'द लास्ट मुगल' में लिखते हैं कि पांच शहजादे ऐसे भी हैं जिनका जिक्र बमुश्किल ही मिलता है। मिर्जा जवां बख्त को जीनत महल, जफर के बाद बादशाह बनवाना चाहती थीं। अंग्रेजों से सिफारिश भी की लेकिन बात नहीं बनी। जबकि पांच अन्य शहजादे 1857 की बगावत में खासे सक्रिय रहे। इनमें से चार शहजादे तो कम प्रतिभा और दरबार में कम मुकाम वाले थे। 1857 से पहले उनके दरबार की डायरी में कोई खास जिक्र भी नहीं है। मिर्जा खिजर सुल्तान, जफर का नौ वां बेटा था। वह क्रांति के समय महज 23 साल का था। वह अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात था। गालिब ने उसे हजरत युसूफ की तरह खूबसूरत कहा था। वह शायरी भी करता था और एक अच्छा निशानेबाज भी था। लेकिन दरबार की डायरी में उसका जिक्र सिर्फ एक बार किया गया है। जब उसने 1852 में अपने पिता से हाथी और महरौली में एक मकान की फरमाइश की थी। जिसे फौरन ठुकरा दिया गया था। शायद इसके पीछे यह भी कारण था कि वह मिर्जा फाखरू के करीबी था। जो उस समय शाही नाराजगी झेल रहे थे। दरबार की डायरी में दूसरी बार मिर्जा खिजर सुल्तान का जिक्र तब है जब उसे जफर ने डांटा था। उस पर आरोप था कि उसने अपनी बीवी पर हाथ उठाया था। मिर्जा खिजर, दूसरे शहजादे अबू बक्र का बहुत करीबी दोस्त था। जिसने बागियों की तरफदारी की थी। मिर्जा अबू बक्र, मिर्जा फाखरू का सबसे बड़ा बेटा था और जफर का सबसे बड़ा पोता भी। 1857 से पहले उसका जिक्र सिर्फ एक बार किया गया जब नवंबर 1853 में उसने एक हादसे में अपनी ही बंदूक से अपनी ही अंगुली उड़ा ली थी। तीसरा शहजादा और भी गुमनाम था। 1857 से पहले उसके बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था कि वह जफर का 11वां बेटा है। 1852 में इसकी मिर्जा फाखरू की बेटी से शादी हुई थी। चौथा बागी शहजादा मिर्जा अब्दुल्लाह भी जफर का पोता था। यह जफर के सबसे बड़े बेटे मिर्जा शाहरुख का बेटा था। जिसकी 1847 में मौत हो गई थी। पिता

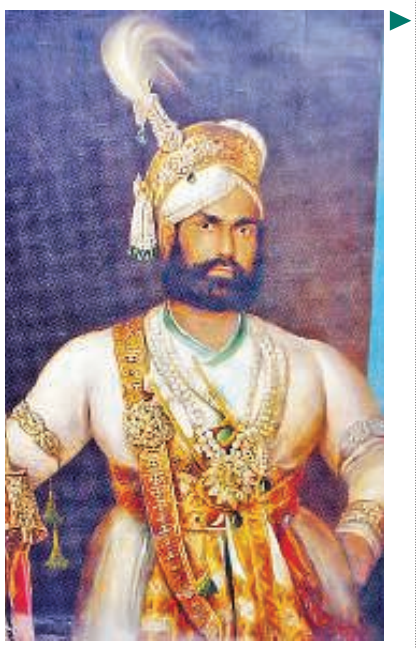
मिर्जा मुगल ● सौजन्य : द लास्ट मुगल किताब

की मौत के बाद अब्दुल्लाह अपनी मां के साथ हज पर गया था। हज से वापस लौटने पर जफर ने इसे बतौर इनाम एक सफेद घोड़ा दिया था।

जब जफर का पांचवा बेटा मिर्जा मुगल जबरन बना कमांडर

पांचवां शहजादा मिर्जा मुगल इन चारों से भिन्न था। वह जफर का पांचवा बेटा था। 1857 में वह 29 साल का था और अपनी प्रभावशाली सौतेली मां जीनत महल से सिर्फ नौ साल छोटा था। बाकि चार शहजादों के विपरीत मिर्जा मुगल के बगावत करने से पहले दरबार के रिकॉर्ड में काफी जिक्र है। उनका दरबार में काफी अहम दर्जा था। इन्हें किले का नाजिर और किलेदार का अहम पद मिला हुआ था।

मिर्जा मुगल की दो तस्वीरें मिलती हैं। एक 1833 में जफर के ताजपोशी के दौरान की है, जिसमें वह एक गंभीर दस वर्षीय बालक हैं और पूरे दरबारी लिबास में हैं। लेकिन 1850 में ऑगस्ट शोफ्ट की एक पेंटिंग में वह एक सुंदर, जोशीले और चुस्त जवान के रूप में दिखते हैं। मिर्जा मुगल के बारे में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि जब बगावत के पहले दिन सिपाही दिल्ली आए तो वो कहां थे लेकिन 12 मई की सुबह वो दरबार में अपने छोटे भाइयों के साथ हाजिर हुए और सबने दर्खास्त की कि उनको फौज का कमांडर बनाया जाए। जफर ने जीनत महल और हकीम अहसनुल्लाह खां से मशवरे के बाद यह दर्खास्त नामंजूर कर दी।

अहसनुल्लाह ने कहा कि उनकी उम्र और तजुर्बा इस काबिल नहीं कि उनको कमांडर बनाया जाए और वह फौज के अफसरों की जिम्मेदारी समझ सकें। वह यह सुनकर बहुत नाखुश हुए और अगले दिन फिर फौज के अफसरों के साथ आए। जिन्होंने फिर सिफारिश की। लेकिन जफर ने दोबारा मना कर दिया। कहा कि तुम्हें यह काम करना नहीं आता। तुम अफसर बनकर क्या करोगे? लेकिन शहजादे और अफसर अपनी बात पर अड़े रहे। यहां तक की दो दिन बाद 15 मई को वह अलग अलग कमांडर के ओहदे पर नामजद हो गए और उनको लिबासे-फाखरा दिया गया। और सिपाहियों की मर्जी से मिर्जा मुगल को कमांडर इन चीफ का खिताब दिया गया। यह मुमकिन है कि मिर्जा मुगल ने अपने भाइयों के साथ बगावत शुरू होने से पहले क्रांतिकारियों से मुलाकात की हो। कम से कम जीनत महल का तो यही कहना था। जब जीनत महल को बगावत के बाद कैद किया गया, तो लेफ्टिनेंट एडवर्ड ओमैनी ने 30 सितंबर 1857 की अपनी डायरी में लिखा 'आज सुबह सान्डर्स आए। पूर्व रानी से तफसील से बातचीत की, उन्होंने वही कहा जो मुझसे कहा था। यही कि खुद उनका, या उनके बेटे जवां बख्त या भूतपूर्व बादशाह जफर का बगावत से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उनके हरम के बेटे मिर्जा मुगल और खिजर सुल्तान और उनके पोते अबू बक्र का इसमें काफी अहम हिस्सा था। खुद, उनके इल्म में बगावत की पहले से कोई सूचना नहीं थी। लेकिन शायद उन तीनों को पता था।

अब क्या सच है, क्या झूठ यह चर्चा का विषय है लेकिन दरबार की डायरी में कई पन्ने अभी भी पलटने बाकि हैं।

सिंधिया घराने का दिल्ली से नाता

दिल्ली की देहरी

नलिन चौहान
दिल्ली के अनजाने इतिहास के खोजी

देश में हाल के दिनों में हुई राजनीतिक गतिविधियों के कारण सिंधिया परिवार सुर्खियों में है। अगर इतिहास में झांके तो पता चलता है कि अंग्रेज कंपनी बहादुर ने वर्ष 1830 में पटपड़गंज की लड़ाई में सिंधिया राजवंश की सेना को हराकर ही दिल्ली पर कब्जा जमाया था। इस तरह सिंधिया घराना और दिल्ली का इतिहास एक-दूसरे से गुंथा हुआ है। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों पर सिंधिया परिवार की उपस्थिति आज भी नजर आती है। दिल्ली में सिरेमिक (मिट्टी के बर्तन) उद्योग का आरंभ वर्ष 1914 में दिल्ली पॉटरी वर्क्स की स्थापना के साथ हुआ। फिर वर्ष 1923 में सिंधिया या ग्वालियर पॉटरी वर्क्स की शुरुआत हुई। दूसरे विश्व युद्ध में इस उद्योग की इकाइयों की संख्या में इजाफा हुआ और उत्पादन में विविधता बढ़ने के साथ वृद्धि हुई।

कारीगरों को नया स्थान उपलब्ध कराने के लिए पॉटरी वर्क्स की शुरुआत : 1957 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद के रूप में संसद पहुंचने वाली विजयाराजे सिंधिया ने इस विषय पर अपनी आत्मकथा में लिखा है कि माधोराव सिंधिया ने ग्वालियर पॉटरी शुरू कर स्वयं के उद्योग स्थापित न करने के अपने नियम को तोड़ा। उन्होंने ऐसा निर्णय इसलिए किया, क्योंकि वे गांवों के पारंपरिक कारीगरों को उनके उत्पाद की बिक्री के लिए एक नया स्थान उपलब्ध करवाना चाहते थे। यह रियासत के राजा की दूरदर्शिता और मानवीय पक्ष को दर्शाता है। उन दिनों तीस एकड़ के भूखंड वाली यह फैक्ट्री, नई दिल्ली के दक्षिण में लगभग दस मील की दूरी पर स्थित थी। आज भी सरोजनी नगर के लेखा विहार में सिंधिया पॉटरिज कंपाउंड है, जिसकी बाईं ओर सरोजनी नगर बाजार है तो दाईं ओर अफ्रीका एवेन्यू की सड़क, जबकि इसका प्रवेश द्वार रिंग रोड की तरफ है। सिंधिया पॉटरी के नाम से मशहूर और करीब 40 एकड़ में फैले सिंधिया परिवार की यह जमीन बेशकीमती है। इसे लेकर अब न्यायालय में पारिवारिक संपत्ति भी विवाद चल रहा है।

आधुनिक दिल्ली में बस सेवा का प्रारंभ बहुत साधारण रूप में हुआ था। उस समय कुछ निजी वाहन-संचालकों ने कुछ रास्तों पर बसें चलाना शुरू किया। वर्ष 1940 में ग्वालियर एंड नार्दन इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिल्ली में बसें चलाने का परमिट दिया गया। फिर 14 मई, 1948 को भारत सरकार ने सिंधिया की कंपनी से ही दिल्ली की शहरी बस सेवाओं को अपने अधिकार में ले लिया और परिवहन मंत्रालय को सीधे नियंत्रण में लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के तहत उसे दो वर्ष चलाया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1921 में ग्वालियर एंड नार्दन इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी 19 लाख रुपये की पूंजी निवेश के साथ से शुरू की गई थी, जबकि वर्ष 1925 के बाद ग्वालियर दरबार ने राज्य में मोटर-लॉरी सेवाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए कंपनी का कामकाज अपने हाथ में ले लिया था। तब यह कंपनी ग्वालियर रियासत के साथ-साथ कुछ पड़ोसी राज्यों की परिवहन जरूरतों को भी पूरा करती थी।

दिल्ली परिवहन निगम का कनॉट प्लेस में स्थित कार्यालय आज भी सिंधिया हाउस ही कहलाता है। प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनके ठेकेदार दादा सुजान सिंह ने अपने लिए वेंगर्स से लेकर अमेरिकन एक्सप्रेस तक का कनॉट प्लेस का एक पूरा ब्लॉक बनवाया। उन दिनों यह सुजान सिंह ब्लॉक कहलाता था। इतना ही नहीं, उन्होंने ही रीगल बिल्डिंग, नरेंद्र प्लेस, जंतर मंतर के पास सिंधिया हाउस बनाया। ये सब उनकी निजी संपत्तियां थीं। अंग्रेजी लेखक रस्किन बांड अपनी पुस्तक 'सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ' में बीसवीं सदी के चौथे दशक की दिल्ली के बारे में लिखा है कि उन्होंने कनॉट सर्कस के सामने एक अपार्टमेंट वाली इमारत सिंधिया हाउस में एक फ्लैट ले लिया था। यह मुझे पूरी तरह से माफिक था, क्योंकि यहां से कुछ ही मिनटों की दूरी पर सिनेमा घर, किताबों की दुकानें और रेस्त्रां थे।

27 भवनों के सरकारी अधिग्रहण में सिंधिया हाउस भी : महाराज माधोराव ने दिल्ली के सिविल लाइन क्षेत्र में अपना तीसरा घर ग्वालियर हाउस, 37, राजपुर रोड पर बनवाया। इसके मूल में वर्ष 1911 में अंग्रेजों के दिल्ली दरबार में कोलकाता (पहले कलकत्ता) से राजधानी के दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा थी। जिसके बाद अंग्रेज सरकार ने सभी राजा-रजवाड़ों को दिल्ली में अचल संपत्ति लेने का आदेश दिया था। उसमें भी विशेष कर राजपूताना और मध्य भारत के राज प्रमुखों से यह बात कही गई थी। अंग्रेजों के राज में ग्वालियर रियासत को हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर और बड़ौदा को सबसे अधिक 21 तोपों की सलामी की पात्रता मिली हुई थी।

उस दौर में इंडिया गेट से हटकर सिविल लाइंस इलाके में, ग्वालियर, जामनगर, कोल्हापुर, नाभा, सिरोही और उदयपुर रियासतों ने अपने भवन निर्मित किए थे। 25 अगस्त, 1948 को संविधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 470 के उत्तर में नरहर विष्णु गाडगिल ने बताया था कि दिल्ली में रियासतों के कुल 27 भवन हैं, जिसमें से भारत सरकार ने 11 इमारतों का सरकारी कार्यालय या आवास के रूप में उपयोग के लिए अधिग्रहण किया है। इन 27 भवनों में ग्वालियर हाउस भी शामिल था।

37, राजपुर रोड के इसी बंगले में रहता था राज परिवार

वरिष्ठ अंग्रेजी पत्रकार कूमी कपूर ने अपनी पुस्तक द इमरजेंसी : ए पर्सनल हिस्ट्री बॉय में तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौर से जुड़ी इसी भवन की कहानी लिखी है। पुस्तक के अनुसार सरकार ने उनके (विजयराजे सिंधिया) बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। आयकर अधिकारियों ने ग्वालियर रियासत की दिल्ली, पुणे, मुंबई और ग्वालियर में सभी संपत्तियों पर छापा मारा। अधिकारियों ने दिल्ली में 37, राजपुर रोड के बंगले, जहां पर राज परिवार रहता था को अधिग्रहित कर लिया था। इतना ही नहीं, तब इस इमारत को बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन की निगरानी से जुड़े अधिकारियों को आवंटित कर दिया गया। तब विजयाराजे सिंधिया तिहाड़ जेल में भी कैद रहीं। आधुनिक भारतीय संसदीय इतिहास में विजयाराजे सिंधिया अपने राजनीतिक जीवन में सात बार लोकसभा और दो बार राज्यसभा की सदस्य रहीं, जो एक महिला नेता के नाते रिकॉर्ड है।

स्पाइरल आलू का तंदूरी स्वाद

जायका

सदाबहार सब्जी आलू। विभिन्न सब्जियों के आलावे आलू के पराठे और चिप्स भी खूब खाते होंगे, लेकिन एक बार स्पाइरल पोटैटो खा कर देखिए। सोच रहे होंगे कहां तो ज्यादा दूर नहीं बस लक्ष्मी नगर स्थित अमृतपाल सिंह की दुकान पर पहुंच जाएं। वे स्पाइरल पोटैटो का ऐसा स्वाद चखाएंगे जिसे खाने के बाद आप हर शाम यहां पहुंच जाएंगे। अमृत साधारण आलू को भी इतना क्रंची और चटपटा बना देते हैं कि लोग उसका स्वाद लेने के लिए दूर-दूर से यहां आते हैं। शाम होते ही लक्ष्मी नगर स्थित अमृत स्पाइरल पोटैटो पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ जुटने लगती है। भले ही आप आलू से परहेज करते हों लेकिन एक बार स्पाइरल पोटैटो खा कर देखें आलू के दीवाने हो जाएंगे।

दोस्त से मिली प्रेरणा : अमृतपाल सिंह करीब एक साल से स्पाइरल पोटैटो बना रहे हैं। इसके पहले वे इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते थे। लेकिन उनकी रुचि उस काम में नहीं थी। उन्हें तो खाना बनाने का शौक था। एक दिन उनके एक दोस्त ने सुझाव दिया कि आजकल स्पाइरल पोटैटो काफी लोकप्रिय है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। फिर क्या था दोस्त का सुझाव पाते ही उन्हेंने अपने शौक को आमदनी का जरिया बना लिया और लोगों को आलू का उम्दा स्वाद चखाने लगे।

तंदूर फ्लेवर भी उपलब्ध : यहां आपको 100 रुपये में स्वादिष्ट स्पाइरल पोटैटो मिल जाएंगे। अगर इसमें पेरिफेरी फ्लेवर चाहिए तो 120 रुपये में आप उसका स्वाद भी ले सकते हैं। अगर थोड़ा हेल्दी स्वाद लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में तंदूरी फ्लेवर भी उपलब्ध है। अमृत कहत हैं स्पाइरल पोटैटो के लिए वे पहले आलू को उबालते हैं। फिर उबले हुए आलू को गोल-गोल काटकर एक स्टिक में लगाकर 90 सेकेंड तक

स्पाइरल पोटैटो तैयार करते अमृतपाल सिंह

उसे पकाते हैं। उसके बाद घर पर तैयार 10 से 12 तरह के पिसे मसाले उसमें मिलाकर उसे चटपटा बनाया जाता है। इसे टमाटर और चिली सॉस, मियोनीज व कॉर्न फ्लैक्स के साथ परोसा जाता है। अगर चटपटा खाने के बाद कॉपी पीने का मन हो तो यहां उसकी भी सुविधा है। हाथ की पीसी कॉफी पेस्ट का स्वाद ले सकेंगे।

फूड फेस्टिवल में मिली अच्छी प्रतिक्रिया : अमृत ने पिछले वर्ष जेएलएन स्टेडियम में आयोजित स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में भी भाग लिया था। फेस्टिवल में आने वाले लोगों द्वारा उनके स्पाइरल पोटैटो को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। कहते हैं शेफ संजीव कपूर भी उनके स्टॉल पर आए और उन्होंने भी उनकी डिश की खूब तारीफ की। हाल ही में अमृत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में भी स्टॉल लगाया जहां छात्रों ने जमकर इसका स्वाद लिया।

-रितु राणा

खुलने का समय : रोजाना शाम पांच बजे से रात साढ़े दस बजे तक।

नजदीकी मेट्रो स्टेशन : लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन से पैदल ही यहां जा सकते हैं।

लो जी अब आलू हो गया टेस्टी और क्रिस्पी ● जागरण

निजी हवाई अड्डों ने की राजस्व साझा करने से छूट की मांग

नई दिल्ली : निजी हवाई अड्डों ने सरकार से तीन महीने के लिए राजस्व साझा करने में छूट की मांग की है। कोरोना के चलते बुरी तरह से प्रभावित हवाई यातायात के कारण इस सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके साथ ही हवाई अड्डों की ओर से हवाई टिकट पर अतिरिक्त फीस लगाने की इजाजत भी मांगी गई है। हवाई अड्डों की संचालक कंपनियों का कहना है कि यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए उन्हें अलग से संसाधन जुटाने पड़ रहे हैं, जिनमें काफी अधिक खर्च हो रहा है। (आइएएनएस)

सातों दिन और चौबीसों घंटे शिपमेंट को मंजूरी देने का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है। इससे ऑटो सेक्टर को बड़ा फायदा होगा।

— राजन वढ़ेरा
महानिदेशक, सियाम

सेंसेक्स	34,103.48 ▲ 1,325.34	निफ्टी	9,955.20 ▲ 365.05	सोना (प्रति दस ग्राम)	₹ 42,600 ▼ ₹1,097	चांदी (प्रति किलोग्राम)	₹ 44,130 ▼ ₹1,574	$ डॉलर	₹ 73.80 ▼ ₹ 0.48	क्रूड (ब्रेंट) (प्रति बैरल)	$ 34.01

बीते 12 वर्षों में नहीं आई थी सेंसेक्स-निफ्टी की ट्रेडिंग रोकने की नौबत

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार को शुरुआती सत्र में लोअर सर्किट तक गिरने के चलते शेयर बाजारों में कुछ देर तक कारोबार रोकना पड़ा। देश के प्रमुख शेयर बाजारों में यह स्थिति 12 वर्ष से अधिक समय के बाद सामने आई।

कारोबारी सत्र के शुरुआती 15 मिनट में ही भारी बिकवाली के कारण प्रमुख सूचकांको में 10 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते बीएसई और एनएसई में 45 मिनट तक ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। नियमों के मुताबिक एक सीमा से अधिक गिरावट के बाद शेयर मार्केट में कुछ समय तक कारोबार पर रोक लगा दी जाती है। ट्रेड रोकने का मकसद अफरातफरी को कम करना और निवेशकों के बीच धैर्य बढ़ाना होता है।

इससे पहले 22 जनवरी, 2008 को ऐसी ही स्थिति बनी थी, जब कारोबार को अस्थायी तौर पर रोकना पड़ा था। उस दौरान सेंसेक्स में तब तक की सबसे बड़ी गिरावट (1,408 अंक) दर्ज की गई थी। सेंसेक्स में पहली चार अंकों की गिरावट तत्कालीन वैश्विक मंदी की आशंका के कारण देखने को मिली थी। इसके बाद पांच अक्टूबर 2012 को भी भारी गिरावट

- **इससे पहले 22 जनवरी, 2008 को 1,400 अंकों से अधिक की गिरावट के बाद लगी थी सेंसेक्स-निफ्टी में लोअर सर्किट**
- **अलग-अलग शेयरों में लोअर या अपर सर्किट लगने की घटनाएं ज्यादा आम हैं**

के चलते एनएसई में ट्रेडिंग रोकनी पड़ी थी। चीन से उपजे कोरोना वायरस के प्रकोप से वैश्विक मंदी की आशंका जाहिर की जा रही है। इसके कारण पूरी दुनिया के बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है।

एशिया के अधिकतर शेयर बाजारों में भारी गिरावट से बचने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। गिरावट से चिंतित दक्षिण कोरिया ने शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगाई हुई है। पिछले महीने कोस्पी छह परसेंट और इस महीने अब तक चार परसेंट गिरा चुका है। इंडोनेशिया ने तेज गिरावट से निपटने के लिए कारोबारी सत्र के दौरान विराम की नीति अपनाई है।

इंडोनेशिया का प्रमुख सूचकांक भी इस सप्ताह 5.7 परसेंट और फरवरी के दौरान आठ परसेंट का गोता लगा चुका है।

कब लगती है ट्रेडिंग पर रोक

- दोपहर एक बजे से पहले 10 परसेंट ऊपर-नीचे होने पर 45 मिनट की बंदी
- दोपहर एक से ढाई बजे के बीच 10 परसेंट ऊपर-नीचे होने पर 15 मिनट की बंदी
- ढाई बजे के बाद 10 परसेंट ऊपर-नीचे होने पर कारोबार नहीं रोका जाता
- एक बजे से पहले 15 परसेंट ऊपर-नीचे होने पर एक घंटे 45 मिनट की बंदी
- एक बजे के बाद और 2 बजे से पहले 15 परसेंट इधर-उधर होने पर दो घंटे 45 मिनट की रोक
- दो बजे के बाद 15 परसेंट की गिरावट होने से पूरा दिन के लिए ट्रेडिंग पर रोक
- दिन में किसी भी समय 20 परसेंट की गिरावट होने से पूरे दिन के लिए ट्रेडिंग पर रोक

इसी महीने की नौ तारीख को डाऊ जोन्स 2,000 अंक तक खिसक गया था।

सेंसेक्स में एक दिन में 5380 अंकों की हुई रिकवरी

प्रथम पृष्ठ से आगे

इस तरह से देखा जाए तो बीएसई के सेंसेक्स में एक दिन में 5380 अंकों की रिकवरी हुई। अगर 3,474 अंकों की गिरावट ऐतिहासिक थी जो यह रिकवरी भी ऐतिहासिक रही। लेकिन इस रिकवरी के बावजूद निवेशक वर्ग भारतीय शेयर बाजार में पिछले कारोबारी हफ्ते के अपने अनुभव को भुलाना चाहेगा। इस हफ्ते सेंसेक्स में कुल 3,473 अंकों (9.24 फीसद) और निफ्टी में 1,034 अंकों (9.41 फीसद) की गिरावट हुई है। वर्ष 2008 के बाद किसी भी एक कारोबारी हफ्ते में देश के शेयर बाजार में दर्ज की गई यह सबसे बड़ी गिरावट है। 9 मार्च और 12 मार्च को भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हो चुकी है। पिछले चार कारोबारी दिनों में निवेशकों का 15 लाख करोड़ रुपये का चूना लग चुका है।

कारण जो भी रहा है लेकिन पिछले तीन कारोबारी दिनों के दौरान भारी कमी दर्ज कर चुकी चुनिंदा कंपनियों के शेयर भाव शुक्रवार को खूब तेज हुए। एसबीआइ (13.83 फीसद), टाटा स्टील (13.65 फीसद), एचडीएफसी (10.19 फीसद), सन फार्मा (8.29 फीसद), भारती एयरटेल (5.79 फीसद) में निवेशकों ने जमकर निवेश किया। हालांकि नेस्ले, एशियन पेंट्स, एचयूएल, एचसीएल, कोल इंडिया, विप्रो जैसी कई कंपनियों के शेयरों में वैसे घाटा भी उठाना पड़ा।

इस हफ्ते की दर्ज ऐतिहासिक गिरावट के लिए वैसे तो कोरोना वायरस का फैलता भय ही प्रमुख तौर पर जिम्मेदार रहा है लेकिन कुछ दूसरे कारकों ने भी माहौल पर नकारात्मक असर डाला है। जैसे, निजी सेक्टर के यस बैंक पर आरबीआइ की लगी पाबंदी भी एक वजह है। क्रूड की कीमतों में हो रही गिरावट से संस्थागत निवेशकों में निराशा का माहौल बना है। कई विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि पिछले दो-तीन तिमाहियों से खराब आर्थिक प्रदर्शन के बावजूद जिस तरह से कई कंपनियों के शेयरों के भाव बढ़े थे, उनके भाव अपने वास्तविक स्तर पर आ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कोरोना वायरस सबसे बड़ा कारण रहा है। जिस तरह से तमाम बड़े देशों के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को घटाया है उससे साफ संकेत मिल गया है कि इस बार मंदी का खतरा ज्यादा गंभीर है।

विमानन कंपनियों के शेयर लुढ़के : यात्रा पाबंदियों के चलते विमानन उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को सेक्टर के स्टॉक्स में 10 परसेंट तक की गिरावट देखने को मिली। इस दौरान इंडिगो और स्पाइसजेट के शेयरों को सबसे ज्यादा धक्का लगा। शुक्रवार को कारोबारी सत्र के दौरान इंडिगो एविएशन के शेयर 14.08 परसेंट तक लुढ़क गए। हालांकि बाद में इनमें सुधार हुआ और 0.76 परसेंट गिरावट के साथ 1,010.75 रुपये के भाव पर बंद हुए। इस दौरान स्पाइसजेट के शेयर 9.99 परसेंट के लोअर सर्किट तक गिरकर 43.70 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बिके।

सोना-चांदी की चमक मलिन

नई दिल्ली, प्रेट्र : शुक्रवार को स्थानीय सराफा बाजारों में गिरावट का रुख रहा। इस दौरान सोना 1,097 अंक नीचे खिसककर 42,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट देखने को मिली। यह 1,574 रुपये लुढ़ककर 44,130 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर थमी। पिछले कुछ सत्रों के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव में सुधार देखने को मिला है, जिससे सोने में निवेश घटा है। जानकारों के मुताबिक रुपये सहित अन्य असेट में सुधार के चलते सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट में सोना 1,584 डॉलर और चांदी 15.65 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) पर बिके। आमतौर पर शेयर के भाव टूटने पर सोने के भाव में तेजी देखी जाती है, लेकिन पिछले तीन दिनों से सोने के दाम में मामूली गिरावट हो रही है। दिल्ली के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने का दाम प्रति 10 ग्राम 44,490 रुपये था। हालांकि कुछ समय पहले ही सोना 45 हजारी होकर लौटा है। शेयर बाजारों की गति को देखते हुए सोने ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। यही वजह है कि फरवरी के पहले सप्ताह में 41,100 रुपये के आसपास रहने वाला सोना इस महीने 44,500 रुपये के स्तर तक जा चुका है। एक माह के दौरान सोने ने 10 फीसद का रिटर्न दिया है जबकि शेयर बाजार में 10 फीसद से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है।

इकोनॉमी पर सरकार की कड़ी नजर

तैयारी ▶ वित्त मंत्री ने कहा – बाजार को संभालने के लिए आरबीआइ जल्द करेगा उपाय

उद्योग जगत के साथ लगातार हो रहीं बैठकें, हालात सुधारने की पूरी कोशिश हो रही

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस से संकट में आए शेयर बाजार एवं अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए शुक्रवार को सरकार ने चौतरफा सक्रियता दिखाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) वैश्विक एवं भारतीय स्टॉक बाजार पर लगातार निगरानी रख रहा है। कोरोना वायरस की वजह से संकट में आए उद्योग को उबारने के लिए विभिन्न मंत्रालय की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित विभाग उद्योग जगत के साथ लगातार संपर्क में हैं। रोजाना उनके साथ बैठकें की जा रही हैं और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना का असर पूरी दुनिया के बाजार पर है और इस पूरे प्रकरण पर मंत्रालय की पैनी नजर है। मैं आरबीआइ के साथ मिलकर मामले पर नजर रख रही हूं। उन्होंने बताया कि उद्योग जगत की जरूरतों को लेकर वह पहले ही उनके साथ बैठकें कर चुकी है। राज्यों के साथ भी सरकार लगातार संपर्क में है। शुक्रवार को सुबह शेयर बाजार में भारी गिरावट रही, हालांकि बाद में शेयर बाजार में रिकवरी देखी गई। गुरुवार को शेयर बाजार में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई थी।

इकोनॉमी की बुनियाद मजबूत : सीईए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : शुक्रवार की सुबह बाजार में हुई भारी गिरावट के बाद बाजार को संभालने के लिए मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की बुनियाद मजबूत है। भारतीय शेयर बाजारों में मौजूदा गिरावट की प्रमुख वजह दुनियाभर के शेयर बाजारों का टूटना है। उनके मुताबिक कुछ सप्ताह में बाजार संभल जाएगा। उन्होंने बताया कि रूस, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी अर्जेंटीना, अमेरिका व जापान जैसे देशों के शेयर बाजारों में इस वर्ष 31 जनवरी से अब तक 20 फीसद तक की गिरावट हो चुकी है। इसी के चलते भारतीय शेयर बाजारों पर भी दबाव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इकोनॉमी की बुनियाद पर कोई सवाल हो। सीईए खुदरा मंहगाई दर में कमी आ गई है और जुलाई तक कोर मंहगाई दर में भी गिरावट आ जाएगी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भी बढ़ोतरी हो रही है और कैपिटल गुड्स में 10 फीसद तक का इजाफा है जो मैन्यूफैक्चरिंग के लिए अच्छा संकेत है।

जीएसटी काउंसिल की बैठक आज, कारोबारियों को राहत संभव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: तय समय के भीतर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने वाले कारोबारियों के लिए समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित होगी। बैठक में जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) में होने वाली समस्या को दूर करने के लिए इन्फोसिस अपना प्रेजेंटेशन दे सकती है। अभी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2020 है। लेकिन जीएसटी नेटवर्क में तकनीकी खामियां आने की शिकायत से कारोबारियों को रिटर्न फाइल करने में भारी दिक्कत हो रही है। सरकार ने जीएसटी नेटवर्क विकसित करने वाली कंपनी इन्फोसिस को इस मामले में तलब किया है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की बैठक में आगामी एक अप्रैल से आरंभ होने वाली ई-इनवॉयसिंग प्रणाली पर भी चर्चा की जाएगी। इस प्रणाली में किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत महसूस होने पर उसकी इजाजत दी सकती है।

निर्यात बढ़ोतरी के लिए नई स्कीम को मंजूरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना संकट से जूझ रहे निर्यात बाजार को शुक्रवार को सरकार ने बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने निर्यात के लिए नई स्कीम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स (आरओडीटीईपी) को मंजूरी दे दी। इसके तहत निर्यात होने वाले उत्पादों को तैयार करने के दौरान लगने वाले कई प्रकार के कर एवं शुल्क से निर्यातकों को छूट मिल जाएगी। अभी निर्यात होने वाले उत्पादों पर कई प्रकार के ऐसे कर लगते हैं जिन्हें वापस नहीं किया जाता है। इनमें बिजली शुल्क, मंडी टैक्स, निर्यात दस्तावेज पर लगने वाले स्टांप शुल्क, बिजली उत्पादन में लगे कोयले पर सीजीएसटी व अन्य सेस, परिवहन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन पर वैट एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसी चीजें शामिल हैं। अब निर्यातकों को इन चीजों पर लगने वाले शुल्क वापस मिल जाएंगे। इससे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता में इजाफा होगा। इस स्कीम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस स्कीम से इंजीनियरिंग व लेदर उत्पाद जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इस स्कीम के तहत मिलने वाली छूट विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के अनुरूप होगी। उन्होंने बताया कि भारत लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज (एलडीसी) की श्रेणी से बाहर आ चुका है। ऐसे में डब्ल्यूटीओ के नियमों के मुताबिक निर्यात पर मिलने वाले इंसेंटिव अब नहीं दिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई स्कीम को निर्यात क्षेत्र की प्राथमिकता के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और इसके साथ ही मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम (एमईआईएस) को चरणबद्ध तरीके से वापस ले लिया जाएगा। अभी निर्यातकों को ड्यूटी ड्रॉबैक और जीएसटी के रिफंड मिलते हैं।

फैसले

- **कई प्रकार के कर व शुल्क में छूट, आरओडीटीईपी मंजूर**
- **इंजीनियरिंग व लेदर उत्पाद जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों को मिलेगा लाभ**

प्रतीकात्मक

फरवरी के निर्यात में 2.91 फीसद की बढ़ोतरी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना संकट की वजह से सप्लाई चेन एवं विश्व बाजार के प्रभावित होने के बावजूद फरवरी माह में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 2.91 फीसद की बढ़ोतरी रही। बड़ी बात यह है कि छह माह की लगातार गिरावट के बाद वस्तुओं के निर्यात में इजाफा दर्ज किया गया है। इस साल फरवरी में 27.65 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया। फरवरी के दौरान वस्तुओं के आयात में पिछले साल फरवरी के मुकाबले 2.48 फीसद की बढ़ोतरी रही। इस दौरान 37.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक फरवरी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के निर्यात में 37.05 फीसद, केमिकल्स में 16.33 फीसद, पेट्रोलियम उत्पाद में 10.08 फीसद, इंजीनियरिंग गुड्स में 8.74 फीसद तो ड्रग्स व फार्मा के निर्यात में 8.33 फीसद की बढ़ोतरी रही।

बाजार की दशा सुधारने के लिए हर कदम उठाने को सेबी तैयार

नई दिल्ली, प्रेट्र : पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को कहा कि शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल से निपटने के लिए वह हर तरह के जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार है। सेबी ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस महामारी से जुड़ी चिंताओं के चलते पिछले कुछ दिनों में अन्य वैश्विक बाजारों की तरह ही भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट दिखी है। कोराना वायरस की वजह से कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें भी गिरी हैं और आर्थिक मंदी की आशंका का डर भी बढ़ा है। नियामक ने कहा, 'सेबी और शेयर बाजार जरूरत के हिसाब से उपयुक्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं।'

- **पूंजी बाजार नियामक ने कहा - वैश्विक बाजारों के चलते दिख रही गिरावट**
- **दुनियाभर के शेयर बाजारों में स्थिति भारत से ज्यादा**

प्रबंधन की मजबूत व्यवस्था की है। यह व्यवस्था बीएसई-सेंसेक्स और एनएसई-निफ्टी के साथ-साथ कंपनियों के शेयरों (नकद और डेरिवेटिव्स) की चाल में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने पर स्वतः काम करने लगती है।

वैश्विक बाजारों से तुलना करते हुए सेबी ने कहा कि फरवरी और मार्च में अब तक घरेलू शेयर बाजार 19 प्रतिशत से अधिक गिरा है। जबकि रूस, ब्राजील और फ्रांस के बाजार 30 प्रतिशत से अधिक गोता लगा चुके हैं। ब्रिटेन का एफटीएसई 100 सूचकांक 28 प्रतिशत, अमेरिका का नास्डैक 21 प्रतिशत और डाऊ जोन्स 25 प्रतिशत गिर चुका है।

ऑटोमोबाइल पर कोरोना का वार, 19 परसेंट खिसकी बिक्री

नई दिल्ली, प्रेट्र : ऑटोमोबाइल कारोबार पर मंदी की मार जारी है। बीती फरवरी में ऑटो उद्योग की बिक्री में 19.08 परसेंट की गिरावट देखने को मिली। बीएस-4 मानक समाप्त होने की अंतिम तिथि नजदीक आने से इनकी थोक बिक्री पहले से ही गिरी हुई है। कोरोना के प्रकोप से खुदरा बिक्री भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सियाम के आकड़ों के मुताबिक समीक्षाधीन अवधि के दौरान घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री 7.61 परसेंट गिरकर 2,51,516 रही। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 2,71,243 यात्री वाहन बिके थे। इस दौरान कारों की बिक्री में 8.77 परसेंट की गिरावट देखी गई।

ऑटो कारोबारियों के संगठन सियाम ने बताया कि पिछले महीने अगल-अलग श्रेणियों में कुल 16,46,332 वाहन बिके, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 20,34,597 वाहन ग्राहकों के हवाले किए गए थे। सियाम के प्रेसिडेंट राजन वढ़ेरा ने कहा कि प्राथमिक तौर पर वाहनों की बिक्री में गिरावट की वजह आर्थिक सुस्ती और बीएस-4 वाहनों की उत्पादन में कमी है। कोरोना के चलते चीन से होने वाली आपूर्ति भी बाधित हुई है, जिससे उत्पादन और प्रभावित होने की आशंका है।

- **बीएस-4 वाहनों के उत्पादन में कमी से भी बिक्री हुई प्रभावित**
- **पिछले महीने अलग-अलग श्रेणियों में कुल 16,46,332 वाहन बिके**

वढ़ेरा ने कोरोना को लेकर किए गए सरकारी प्रयासों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन शिपमेंट को मंजूरी देने का प्रावधान स्वागत योग्य कदम है। सेक्टर की अग्रणी कंपनी मारुति सुजुकी के यात्री वाहनों में 2.34 परसेंट की गिरावट आई। इस दौरान कंपनी ने 1,33,702 वाहन बेचे। दूसरी ओर इसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी ह्यूंडई को बिक्री में 7.19 परसेंट की गिरावट का सामना करना पड़ा। घरेलू बाजारों की पुरानी कंपनियों की अपेक्षा नई कंपनी किआ मोटर्स ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल 15,644 वाहन बेचे।

बीते महीने दोपहिया वाहन कारोबार की बिक्री में 19.82 परसेंट की कमी दर्ज की गई। इस दौरान कुल 12,94,791 दोपहिया वाहन बिके, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 16,14,941 वाहन बिके थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान दोपहिया वाहन कारोबार की अग्रणी कंपनी बजाज में 20.05 परसेंट और टीवीएस मोटर्स की बिक्री में 26.73 की गिरावट देखने को मिली। गौरतलब है कि पिछले पूरे वर्ष के दौरान ऑटो सेक्टर दबाव में रहा है।

एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह तिथि इसी महीने की 17 तारीख को समाप्त हो रही थी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाले पैनल ने इच्छुक खरीदारों को 30 अप्रैल तक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआइ) जमा करने का समय देने का फैसला किया। इस बीच, जेट एयरवेज के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने एनसीएलटी से कंपनी के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 90 दिन बढ़ाने का आग्रह किया है।

इस दौरान सरकार ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवारों की मांग और कोरोना के चलते बनी असमंजस की स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया गया है। ज्ञात हो कि इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने एयर इंडिया में 100 परसेंट हिस्सेदारी बेचने की घोषणा करते हुए विनिवेश प्रक्रिया शुरू की थी। इससे पहले इस सार्वजनिक कंपनी को बेचने की कोशिश विफल साबित हुई थी। लेकिन इस बार कई उम्मीदवार इसको खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं।

बंद पड़े जेट एयरवेज के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में याचिका दायर कर समय बढ़ाने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। इससे पहले जेट एयरवेज के कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने बोली जमा करने की अवधि दो महीना बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका दायर करने की बात कही थी। सीओसी का कहना है कि उसे अभी तक कोई उपयुक्त खरीदार नहीं मिला है।

- **इच्छुक कंपनियां अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकती हैं बोली**

राशन प्रणाली सुधारने के लिए राज्य सरकारें खरीदेंगी अनाज

पहल

डीसीपी स्कीम को बढ़ावा, वित्त मंत्रालय से मांगे 13 हजार करोड़ रुपये, अनाज खरीद, भंडारण व पीडीएस पर बांटने का दायित्व उठाएंगे राज्य

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्य सरकारें किसानों से अनाज की सरकारी खरीद कर अपने प्रदेश की राशन प्रणाली की जरूरतों को स्थानीय स्तर पर पूरा करेंगी। इस योजना के लिए खाद्य मंत्रालय उन्हें हर तरह की मदद देगा। इस बाबत खाद्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 13 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी की मांग की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पर अमल के लिए अनाज की स्थानीय खरीद और राशन दुकानों पर वितरण में जहां सहूलियत होगी, वहीं अन्य कई तरह की फिजूलखर्ची कम होगी।

ज्यादातर राज्य सरकारें डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट (डीसीपी) स्कीम के तहत अनाज की खरीद करती हैं। कुछ राज्यों में केंद्रीय खरीद एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) सरकारी खरीद करती है। लेकिन अब नई व्यवस्था में राज्यों से कहा गया है कि वे अपनी एजेंसियों के मार्फत किसानों से सीधी खरीद करेंगी। खरीदे गए अनाज का रखरखाव और राशन प्रणाली पर अनाज के वितरण का दायित्व सीधे राज्यों को सौंपा जाएगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में अनाज की खरीद और राशन प्रणाली के तहत अनाज के वितरण के लिए कई तरह का फॉर्मूला निर्धारित किया गया है। इसमें पहला, राज्य सरकारें डीसीपी स्कीम के तहत खरीद कर अनाज केंद्रीय एजेंसी एफसीआइ को सौंप देती हैं। जबकि दूसरे प्रावधान में केंद्रीय एजेंसी सीधी खरीद कर राज्यों को उनकी राशन प्रणाली की जरूरत के मुताबिक अनाज की आपूर्ति करती है। लेकिन तीसरा प्रावधान यह है कि राज्य सरकारें सीधे किसानों से अनाज की खरीद करें और अपनी राशन प्रणाली के लिए अनाज का भंडारण और वितरण करें। बाकी बचे अनाज को केंद्रीय एजेंसी को सौंप दें। राज्य सरकारों को इसके लिए सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा।

डीसीपी स्कीम में खरीद के लिए चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आंध्र प्रदेश, केरल, असम और ओडिशा जैसे राज्यों ने इसके लिए अतिरिक्त धन की मांग की है। खाद्य सचिव रविकांत ने इस बाबत वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस स्कीम के तहत होने वाली खरीद के लिए अतिरिक्त धनराशि मांगी है। जबकि अगले वित्त वर्ष के आम बजट में डीसीपी स्कीम के लिए 37 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि इस स्कीम से अनाज की खरीद, ढुलाई, रखरखाव और वितरण में होने वाली कई तरह की गंभीर चुनौतियां कम हो जाएंगी।

चीनी उद्योग को उबारने की कोशिशें जारी : पासवान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि चीनी उद्योग को उबारने के लिए पेट्रोलियम पदार्थों में जैव-ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले एथनॉल की मात्रा अब दस फीसद तक होगी। फिलहाल अभी पेट्रोलियम पदार्थों में इसकी मात्रा पांच फीसद ही है, जो इससे पहले मात्र दो फीसद थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकारा कि इन सारे उपायों के बाद भी चीनी उद्योग संकट में दिख रहा है।

केंद्रीय मंत्री पासवान शुक्रवार को राज्यसभा में चीनी मिलों के संकट से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग को उबारने के लिए सरकार की ओर से उन्हें लगातार मदद दी जा रही है। बावजूद इसके चीनी मिल मालिक नुकसान का हवाला देकर किसानों को भुगतान देने में आनाकानी करते हैं। उन्होंने साफ किया कि हम सिर्फ किसानों से गन्ना खरीद की दरें तय करते हैं। चीनी मिल मालिक यदि किसानों का शोषण कर रहे और भुगतान नहीं कर रहे है तो ऐसी मिलों के खिलाफ राज्य सरकारों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह राज्य सरकारों के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। एक पूरक प्रश्न के जवाब में पासवान ने बताया कि देश में कुल 747 चीनी मिलें है। लेकिन में इनमें से वर्ष 2018-19 में 529 ही कार्यरत थीं, जबकि वर्ष 2019-20 में कुल 446 चीनी मिले ही कार्यरत रह गई हैं। बाकी मिलें बंद हो गईं। वहीं, कुल मिलों में 43 सरकारी चीनी मिलें हैं, जबकि 329 सहकारी चीनी मिलें और 375 निजी मिलें हैं।

पासवान का कहना था कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले वर्षों में चीनी का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन खपत में से कम से करीब सौ लाख टन चीनी स्टॉक में पड़ी है।

सूरतेहाल

- **केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने चीनी उद्योग पर संकट की बात स्वीकारी**
- **कहा- चीनी कंपनियां किसानों के भुगतान में करती हैं आनाकानी**
- **उद्योग की बेहतरी के लिए पेट्रोल में एथनॉल का मिश्रण अब 10 फीसद तक होगा**

300 सदस्यों में से 261 का समर्थन मिला है ग्रीस की संसद में राष्ट्रपति कैटरीना साकेलारोपूलू को। उन्होंने शुक्रवार को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वह हाई कोर्ट की जज भी रह चुकी हैं।

यूरोप में चिंता की लहर, उठाए कड़े कदम

कोरोना का कहर ▶ ईयू देशों में 22 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित, अकेले इटली में 1,016 की हुई मौत

पड़ोसी देशों ने इटली से आवाजाही पर लगाई पाबंदियां, रोम में चर्च बंद

5,043 लोगों ने दुनियाभर में वायरस के चलते गंवाई जान

125 देशों में एक लाख 34 हजार 300 लोग संक्रमित

110 नए मामले दक्षिण कोरिया में शुक्रवार को आए सामने

कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए लोग एक-दूसरे से हाथ मिलाने से परहेज कर रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने व्हाइट हाउस में एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते के जरिए किया। वराडकर भारतीय मूल के हैं। रायटर

ब्रसेल्स, एजेंसियां : चीन के बाद इटली के कोरोना वायरस का नया केंद्र बनने से पूरे यूरोप में चिंता की लहर है। वायरस के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कई यूरोपीय देशों ने कड़े कदम उठाए हैं। इन देशों ने इटली से आवाजाही पर पाबंदियां लगाई हैं। यूरोपीय यूनियन (ईयू) के सभी 27 सदस्य देशों में वायरस पहुंच चुका है। इन देशों में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 22 हजार के पार पहुंच गया है। इनमें से 15 हजार पीड़ित अकेले इटली में हैं।

इटली की राजधानी रोम में सभी कैथोलिक चर्च बंद कर दिए गए हैं। इस यूरोपीय देश में अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। छह करोड़ की आबादी वाले देश में पहले ही सभी कारोबार, स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, रेस्तरां और पब बंद किए जा चुके हैं। इसके चलते तमाम पर्यटन स्थल और सड़कें सूनी हो गई हैं।

ईयू के गृह मंत्रियों ने शुक्रवार को एक बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए समन्वित प्रयास पर जोर दिया। स्वीडन के गृहमंत्री माइकल डेमबर्ग ने कहा, 'देशों में विभिन्न स्तर पर समस्या है। हम उम्मीद करते हैं कि सभी देश जो नए उपाय कर रहे हैं, उसके बारे में दूसरे यूरोपीय देशों को भी सूचित करेंगे।' इटली के कुछ पड़ोसी देशों जैसे आस्ट्रिया और स्लोवेनिया ने अपनी सीमाओं पर यातायात पर सख्ती करना शुरू कर दिया है।

चेक गणराज्य और पोलैंड भी इसी तरह के कदम उठा रहे हैं। इन कदमों से खाद्य पदार्थों और दवाओं की आपूर्ति पर सवाल खड़े हो गए हैं। यूरोप में इटली के बाद स्पेन और फ्रांस ज्यादा प्रभावित हैं।

लंदन में पास्ता, आटा और टॉयलेट पेपर की किल्लत : ब्रिटेन में सख्त कदम उठाए जाने से लोग घरों में खाने-पीने का सामान जमा करने के लिए सुपरमार्केट की ओर दौड़ पड़े। इसके चलते लंदन के कई सुपरमार्केट में पास्ता, आटा, फ्रोजेन फूड और टॉयलेट पेपर की किल्लत हो गई।

सर्वाधिक प्रभावित देश		
देश	मौत	संक्रमित
चीन	3176	80,813
इटली	1016	15,113
ईरान	514	11,364
स्पेन	86	3146
दक्षिण कोरिया	72	7979
फ्रांस	61	2876
अमेरिका	41	1716
जापान	24	1380
ब्रिटेन	10	590

इवांका से मिलने वाले ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्री भी चपेट में

अमेरिका की यात्रा से कुछ दिनों पहले लौटे ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पीटर डटन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। उन्हें ब्रिसबेन के अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्होंने अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका से भी मुलाकात की थी।

ईरान में एक ही दिन में 85 लोगों की जान गई

ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस से 85 और लोगों की जान चली गई। एक दिन में यह सर्वाधिक मौत है। इसे लेकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 514 हो गई है। जबकि 1,289 नए मामले सामने आए हैं।

कुवैत में जुमे की नमाज घर में ही अदा करने की अपील

कुवैत के धार्मिक मामलों के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे घर में ही जुमे की नमाज अदा करें। खाड़ी देशों ने कोरोना से निपटने के उपाय तेज कर दिए हैं। बहरीन में सैकड़ों कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया।

नई सेटेलाइट तस्वीरों में दिखीं ईरान में सामूहिक कब्रें

फैली दहशत

- कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर बढ़ी चिंता, मरने वालों का आंकड़ा 500 के पार पहुंचा

लंदन, एजेंसियां : नई सेटेलाइट तस्वीरों में ईरान के शहर कोम में सामूहिक कब्रें दिखाई दी हैं। इससे ईरान में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 11,364 तक पहुंच गई है जबकि इसकी वजह से 514 लोगों की मौत हो चुकी है।

न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित खबरों के मुताबिक इन सेटेलाइट तस्वीरों में दफनाने के लिए दो बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इनमें से प्रत्येक 90 मीटर लंबा है। अमेरिका स्थित मैक्सर टेक्नोलॉजीस में प्रकाशित एक अन्य तस्वीर में दिखाया गया है कि अक्टूबर, 2019 में ज्यादातर कब्रिस्तान अप्रयुक्त पड़ा था। लेकिन पहले आधा खाली पड़ा एक हिस्सा इस माह की शुरुआत में पूरा भर गया, जबकि एक अन्य अप्रयुक्त हिस्से पर काम शुरू हो गया था। एक विश्लेषक ने तस्वीरों में चूने के ढेर की ओर भी संकेत किया है। ईरान के अधिकारी पहले ही कोरोना वायरस से मरने वालों को दफनाने में चूने के इस्तेमाल की पुष्टि कर चुके हैं। चूने का इस्तेमा ल सामूहिक कब्रों में शवों को सड़ने से बचाने और उनसे निकलने वाली दुर्गंध को कम करने के लिए किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस स्थल पर भूखंडों को अन्य क्रबों से अलग तरीके से खोदा गया था, इसका मतलब है कि इन्हें जल्दबाजी में खोदा गया है ताकि देश में मरने वालों की संख्या के लिहाज से उनकी उपलब्धता बनी रहे।

लंदन स्थित मेट्रो न्यूज पेपर के मुताबिक, पिछले महीने कोम के एक विधायक ने ईरान सरकार पर कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि उनके शहर में ही 50 लोगों की मौत हो चुकी थी। उस समय ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया था कि कोरोना वायरस से उनके देश में सिर्फ 12 लोगों की मौत हुई है। इन आरोपों का खंडन करने वाले देश के उपस्वास्थ्य मंत्री ईराज हरीरची भी बाद में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इस वायरस से मरने वालों में ईरान के सांसद, पूर्व राजनयिक और सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमैनी के वरिष्ठ सलाहकार भी शामिल हैं।

कोरोना वायरस के नए मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ईरानी सुरक्षा बल अगले 24 घंटों में अपने शहरों की सड़कें खाली कराएंगे। ईरान की समाचार एजेंसी इरना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अमेरिका की आधी आबादी पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा

न्यूयॉर्क टाइम्स से

30 से ज्यादा राज्यों में फैला वायरस, 1700 से अधिक लोग संक्रमित

वाशिंगटन : कोरोना वायरस से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खौफ है। अंदेशा जताया जा रहा है कि अमेरिका की आधी आबादी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ सकती है। कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि आखिर आधी अमेरिकी आबादी और खासतौर पर बुजुर्गों पर यह खतरा क्यों मंडरा रहा है? अमेरिका के 30 से ज्यादा राज्यों में यह वायरस फैल चुका है। अब तक 1700 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और 41 की मौत भी हो चुकी है।

अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि बुजुर्गों के लिए कोरोना वायरस गंभीर खतरा है। इनमें से 50 फीसद लोग सेहत संबंधी किसी ना किसी समस्या से जूझ रहे हैं। हृदय रोग, कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां कोरोना वायरस के संक्रमण को गंभीर कर सकती हैं। कुछ हालिया अध्ययनों में इन खतरों को लेकर आगाह किया गया है। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ विलियम शेफनर ने कहा, '60 साल से ज्यादा उम्र वाले और बीमारियों से जूझ रहे लोगों को निजी तौर पर सचेत हो जाना चाहिए।'

ये हो सकते हैं कारण : डॉ विलियम समेत कई जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कुछ ऐसे कारण बताए हैं, जिनसे कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। उनका कहना है कि अनुमानित 3.4 करोड़ अमेरिकी धूमपान करते हैं और इनमें से 1.6 करोड़ धूमपान संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं। टाइप-1 या टाइप-2 डायबिटीज रोगियों के साथ ही अस्थमा, हृदय रोग और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोग भी वायरस के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।

कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद होने से छात्रों में अनिश्चितता

अमेरिका के कई राज्यों में कोरोना वायरस के चलते स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद किए जाने से छात्रों में अनिश्चितता का माहौल है। खासतौर पर विदेशी छात्रों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। कम आय वाले छात्रों में चिंता इस बात को लेकर है कि क्या वे घर लौटने का खर्च उठा सकते हैं? जबकि अंतरराष्ट्रीय छात्र ऑनलाइन क्लासेज को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनके वीजा में आमतौर पर ऑनलाइन क्लासेज की अनुमति नहीं है। रिसर्च से जुड़े छात्र अपने प्रोजेक्ट पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर परेशान हैं।

वायरस के खिलाफ जनता की लड़ाई के चीन के दुष्प्रचार का विरोध

बीजिंग, रायटर : कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से चीन की जनता में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों में सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती थी, वो अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जनता की लड़ाई बताने और उसे जीतने के सरकारी दावे का जमकर विरोध कर रहे हैं।

दरअसल, इसी हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग कोरोना वायरस के केंद्र वुहान शहर का दौरा किया था। उसके बाद ही चीन सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को जनता की लड़ाई बताने का ताना-बाना बुना और उसे जीत लेने का दावा भी करने लगी। लेकिन मौतों के बढ़ते आंकड़ों के बीच सरकार के इस दावे ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। लोग सरकार के इस दुष्प्रचार के खिलाफ सोशल मीडिया पर टूट पड़े। महामारी बन चुकी इस बीमारी के खिलाफ सबसे पहले आगाह करने वाली वुहान की डॉक्टर एई फेन के आवाज को जहां सरकार ने दबा दिया था, लोग उनके साक्षात्कार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। मानव और अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो रहे इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में चीन सरकार की लापरवाही पर लोगों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है।

सोशल मीडिया पर निगरानी रखने वाले चीन सरकार के एआइ सॉफ्टवेयर को धोखा देने के लिए वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल के आपात विभाग के प्रमुख डॉ. एई के साक्षात्कार को लोगों ने कम से कम पांच भाषाओं में अनुवाद करने के बाद उसे 22 अलग-अलग तरीकों से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। साक्षात्कार के मजमून के साथ इमोजी, ब्रेल, ओरोकल बोन स्क्रिप्ट, मोर्स कोड, गाने की शीट और यहां तक कि एल्विश भाषा में पेश किया गया है। बीजिंग में फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी में मीडिया विभाग में प्रोफेसर झांग जियांग का कहना है कि इस महामारी के दौरान सरकार के दुष्प्रचार के खिलाफ लोगों के विरोध की तीव्रता और पैमाना अभूतपूर्व है। हाल ये है कि कई बार तो इंटरनेट सेवा तक बैठ गई।

बढ़ता गुस्सा

- कोरोना के प्रति सबसे पहले आगाह करने वाले डॉक्टर के इंटरव्यू की सोशल मीडिया पर बाढ़
- सरकार की निगरानी को धोखा देने के लिए कई तरीकों और भाषाओं का लोग कर रहे इस्तेमाल

चीन में वालेंटियर पहुंचा रहे सब्जी : चीन में कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने में कम्युनिटी वालंटियर्स की बड़ी भूमिका रही है। वालंटियर्स संक्रमण की वजह से ठप हुए शहर में लोगों तक दवाइयां और खाने-पीने की चीजें मुहैया करा रहे हैं। यह तस्वीर कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित वुहान शहर की है। एएफपी

चीनी पत्रिका 'पीपुल' के साथ बातचीत में एई ने कहा है कि जब उन्होंने सबसे पहले इस वायरस को लेकर आगाह किया था, तब शुरुआती एहतियाती कदम उठाने और उसे रोकने के उपाय करने के बजाय उन्हें ही अफवाह फैलाने और लोगों में डर पैदा करने के लिए दंडित किया गया। शुरुआती सूचना को दबा दिया गया। अगर उन्हें पता होता कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे तो वो चुप नहीं बैठती, बल्कि पूरी दुनिया को इसके बारे में बता दी होतीं।

सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ली कुआन येव स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में एसोसिएट प्रोफेसर अल्फ्रेड यू कहते हैं कि शी के नेतृत्व में चीन में सेंसरशिप और कठोर हुई है। इस दौर के गुजर जाने के बाद भी वह जारी रहने वाली है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जानती है कि बहुत लोग नाराज हैं। बचाव के लिए आक्रमण की नीति को अपनाना पार्टी की प्रवृत्ति रही है। शी को कोट करते हुए सरकारी टेलीविजन ने कहा कि इस वायरस से संक्रमित होने और घरों में कैद रहने वालों में गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। हमें उसे समझना चाहिए और उसकी अनदेखी करनी चाहिए।

शी चिनफिंग। फाइल

हुबेई प्रांत में पहला केस नवंबर में ही सामने आया था

चीन के हुबेई प्रांत में पिछले साल 17 नवंबर को ही कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आ गया था। लेकिन चीन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उसे पहचान नहीं सके। नतीजा सबके सामने है हुबेई के वुहान शहर को अपनी चपेट में लेने वाला यह वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और महामारी का रूप ले चुका है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

दुनिया कोरोना से जूझ रही, किम जोंग हथियारों से

सियोल, एपी : पड़ोसी देश चीन और दक्षिण कोरिया समेत सारी दुनिया भले ही कोरोना वायरस के खतरे से जूझ रही हो लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हथियारों के विकास में व्यस्त हैं। गुरुवार को किम ने अपनी सेना के तोपखाने का अभ्यास देखा। माना जा रहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरिया की युद्ध क्षमता को बढ़ाना था। इस बीच अमेरिका की उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल टेरेंस ओशौगनेसी ने कहा है कि उत्तर कोरिया नई अंतर महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल (आइसीबीएम) के परीक्षण की तैयारी कर रहा है। इससे अमेरिका पर हमले का खतरा बढ़ेगा। अमेरिका के शीर्ष जनरल ने संसद की सैन्य मामलों की उपसमिति के समक्ष पेश रिपोर्ट में यह बात कही है। 2017 में हुए आइसीबीएम के परीक्षणों के बाद किम जोंग उन ने घोषणा की थी कि मिसाइलों के विकास और परीक्षण का दौर पूरा हुआ, अब उनकी तैनाती की जाएगी।

न्यूज गैलरी

कनाडाई पीएम की पत्नी भी कोरोना की चपेट में

ओटावा : कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी ग्रेगोर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। ट्रूडो के दफ्तर ने लोगों को आश्वस्त किया है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं। कनाडा के छह प्रांतों में कोरोना वायरस के करीब 150 मामलों की पुष्टि हुई है और एक मरीज की जान गई है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने गुरुवार को बताया कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद सोफी का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, '44 वर्षीय सोफी में कोरोना वायरस के लक्षण मामूली हैं। उन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री की सेहत अच्छी है और उनमें कोई लक्षण नहीं पाया गया। डॉक्टरों की सलाह पर हालांकि वह भी दो हफ्ते के लिए आइसोलेशन में रहेंगे।' (एएफपी)

सोफी ग्रेगोर। रायटर

नेपाल ने भी बंद की माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई

काठमांडू : चीन के बाद नेपाल ने भी कोरोना संक्रमण के डर से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई बंद कर दी है। नेपाल के पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराई ने शुक्रवार को एलान किया कि इस साल वसंत ऋतु में होने वाली एवरेस्ट समेत हिमालय की अन्य चोटियों की चढ़ाई निलंबित कर दी गई है। इसके तहत इस साल मार्च से मई तक किसी प्रकार का पर्वतारोहण नहीं होगा। इससे पहले चीन ने भी अपनी तरफ से होने वाली एवरेस्ट की चढ़ाई स्थगित कर दी थी। वसंत में अच्छे मौसम के कारण एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या ज्यादा होती है। नेपाल सरकार के इस कदम से विदेश से आने वाले सैकड़ों पर्वतारोहियों के अभियान खटाई में पड़ गए हैं। इससे नेपाल सरकार को लाखों डॉलर का नुकसान होने की संभावना है। नेपाल में कोरोना को लेकर 450 लोगों के बीच की गई जांच के बाद एक छात्र के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यह छात्र चीन से आया था। (रायटर)

अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित विद्रोहियों पर किए हवाई हमले

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका ने गुरुवार को इराक में ईरान समर्थित विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इन हमलों में शिया विद्रोहियों के पांच हथियार भंडारों को निशाना बनाया गया। आशंका जताई गई है कि इन्हीं विद्रोहियों ने एक दिन पहले इराक की राजधानी बगदाद के पास स्थित एक सैन्य ठिकाने पर 18 रॉकेट दागे थे। इसमें दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश सैनिक की मौत हो गई थी और 12 अन्य घायल हो गए थे।

अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि इराक में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने पांच स्थानों और मुख्य रूप से कताइब हिजबुल्ला के हथियार ठिकानों को निशाना बनाया। ज्यादातर हमले बगदाद के आसपास के इलाकों में किए गए। अधिकारियों ने इन हमलों में करीब 50 विद्रोहियों के मारे जाने का अंदेशा जताया है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि हथियार भंडारण के पांच ठिकानों को निशाना बनाकर विद्रोहियों की हमले करने की क्षमता को तबाह कर दिया गया। इन ठिकानों पर रखे गए हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका और गठबंधन बलों के खिलाफ किया जाता था। रॉकेट हमले के बाद रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा था, 'अमेरिका अपने लोगों, हितों और सहयोगियों के खिलाफ किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्षेत्र में तैनात अपने बलों की रक्षा के लिए हम जरूरी कार्रवाई करेंगे।'

गठबंधन सैनिकों का ठिकाना है ताजी एयरबेस : उत्तरी बगदाद के ताजी एयरबेस को बुधवार को रॉकेट हमले का निशाना बनाया गया था। इस एयरबेस को अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने अपना ठिकाना बना रखा है। माना जा रहा है कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने ये रॉकेट दागे थे। लेकिन इस हमले की अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

- रॉकेट हमले में दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश सैनिक की मौत के बाद की जवाबी कार्रवाई
- हमलों में करीब 50 विद्रोहियों के मारे जाने का है अंदेशा

अमेरिका के हवाई हमले के बाद इराक में नागरिक एयरपोर्ट पर हुए नुकसान को देखते करते इराकी सुरक्षा बलों के अधिकारी। रायटर

फेडरल कोर्ट के जज ने दिया चेल्सी मैनिंग की रिहाई का आदेश

वाशिंगटन, आइएएनएस : अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट के जज ने विकिलीक्स मामले से जुड़ी पूर्व सैन्य विश्लेषक चेल्सी मैनिंग को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। अमेरिकी सेना में रहने के दौरान ही लिंग परिवर्तन ऑपरेशन के जरिये पुरुष से महिला बनी मैनिंग ने वर्ष 2010 में लाखों गोपनीय सैन्य और राजनयिक दस्तावेज विकिलीक्स को लीक किए थे। इनमें इराक और अफगानिस्तान युद्ध से जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी थे। मैनिंग ने ये दस्तावेज 2009 में इराक में एक अमेरिकी यूनिट में खुफिया विश्लेषक के तौर पर काम करने के दौरान हासिल किए थे।

अमेरिकी मीडिया के अनुसार, जज एंटोनी जे ट्रेंगा ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा, 'ग्रैंड ज्यूरी के समक्ष पेशी की जरूरत नहीं रह जाने के चलते मैनिंग को हिरासत में रखे जाने का कोई मकसद नहीं रह गया है।' जज ने हालांकि मैनिंग पर लगाए गए दो लाख 56 हजार डॉलर (करीब एक करोड़ 90 लाख रुपये) के जुर्माने को बरकरार रखा है। 32 वर्षीय मैनिंग ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के खिलाफ गवाही देने से इन्कार कर दिया था। इसी के चलते उसे पिछले साल मई में हिरासत में ले लिया गया था। मैनिंग ने बुधवार को वर्जीनिया हिरासत केंद्र में आत्महत्या करने की कोशिश की थी।

- पूर्व सैन्य विश्लेषक ने विकिलीक्स को लीक किए थे लाखों गोपनीय दस्तावेज
- रिहाई के आदेश से एक दिन पहले ही की थी आत्महत्या की कोशिश

मिली थी 35 साल जेल की सजा

मैनिंग को पहली बार वर्ष 2010 में गिरफ्तार किया गया था। उस समय जासूसी कानून का उल्लंघन करने के मामले में उसे 35 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन राष्ट्रपति से माफी मिलने पर मैनिंग वर्ष 2017 में रिहा हो गई थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में उसकी सजा माफ कर दी थी।

चेल्सी मैनिंग। फाइल/रायटर

ईशनिंदा में आरोपित अफगान लेखक आठ साल बाद रिहा

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान में ईशनिंदा के मामले में आठ साल से जेल में बंद लेखक जमान अहमदी को गुरुवार को रिहा कर दिया गया। अहमदी को 2012 में इस मामले में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने अपने एक लेख में अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में बुद्ध की विशाल प्रतिमाओं को तोड़े जाने के कारणों का जिक्र किया था। इसी लेख के चलते उन पर ईशनिंदा का मामला चला था।

अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था। जेल से बाहर निकलने के बाद अहमदी ने कहा कि उन्होंने अदालत से अपनी रिहाई के अलावा आरोप वापस लेने का भी अनुरोध किया था। अहमदी के वकील ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि न्याय कुछ हद तक ही मिल पाया।

रूस में सभी 85 राज्यों की विधानसभाओं ने लगाई पुतिन को बनाए रखने पर मुहर

मॉस्को, रायटर : रूस में सभी 85 राज्य विधानसभाओं ने व्लादिमीर पुतिन को 2024 के बाद भी राष्ट्रपति बनाए रखने के संविधान संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। संसद के दोनों सदन इस प्रस्ताव को पहले ही पारित कर चुके हैं। यह जानकारी आरआइए न्यूज एजेंसी ने दी है।

पुतिन (67) करीब दो दशक से रूस की सत्ता में शीर्ष पुरुष बने हुए हैं। इस दौरान वह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं। 2024 में राष्ट्रपति के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार इसके बाद वह तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। लेकिन बुधवार को संसद ने एक प्रस्ताव पारित कर उनके राष्ट्रपति के तौर पर पूर्व के सभी कार्यकालों को शून्य घोषित कर दिया है। इसके चलते पुतिन छह-छह साल के दो कार्यकालों के लिए फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसलिए 2024 में उनके फिर से चुनाव लड़ने और राष्ट्रपति बनने की संभावना प्रबल हो गई है। वह सन 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। पुतिन ने इसके लिए रूपरेखा जनवरी से ही तैयार करनी शुरू कर दी थी। इसके लिए दिमित्री मेदवेदेव से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया था और अन्य बड़े पदों पर भी बदलाव किया गया था।

क्षेत्रीय विधानसभाओं के बाद अब रूस की संवैधानिक अदालत संविधान में संशोधन वाले इस पारित प्रस्ताव की समीक्षा करेगी। इसके बाद अप्रैल में जनता की राय जानने के लिए मतदान कराया जाएगा। इस बीच ड्यूमा के स्पीकर याचेस्लाव वोलोदिन ने सांसदों ने कहा है कि विदेशी मीडिया रूस के खिलाफ अभियान चलाकर व्लादिमीर पुतिन के पक्ष हुए इस संविधान संशोधन का विरोध कर रहा है। सांसद यह बात जनता के बीच जाकर बताएं।

- 2036 तक व्लादिमीर पुतिन को सत्ता में बनाए रखने का मामला

व्लादिमीर पुतिन। फाइल

मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पाक को जवाबदेह ठहराने की मांग

जिनेवा (स्विटजरलैंड), एएनआइ : वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से सिंधी लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने का अनुरोध किया है।

यूएनएचआरसी के 43वें सत्र को संबोधित करते हुए वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के महासचिव लखु लुहाना ने कहा, 'अपने ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए सिंधी लोगों के संघर्ष में हर आवाज को निर्मम तरीके से खामोश करने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा सिंधी लोगों को जबरन गायब करने का सिलसिला जारी है। पिछले तीन साल में 300 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया जा चुका है। इनमें जाने-माने नेता, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हैं। पिछले तीन दिनों में चार और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपहरण किया जा चुका है। स्वदेशी सिंधी हिंदुओं का निर्दयता से उत्पीड़न जारी है। इसमें सैकड़ों सिंधी हिंदू लड़कियों (ज्यादातर नाबालिग) का जबरन धर्मांतरण और शादी, उनके पूजा स्थल व संपत्तियों पर हमले और ईशनिंदा के झूठे मामलों पर फंसाना शामिल है।' उन्होंने आगे कहा, 'आखिरी दुखद मामला 15 साल की लड़की महक कुमारी का है जिसने अदालत में बार-बार माता-पिता के साथ जाने का बयान दिया, इसके बावजूद उसे तथाकथित संरक्षण गृह में भेज दिया गया जो वास्तव में एक कारावास है। न्यायिक प्रणाली समेत पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था ने कोई राहत प्रदान नहीं की और अपराधी बेखौफ हैं।'

- वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने यूएनएचआरसी से किया अनुरोध

राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
स्पोर्ट्स
शनिवार 14 मार्च 2020
www.jagran.com

कोरोना वायरस की वजह से सचेत रहना जरूरी है। उम्मीद है भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज जल्द होगी।
— आरपी सिंह, पूर्व भारतीय गेंदबाज

ऑल इंग्लैंड ओपन में हारीं भारतीय शटलर पीवी सिंधू

बर्मिंघम, आइएएनएस : मौजूदा विश्व चैंपियन भारत की पीवी सिंधू शुक्रवार को यहां जारी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। सिंधू को क्वार्टर फाइनल में जापान की नोजोमी ओकुहारा ने हराया। ओकुहारा ने एक घंटे आठ मिनट तक चले मुकाबले में सिंधू को 12-21, 21-15, 21-13 से हराया।

कोरोना ने किया भारतीय क्रिकेट को क्लीन बोल्ड

आज आइपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नए कार्यक्रम पर होगी चर्चा, नए आयोजन स्थलों पर भी विचार करेंगे अधिकारी

अभिषेक त्रिपाठी ● नई दिल्ली

कोरोना वायरस ने क्रिकेट को बोल्ड कर दिया है और इसकी चपेट में आने के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) इससे बचने के उपाय खोज रहा है। आइपीएल गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को मुंबई में बैठक होगी और उसमें क्रिकेट की सबसे महंगी लीग का नया कार्यक्रम तय किया जाएगा। पहले यह लीग 29 मार्च से 24 मई तक होनी थी लेकिन अब इसे 15 अप्रैल तक टाल दिया गया है।

बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि अगर कोरोना का डर कम होता है और केंद्र सरकार विदेशी खिलाड़ियों के वीजा पर निलंबन को 15 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाती है तो इस लीग को 16 अप्रैल से शुरू किया जा सकता है। हमारी पहली कोशिश होगी कि इसे 24 मई तक ही खत्म किया जाए। हमारे पूर्व कार्यक्रम के हिसाब हमें 57 दिन में 60 मैच खेलने थे। इसमें सिर्फ छह रविवार को ही दो-दो मुकाबले होने थे। अगर हम 16 अप्रैल से लीग शुरू कर पाते हैं तो हमारे पास 38 दिन होंगे जिसमें हम आसानी से 60 मैच करा लेंगे। अगर एक-दो दिन कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना पढ़ा तो वह भी कर लिया जाएगा।

अन्य मैदानों का विकल्प भी खुला: इस बार के आइपीएल मैच मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मोहाली, गुवाहाटी, हैदराबाद और जयपुर में होने थे लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। इसके बाद बीसीसीआइ अन्य विकल्पों की तलशा में भी है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और पूर्व आइपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा है कि अगर कोई राज्य आइपीएल के मैच आयोजित कराने से मना करता है तो वह कुछ मैचों को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित करवा सकते हैं। कुछ अन्य विकल्प राजकोट, इंदौर, रायपुर, विशाखापत्तनम हो सकते हैं। पुणे को इसमें शामिल नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि पहले ही इस शहर में 10 कोरोना के केस मिल चुके हैं। बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि आइपीएल का प्रारूप ऐसा है कि हर टीम को दूसरी टीम से दो बार खेलना होता है। ऐसे में हमें एक दिन में दो मुकाबले कराने होंगे। वहीं फ्रेंचाइजी मालिकों को उम्मीद है कि अगर 16 अप्रैल से आइपीएल होता है तो राज्य सरकारें इसे अपनी मंजूरी दे सकती हैं क्योंकि तब तक स्थिति बदल सकती है। बीसीसीआइ के एक सूत्र ने कहा कि आइपीएल कराने में राज्य सरकार का सहयोग अहम होता है क्योंकि वह हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं एक अन्य मामला भी सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि बीसीसीआइ ने मैच कराने की फीस फ्रेंचाइजियों पर बढ़ा दी है। 30 लाख की जगह 50 लाख की गई फीस का फ्रेंचाइजी विरोध कर रही हैं। ऐसे में अगर फ्रेंचाइजियों को स्पांसरशिप से रकम नहीं मिल पाती है, तो वह इसमें मोलभाव करेंगे। अगर टूर्नामेंट बंद दरवाजे में होता है तो फिर फ्रेंचाइजी गेट मनी के साथ ही स्पांसरशिप रकम भी काफी संख्या में गंवा देंगी।

लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मास्क पहनकर बाहर निकले दक्षिण अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी ● एएनआइ

भुवनेश्वर के साथ मास्क लगाकर यात्रा करते भारतीय खिलाड़ी चहल ● इंस्टाग्राम

जल्द से जल्द स्वदेश लौट जाएगी द. अफ्रीकी टीम

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें शुक्रवार को ही लखनऊ पहुंचीं थीं और उसी के बाद सीरीज स्थगित करने की घोषणा हो गई। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी लखनऊ से अपने-अपने गंतव्य चले जाएंगे जबकि दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी शनिवार की सुबह दिल्ली पहुंचेंगे और यहां से स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। यह दूसरी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज है जो रद की गई है।

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज स्थगित

कोलंबो: इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ अगले सप्ताह से शुरू हो रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज को स्थगित कर दिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पहला टेस्ट 19 मार्च से गॉल में जबकि दूसरा टेस्ट 27 मार्च से कोलंबो में खेला जाना था। ईसीबी ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलने के कारण श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से चर्चा करने के बाद यह दौरा स्थगित कर दिया गया है। हमनें अपने खिलाड़ियों को वतन वापसी का आदेश दिया है। इस समय पर हमारे खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ मानसिक और शारीरिक तौर पर टूटे हुए हैं। हम अपने खिलाड़ियों जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलाना चाहते हैं। इस समय क्रिकेट को जारी रखना एक गलत फैसला होगा।

2008 में इंग्लैंड की टीम सात वनडे और दो टेस्ट खेलने के लिए भारत पहुंची थी। कटक में खेले गए पांचवें वनडे के दिन मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बाद बाकी दो वनडे रद किए गए। इसके बाद इंग्लैंड ने कुछ दिन बाद आकर दो टेस्ट की सीरीज खेली थी

2014 15 में वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर पांच वनडे, एक टी-20 और तीन टेस्ट खेलने पहुंची। वनडे सीरीज का तीसरा मैच साइक्लोन के कारण रद हो गया। वेतन नहीं बढ़ने से अपने क्रिकेट बोर्ड से नाराज वेस्टइंडीज टीम के कप्तान ड्वेन ब्रावो टॉस करने ही नहीं आए। इसके बाद टीम वापस लौट गई

फिलहाल आइपीएल स्थगित है। हर किसी की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। किसी के पास भी विकल्प नहीं है।
सौरव गांगुली, बीसीसीआइ अध्यक्ष

आइपीएल में खेलने का निर्णय खिलाड़ियों का होगा। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर इसमें खेलने और नहीं खेलने के लिए स्वतंत्र हैं। **न्यूजीलैंड क्रिकेट**

बीसीसीआइ सचिव जय शाह से मेरी बात हुई और दोनों टीमों के खिलाड़ियों से भी चर्चा की गई जिसके बाद हमने खाली मैदान में मैच कराने की जगह उसे स्थगित करने का फैसला किया। इस मैच के बदले लखनऊ और कोलकाता में बाद में मैच आयोजित किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका टीम फिर भारत आएगी।
राजीव शुक्ला, पूर्व आइपीएल चेयरमैन

दुनियाभर के शटलरों की जान जोखिम में

जबरदस्ती टूर्नामेंट कराने को अडिग है विश्व बैडमिंटन संघ
ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेल रहे हैं खिलाड़ी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: दुनिया के शीर्ष शटलरों ने विश्व बैडमिंटन फेडरेशन (डब्ल्यूबीएफ) पर आरोप लगाया है कि उसने कोरोना वायरस की चेतावनी को हल्के में लिया और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप कराकर उनकी जान खतरे में डाल दी। बता दें कि ब्रिटेन के बर्मिंघम में अभी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। साइना नेहवाल, पीवी सिंधू और पारुपल्ली कश्यप जैसे भारत के शीर्ष खिलाड़ी इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए ब्रिटेन में मौजूद हैं।

बुधवार को ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था। दुनिया भर में जब इतने सारे टूर्नामेंट रद या स्थगित हो रहे हैं उस वक्त बीडब्ल्यूएफ ने इस टूर्नामेंट को कराने का फैसला किया। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल, पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत और पूर्व शीर्ष दस खिलाड़ी हंस क्रिस्टियन विटिंघुस बीडब्ल्यूएफ से सभी आगामी टूर्नामेंट को निलंबित करने की गुहार लगा चुके हैं। डेनमार्क के विटिंघुस ने कहा कि मुझे नहीं पता यह क्यों हो रहा है। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए विश्व भर में नहीं घूमना चाहिए। उन्होंने बीडब्ल्यूएफ से मांग की कि सभी तरह के टूर्नामेंट रद कर दिए जाएं। उन्होंने लिखा कि कुछ टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, कुछ टूर्नामेंट रद हो गए हैं। खिलाड़ी ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथियों के भी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं अगर टूर्नामेंट नहीं खेलें तो फिर उन्हें ओलंपिक में क्वालीफाई करने का मौका गंवाना पड़ रहा है। हम इस स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं।

उनकी इस पोस्ट को साइना नेहवाल, श्रीकांत, पारुपल्ली कश्यप और एचएस प्रणय जैसे भारतीय खिलाड़ियों के अलावा स्पेन के कोच फर्नांडो रिवास ने रीट्वीट किया। साइना ने लिखा कि मुझे भी यह समझ नहीं आया बीडब्ल्यूएफ। श्रीकांत ने भी लिखा कि मैं विटिंघुस की बात से सहमत हूं और बीडल्यूएफ को इस बारे में सोचना चाहिए। कश्यप ने लिखा कि कृपया जाग जाओ बीडब्ल्यूएफ। विश्व के पूर्व नंबर 13 खिलाड़ी अजय जयराम ने लिखा कि मुझे लगता है कि जब तक स्थिति सही नहीं हो जाती बीडब्ल्यूएफ को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को रोक देना चाहिए। वे इस स्थिति को बहुत हल्के में ले रहे हैं। विश्व बॉडी ने अभी तक तय कार्यक्रम के मुताबिक ही ओलंपिक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट कराने का फैसला किया है। वह इससे जुड़े कायदों में किसी तरह का बदलाव करने की नहीं सोच रहा है।

नौ विदेशी खिलाड़ी लौटे

कराची: इंग्लैंड के जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स और जेम्स विंस सहित नौ खिलाड़ी पाकिस्तान प्रीमियर लीग से हटकर स्वदेश लौट गए हैं। पीसीबी प्लेऑफ के मुकाबलों को सेमीफाइनल में बदलकर टूर्नामेंट को जल्द खत्म करेगा। टाइमल मिल्स, लियम डॉसन, लिविंगस्टोन, लुइस ग्रेगॉरी, ब्रेथवेट, रिली रोसो और जेम्स फोस्टर (कोच) भी स्वदेश लौट गए हैं।

पीवी सिंधू ने मुझे फोन किया था। मैंने उनसे कहा कि जो भी खिलाड़ी बाहर अहम टूर्नामेंट खेल रहे हैं वह खेलना जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें उस देश की दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। खिलाड़ियों को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए।
किरन रिजिजू, खेल मंत्री

ईपीएल, चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग स्थगित

लंदन: इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब आर्सेनल के मुख्य कोच मिकेल अर्टेटा और चेल्सी के कैलम हडसन ओडोई को कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया है। इसके बाद लीग को चार अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आर्सेनल ने कहा है कि उसने अपना लंदन कोलनी ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिया है। अर्टेटा ने कहा कि यह काफी निराशाजनक है। अच्छा नहीं महसूस करने के बाद मैंने टेस्ट कराए और मेरे कोरोना वायरस से पीड़ित होने की पुष्टि हुई। जब निर्देश मिलेगा, तब मैं काम पर लौटूंगा। लीसेस्टर सिटी के कुछ खिलाड़ियों के अंदर भी कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग को भी अगले सप्ताह तक स्थगित कर दिया गया है।

इन पर पड़ा असर

- चेन्नई में दो मार्च से लगा चेन्नई सुपरकिंग्स का कैंप रद हुआ
- ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने द. अफ्रीका का दौरा रद किया
- प्रो. गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने 16 मार्च से सभी टूर्नामेंट स्थगित किए। महिलाओं की विश्व बॉडी ने भी तीन स्पर्धाएं स्थगित की
- द. अमेरिका में कोपा लिबरटाडोज कप रद किया गया। द. अमेरिकी विश्व कप क्वालीफायर्स स्थगित
- ऑस्ट्रेलिया ग्रांप्रि फॉर्मूला-1 रेस रद, यहां मैकलारेन के एक टीम सदस्य को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया था। बहरीन और वियतनामी ग्रांप्रि भी रद
- ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन के सभी टूर्नामेंट 31 मई तक स्थगित
- महिला टेनिस संघ ने मैक्सिको, कोलंबिया में टूर्नामेंट रद किए
- आइ-लीग के बचे सभी मुकाबले बंद दरवाजे में होंगे

पहली पारी में बढ़त के आधार पर बंगाल को हरा सौराष्ट्र ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी

जयदेव की अगुआई में सौराष्ट्र का सपना पूरा

राजकोट, प्रेट्र: कप्तान जयदेव उनादकट के महत्वपूर्ण मौके पर शानदार स्पेल से सौराष्ट्र ने शुक्रवार को यहां बंगाल के खिलाफ पहली पारी में बढ़त के आधार पर हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। बंगाल पांचवें दिन का खेल शुरू होने से पहले पहली पारी में बढ़त हासिल करने की बेहतर स्थिति में दिख रहा था। अनुस्तुप मजूमदार (63) और अर्णब नंदी (नाबाद 40) ने गुरुवार को अंतिम सत्र में 91 रन जोड़कर टीम की उम्मीदें जगा दी थी, लेकिन सेमीफाइनल में गुजरात के खिलाफ अंतिम दिन सात विकेट लेकर सौराष्ट्र को फाइनल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उनादकट ने फिर से सही समय पर बेहतरीन गेंदबाजी की और अपनी टीम को इतिहास रचने के करीब पहुंचाया।

बायें हाथ के इस तेज गेंदबाज ने मजूमदार को एलबीडब्ल्यू किया और फिर आकाशदीप को रन आउट किया। इन दोनों के तीन गेंद के अंदर आउट होने से मैच का पासा पलट गया। उनादकट ने सत्र में 13.23 की औसत से सर्वाधिक 67 विकेट लिए लेकिन वह सर्वकालिक रिकॉर्ड से एक विकेट पीछे रह गए। सुबह के सत्र में एक घंटे दस मिनट का खेल महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस बीच 27 रन बने और बंगाल ने अपने बाकी बचे चारों विकेट गंवाए। उसकी टीम 381 रन पर आउट हो गई और इस तरह से सौराष्ट्र ने पहली पारी में 44 रन की बढ़त हासिल की। सौराष्ट्र ने अपनी पहली पारी में 425 रन बनाए थे। सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में जब 34 ओवर में तीन विकेट पर 105 रन बनाए थे तब दोनों कप्तानों ने मैच समाप्त करने पर सहमति जता दी। सौराष्ट्र ने इस तरह से रणजी ट्रॉफी चैंपियन में अपना नाम लिखवाया जबकि बंगाल का 1989-90 के बाद पहला खिताब जीतने का इंतजार बढ़ गया। उप विजेता बनने के बावजूद बंगाल के लिए यह यादगार सत्र रहा और वह 13 साल बाद फाइनल में पहुंचा। उसकी तरफ से तेज गेंदबाजी की तिकड़ी आकाशदीप, मुकेश कुमार और ईशान पोरेल तथा अनुभवी बल्लेबाज मनोज तिवारी और मजूमदार ने अहम भूमिका निभाई। सौराष्ट्र के लिए शेल्डन जैकसन, अर्पित वासवदा और कप्तान उनादकट की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कोरोना वायरस के खतरे के कारण यह मैच खाली स्टेडियम में खेला जा रहा था।

ऐतिहासिक जीत

बंगाल को हराने के बाद रणजी ट्रॉफी जीतने वाली सौराष्ट्र की टीम ● प्रेट्र

भारतीय टीम में वापसी की भूख बढ़ गई है: उनादकट

राजकोट, प्रेट्र: सौराष्ट्र के कप्तान जयदेव उनादकट ने टीम को रणजी ट्रॉफी दिलाने के बाद कहा कि इस शानदार घरेलू सत्र के बाद भारतीय टीम में वापसी की उनकी भूख काफी बढ़ गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि अब लोग सिर्फ उनके आइपीएल प्रदर्शन की ही बात नहीं करेंगे। टीम के मुख्य तेज गेंदबाज उनादकट ने इस सत्र में 67 विकेट हासिल किए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल और फाइनल में अपनी गेंदबाजी से जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनादकट ने कहा, 'मेरे अंदर अब भी वापसी की वही भूख है। यह भूख अब और ज्यादा बढ़ गई है और यह मुझे पूरे सत्र में प्रोत्साहित करती रही। ईमानदारी से कहूं तो सत्र में शानदार खेलने के लिए शारीरिक रूप से काफी चुनौतियां रहीं। लगभग प्रत्येक मैच में तेज गेंदबाज के तौर पर इतने लंबे स्पैल फेंकना काफी चुनौतीपूर्ण रहा।

संक्रमण के डर से पहली बार दर्शकों की मौजूदगी के बिना खेला गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला, अर्जेंटीना में फुटबॉल मैच के दौरान रहा दर्शक दीर्घा में सन्नाटा

कोरोना वायरस के कारण खाली हुए दुनियाभर के स्टेडियम

निखिल शर्मा ● नई दिल्ली

ऐसे हालत पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। कोरोना वायरस ने दुनियाभर में खेल को लाचार बना दिया है। ऐसा लाचार जो चल तो रहा है, लेकिन उसकी सांसें, जीवटता और हौसला टूट सा गया है। शुक्रवार को खेलों की दुनिया में ऐसे दिन की शुरुआत हुई जहां खेलने के लिए खिलाड़ी तो मौजूद थे, लेकिन उनका समर्थन करने वाले दर्शक मौजूद नहीं थे। सही मायनों में शुक्रवार को दुनिया भर में हुए खेल गूंगे, बेजान और नीरस दिखाई दिए।

सिडनी में समर्थन के लिए सिर्फ एक स्टैच्यू: ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर दर्शक अपनी टीम की आधी जान माने जाते हैं। स्टैंड में बैठकर वे खिलाड़ी पर छींटाकशी करके और हाथों में बीयर का गिलास लेकर विरोधी टीम के हौसले पस्त करते हैं, लेकिन शुक्रवार को यहां अलग नजारा था। सिडनी के खाली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे हुआ। दर्शकों के नाम पर स्टैंड में स्टीफन हेरल्ड उर्फ यब्बा का सिर्फ एक स्टैच्यू था, जो कभी अपनी एक लाइनर से कंगारू टीम का हौसला बढ़ाता था। 2008 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रशंसक हेरल्ड को सम्मान देने के लिए उनका स्टैच्यू लगाया गया था। इस मैच के लिए इस स्टैच्यू को दर्शक दीर्घा में रखा गया।

जब ध्यान हटा सावधानी हटी: ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान आरोन फिंच और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टॉस के लिए मैदान पर पहुंचे, तो विलियमसन ने गलती से हाथ मिला लिया। इसके बाद वह अपने हाथ को पोछते नजर आए। हालत यह थी कि जब गेंदबाज विकेट ले रहे थे तो खुशी भी नहीं मना पा रहे थे। एक-दूसरे से हाथ मिलाने या गले मिलने से परहेज कर रहे थे।

जब खुद गेंद उठानी पड़ी: ऑस्ट्रेलियाई पारी में 18वें ओवर में ईश सोढ़ी की पहली गेंद पर फिंच ने छक्का लगाया। दर्शकों के नहीं होने के कारण क्षेत्ररक्षक लॉकी फर्ग्यूसन को स्टैंड में जाकर गेंद लाने पर मजबूर होना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अमूमन ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता है।

फुटबॉल के दीवाने देश अर्जेंटीना में सन्नाटा: कोरोना वायरस की वजह से यूरोपीय फुटबॉल पर लगभग विराम लग गया है। ला लीगा स्थगित कर दी गई है और इंग्लिश प्रीमियर लीग पर काले बादल छाए हुए हैं। वहीं फुटबॉल के लिए दीवाने डिएगो माराडोना और लियोन मेसी के देश अर्जेंटीना में फुटबॉल मैच में ऐसी शांति पहले कभी देखने को नहीं मिली। कोपा लिबरटाडोज के ग्रुप मुकाबले में शुक्रवार सुबह अर्जेंटीना के रेसिंग क्लब और पेरू के अलिंजा लीमा क्लब के बीच मुकाबला था। इस मैच में सिर्फ एक गोल रेसिंग क्लब के गैस्टन रेनियेरो ने किया, लेकिन गोल करने की खुशी में दर्शकों के पास पहुंचकर जश्न मनाने की कसक उनके मन में रही, क्योंकि यह स्टेडियम पूरी तरह से खाली था।

ये भी हुए बंद दरवाजे में: सौराष्ट्र की ने बंगाल को हरा शुक्रवार को इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। यह उनके लिए काफी खास था कि क्योंकि उन्होंने यह खिताब अपने घर राजकोट में जीता लेकिन इस जश्न में उनके साथ उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे।

सिडनी में ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के बीच हुए पहले वनडे में खाली पड़े स्टैंड ● एएफपी

ऑस्ट्रेलिया को मिली एक अदद जीत

सिडनी, एएफपी: ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को यहां खाली सिडनी क्रिकेट मैदान (एससीजी) में खेले गए पहले वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 71 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम ने मेजबान टीम को 50 ओवर में सात विकेट पर 258 रन पर रोक दिया, लेकिन इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी आक्रमण के दबदबे के सामने कीवी बल्लेबाज ढह गए और पूरी मेहमान टीम 41 ओवर में 187 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के लिए यह जीत मनोबल बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसे द. अफ्रीका और भारत के खिलाफ सीरीज में पिछले लगातार पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा था।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान आरोन फिंच ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने स्पिनर मिशेल सेंटनर (2/34) और ईश सोढ़ी (3/51) की शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। फिंच (60)और डेविड वार्नर (67) के बीच 124 रन की बेहतरीन सलामी साझेदारी की बदौलत एक समय ऑस्ट्रेलियाई पारी 300 रन के पार जाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी लय खो दी। फिंच का भाग्य ने भी साथ दिया, लेकिन वार्नर ने बेदाग अर्धशतकीय पारी खेली। लॉकी फर्ग्यूसन (2/60) ने वार्नर को मिडऑन पर कैच कराकर यह साझेदारी तोड़ी। सेंटनर ने इसके बाद फिंच को विकेटकीपर टॉम लाथम के हाथों कैच कराया। सेंटनर ने स्टीव स्मिथ (14) को भी क्लीन बोल्ड किया।

लगातार पांच वनडे हारने के बाद मिली पहली जीत, न्यूजीलैंड को 71 रन से दी शिकस्त

रिचर्डसन के परीक्षण की रिपोर्ट नकारात्मक

सिडनी, प्रेट्र: गले में खराश के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से बाहर किए गए तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन का कोविड-19 का परीक्षण नकारात्मक पाया गया, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम में उनकी वापसी की राह मजबूत हो गई। इस सप्ताह की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ लौटे दायें हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्डसन ने गुरुवार को मेडिकल स्टाफ को गले में खराश की सूचना दी थी। इसके बाद उन्हें एहतियाती तौर पर कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए भेजा गया था।

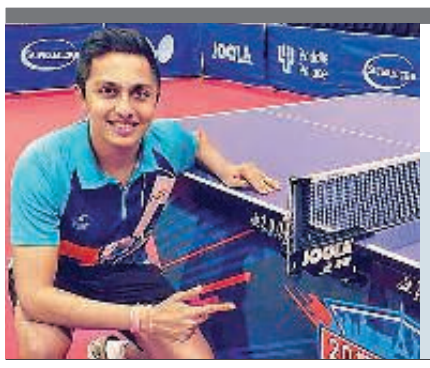

ओमान ओपन में युवा मुदित दानी की अच्छी शुरुआत

मस्कट, आइएएनएस : भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी ने यहां जारी 2020 आइटीटीएफ चैलेंजर प्लस ओमान ओपन में शुक्रवार को शानदार जीत करते हुए अपना पहला मुकाबला 4-0 से जीत लिया। मुदित ने पुरुष सिंगल्स के राउंड-ऑफ-64 के अपने पहले मैच में ओमान के असद अलरियासी को 11-6, 11-2, 11-5, 11-4 से हराया। अगले दौर में मुदित का सामना मार्कोस फ्रीटास से होगा।

लोग क्रिकेट के लिए भूखे हैं। मुझे लगता है कि रोड सेफ्टी सीरीज बेहतरीन कदम था।
– ब्रायन लारा, वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी

इतिहास में जगह बनाने उतरेंगे एटीके, चेन्नई

आइएसएल ▸ दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला आज गोवा में, दो बार जीता है दोनों टीमों ने खिताब

तीसरे खिताब के प्रयास में बंद दरवाजे में मैदान में उतरेंगी दोनों टीम

फातोर्दा (गोवा), आइएनएस : इंडियन सुपर लीग (आइएसएल) का छठा सत्र समाप्त होने को है। इसका अंतिम यानी फाइनल मुकाबला दो बार के चैंपियन क्लबों-एटीके एफसी और चेन्नइयन एफसी के बीच शनिवार को यहां के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला जाएगा। दो-दो बार यह खिताब जीतने के बाद एटीके और चेन्नइयन अब तीसरे खिताब के साथ इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहेंगे और इसके लिए फातोर्दा में जोरदार भिड़ंत की उम्मीद है। कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए फाइनल मुकाबला बंद दरवाजों के बीच खेला जाएगा। इस मैच में कोई दर्शक नहीं होगा।

एटीके ने जहां दो चरण के सेमीफाइनल में मौजदा चैंपियन बेंगलुरू एफसी को हराया था जबकि चेन्नइयन एफसी ने एफसी गोवा को हराते हुए तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है। दोनों क्लब लीग इतिहास में पहली बार फाइनल में आमने-सामने हैं। मजेदार बात यह है कि दोनों फाइनल में पहुंचने के बाद अब तक एक बार भी नहीं हारे हैं।

फाइनल से एक दिन पहले ट्रॉफी के साथ मौजूद दोनों टीम के कप्तान। प्रेट्र

एटीके ने जहां लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट कटाया है वहीं चेन्नइयन ने दूसरे हाफ के बाद वापसी करते हुए फाइनल में पहुंचने का गौरव हासिल किया। नए मैनेज ओवेन कोएल ने दिसंबर की शुरुआत में इसका चार्ज संभाला था और तब से इस टीम ने आठ मैच जीते। कोएल के आने से पहले चेन्नइयन एफसी ने सिर्फ एक मैच जीता था।

अब कोएल ने चमत्कार कर दिखाया है। चेन्नइयन एफसी के लिए नेरीजुस वाल्सकिस काफी अहम साबित होंगे क्योंकि इस खिलाड़ी के नाम 14 गोल हैं। वह तथा रफाएल क्रीवेलारो ने इस टीम के लिए कई मौकों पर अहम प्रदर्शन करते हुए हार को जीत में बदला है। विंगर लालियानजुआला चांग्ते भी इस टीम के लिए अहम कड़ी हैं। खासतौर पर बीते तीन मैचों में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वह प्लेऑफ के दोनों लेग में गोल करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं।

कोएल ने कहा कि मेरे मन में एटीके के लिए काफी सम्मान है। इनके पास कई अच्छे खिलाड़ी हैं। हम अपने स्टाइल के मुताबिक खेलेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि इसी तरह हम मैच जीत सकते हैं। हम दबाव में हैं क्योंकि हम फाइनल में हैं और हम दबाव में रहना चाहते हैं क्योंकि दबाव में ही हम अच्छा खेलते हैं। यह टीम जब फोकस्ड रहती है और अपने खेल पर ध्यान लगाती है तो हमारी क्वालिटी निखरकर सामने आती है।

दूसरी ओर, एटीके मुख्य रूप से रॉय कृष्णा और डेविड विलियम्स की कलाकारी पर आश्रित होगा। रॉय के नाम 15 गोल हैं और वह गोल्डन बूट की दौड़ में मजबूती से शामिल हैं। विलियम्स भी इस सीजन में समान रूप से खतरनाक दिख रहे हैं। बेंगलुरू के खिलाफ प्लेऑफ में विलियम्स ने दो गोल किए थे। इसके अलावा मिडफील्ड में इदु गार्सिया और जेवियर हर्नांदेज की अहम भूमिका होगी। विंग बैक प्रबीर दास इस टीम के शानदार आक्रमण विकल्प बनकर सामने आए हैं। साल 2014 में एटीके को खिताब दिलाने वाले कोच एंटोनियो हाबास ने कहा कि हमें फाइनल का लुत्फ लेना होगा और इसे जीतना होगा साथ ही हमें विपक्षी टीम का सम्मान भी करना होगा। हमारे पास 90 मिनट होंगे और यह बात जेहन में रखना होगा कि किसी खिलाड़ी को अपने पूरे करियर में दोबारा फाइनल खेलने का मौका नहीं मिलेगा।

2024 व 2028 ओलंपिक के लिए साई ने कसी कमर

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

निर्णय

- शुक्रवार को हुई अहम बैठक में लिए गए कई फैसले
- बेहतर सुविधा देने के लिए तैयार है भारतीय खेल प्राधिकरण

2024 और 2028 ओलंपिक को नजर में रखते हुए शुक्रवार को भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की गवर्निंग बॉडी की बैठक में अहम फैसले लिए गए।

साई ने फैसला किया है कि देश में 23 नए राष्ट्रीय केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों में सभी राज्य केंद्र और साई के अकादमिक इंस्टीट्यूट के लिए जारी स्कीम लागू होगी। यहां पर 14 खास खेलों पर ध्यान दिया जाएगा। इन केंद्रों पर एथलीटों की डाइट, संसाधनों और खेल विज्ञान पर ध्यान दिया जाएगा।

इसी के साथ 350 खेल विज्ञान विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जाएगी। साथ ही 100 विशेषज्ञ रसोई विभाग रसोई स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ डाइट मिल पाए। इसी के साथ बैठक में तय हुआ कि 25 नए हॉस्टल, 8000 लोगों के रहने के लिए जगह का निर्माण किया जाएगा। वहीं पटियाला और बेंगलुरु केंद्रों में नए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 56 करोड़ रुपये पास किए गए। साथ ही खेल विज्ञान संसाधन के लिए 80 करोड़ रुपये पास किए गए।

वहीं साई अभ्यास केंद्र के अंतर्गत 21 विशेष जगह केंद्र भी जोड़े गए हैं। इन दोनों के लिए फंडिंग खेलो इंडिया स्कीम से होगी। हालांकि कोचों और अधिकारियों का वेतन साई देगा।

क्षेत्र के हिसाब से खिलाड़ियों की क्षमता की पहचान की जाएगी, जिससे उन्हें सही खेल में आगे बढ़ाया जा सके। मसलन, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पश्चिम में एथलेटिक्स और कुश्ती में संभावना है तो यहां इन खेलों में फोकस किया जाएगा। साई को तकनीकी मजबूती दिलाने के लिए उसके ढांचे में भी सुधार किया जाएगा। इसके लिए सर्वश्रेष्ठ कोच और खेल विज्ञान स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिससे ओलंपिक में बेहतर परिणाम पाए जा सकें।

इसी के साथ साई प्रयास कर रहा है कि खेल संसाधनों को खिलाड़ियों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए, इसमें खिलाड़ियों को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में फ्री चीजें उपलब्ध होंगी।

विवादों के बाद विश्व कप के दौरान भारतीय कप्तान ने दिया इस्तीफा

50 साल से ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ियों के क्रिकेट विश्व कप के दौरान शैलेंद्र का इस्तीफा

केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका : पाकिस्तान के खिलाफ 50 साल से ज्यादा उम्र के खिलाड़ियों के विश्व कप के दूसरे मैच से पहले शैलेंद्र सिंह ने भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ दी। शैलेंद्र ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका की वेटरंस क्रिकेट एसोसिएशन की उपस्थिति में मैंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि इस विश्व कप कमेटी के एक वरिष्ठ सदस्य के कार्यों की वजह से भारतीय टीम के साथ समझौता किया जा रहा था। मुझसे कहा गया कि अगले चार राउंड रॉबिन मैचों में से दो मैचों में मुझे दो खास खिलाड़ियों को शामिल करना और उन्हें खिलाना होगा। ये चार मैच भारत को पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, वेल्स और नामीबिया के खिलाफ खेलना है। आगे मुझे निर्देश दिया कि भारतीय चयन समिति से भारत को इंटरनेशनल वेटरंस क्रिकेटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया (आइवीसीसीआइ) के अध्यक्ष और प्रमुख कोच को हटाना होगा। उक्त व्यक्ति ने भारतीय क्रिकेट टीम की चयनसमिति का फैसला किया। यह क्रिकेट के प्रति निष्ठा और ईमानदारी के सिद्धांतों से परे है, जिसको मैं किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता और न ही इसमें शामिल हो सकता हूं। अपनी ईमानदारी बरकरार रखते हुए मैं इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का कप्तान बने नहीं रह सकता और ना ही खेलना जारी रख सकता हूं।

शैलेंद्र ने कहा कि भारतीय क्रिकेट के अपने 35 सालों के निष्कलंक रिकॉर्ड के दौरान मैंने कभी क्रिकेट की विश्वसनीयता के साथ ऐसा खिलवाड़ और छेड़छाड़ का ऐसा प्रयास नहीं देखा। आइवीसीसीआइ के अध्यक्ष और प्रमुख कोच अजॅय रॉय ने भी इस्तीफा दे दिया है। रॉय ने कहा कि वर्तमान स्थिति मेरे लिए अस्वीकार्य है। मैं बेहद परेशान हूं और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली भारतीय टीम से किनारा करता हूं।

ट्रंप के सुझाव को जापान के ओलंपिक मंत्री की ना

फैसला

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी ओलंपिक को एक वर्ष तक स्थगित करने की सलाह
- ओलंपिक मंत्री बोली, तय समय पर ही होगा खेलों का आयोजन

टोक्यो, एपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया था कि कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक को एक वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए, लेकिन जापान की ओलंपिक मंत्री सेइको हशीमोतो ने उनके सुझाव को नकार दिया है। हाशीमोतो ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद (आइओसी) और ओलंपिक आयोजन समिति खेलों को रद या स्थगित करने पर कैसा भी विचार नहीं कर रही है।

फिलहाल आइओसी और आयोजनकर्ता तय समय यानी 24 जुलाई से ओलंपिक कराने पर अड़े हुए हैं। ट्रंप ने कहा था कि बिना दर्शकों के ओलंपिक देखना अच्छा नहीं होगा। यह मेरा विचार है कि ओलंपिक को एक वर्ष के लिए स्थगित कर देना चाहिए। हाशिमोतो ने कहा कि टेलीविजन प्रसारणकर्ता और प्रायोजकों ने ओलंपिक में अरबों रुपये लगाए हैं और खेल कैलेंडर में बेहद कम जगह है जिसमें ओलंपिक कराया जा रहा है। सिर्फ विश्व युद्ध के समय ओलंपिक रद हुआ था। हम सर्वश्रेष्ठ करना चाहते हैं जिससे किसी को दिक्कत नहीं हो। हम अपना अधिक से अधिक जोर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ओलंपिक को रद करने से काफी प्रभाव पड़ेगा। इससे 11,000 ओलंपिक और 4,400 पैरालंपिक खिलाड़ियों, स्टाफ, एयरलाइंस, होटल पर फर्क पड़ेगा।

आइओसी ने गुरुवार को ही टॉर्च सेरेमनी ग्रीस में आयोजित की, जिससे ओलंपिक की आस बंधी है। 20 मार्च को यह टॉर्च जापान में पहुंचेगी। वहीं टोक्यो आयोजनकर्ताओं ने टॉर्च आगमन सेरेमनी को भी कम लोगों की मौजूदगी में आयोजित करने का फैसला किया है।

डब्ल्यूएचओ की सलाह मानेगा आइओसी : बाक

बर्लिन : आइओसी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने गुरुवार को कहा कि टोक्यो ओलंपिक को रद या स्थगित करने के मामले में हम विश्व स्वास्थ्य संगठन (आइओसी) की सिफारिशों का पालन करेंगे। जर्मन टेलीविजन एआरडी को दिए गए साक्षात्कार में बाक ने कहा कि आइओसी फरवरी के मध्य से ही इस मामले को लेकर डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों के संपर्क में है। हम उनकी सलाह का अनुसरण करेंगे। आइओसी अब भी टोक्यो में सफल खेलों के तैयारियों पर काम कर रही है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए अधिकतर देशों ने कड़े कदम उठाए हैं जिसके कारण कई ओलंपिक क्वालीफायर्स रद करने पड़े हैं और बाक ने भी माना कि क्वालीफाइंग प्रतियोगिताओं को लेकर गंभीर समस्या है। यहां हमें लचीला रवैया अपनाना होगा। प्रतियोगिताओं को स्थगित करके या क्वालीफिकेशन मानदंडों में बदलाव करके ऐसा किया जा सकता है। बाक ने कहा कि विशेषकर कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देशों के खिलाड़ियों को इन मुश्किल परिस्थितियों में उचित क्वालीफिकेशन देना जरूरी है।

विविध

झंडाजी के आरोहण के समय टूटा ध्वज दंड, सात घायल

जागरण संवाददाता, देहरादून

झंडेजी के आरोहण के समय ध्वज दंड का एक हिस्सा टूटकर श्रद्धालुओं पर आ गिरा। श्रद्धालुओं की सूझबूझ और अनुशासन के चलते भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने से बच गई। संयोग से समय रहते हालत नियंत्रित हो गए और बड़ा हादसा टल गया। झंडेजी के आरोहण के लिए उस वक्त मेला स्थल पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। हालांकि, घटनाक्रम में सात श्रद्धालु चोटिल हो गए। इन सभी का उपचार चल रहा है, डॉक्टरों ने इनकी हाल खतरे से बाहर बताई है।

दून की पहचान से जुड़े एतिहासिक झंडा मेले को लेकर श्री गुरुराम राय दरबार साहिब में पखवाड़े भर से तैयारियां चल रही थीं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से मेले के लिए संगतें यहां पहुंची हैं। शुक्रवार को तय कार्यक्रम के मुताबिक झंडेजी के आरोहण के लिए सुबह करीब आठ बजे तेज वर्षा व ओलावृष्टि के बीच पूजा-अर्चना का क्रम शुरू हुआ, जो दोपहर तीन बजे तक चला। इसके बाद ध्वज दंड आरोहण की प्रक्रिया शुरू हुई।

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 344 साल पुराने ऐतिहासिक झंडा मेले के दौरान शुक्रवार शाम झंडेजी का आरोहण करते समय ध्वजदंड टूटकर श्रद्धालुओं पर गिर गया। घटना के बाद ध्वज दंड के टूटे हिस्से को संभालते श्रद्धालु। राजेश बड़थ्वाल

श्री दरबार साहिब के सज्जादानशीन श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज, संगतों एवं श्रद्धालुओं की मौजूदगी में झंडे जी का आरोहण कर रहे थे कि तभी करीब पौने पांच बजे अचानक ध्वज दंड का एक हिस्सा टूटकर श्रद्धालुओं पर आ गिरा। इससे श्रद्धालु सकते में आ गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी ने भी संयम नहीं तोड़ा। ध्वज दंड टूटते ही वहां मौजूद सेवकों ने मानव श्रृंखला बनाकर अफरा-तफरी होने से रोक ली। ध्वज दंड के टूटे हिस्से की चपेट में आए सात श्रद्धालु घायल हो गए। उन्हें दरबार साहिब प्रबंधन ने एंबुलेंस के जरिये श्रीमहंत इंद्रेश चरण अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों की टीमें घायलों का उपचार कर कर रही हैं। इसके बाद देर शाम को झंडेजी के आरोहरण तय करने पर सहमति बनी। श्री दरबार साहिब के जनसंपर्क अधिकारी भूपेंद्र रतूड़ी ने बताया कि घटना कैसे हुई, यह तो जांच का विषय है।

देर शाम झंडेजी के आरोहण के साथ मेला विधिवत शुरू : झंडा मेला में ध्वज दंड टूटने की घटना के करीब दो घंटे बाद ही नए झंडेजी का आरोहण कर लिया गया। इसी के साथ एतिहासिक झंडा मेला विधिवत शुरू हो गया। दरबार साहिब प्रशासन के अनुसार ध्वज दंड जहां से टूटा था, उसका निचले हिस्से को हटाकर बाकी हिस्से का शाम छह बजकर 40 मिनट पर आरोहण किया गया है। आरोहण से पूर्व सभी पूजा-अर्चना की औपचारिकता भी पूरी की गईं। आरोहण के बाद श्री झंडेजी पर संगतों के शीश नवाने का सिलसिला शुरू हो गया व हजारों श्रद्धालुओं ने आर्शीवाद लिया।

बदरी-केदार मंदिर समिति में नियुक्तियों को लेकर विवाद

जागरण संवाददाता, चमोली

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में नियुक्तियों का मामला तूल पकड़ गया है। आरोप है कि ये नियुक्तियां बैक डेट में की गईं और इनमें नियमों का पालन भी नहीं किया गया है। शुक्रवार को जोशीमठ क्षेत्र की महिलाओं ने तहसीलदार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज उच्चस्तरीय जांच की मांग की। हालांकि मंदिर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल ने कहा कि ये नियुक्तियां नियमानुसार हैं और अस्थायी तौर पर की गई हैं।

गौरतलब है कि सरकार ने चार धाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया। अब श्री बदरी-केदार मंदिर समिति इसी बोर्ड में समाहित हो गई है। मंदिरों के रखरखाव की जिम्मेदारी इसी बोर्ड की है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हुई। सूची में उन लोगों के नाम हैं जिन्हें बोर्ड में समाहित होने से पूर्व समिति ने नियुक्ति दी है। तहसीलदार से मिलने आईं महिलाओं में शामिल पूर्व सभासद पूर्व सभासद ललिता देवी और रंजना शर्मा ने आरोप लगाया कि समिति का अस्तित्व समाप्त होने से ऐन पहले 17 लोगों को अवैध तरीके से नियुक्त किया गया है। उन्होंने मंदिर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति के एक्ट के मुताबिक नियुक्तियां तभी की जा सकती हैं जब मंदिर समिति की नियुक्ति समिति संस्तुति करे और इसका प्रस्ताव मानव संसाधन उप समिति को भेजे, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन करे बिना ही नियुक्त कर दिए गए। श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के निवर्तमान अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल ने कहा कि मंदिर समिति में हुई नियुक्तियां अस्थाई हैं।

फर्जी डिग्री मामले में मानव भारती विवि की रजिस्ट्रार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोलन

एसआइटी विश्वविद्यालय परिसर में छानबीन कर रही है। रजिस्ट्रार अनुपमा को शुक्रवार शाम करीब छह बजे विश्वविद्यालय परिसर से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
–अभिषेक यादव, एसआइटी प्रमुख एवं एसपी सोलन

हिमाचल प्रदेश के सोलन स्थित मानव भारती विश्वविद्यालय, कुमारहट्टी के फर्जी डिग्री मामले में पुलिस के विशेष जांच दल (एसआइटी) ने शुक्रवार को तीसरी गिरफ्तारी की।

विवि की रजिस्ट्रार अनुपमा को अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद शुक्रवार शाम को विवि परिसर से गिरफ्तार किया गया। वह कुल्लू जिले की निवासी हैं और कई माह से यहां रजिस्ट्रार के पद पर सेवाएं दे रही थीं। बताया जा रहा है कि डिग्रियों पर अकसर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं। ऐसे में अनुमान है कि विवि से वितरित फर्जी डिग्रियों पर भी उनके हस्ताक्षर होंगे। शुक्रवार को ही विवि के चेयरमैन की याचिका पर भी सुनवाई थी, लेकिन समय से पहले ही अर्जी को वापस ले लिया है। पुलिस चेयरमैन की तालाश के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

दो आरोपितों को 16 तक पुलिस रिमांड : मामले में पकड़े गए डाटा ऑपरेटर प्रमोद कुमार और असिस्टेंट सहायक मनीष गोयल को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। उनका रिमांड शुक्रवार को खत्म हो रहा था। पुलिस ने दोनों का रिमांड पांच दिन बढ़ाने के लिए अदालत से आग्रह किया। पुलिस ने कहा कि डाटा ऑपरेटर से अभी और पूछताछ की जरूरत है। कुछ रिकॉर्ड माधव विश्वविद्यालय राजस्थान से कब्जे में लेने हैं। इसके लिए वह आरोपित को साथ ले जाना चाहती है। इसके अलावा मनीष गोयल से पूछताछ के आधार पर अभी और गिरफ्तारियां करने के प्रयास में हैं।

तृणमूल विधायक ने बनवाईं तीन प्रतिमाएं, ताकि लोग उन्हें भूल न जाएं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

जान का खतरा

- महानगर से सटे गोसाबा से दो बार जीते विधायक ने बना रखी हैं प्रतिमाएं
- विधायक की सुरक्षा में तैनात हैं 11 पुलिस कर्मी, प्रशासन का दावा-नहीं है कोई खतरा

हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है। लेकिन जब सूबे के सत्तारूढ़ दल का विधायक दिन रात इस भय से त्रस्त हो कि उनकी हत्या हो सकती है और लोग उन्हें भूला सकते हैं तो बात कुछ अजीब लगती है। बात बंगाल की राजधानी कोलकाता से सटे दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा से लगातार दो बार जीते 71 वर्षीय तृणमूल विधायक जयंत नश्कर की है। उन्हें डर है कि उनकी हत्या हो सकती है और लोग उन्हें भूले नहीं इसीलिए उन्होंने अपनी दो आदमकद व एक आवक्ष प्रतिमा बना ली है। उक्त प्रतिमा को वह हर दिन सुबह उठने के बाद उसकी घंटों सफाई करते हैं।

गोसाबा के विधायक ने तीन साल पहले कोलकाता के कुम्हारटोली के एक मूर्तिकार को काम पर रखा था, उनसे उन्होंने फाइबर ग्लास और मिट्टी से अपनी दो आदमकद मूर्तियां तैयार कराई हैं।

कुछ वर्ष पहले अलीपुर सेंट्रल से चार कुख्यात अपराधी फरार हो गए थे। उन अपराधियों की फिर से गिरफ्तारी भी हो गई। उन लोगों ने पूछताछ में बताया था कि कुछ स्थानीय नेताओं ने नश्कर की हत्या के लिए उन लोगों को सुपारी दी थी। विधायक का कहना है कि जिले के तत्कालीन एसपी प्रवीण त्रिपाठी ने मुझे इस बारे में सूचित किया था। राज्य सरकार ने मेरी सुरक्षा को बढ़ाकर वाई श्रेणी का कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय मेरी सुरक्षा में 11 पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इसी भय की वजह से मैंने तब अपनी मूर्तियां बनवाने का फैसला किया ताकि अगर मैं मर भी जाउं तो लोग इन मूर्तियों के माध्यम से मुझे याद रखें।

नश्कर का कहना है कि वह तृणमूल में शुरू से ही हैं। उनके परिवार के सदस्यों को भी डर है कि मेरी हत्या हो सकती है। वे लोग हर समय मेरे बारे में खोजखबर लेते रहते हैं।

पांच बच्चों के पिता नश्कर ने कहा कि तृणमूल के भीतर ही मेरे कई दुश्मन हैं। ये नेता पहले अन्य दलों में थे तब से वे मेरे दुश्मन हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने मूर्तिकार की तलाश शुरू की। मूर्तिकार के लिए मुझे पांच बार कुम्हारटोली में जाना पड़ा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह सब करते हुए मुझे भी अजीब लगा लेकिन डर है इसीलिए मूर्तियां तैयार कराई हैं।

इन प्रतिमाओं को कुछ साल पहले बनाया गया, लेकिन किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। मूर्तियों को मैंने अपने घर के एक कमरे में रखा है। अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी एक बड़े कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने मूर्तियां देख ली और फोटो क्लिक किए। जब आप जैसे लोग पूछ रहे हैं तो मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा है।

यह पूछे जाने पर कि उनकी प्रतिमाओं को कहां स्थापित किया जाएगा तो उन्होंने कहा कि स्थानीय स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कहा कि उनकी प्रतिमा उस स्कूल में लगेगी, क्योंकि मैं उस स्कूल का 1993 से 2016 तक सचिव रहा हूं। अन्य दो के बारे में, सोचा नहीं है। अगर स्थानीय लोग चाहेंगे तो इसे वहां लगाएंगे जहां से वे विधायक बनते आ रहे हैं।

पार्टी जिला अध्यक्ष ने ली चुटकी, कहा- मजेदार है

इस मुद्दे पर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष शौकत मोला से जब पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें और अधिक मूर्तियों तैयार कराना चाहिए ताकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक कोने में एक मूर्ति स्थापित कर सकें। मोला ने कहा, मैंने कभी इस तरह की बात नहीं सुनी। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जिसे कोई समझ नहीं है। यह मजेदार है।

पटना में स्वाइन फ्लू से छह लोग संक्रमित

जासं, पटना : कोरोना की दहशत के बीच स्वाइन फ्लू लगातार पटना में पांव पसारता जा रहा है। महज आठ दिन में इसके रोगियों की संख्या छह हो चुकी है। इनमें से एक की हालत गंभीर है। उसे एक निजी नर्सिंग होम में वेंटीलेटर पर रखा है। सिविल सर्जन डॉ. राजकिशोर ने बताया कि स्वाइन फ्लू के पहले रोगी की पहचान छह मार्च को गायघाट निवासी के रूप में की गई थी। इसके बाद एक-एक करके छह मामले सामने आए। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी संक्रमितों के स्वजनों को भी एहतियातन दवाएं दी गई हैं।

मौसम विशेष

पंजाब, उत्तरी हरियाणा व दिल्ली में कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होगी। एक-दो स्थानों पर ओलावृष्टि संभव है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में घने बादल रहेंगे। अनेक स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा और बर्फबारी जारी रहेगी।

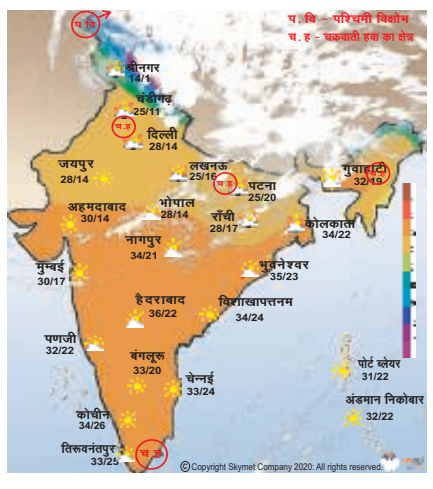

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	31/18/सा	अहमदाबाद	38/15/सा
कोलकाता	34/23/आंबा	बड़ौदा	39/16/सा
चेन्नई	33/25/आंबा	नागपुर	34/20/सा
हैदराबाद	35/23/आंबा	इन्दौर	29/12/आंबा
बंगलूरु	34/19/आंबा	रांची	27/16/आंबा
त्रिवेन्द्रम	34/25/आंबा	पटना	26/18/आंबा
गुवाहाटी	35/23/आंबा	जमशेदपुर	30/17/सा
गंगटोक	16/11/सा	पुणे	33/19/सा

राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

आजकल

शनिवार 14 मार्च 2020

16

www.jagran.com

देश की पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई

1931 में आज ही अर्देशीर ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। एक राजकुमार और जिप्सी लड़की की प्रेम कहानी पर आधारित इस फिल्म का कथानक जोसेफ डेविड पेनकर के पारसी नाटक से लिया गया था। 78 कलाकारों ने इस फिल्म में आवाज की रिकार्डिंग कराई थी।

परमाणु हथियारों से लैस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त

1961 में आज ही अमेरिकी वायुसेना का लड़ाकू विमान बी-52एफ कैलिफोर्निया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये दो परमाणु हथियारों से लैस था। सेफ्टी डिवाइस के पूरी तरह से काम करने के चलते परमाणु हथियार में विस्फोट नहीं हुआ और बड़ी अनहोनी टल गई।

सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन

आइंस्टीन का जन्म आज ही 1879 में तत्कालीन जर्मन साम्राज्य के उल्म शहर के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी गणित और भौतिक विज्ञान में विशेष रुचि थी। उनकी पहली शादी मिलेवा मैरिक से हुई। कुछ समय बाद दूसरा विवाह एल्सा से किया। उन्हें प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल मिला। सापेक्षता का सिद्धांत, कोशिकीय गति, अणुओं की ब्राउनियन गति समेत उनके कई योगदान हैं। वर्ष 1914 से 1932 तक वे बर्लिन में रहे। हिटलर की यहूदियों के प्रति घृणा देख कर आइंस्टीन अमेरिका चले गए। 18 अप्रैल 1955 में उन्होंने प्रिंस्टन के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली।

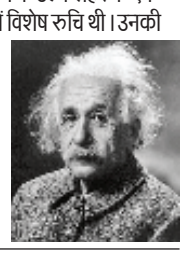

सौरमंडल में 139 नए छोटे ग्रहों की हुई खोज

रहस्यमय ब्रह्मांड ▶ ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए खगोलविदों ने नई प्रणाली का किया उपयोग

अब और आसान हो सकती है खगोलीय पिंडों की खोज

सौरमंडल में नेपच्यून से भी अधिक दूरी पर स्थित ग्रहों को टीएनओ कहा जाता है। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : खगोलविदों ने हमारे सौर मंडल में 139 नए ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स (टीएनओ) के साथ सौरमंडल से बाहर एक ग्रह भी खोजा है। टीएनओ ऐसे ग्रहों का कहा जाता है जो नेपच्यून यानी वरुण से भी ज्यादा दूरी पर स्थित हैं और सूर्य का चक्कर लगाते हैं।

नई खोज के बारे में 'एस्ट्रोफिजिकल जर्नल सप्लीमेंट सीरीज' में विस्तार से बताया गया है। साथ ही, इसमें एक जैसी वस्तुओं की खोज के लिए एक नई प्रणाली के बारे में भी बताया गया है। खगोलविदों का अनुमान है कि इस प्रणाली का उपयोग नए खगोलीय पिंडों की खोज के लिए किया जा सकता है।

अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैरी बर्नस्टीन ने कहा, 'आप जितने आसमान को देख पा रहे हैं और जितनी धुंधली चीजों को पकड़ पा रहे हैं, इसी पर नए टीएनओ की खोज भी निर्भर करती है।'

डार्क एनर्जी सर्वे के डाटा का किया उपयोग : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ता पेड्रो बर्नार्डिनेली ने एक अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट 'डार्क एनर्जी सर्वे' के चार साल के डाटा का उपयोग किया, जिसमें अंतरिक्ष में 700 करोड़ बिंदुओं का रिकॉर्ड है। शोधकर्ताओं ने इन बिंदुओं में से तारे, आकाशगंगाओं और सुपरनोवा को अलग-अलग किया। फिर भी इसमें 2.2 करोड़ खगोलीय पिंड मौजूद थे। इसके बाद अध्ययनकर्ताओं ने इनमें से 400 ऐसे संभावित खगोलीय पिंड चिह्नित किए जो छह या उससे अधिक रातों तक नजर आए थे। कई महीनों तक तस्वीरों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने 316 टीएनओ की सूची बनाई गई। इनमें से 139 पहली बार नजर आए थे। ये खगोलीय पिंड टीएनओ ही हैं, इसका पता लगाने के लिए बर्नार्डिनेली ने कई तस्वीरों को क्रमबद्ध करने का एक नया तरीका विकसित किया। इसका प्रयोग कर उन्होंने कई सामान्य पिंडों का अलग किया।

खोजे जा चुके हैं तीन हजार से टीएनओ : बता दें कि अब तक अब तक खगोलविदों ने सौर मंडल में प्लूटो सहित करीब तीन हजार टीएनओ का पता लगाया है। खगोलविदों का अनुमान है कि यह संख्या अंतरिक्ष में वास्तविकता में मौजूद टीएनओ का 10 फीसद है, जबकि 90 फीसद के बारे में अभी पता ही नहीं लग पाया है।

प्लूटो भी है टीएनओ

खगोलविदों को उम्मीद है कि नई विधि से भविष्य में वैज्ञानिक सैकड़ों नए टीएनओ खोज सकते हैं। उनका मानना है कि कई टीएनओ पृथ्वी से इतने दूर हैं कि उन्हें सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। सबसे चर्चित टीएनओ प्लूटो, पृथ्वी की तुलना में सूर्य से 40 गुना अधिक दूर है।

आकाश का हो सकता है सर्वेक्षण

शोधकर्ताओं का कहना है कि बर्नार्डिनेली द्वारा विकसित विधि का उपयोग आगामी खगोलीय सर्वेक्षणों में टीएनओ की खोज के लिए किया जा सकता है। इसके जरिये पूरे आकाश का सर्वेक्षण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि टीएनओ का यह कैटलॉग सौर प्रणाली के बारे में अनुसंधान के लिए एक उपयोगी वैज्ञानिक उपकरण सिद्ध हो सकता है और हमें अचरज भरे आकाश के बारे में कई रहस्यमय जानकारियां मिल सकती हैं।

दूषित हवा में सांस लेने से बढ़ता है मोटापा व मधुमेह

- अमेरिका की कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन
- कहा- वाहनों से उत्सर्जित होने वाली गैसें सूर्य के संपर्क में आने से हो जाती हैं विषाक्त

वायु प्रदूषण से पुरानी बीमारियों के उभरने की रहती है आशंका। फाइल

वाशिंगटन, प्रेट्र : वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इस बात की नए अध्ययन में भी पुष्टि की गई है। इसमें दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण आंत के बैक्टीरियाओं पर भारी असर पड़ सकता है, जिससे मोटापा, मधुमेह, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार के साथ-साथ अन्य पुरानी बीमारियों के भी उभरने की आशंका रहती है।

जर्नल 'इन्वायरनमेंटल इंटरनेशनल' में प्रकाशित यह पहला शोध है जिसमें बताया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य की आंत के माइक्रोबायोम की संरचना और काम करने का तरीका बदल जाता है। हमारे शरीर के भीतर रहने वाले खरबों सूक्ष्मजीवों के संग्रह को माइक्रोबायोम कहते हैं।

अमेरिका की कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि वाहनों से उत्सर्जित होने वाली गैसें जब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आती हैं तो वे बेहद खतरनाक हो जाती हैं। इन्हें 'गैसियस पल्यूशन ओजोन' कहा जाता है। अध्ययन में बताया गया है कि इसके उच्च स्तर के संपर्क में आने वाले वयस्कों में माइक्रोबियल डाइवर्सिटी कम हो जाती है और उन्हें मोटापे के साथ-साथ कई अन्य बीमारियां घेर सकती हैं।

प्रभावित होती है आंतों की कार्यप्रणाली : कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर तान्या एल्डेरेट ने कहा, 'पिछले कई अध्ययनों में हमें यह पता चल चुका है कि वायु प्रदूषक श्वास संबंधी बीमारियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इसका असर हमारी आंतों पर भी देखने का मिला है। वायु प्रदूषण के कारण इसकी पूरी कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है और समय पर उचित उपचार न दिए जाने पर जान का खतरा भी हो सकता है।'

प्रदूषण से होती है 88 लाख की मौत : अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण सालाना 88 लाख लोगों की जान चली जाती है। यह आंकड़ा धूमपान कारण मरने वालों से ज्यादा है।

शरीर की क्षमता भी होती है प्रभावित : एल्डेरेट ने कहा कि अभी तक जितने भी अध्ययन हुए हैं ज्यादातर में रेस्पिरेट्री हेल्थ (श्वसन स्वास्थ्य) पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि अध्ययन से पता चला है कि प्रदूषण रक्त शर्करा को विनियमित करने और मोटापे के लिए जोखिम को प्रभावित करने की शरीर की क्षमता को भी बाधित कर सकता है।

ऐसे किया अध्ययन

वायु प्रदूषण के कारण आंतों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी जांच करने के लिए शोधकर्ताओं ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के 101 युवाओं के मल के नमूनों का विश्लेषण करने के लिए अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया। उन्होंने ओजोन पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रस ऑक्साइड के की गणना करने के लिए प्रतिभागी के पते के पास एयर-मॉनिटरिंग स्टेशनों के डाटा का भी विश्लेषण किया। इस दौरान शोधकर्ताओं ने ओजोन का आंतों पर अब तक का सबसे बड़ा प्रभाव देखा। उन्होंने कहा कि ओजोन के संपर्क में रहने वालों में बैक्टीरिया की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण उनके बीमार होने का खतरा बना रहता है।

इधर-उधर की

चूक किसकी, इंटरनेट पर मचा संग्राम

मेलबर्न, एजेंसी : सड़क दुर्घटनाओं से हम रोज दो-चार होते हैं, लेकिन उसे भूलकर आगे के काम पर जुट जाते हैं। यहां एक कार और साइकिल सवार के बीच हुई टक्कर का किसी ने वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया तो गलती निकालने के लिए ऑनलाइन समुदाय दो हिस्सों में बंट गया। दरअसल, सड़क के एक टी प्वाइंट पर मुड़ती कार ने तेजी से आ रहे साइकिल सवार को टक्कर मार दी। साइकिल सवाल जिस दिशा से आ रहा था, उसके ठीक सामने सफेद रंग की एक वैन खड़ी थी, जिसके चलते सामने मुड़ती कार उसे नहीं दिखाई दी। ऐसा ही कुछ कार चालक के साथ भी हुआ होगा। बहरहाल, एक लाख से ज्यादा बार इस वीडियो को देखा जा चुका है। 1700 प्रतिक्रियाएं अब तक लोग दे चुके हैं। कुछ लोग कार चालक को गलत ठहरा रहे हैं तो कुछ उससे सहानुभूति जता रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों चालकों की गलती बता रहे हैं।

शुरुआती दौर में फ्लू जैसे लक्षण दिखा सकती है कीटो डाइट

- ऑस्ट्रेलिया की तस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता ने किया अध्ययन
- कहा-चार सप्ताह के बाद धीरे-धीरे घटने लगते हैं इसके लक्षण

यह अध्ययन फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। फाइल

सिडनी, आइएएनएस : हाल के वर्षों में कीटो या कीटोजेनिक डाइट का चलन बढ़ा है। इसमें कम कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं। इसके जरिये खास तौर से अभिनेता और अभिनेत्रियां खुद को फिट रखती हैं। एक नए अध्ययन में इस डाइट के दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। इसमें बताया गया है कि जब भी लोग अपना वजन कम करने के लिए कीटोजेनिक आहार लेना शुरू करते हैं तो शुरुआती हफ्तों में ही इससे व्यक्ति में फ्लू जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं।

फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन नामक जर्नल में प्रकाशित में बताया गया है कि ये लक्षण पहले सात दिनों में चरम पर होते हैं और चार सप्ताह के बाद धीरे-धीरे घटते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता इमैनुएल बोस्तेक ने कहा, 'कीटो डाइट से होने वाले फ्लू की रिपोर्ट यूं तो सामान्य ही रहती हैं पर फिर भी इससे थकान, मतली, चक्कर आना, ऊर्जा में कमी, बेहोशी और दिल की धड़कन में बदलाव आदि देखने को मिलता है।'

शोधकर्ताओं ने कीटो डाइट के दुष्प्रभावों को 'कीटो फ्लू' नाम दिया है। इसके लक्षणों के विकसित होने का पता लगाने के लिए उन्होंने 43 ऑनलाइन मंचों की पहचान की 101 लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों को मैन्युअल रूप से एकत्र किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया में इसके दुष्प्रभावों के बारे में पोस्ट किया था। हालांकि इस डाइट की आदद होने पर दुष्प्रभाव खुद-ब-खुद कम हो जाते हैं।

इसीलिए बढ़ रहा है इसका चलन : माना जाता है कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन से शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन का उत्पादन होता है। इससे शरीर में फैट जमा होने लगता है, जबकि कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करके फैट से ही ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस प्रक्रिया को कीटोसिस कहा जाता है। इस डाइट में फैट का सेवन ज्यादा, प्रोटीन का सेवन मध्यम और कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ली जाती हैं।

बढ़ती है हृदय रोगों की संभावना : कुछ डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि कीटो डाइट जल्दी वजन घटाने का कारण बन सकता है, लेकिन दीर्घकालिक मामले में यह अन्य आहारों की तुलना में अधिक प्रभावी नहीं है। कुछ विशेषज्ञ इसे चिंताजनक भी बताते हैं क्योंकि यह उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन को प्रोत्साहन देता है, जिनसे हृदय रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है।

पाचन तंत्र पर असर डालती है कीटोजेनिक डाइट

कीटो या कीटोजेनिक डाइट के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। इसे आहार का हिस्सा बनाने से व्यक्ति को आपको पर्याप्त मात्रा में फाइबर और पोषक तत्व नहीं मिल पाते और कम कार्बोहाइड्रेट लेने का सीधा प्रभाव आपके पाचन तंत्र पर पड़ता है। इससे व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे शरीर की मांसपेशियों में अकड़न, खिंचाव और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिसका प्रमुख कारण इलेक्ट्रोलाइट में गड़बड़ी होना है। आम तौर पर शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर यह समस्या सामने आती है। कीटो डाइट में भूख कम लगती है शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। कई मामलों में कीटो डाइट के चलते विटामिन्स की कमी के मामले भी सामने आए हैं।

फोटो न्यूज

अंतरिक्ष में जाने के लिए परीक्षा

रूस के स्टार सिटी में स्थित कॉस्मोनॉट परीक्षण केंद्र में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अभियान के सदस्य इवान वैगनर अंतिम परीक्षा की तैयारियों में जुटे हैं। अंतरिक्ष जाने वाले यात्रियों को यहां कठिन परीक्षा और परीक्षण से गुजरना पड़ता है। नए मिशन का शुभारंभ नौ अप्रैल से कजाखिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से होगा। ईपीए

लिवर कैंसर के खतरे को कम करती है एस्प्रिन

शोध अनुसंधान

दर्द और बुखार से राहत पाने में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली एस्प्रिन दवा का एक नया फायदा सामने आया है। एक अध्ययन में पाया गया है कि एस्प्रिन की निम्न खुराक के सेवन से लिवर कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, इस दवा से खासतौर पर उन लोगों को फायदा हो सकता है, जिनमें लिवर कैंसर का उच्च खतरा होता है। ऐसे लोग अगर एस्प्रिन की निम्न खुराक लेते हैं तो इस बीमारी की चपेट में जाने की आशंका कम हो सकती है। यह निष्कर्ष लिवर संक्रमण से पीड़ित करीब 50 हजार वयस्कों किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। अमेरिका के मैसाच्युसेट्स जनरल हॉस्पिटल के शोधकर्ता ट्रेसी सिमोन ने कहा, 'लिवर कैंसर की दर और लिवर डिजीज से मृत्युदर बढ़ती जा रही है। फिलहाल लिवर कैंसर की रोकथाम या लिवर कैंसर के कारण मौत के खतरे को कम करने के लिए कोई स्थापित उपचार नहीं है।' -आइएएनएस

हार्ट अटैक से उबरने में स्टेम सेल्स की नई भूमिका का लगाया पता

शोधकर्ताओं ने हार्ट अटैक से उबरने में स्टेम सेल्स की नई भूमिका पाई है। उन्होंने दिल का दौरा (हार्ट अटैक) पड़ने के बाद स्वस्थ होने में ऐसे तंत्रों का पता लगाया है, जिन्हें स्टेम सेल सक्रिय करती हैं। स्टेम सेल्स कार्डिक मसल्स को चंगा करती हैं। इस नई खोज से यह पता चल सकता है कि यह सेल्स किस तरह काम करती हैं। अमेरिका के मायो क्लीनिक के शोधकर्ता आंद्रे टेरजिक ने कहा, 'हार्ट अटैक के चलते कितना बदलाव आया, वह हृदय के लिए खुद को दुरुस्त करने या आगामी नुकसान की रोकथाम के लिहाज से बेहद अहम होता है। हालांकि कार्डियोपोएटिक स्टेम सेल थेरेपी पूरी या आंशिक तौर पर उबार सकती है। हृदय को उबरने में स्टेम सेल्स के वास्तविक काम को अभी तक अच्छी तरह समझा नहीं जा सका है।' शोधकर्ताओं का कहना है कि अब हृदय रोग के उपचार की नई विधियों का विकास भी संभव हो सकता है। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

कोरोना वायरस से बचने के सुझावों पर अमिताभ ने लिखी कविता...

कोरोना वायरस को लेकर मचे कोहराम को देखते हुए सेलिब्रिटीज भी आगे बढ़कर अपने प्रशंसकों को इससे बचने के उपाय और सावधानियां बता रहे हैं। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने प्रशंसकों को एक अलग अंदाज में कोरोना से बचने के उपाय बताए हैं। गुरुवार की रात उन्होंने सोशल मीडिया पर कविता पढ़ते हुए एक वीडियो साझा किया। इस कविता में वह लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बता रहे हैं। कविता की पंक्तियां यूं हैं :

बहुतेरे इलाज बतावें, जन जनमानस सब,
केकर सुनैं, केकर नाहीं, कौन बताए ई सब
केयु कहिस कलौंजी पीसौ, केयु आँवला रस
केयु कहस घर में बैठो, हिलो न टस से मस
ईर कहेन औ बीर कहेन, कि ऐसा कुछ भी करो ना,
बिन साबुन से हाथ धोई के, केहू के भैया छुओ ना
हम कहा चलो हमौ कर देत हैं, जैसन बोलैं सब
आवय देयो, करोना-फिरोना, ठेंगुआ दिखाउब तब!

इस कविता में अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस से बचने के लिए विभिन्न लोगों से मिलने वाले सुझावों का उल्लेख किया है।

अनुष्का ने साझा कीं 'एनएच 10' की यादें

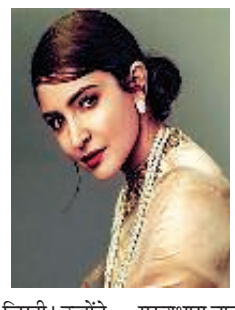

अभिनेत्रियां फिल्मों में अभिनय करने के अलावा खुद को निर्माण के क्षेत्र में भी साबित कर रही हैं। अनुष्का शर्मा उन्हीं अभिनेत्रियों में शुमार हैं। पांच साल पहले उन्होंने फिल्म 'एनएच 10' का निर्माण किया था। फिल्म में नील भूपलम और अनुष्का ने अभिनय किया था। शुक्रवार को इस फिल्म की रिलीज के पांच साल पूरे होने पर अनुष्का ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, 'एनएच10 को बनाने का फैसला मेरे लिए काफी स्वाभाविक था। मैं कुछ अलग करना चाहती थी, दर्शकों का मनोरंजन करना चाहती थी। मैं उन्हें कुछ ऐसा देना चाहती थी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है। मैं 25 साल की थी। मुझे फिल्म निर्माण का कोई अनुभव नहीं था। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर इस प्रोडक्शन हाउस की ईंट जोड़ी है। मैं आश्वस्त थी कि इस फिल्म के साथ हम मनोरंजन का विस्तार कर पाएंगे। एक कलाकार के तौर पर, मैंने अपने पूरे करियर में मुद्दापरक कंटेंट का समर्थन किया है और ऐसी फिल्म बना पाए हैं। हमने नॉन कॉमर्शियल मुख्यधारा वाली फिल्में बनाई हैं। हमारी कंपनी ने जो बनाया है, उस पर मुझे गर्व है। शुरुआत 'एनएच 10' से हुई थी।' फिलहाल, अनुष्का शर्मा महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी की बायोपिक में काम कर रही हैं।

बचपन को दुलारते हुए पचपन के आमिर खान...

आमिर खान आज (14 मार्च को) अपना जन्मदिन मना रहे हैं। वह 55 साल के हो गए हैं। पिछले जन्मदिन पर आमिर ने अपनी नई फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' की घोषणा की थी। इन दिनों आमिर खान अमृतसर में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में आमिर की एक तस्वीर सामने आई है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल, यह तस्वीर 'लाल सिंह चड्ढा' के सेट की है। आमिर एक प्यारे से बच्चे को गोद में लिए हुए हरियाली के बीच में खड़े हैं। आमिर क्लीन शेव्ड नजर आ रहे हैं। इससे पहले उनकी जो तस्वीर फिल्म को लेकर सामने आई थी, उसमें वह सरदार के किरदार में दिखे थे। आमिर की यह तस्वीर अभिनेता और गायक गिप्पी ग्रेवाल ने शेयर की है। दरअसल, आमिर की गोद में जो बच्चा है, वह गिप्पी का बेटा है, जिसका नाम गुरबाज सिंह ग्रेवाल है। तस्वीर को साझा करते हुए गिप्पी ने लिखा है- 'आमिर खान भाई के लिए बहुत इज्जत है।' 'लाल सिंह चड्ढा' फिल्म हॉलीवुड फिल्म 'द फॉरेस्ट गंप' की आधिकारिक रीमेक होगी।

...तो एक्टिंग छोड़ देंगी कंगना : रंगोली चंदेल

सोशल मीडिया पर कुछ मजेदार, तो कुछ अजब-गजब चैलेंजेज चलते रहते हैं। बात करें अगर कंगना रनोट की बहन रंगोली चंदेल की, तो अब उन्होंने हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियों को खुली चुनौती दे दी है। अपने ट्वीट्स की वजह से चर्चा में रहने वाली रंगोली ने लिखा, 'मैं इंडस्ट्री को चैलेंज देती हूं। क्या कंगना के अलावा कोई अभिनेत्री है, जो 60-100 करोड़ के फिल्म की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकती है? अगर ऐसा कोई नाम है, तो कंगना एक्टिंग करना छोड़ देंगी।' पिछले दिनों अहमद खान ने कंगना की फिल्म 'मणिकर्णिका' पर सवाल उठाए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि कंगना की 'धाकड़' फिल्म रुक गई है, जिसके बाद कंगना और 'धाकड़' के निर्देशक ने अहमद को नोटिस भेजने की बात कही थी। इस ट्वीट के जवाब में रंगोली ने कई ट्वीट्स किए थे। रंगोली ने यह भी कहा कि ट्वीट में रंगोली ने एक बार फिर आलिया पर कमेंट करते हुए लिखा, 'आलिया को 'गंगूबाई काठियावाड़ी' फिल्म 'राजी' की वजह से मिली। संजय लीला भंसाली के बिना उन्हें यह फिल्म नहीं मिलती।' रंगोली के चैलेंज पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा, 'तापसी, रानी, विद्या, दीपिका, कट्टीना, प्रियंका, अनुष्का, करीना, भूमि, यामी.. लिस्ट बहुत लंबी है।'

लड़की को थप्पड़ मारने पर भड़कीं नेहा, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

इन दिनों एम टीवी के रियलिटी शो 'रोडीज रेवोल्यूशन' में बतौर जज नजर आने वाली अभिनेत्री नेहा धूपिया गुरुवार को ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी थीं। दरअसल, शो के एक प्रतिभागी ने बताया कि जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड के उसके अलावा पांच ब्वॉयफ्रेंड्स हैं, तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा। यह सुनकर नेहा भड़क गईं। उन्होंने उस लड़के को फटकार लगाते हुए कहा कि गलती उसकी ही होगी। वह लड़की को खुश नहीं रख पाया होगा, तभी वह धोखा दे गई। नेहा ने कहा कि अगर वह पांच लड़कों के साथ है, तो यह उसकी च्वॉइस है। ये बातें उस लड़की को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं देतीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर नेहा के मीम्स बनने लगे। एक मीम में लिखा गया है कि मैं चार लड़कियों के साथ हूं। अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर रहा हूं। मेरी गर्लफ्रेंड को पता चल गया है। वह मुझे धमकी दे रही है। क्या आप मेरे लिए एक वीडियो बना सकती हैं कि यह मेरी च्वॉइस है। वह वीडियो मैं उसे भेज दूंगा। केवल आप ही मुझे इस हालात से निकाल सकती हैं। एक मीम में एक डॉग बनाया गया है, जो फटी आंखों के साथ इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। एक यूजर ने लिखा कि अगर उनके पति उन्हें चीट करेंगे, तो क्या नेहा का यही जवाब होगा कि यह उनकी च्वॉइस थी? एक अन्य यूजर ने लिखा कि नेहा की यह वीडियो क्लिप देखने के बाद जो वास्तविक फेमिनिस्ट्स हैं, वे भी बेहोश हो गई हैं। नेहा के साथ शो के दूसरे जज निखिल चिनप्पा को भी ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि वीडियो के बीच में उनकी भी आवाज आ रही है, जिसमें वह नेहा की बात से सहमत हैं। इस बीच नेहा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

...जब साथ आए कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर

कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच की कड़वाहट से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। एक झगड़े के बाद सुनील ने कपिल का कॉमेडी शो भी छोड़ दिया था। कपिल द्वारा माफी मांगने पर भी दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए। दर्शक उनकी जोड़ी को फिर साथ लाने की इच्छा जताते रहे। सलमान खान ने दोनों की सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन विफल रही। हालांकि सुनील ने कपिल की शादी पर उन्हें विश जरूर किया था। अब एक शादी के आयोजन में दोनों लंबे वक्त बाद एक ही फ्रेम में दिखे। दरअसल, कपिल, गायक मीका सिंह और सुनील ग्रोवर के कॉमन दोस्त कपिल कुमारिया की बेटी की शादी पर ये दोनों मंच पर एक साथ थिरकने उतरे। डांस के वीडियो को उनके दोस्त ने ही सोशल मीडिया पर साझा किया था, जिसे कपिल ने रीट्वीट भी किया।